राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2	सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का इक्कीसवां दिवस	संख्या: 12

मंगलवार,
23 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री अमृतलाल मीणा।

बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने की कार्ययोजना

173. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत उच्चतम न्यायालय ने निर्णय पारित किया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रदेश में बंधुआ श्रमिकों का सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): (1) बंधक श्रमिक की शिकायत/सूचना प्राप्त होने पर बंधक श्रम पद्धति (उत्साधन) अधिनियम, 1976, राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया तथा केन्द्रीय बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना-2021 के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां। बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, के तहत् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बंधुआ श्रमिक मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ व अन्य के प्रकरण में जारी निर्णय दिनांक 16.12.1983 की प्रति निर्णय की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु इंटरनेट लिंक https:// webapi.sci.gov.in/jonew/judis/9643.pdf पर उपलब्ध है।

(3) केन्द्रीय क्षेत्र बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना-2021 के तहत् 3 वर्ष में एक बार सर्वे करवाया जाना अपेक्षित है। तदापि बंधक श्रम उन्मूलन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी मानक

संचालन प्रक्रिया दिनांक 03.05.2017 के तहत् उपखण्ड स्तर पर बंधक श्रमिकों से संबंधित सूचना वर्ष में 2 बार संकलित की जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बंधक श्रमिकों के सर्वे की क्या प्रक्रिया है और राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में बंधक श्रमिक उन्मूलन हेतु कहां-कहां, क्या-क्या कार्यवाही की गई और आगे इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सर्वे लगातार करना एक सतत प्रक्रिया है। अभी जो स्पेशल केन्द्रीय सर्वे किया जा रहा है, वह पिछले तीन वर्ष में कोटा, जयपुर, श्रीगंगानगर में किया जा चुका है और अभी उदयपुर में सर्वे चल रहा है। निरंतर सर्वे की प्रक्रिया जिला कलेक्टर के माध्यम से विजिलेंस कमेटी बनी हुई है, उनके माध्यम से निरंतर यह प्रक्रिया की जा रही है और लगातार कार्यवाही प्रगतिशील है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की क्या प्रक्रिया है? विगत तीन वर्षों में कितने बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास हुआ है?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुनर्वास हेतु नियम यह है कि अधिनियम के अंतर्गत उन्मुक्त कराये गये श्रमिक के पुनर्वास का दायित्व जिला प्रशासन पर है। जिला प्रशासन विभिन्न विभागों से उन्मुक्त श्रमिक का आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास करता है। जिसमें तात्कालिक सहायता के रूप में 30 हजार रुपये तथा पुनर्वास हेतु विभिन्न श्रेणियों के लिये 1 लाख से 3 लाख मय तात्कालिक सहायता रुपये 30 हजार, पुनर्वास के प्रावधान किये गये हैं। उन्मुक्त कराये गये बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु शेष राशि का भुगतान नियोजक के दोषी सिद्ध होने के उपरांत उनके मूल निवास से सम्बन्धित जिला कलेक्टर के स्तर से कराया जाता है और जो आंकड़ा आप चाह रहे हो, वह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

कर संग्रहण से प्राप्त राशि

174. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक जीडीपी और कर संग्रहण कितना था? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में प्रदेश पर कर्ज का भार बढ़ा है? यदि हां, तो कर्ज सहित चुकाये गये ब्याज का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में सरकार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, आवास व समाज कल्याण पर किये

गये व्यय का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में वेतन व भत्तों पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): (वित्त मंत्री के स्थान पर): (1) प्रदेश में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक जीडीपी और कर संग्रहण की सूचना निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये करोड़ में)

वर्ष	जीएसडीपी		राज्य का स्वयं का कर राजस्व
	प्रचलित मूल्यों पर	स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	
2018-19	911519	643278	57380.34
2019-20	1000032	678316	59244.98
2020-21	1017917	665963	60283.44
2021-22	1194961	725586	74807.98
2022-23	1357851	782287	87346.38
2023-24	1528385	845115	110600.52 (RE 2023-24)

जीएसडीपीः वर्ष 2021-22 संशोधित अनुमान तृतीय, वर्ष 2022-23 संशोधित अनुमान द्वितीय एवं वर्ष 2023-24 द्वितीय अग्रिम अनुमान।

(2) जी हां, उक्त अवधि में प्रदेश पर कर्ज का भार बढ़ा है। उक्त अवधि में कर्ज सहित चुकाये गये ब्याज का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के अन्त में बकाया लोक ऋण	चुकाया गया लोक ऋण	लोक ऋण पर चुकाया गया ब्याज	योग
1	2	3	4	5 (3+4)
2018-19	233238.88	16914.80	17762.67	34677.47
2019-20	259379.91	20032.68	19190.09	39222.77
2020-21	308320.93	41022.98	20663.85	61686.83
2021-22	353556.07	56128.17	23011.61	79139.78
2022-23	388383.87	125737.61	25318.96	151056.57
2023-24 (RE)	443767.37	173872.85	28322.92	202195.77

(3) शिक्षा, चिकित्सा, आवास और समाज कल्याण पर व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये करोड़ में)

वर्ष	शिक्षा	चिकित्सा	आवास	समाज कल्याण
2018-19	34988.08	11861.49	65.94	6805.76
2019-20	33917.26	12143.86	86.67	9223.63
2020-21	35779.08	12620.00	92.97	10467.44
2021-22	40409.63	16311.78	115.65	12177.15
2022-23	44713.23	15445.21	131.89	11365.52
2023-24(RE)	58505.25	23972.72	160.40	13536.53

(4) वेतन और भत्तों पर वर्षवार व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय
2018-19	49232.68
2019-20	48577.42
2020-21	51158.49
2021-22	56685.52
2022-23	59378.17
2023-24(RE)	70215.68

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने लिखित में अपना जवाब दे दिया है। अगर आपकी सहमति हो तो मैं पूरक प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक राज्य का कुल ऋण कितना था और विगत पांच वर्षों में, 2018 से 2024 तक कुल कितना ऋण सरकार ने लिया? कृपया एक तो यह बताएं। दूसरा, आपके द्वितीय बिन्दु में गत सरकार के पांच वर्षों में चिकित्सा क्षेत्र में औसत वार्षिक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा तथा वर्तमान सरकार द्वारा कितना प्रस्तावित किया गया है, बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारी गत सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 को राज्य में कुल ऋण और दायित्व 2,81,182 करोड़ रुपये था। वर्ष 2023-24 में कांग्रेस शासन काल में राज्य के ऋण व अन्य दायित्व दुगुना से भी अधिक बढ़कर 5,70,646 करोड़ रुपये पहुंच गये, जिसके फलस्वरूप राज्य के ब्याज भुगतान में अत्यधिक वृद्धि हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगी कि

1950-51 से 2017-18 तक, मतलब 67 वर्षों में भी राज्य सरकार का कुल ऋण व दायित्व 2,81,182 करोड़ रुपये था, जबकि कांग्रेस सरकार द्वारा 67 वर्षों में जितना ऋण लिया गया, वह उन्होंने पांच वर्षों में लिया और ऋण लेकर राज्य पर भार 2,89,464 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया। इस तरह पिछली सरकार का डेट टू जीएसडीपी रेश्यो 2017-18 में 33.77 प्रतिशत था और 2023-24 में 37.34 प्रतिशत था, मतलब 4 परसेंट इन्क्रीज हो गया है। हमने हमारे प्रथम पूर्ण बजट में डेट टू जीएसडीपी रेश्यो में कमी करते हुए इसे 35.97 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रयास किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारे चिकित्सा में कितना व्यय किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक विस्तार करने के लिये वित्तीय वर्ष में हमने करीब 27,660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत है। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि यह राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख की बात है कि दुगुना से भी ज्यादा ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भाषण नहीं, भाषण नहीं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): भाषण नहीं दे रहा हूं। आप नहीं, अध्यक्ष महोदय पूछेंगे। आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं? बैठिए चुपचाप, फालतू की बात नहीं। ...(व्यवधान)... सरकार को कर्जे से लाद दिया, राजस्थान के लोगों को कर्जे से लाद दिया, ऊपर से भाषण वाली बात करते हो। ...(व्यवधान)... शर्म नहीं आती है आप लोगों को। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप बैठिए, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... मिस्टर रोहित, अगली बार खड़े हुए तो You will be out. विपक्ष के नेता बैठे हैं और आपको खड़े होने के लिये किसने कहा? माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने दो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): यह तो मेरा अधिकार है, इसको कैसे रोकोगे आप? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हां पूछिए। ...(व्यवधान)...आप बैठिए, आप बैठिए। दूसरा पूरक प्रश्न पूछना माननीय सदस्य का अधिकार है, उसमे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इस सदन को चलाना, किस माननीय सदस्य को बुलाना, व्यवस्था रखना, यह आसन का काम है। कोई जबरदस्ती बीच में ही शुरू हो जाए तो मेरा मानना है कि उनको टोका जाये, टोकने के बाद नहीं माने तो नामित किया जाये, नामित के बाद भी नहीं माने तो फिर दूसरी व्यवस्था की जाये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से गत सरकार ने इस राजस्थान को कर्जे में डाला, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि आगे

आने वाले इन पांच सालों में वह क्या योजना रखती हैं? इस विषय में हमें थोड़ी जानकारी दें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने वर्ष 2024-25 के परिवर्तित अनुमानों के अनुसार कुल ऋण व दायित्व 6,40,687 करोड़ 27 लाख रुपये अनुमानित किया है। एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार इसे जीएसडीपी का 38.20 प्रतिशत तक लाया जाना वांछित है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह चौहान। एक सैकण्ड।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, वह पिछले पांच वर्षों का दिया है। इस वर्ष सरकार ने कितना ऋण लेना प्रस्तावित किया है?

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी यही बताया था कि वर्ष 2024 के परिवर्तित बजट अनुमानों के अनुसार कुल ऋण व दायित्व 6,40,687 करोड़ 27 लाख रुपये होना अनुमानित है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

चित्तौड़गढ़ में मगरा विकास योजना

175. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ की पंचायत समिति चित्तौडगढ़ एवं भदेसर में घाटा क्षेत्र के कौन-कौनसे ग्राम मगरा विकास योजना के अन्तर्गत पात्रता रखते हैं? क्या इस हेतु विगत पांच वर्षों में सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के मगरा (घाटा) क्षेत्र में आने वाले ग्रामों को मगरा विकास योजना में सम्मिलित कर विकास कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): (1) मगरा क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत सर्वे में निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करने वाले ग्राम ही योजना में सम्मिलित होने की पात्रता रखते है। जिला कलेक्टर चित्तौडगढ को घाटा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में से मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्रता रखने वाली ग्राम पंचायतों का सर्वे द्वारा चिन्हीकरण कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु विभागीय दिनांक 06.06.2024 को पत्र प्रेषित किया गया है| (संलग्न परिशिष्ट-1)

जी नहीं।

(2) जी हाँ। जिले से सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर

योजनान्तर्गत नवीन ग्रामों को शामिल किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

msk/rtm/23.07.2024/1110/1b

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह क्वेश्चन 2016 में भी था, 2022 में भी था। मगरा योजना के तहत मेरे यहां 83 गांव आते हैं। सर्वे भी हो गया, कलेक्टर साहब की रिपोर्ट भी आयी। 2022 में काफी गांव हुए, पर मेरा विधान सभा क्षेत्र वंचित रह गया। मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा समय बता दें, क्योंकि 2016 में क्वेश्चन था तो भी यही सर्वे हुआ। 83 गांवों की रिपोर्ट आयी। 2022 में क्वेश्चन था, उस टाइम भी रिपोर्ट आ गयी। सब कुछ हो गया और अभी भी रिपोर्ट आ गयी। मेरे को आप समयावधि दे दें कि इतने समय में इन गांवों को मगरा योजना में ले लिया जायेगा, इतना बता दें।

श्री अध्यक्ष: बताइये।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय सदस्य के मगरा क्षेत्र में 83 पंचायतें हैं। 2016 से लेकर 2022 में भी आपका क्वेश्चन लगा, परन्तु राजनीति द्वेषता के कारण बीच में रह गया तो आने वाले समय में जल्दी ही कर देंगे। मैं समझता हूं कि दो महीने के अन्दर इसका समाधान करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा डायलिसिस मशीन की खरीद

176. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा डायलिसिस मशीनें व एनीमिया कार्ड महंगे दामों पर खरीदे गए थे? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि खरीदे गए उपकरणों की जांच की गयी थी? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) पूर्ववर्ती सरकार के समय आरएमएससीएल द्वारा डायलिसिस मशीनें व एनीमिया कार्ड महंगे दामों पर नहीं खरीदे गये हैं। डायलिसिस मशीन व आर.ओ. सिस्टम दिनांक 18.04.2023 को खुली निविदा के माध्यम से टर्नकी आधार पर 364 डायलिसिस मशीन व 182 आरओ सिस्टम हेतु निविदा आमंत्रित की गई। आरटीपीपी एक्ट, 2012 व आरटीपीपी रूल्स, 2013 के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपकरणों के क्रय से पूर्व उपकरणों की दरों का बाजार सर्वे करवाने के पश्चात दरें औचित्यपूर्ण पाये जाने के पश्चात दिनांक 04.10.2023 को LOA जारी किया गया।

एनीमिया कार्ड (सिकल सैल कार्ड):- दिनांक 27.09.2023 को खुली निविदा के माध्यम

से 35 लाख सिकल सैल कार्ड हेतु निविदा आमंत्रित की गई। आरटीपीपी एक्ट, 2012 व आरटीपीपी रूल्स, 2013 के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपकरणों के क्रय से पूर्व उपकरणों की दरों का बाजार सर्वे करवाने के पश्चात दरें औचित्यपूर्ण पाए जाने के पश्चात दिनांक 11.12.2023 को LOA जारी किया गया।

(2) हां। खरीदे गये उपकरणों की तकनीकी समिति द्वारा भौतिक परीक्षण (डेमो) के माध्यम से उपकरणों की जांच करवायी गयी एवं उपकरणों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई। जांच में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने आपको जवाब लिखकर दे दिया और आपने इसको पढ़ दिया। यह बिल्कुल गलत जवाब है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पड़ोसी राज्यों कर्नाटक में 13 लाख 41 हजार 776 में, गुजरात में 15 लाख 32 हजार में, केरल में 12 लाख 56 हजार 800 में, महाराष्ट्र में 11 लाख 49 हजार में तो राजस्थान में यह 21 लाख 19 हजार 516 में डायलिसिस मशीनें खरीदी गयीं, जबकि दूसरी जगह पर 12-13 लाख पर और आप यहां 21 लाख में खरीद रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि दाम बिल्कुल सही हैं। इसी प्रकार से टेण्डर में एक ही व्यक्ति की तीन फर्म, उसमें से एक को टेण्डर दिया। तीनों का आपस में लेनदेन। उनके स्पष्टीकरण को ही आपने सही मान लिया। इतना ही नहीं, टेण्डर शर्तों में शिथिलता देने का प्रजेंटेशन टेण्डर भरने के एक दिन पहले जिस फर्म ने दिया, उसी फर्म का आपने वर्क ऑर्डर दे दिया। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि डायलिसिस मशीनों को कांट्रेक्ट पर लेने का निर्णय पूर्ववर्ती सरकार ने उस समय किया था? यदि हां तो टेण्डर किसके आदेश पर किया गया? सीएचसी पर तो डायलिसिस करने वाले डॉक्टर ही नहीं हैं तो ये डायलिसिस मशीनें वहां पर किसके आदेश से भेजीं? मैं यही पूछना चाहूंगा, फिर दुबारा पूछूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 364 डायलिसिस मशीनें, आरओ प्लांट, उसके साथ में एयर कंडीशनर्स, पलंग, जो भी हैं। इसकी प्रक्रिया 08.02.2022 को शुरू की गयी। पहली बिड/निविदा 08.02.2022 को हुई, उसमें कोई भी बिडर सही नहीं पाया गया। सबको टेक्निकली डिस-क्वालीफाई किया गया। इसमें एक कंडीशन रखी थी कि मेन्युफैक्चरर और जो इम्पोर्टर है, उसी का माल लिया जायेगा। यह फर्स्ट बिड थी। जो द्वितीय बिड थी, वह 23.08.2022 को हुई, उसमें डायलिसिस मशीन, आरओ, एसी और आईसीयू बेड, इसको एक साथ क्लब कर लिया था। इसके अन्दर कोई भी बिडर नहीं आयी। जो तीसरी बिड हुई, 21.10.2022 को। वह टर्नकी हुई। उसके अन्दर, क्योंकि पहली बिड में कोई नहीं आया था। मैन्युफेक्चरर, डायरेक्ट इम्पोर्टर, ऑथोराइज्ड डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबको बुला लिया और इसके अन्दर भी मशीन, आरओ, एसी और आई.सी.यू. बेड को लगाया। वे तीनों की बिड्स कैंसिल हो गयीं। चौथी बिड 18 अप्रेल, 2023 को हुई। सेम कंडीशंस थीं, जो बिड नंबर 3 थी, पर उसमें पलंग और एसी हटा दिये गये।

खाली डायलिसिस मशीन और आरओ इसके अन्दर आया। दो फर्म ने पार्टिसिपेट किया, अपरामया इंजीनियरिंग लिमिटेड और रिवा फार्मास्यूटिकल ने। अपरामया को यह डील दी गयी और रिवा के पेपर इन्कम्पलीट होने के कारण एवं इनकी पास्ट परफोर्मेंस सही नहीं होने के कारण इनको डिस-क्वालीफाई किया गया। यह रिवा फर्म अपील में गयी, एनएचएम में। इसकी अपील रिजेक्ट हुई। फिर यह दुबारा 11.12.2023 को सैकिण्ड अपील में गयी, एसीएस मेडिकल हेल्थ में यह अपील 04.01.2024 को रिजेक्ट की गयी। ये जितने भी तथ्य हैं, मुझे ये डिपार्टमेंट से प्राप्त हुए हैं, मैंने जितने भी बताया हैं।

माननीय सदस्य, ये हमारे वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एमएलए हैं और आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी रहे हैं। आपने एक जो ईश्यू बोला था कि ये वेरिएबल्स क्यों हैं? दूसरे स्टेट में और हमारे स्टेट के अन्दर वेरिएबल्स क्यों हैं ? इसके तीन-चार कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है कि किसी स्टेट ने 2022 में टेण्डरिंग की है, किसी ने 2024 में की है। कितना समय बीत गया, इन्फ्लेशन क्या हुआ, प्रथम तो यह है। दूसरा, अगर जो मशीन है, उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट हैं तो क्या होता है कि फोरेन एक्सचेंज जो है, फोरेन एक्सचेंज का रेट क्या है, फोरेन एक्सचेंज में डॉलर महंगा होता जा रहा है, पाउंड महंगा होता जा रहा है। वह जो एक फर्क था, वह एक दूसरा फर्क है। तीसरा यह है कि हर स्टेट में जो मशीन गयी हैं, वे एक्जेक्ट मशीन नहीं गयी हैं। कोई मशीन में ज्यादा नार्म्स हैं, कोई में कम हैं, यह तीसरा कारण हो सकता है। चौथा कारण है, मैन्युफेक्चरर मशीन देता है तो कोई एक साल की एएमसी लेता है, दूसरा लेता है तीन साल की एएमसी। इसमें भी फर्क आता है। गारंटी पीरियड भी लोग अलग-अलग देते हैं, उसमें भी फर्क आता है। टर्नकी प्रोजेक्ट और नॉन टर्नकी में भी फर्क आता है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको जो डिपार्टमेंट ने दिया, वह जवाब आपने दिया। इसमें मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आर.एम.एस.सी.एल की खरीद में हुई गड़बड़ी की जांच अपने ही अफसरों के द्वारा उन्होंने करवा दी और यह लीपापोती कर ली। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप एसीएस स्तर के जो स्वास्थ्य सचिव हैं, उनके माध्यम से इसकी उच्च स्तरीय जांच करवायें। उच्च स्तरीय जांच करवाकर यदि वे दोषी पाये जाते हैं, इसमें जो अधिकारियों की मिलीभगत हैं, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन करेंगे? यह बता दीजिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य इतने समय एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। जितने भी तथ्य हैं, बार-बार सिंगल बिड क्यों आयी और क्यों-क्यों रिजेक्ट होती गयीं, इसके अन्दर कितनी बिड्स हुईं, इसकी हम ऑडिट करेंगे, जांच करेंगे, जितने भी तथ्य हैं, हम सामने रखेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जांच कराओ ना। ...(व्यवधान)...

mdp/rtm/23.07.2024/11:20/1c

श्री अध्यक्ष: माननीय डोटासरा जी, हर प्रश्न पर खड़े रहना, या तो विपक्ष का नेता खड़ा होगा। प्रश्न काल में किसी को अनुमति नहीं है। ...(व्यवधान)... प्रश्नकाल में नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे नहीं होगा। ...(व्यवधान)... ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष: ऐसे ही होगा। सदन में ऐसे ही होगा। ...(व्यवधान)... मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप खड़े हो गये। आपका काम नहीं है, मेरा काम है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राइट है मेरा।

श्री अध्यक्ष: कोई राइट नहीं है। विपक्ष के नेता को है। ...(व्यवधान)... आपको कोई राइट नहीं है। बिलकुल नहीं है। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं हो। आगे से ये कभी कुछ भी बोलें, अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: तमाशा बना रखा है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... एक सेकण्ड, कोई ऑब्जेक्शन आयेगा, कोई कम्प्लेंट आयेगी, आपत्ति आयेगी, तब ही जांच की जायेगी। आपत्ति आयी है तो जांच करेंगे। माननीय सदस्य, सीनियर सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष: चलिए, अगला प्रश्न। श्री उदयलाल भडाणा।

माण्डल की पंचायत समितियों द्वारा व्यय राशि

177. श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मांडल की ग्राम पंचायतों व तीनों पंचायत समितियों में विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी आय हुई तथा कितनी-कितनी राशि कहां-कहां पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री(श्री मदन दिलावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र मांडल के अन्तर्गत पंचायत समिति मांडल, करेड़ा एवं सुवाणा तथा इनकी ग्राम पंचायतों के विगत 03 वर्षों के आय एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। संबंधित वर्षवार आय में वर्ष का प्रारम्भिक शेष सम्मिलित नहीं है। जिस वर्ष किसी मद में आय से अधिक व्यय हुआ है, आधिक्य व्यय का भुगतान वर्ष के प्रारम्भ में शेष रही राशि से किया गया है।

पंचायत समिति माण्डल, करेड़ा एवं सुवाणा में प्राप्त आय के विरुद्ध प्रमुख मदों पर किये गये व्यय का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मुझे अधूरा दिया गया है। मेरे द्वारा राशि कहां-कहां व्यय की गयी, ये पूछा गया था, जबकि जवाब में मुझे नहीं बताया

गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे प्रश्न का उत्तर पूरा दिलाया जावे। मैंने ये कहा था कि कहां-कहां पर, किस-किस चीज में खर्च हुआ था। केवल मुझे डिटेल दी गयी कि इस पंचायत समिति में इतना आया, इसमें इतना आया।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारी पंचायतें हैं, जब पिछली कांग्रेस सरकार थी, बहुत सारे काम हुए ही नहीं और उनकी एमबी भर दी गयी। सचिव, वहां के जो अधिकारी हैं, सरपंच हैं मिलकर, बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं, एससी/एसटी के होते हैं, कम पढ़े-लिखे होते हैं, उनको चलाता कोई और है। उनको ये भी पता नहीं कि कहां पर क्या खर्चा हुआ। जो उसको चलाता है, वह साइन करवा कर पैसे भर लेता है। मैंने पंचायतवार मांगी थी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि क्या एमबी के अनुसार भौतिक सत्यापन करने की सरकार मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तीनों पंचायत समिति का पंचायतवार मांगा है। काफी बड़ा है। फिर भी इनको ऐसा लगता है कि यहां गड़बड़ हुई है। उन ग्राम पंचायतों के नाम बता दें, मैं पूरी जांच कराऊंगा और जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): मंत्री महोदय, मैं आपको लिखकर दे दूंगा और व्यक्तिगत भी मिल लूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा की गौशालाओं को अनुदान

178. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कहां-कहां व कब से पंजीकृत व अपंजीकृत गोशालाएँ संचालित हैं तथा किन-किन गौशालाओं हेतु सरकार द्वारा कितने-कितने पशुधन के लिए अनुदान राशि दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गौशालाओं में दी जा रही अनुदान राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधान सभा क्षेत्र बिलाडा में वर्तमान में कुल 54 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें से 50 पंजीकृत एवं 04 अपंजीकृत गोशालाएँ हैं। गौशालाओं की सूची मय पता, पशुधन संख्या तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण हेतु 39 पात्र गौशालाओं को दी गई कुल सहायता राशि रुपये 14,88,86,400/- का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। चारे की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिवस से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है।

वर्तमान में बड़े गौवंश हेतु 40 रूपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही गौशालाओं

में अंधे एवं अपाहिज गौवंश तथा नंदीशालाओं में संधारित नर गौवंश को उक्त समान दर पर 12 माह की सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

पात्र गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार बढाया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पहला सवाल मेरा है कि क्या राज्य सरकार गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान दे रही है, इसको बढ़ाकर 12 महीने का अनुदान राशि और समय सीमा 9 महीने से 12 महीने बढ़ाने का विचार रखती है?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016 में तत्कालीन सरकार की माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने स्टांप ड्यूटी पर 10 परसेंट गौ-सेस लगाकर राजस्थान गौ सरंक्षण एवं संवर्द्धन नियम, 2016 बनाया। वर्ष 2018-19 में तत्कालीन सरकार ने मदिरा की बिक्री पर 20 प्रतिशत गौ-सेस लगाया। इससे प्राप्त निधि से गौशालाओं को सहायता राशि व गौशालाओं के विकास के लिए संचालित योजनाओं को राशि दी जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले वर्ष 2023-24 में जो हमारे पास में आय-व्यय हुआ है। स्टांप ड्यूटी पर गौ-सेस 596.41 करोड़ और शराब की बिक्री पर गौ-सेस 631.4 करोड़, कुल आय 1227.45 करोड़ हुई। व्यय 1122.86 करोड़ हुआ। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भविष्य में इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मेरा दूसरा सवाल है कि जब मदिरा, एक्साइज पर जो ड्यूटी है, स्टांप पर ड्यूटी लगी है, करोड़ों रुपये हमको प्राप्त हो रहे हैं। वह सिर्फ इन गायों के लिए गौवंश के लिए ही है। मेरा आपसे आग्रह है कि 9 महीने से इनके 12 महीने आप, गौवंश बड़े को 40 रुपये दे रहे हैं, छोटे को 20 रुपये दे रहे हैं, इसको बढ़ाने का मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो समय बढ़ाने का कह रहा हूं। 180 से 270 दिन पिछली सरकार ने किये थे। अब अपनी सरकार को जो हम गौ-भक्त के नाम से जाने जाते हैं तो 270 की जगह 360 दिन किए जाने का और साथ ही साथ जो ऐसी गौशालाएं हैं, जिनमें आवारा पशु, गौवंश तो डाल दिया जाता है, लेकिन अपाहिज या दुर्घटनाग्रस्त होकर जो गौवंश आता है गौशाला में या जो बीमार हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, जो पंजीकृत गौशालाएं हैं, उसमें ऐसी कितनी हैं जो प्योरली अपाहिज, बीमार और वृद्ध पशुधन ही रखते हैं। उनसे कोई आय नहीं होती है। ऐसी गौशालाएं कितनी हैं? उनके लिए आपने 12 महीने किया है तो दूसरी गौशालाओं के लिए 12 महीने क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपाहिज गौशालाओं की अलग से संख्या नहीं है। सभी गौशालाओं में अपाहिज नंदी और गौवंश को लेने के प्रावधान है। जो अपाहिज हैं, उनके लिए 12 महीने का अनुदान हम देते हैं। दूसरी गायों को 9 महीने का अनुदान देते हैं। अपाहिज के लिए तो 12 महीने का पहले से प्रावधान

है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मैं तो अपाहिज की संख्या पूछ रहा हूं।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): अपाहिज की संख्या, आपको काउंटिंग करके बता देंगे, लेकिन अपाहिज जो गौवंश हैं, उसी में शामिल है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री घनश्याम।

करौली के थानों में दर्ज प्रकरण

179. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला करौली में विगत पांच वर्षों में हत्या, लूटपाट, चोरी, बलात्कार, छेड़खानी, मादक पदार्थों व अवैध हथियारों की तस्करी के कितने मामले दर्ज हुए? उक्त दर्ज मामलों में से कितने मामलों में चालान पेश किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार व थानेवार दर्ज मुकदमों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला करौली में दिनांक 1 जनवरी, 2024 से माह मई, 2024 तक उक्त प्रकार के कितने मामले दर्ज हुए तथा दर्ज मामलों में से कितनों में चालान पेश कर दिये गये? विधान सभा क्षेत्रवार व थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार टोडाभीम में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) जिला करौली में विगत पांच वर्षों (जनवरी 2019 से दिसम्बर 2023 तक) में हत्या के 218, लूटपाट के 106, चोरी के 3080, बलात्कार के 631, छेड़खानी के 919, मादक पदार्थों की तस्करी के 240 व अवैध हथियारों की तस्करी के 536 मामले दर्ज हुए है। कुल 5730 दर्ज मामलों में से अभी तक 2030 मामलों में चालान पेश किया जा चुका है व 29 मामलों में चालान पेश किया जाना शेष है। विधान सभा क्षेत्रवार व थानेवार दर्ज मुकदमों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जिला करौली मे दिनांक 1 जनवरी, 2024 से 31 मई, 2024 तक हत्या के 16, लूटपाट के 19, चोरी के 258, बलात्कार के 60, छेड़खानी के 97, मादक पदार्थों की तस्करी के 52 व अवैध हथियारों की तस्करी के 48 मामले दर्ज हुए हैं। कुल 550 दर्ज मामलों में से अभी तक 89 मामलों में चालान पेश किया जा चुका है व 32 मामलों में चालान पेश किया जाना शेष है। विधान सभा क्षेत्रवार व थानेवार दर्ज मुकदमों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा टोडाभीम सहित सम्पूर्ण राज्य में मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम हेतु की जा रही कार्यवाही एवं कार्ययोजना का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

Ans/rtm 11.30 1d 23.07.2024

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि सरकार के संरक्षण में जो तस्करी हो रही है और मादक पदार्थों का जो व्यवसाय हो रहा है, इसको आप कब तक रोकेंगे इसको रोकने की आपकी क्या कार्य योजना है?

दूसरा प्रश्न, सरकार विशेष टॉस्क फोर्स एक्टिव करके, विशेष अभियान चलाकर, पूर्ण रूप से इस तस्करी को कब तक नियंत्रण करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हमारे क्षेत्र में स्मैक का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। वह पुलिस के माध्यम से ही चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। प्रश्न आ गया। उत्तर आने दीजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न है, इसमें इन्होंने प्रश्न किए, एक तो पांच महीने, जनवरी से लेकर मई तक और पिछले वर्ष का कम्पेरिजन करने के लिए 2023 के अन्दर, एक जनवरी से मई तक, इन्होंने कुछ आंकड़ें मांगे थे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो हत्याएं हुई वह इस वर्ष 15 प्रतिशत कम थी। दूसरा, टोडाभीम के जो रेप्स थी वह 47 परसेंट पिछली साल के अनुसार कम थी। अब आपने मादक पदार्थों के बारे में बात की, यह बहुत गंभीर विषय है। यह खाली करोली का नहीं, ऑल राजस्थान में जिस तरीके से युवा ड्रग्स अलग-अलग टाइप की..

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय,..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिए। एक प्रश्न और पूछ लेना आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अलग-अलग टाइप की ड्रग्स सब जगह अवेलेवल है। बूट पॉलिश भी खा लेते हैं, उससे भी नशा चढ़ता है।

आपने पूछा था एंटी नारकॉटिक्स टास्क फोर्स। अभी नया बजट मुख्य मंत्री जी ने अनाउंस किया, उसमें गठित करने का हो गया है। एडीजी, एसपी और पुलिस थाना, यह नॉरकोटिक्स के ऊपर जरूर कार्यवाही करेगी। जैसे हमने पेपर लीक और एंटी गेंगस्टर के अगेन्स्ट किया था, हम इसके ऊपर भी कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दूसरा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि 15 प्रतिशत कम हुआ, यह सिर्फ चार महीनों का निकाल रहे हैं, जबकि साल तो 12 महीनों की होती है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने पूछा ही पांच के लिए था। स्पेसिफिक प्रश्न में था। आपने पांच का विवरण मांगा, वह आपको दे दिया।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हां, पांच का ही पूछा है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब आप चार साल पहले का बोलेंगे तो मैं आपको दे दूंगा दस्तावेज।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 550 मुक़दमे दर्ज हुए, उसमें 89

पर चालान कर दिया, 32 पर करना बाकी है। तो बाकी 429 मुक़दमे कहां चले गये?, उनमें क्या एफआर लगा दी, क्या निस्तारण हुआ? इतने भारी मुक़दमों पर एफआर कैसे लगा दी, 429 पर?

इसके साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा कि थानों में आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, उनको कब-कब चालू किया जाता है? पुलिस उनको क्यों बंद कर देती है? वह लगातार चालू रहने चाहिए, इस पर आपकी कार्य योजना है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चालान, एफआर की बात की थी, यह पूरी डिटेल मैं पुलिस से प्राप्त करूंगा। सीसीटीव कैमरा बंद क्यों पड़े हैं, क्या परसेंटेज बंद पड़े हैं, पूरी जांच करके मैं आपको आज शाम तक डिटेल दे दूंगा।

श्री अध्यक्षः आप पूछ रहे हैं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो यह पूछना चाहूंगा, वैसे तो परसों ही पुलिस पिटी है, तो क्या कार्यवाही होगी, यह तो आप समझ सकते हैं।

श्री अध्यक्षः चर्चा और होगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कहना चाहूंगा कि पांच वर्षों में लूटपाट और जो घटनाएं बताई हैं, इनमें कितने माल की बरामदगी हो गई। हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, मादक पदार्थ, अवैध हथियारों की तस्करी के मामले दर्ज हैं, इसमें कितने अपराधी नाबालिग है और कितने अन्तर्राज्यीय गिरोह से सम्बन्धित है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मूल प्रश्न का हिस्सा नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मूल प्रश्न का ही है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बालिग कितने थे, बूढे कितने थे, यह मेरे पास अभी यह नहीं है। आपने जो फरमाया है, मैं इसका मालूम करके आपको बता दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बरामदगी बता दो, कितनों में बरामदगी हुई?

श्री अध्यक्षः वह आपको दे देंगे। करोली क्या पूरे प्रांत का। अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता।

अजमेर दक्षिण में मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण

180. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्वीकृत नसीराबाद रोड़ आडी पुलिया से कल्याणीपुरा तक स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्वीकृत सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क हेतु स्वीकृत राशि तत्कालीन बीएसआर दर के

अनुसार थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वीकृत राशि को वर्तमान बीएसआर दर के अनुसार बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (डॉ. मंजू बाघमार): (1) जी हां। नसीराबाद रोड़ आडी पुलिया से कल्याणीपुरा तक की स्वीकृति दिनांक 09.10.2015 को नेहरू नगर से आदर्श नगर पुलिया एस्केप चेनल के साथ-साथ के नाम से जारी हुई थी। इस कार्य के प्रारंभ नहीं होने के कारणों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, आदर्श नगर पुलिया से धोला भाटा तक सड़क निर्माण नगर निगम अजमेर द्वारा किया जा चुका है। सड़क का शेष भाग धोला भाटा से कल्याणीपुरा तक की स्वीकृति बजट घोषणा संख्या 12/2024-25 (लेखानुदान) में 5 करोड़ प्रति विधान सभा क्षेत्र के तहत दिनांक 01.07.2024 को नेहरू नगर से धोला भाटा तक मिसिंग लिंक के नाम से जारी की गई। सड़क निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

कार्य को अनुबंध के अनुसार दिनांक 18.12.2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। नवीन स्वीकृत सड़क नेहरू नगर से धोला भाटा तक मिसिंग लिंक सड़क का तकमीना वर्तमान बीएसआर 2022 के आधार पर बनाया गया है। तकमीनानुसार इस कार्य पर रु 145.00 लाख व्यय करने की योजना है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): प्रश्न का जवाब मेरे पास है, आपकी अनुमति हो तो सीधे पूरक प्रश्न पूछ लूं? माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि वर्ष 2015 में स्वीकृति के समय सड़क की लागत क्या थी? उस समय की लागत व वर्तमान लागत 145 लाख रुपये है, उसमें कितना अंतर है? क्या आप इस बढ़ी हुई राशि को दोषी अधिकारियों से वसूलने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि 2015-16 के बजट घोषणा में यह मिसिंग लिंक घोषित की गई थी। 2015-16 की बीएसआर दर के अनुसार जो राशि थी, वह 104.13 लाख रुपये थी। उस समय सड़क की लम्बाई 3.5 किलोमीटर थी, उसमें से नगर निगम द्वारा 800 मीटर की रोड बना ली गई थी। नहीं बनाने के बहुत सारे कारण रहे थे1 विद्युत पोल हटाने के भी रहे थे, नगर निगम द्वारा सीवरेज लाइन भी वहां पर प्रस्तावित थी, फिर सिंचाई विभाग का कल्याणीपुरा का स्केप चैनल भी था, कुछ निजी खातेदारों की भूमि भी थी, तो वह सड़क नहीं बन पाई थी। उसके बाद कांट्रेक्टर ने उस कार्य को करने के लिए मना कर दिया था। 17.03.2021 को विदड्रा कर दिया गया।

अभी हमने 2024-25 के लेखानुदान में, बजट घोषणा में नई स्वीकृति के लिए 2.7 किलोमीटर की सड़क के लिए 1.45 लाख रुपये स्वीकृत किए, इस दर के अनुसार।

श्री अध्यक्ष: माननीया सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, हालांकि जवाब पॉजिटिव दिया है कि सड़क बना देंगे। मैंने यह पूछा था कि 2015 में बीएसआर रेट के अनुसार इसकी लागत क्या थी और 2024 यानी 9 साल बाद इसकी बीएसआर रेट क्या है? मैंने यह पूछा था, लेकिन इसका जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं।

मैं दूसरा सवाल कर लेती हूं। 2015 से लेकर आज तक यह सड़क नहीं बनी। 2021 में मैं इसको सतर्कता समिति में लेकर गई। 2021 से 2024 तक, आज तक यह सतर्कता समिति में पेंडिग है। क्या सतर्कता समिति के माध्यम से पीडब्ल्यूडी को जो मार्गाधिकार की समस्या आ रही थी, वह मार्गाधिकार की रिपोर्ट और सड़क लोकेशन की जानकारी प्राप्त हो गई है, रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? क्योंकि आपने लिखा है कि हम दिसम्बर, 2024 तक बना देंगे। तो दिसम्बर, 2024 तक जब बनाएंगे जब सतर्कता समिति के माध्यम से आपको सारा रिकार्ड मिल जाएगा। क्या सतर्कता समिति ने उस मार्गाधिकार के साथ, मास्टर प्लान की सड़क के अनुसार आपको डिमार्केशन करके सड़क की रिपोर्ट दे दी है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझसे पहले सवाल पूछा था कि 2015 के अन्दर बीएसआर दर से, मैंने बताया था कि उस समय 1.4 लाख रुपये की हमने घोषणा की थी। 2024-25 के लेखानुदान में नई मिसिंग लिंक घोषित की गई है उसमें 145 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। जैसा कि माननीया सदस्या ने पूछा हैं, उसमें मैं बता दूं कि उपखण्ड अधिशासी अभियंता जल संसाधन विभाग और अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन अधीक्षण अभियंता और सीपीएम, डीएफसीसीआईएल के हस्ताक्षर होने थे, परन्तु सीपीएम डीएफसीसीआईएल के हस्ताक्षर नहीं हो पाए, बाकी सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर हो गए थे, इसलिए वह कार्य उस समय नहीं हो पाया था। उस कार्य को कांट्रेक्टर से विदड्रा करवा लिया गया था। अब इस नई मिसिंग लिंक की स्वीकृति लेखानुदान में दे दी गई है। अब इसका कार्य करवा लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: वह सतर्कता समिति का बता दिया क्या?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): रिपोर्ट मिल गई क्या? हां या ना, बस इतना सा।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): सतर्कता समिति के अन्दर मैं आपको बता दूं। श्रीमती अनिता भदेल, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान सरकार की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि इसके अन्दर सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर हो गए थे लेकिन सीपीएम डीएफसीसीआईएल के हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे इस कारण सड़क नहीं हो पाई। अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अनुसार जिस भी कार्य में बाधा आ रही थी, जैसे पुल निर्माण, विद्युत पोल हटाने का, नगर निगम द्वारा सीवरेज लाइन, वह सारे कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। अब इस मिसिंग लिंक कार्य होगा।

श्री अध्यक्ष: हो गए, दो प्रश्न हो गए। तीन हो गए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बस एक छोटा सा। आपने कहा कि रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आना बाकी है तो दिसम्बर, 2024 तक आपने लिखा है कि सड़क बना देंगे। यदि रिपोर्ट नहीं आएगी तो फिर दिसम्बर तक कैसे बनाएंगे, क्योंकि 9 साल से तो बन नहीं रही है। इतना सा आश्वासन चाहिए कि हम रिपोर्ट मंगाकर बना देंगे, इतना सा कह दे, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: कहलवाना नहीं। जो इनको कहना होगा वह कहेंगे।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): चूंकि उस समय की स्वीकृति थी और अब जो नया प्रस्ताव दिया है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नये लेखानुदान के अन्दर, इस बजट की स्वीकृति जारी कर दी।

VPS-RTM-23.07.2024-11.40-1e

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण

181. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)(श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) के स्थान पर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसान सेवा केंद्रों का निर्माण कराया जाता है? यदि हां, तो जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में अब तक कितने किसान सेवा केंद्रों का निर्माण किया गया है? ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितिवार निर्मित एवं स्वीकृत सेवा केंद्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिलों की शेष ग्राम पंचायतों में उक्त केंद्रों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग)(कृषि मंत्री के स्थान पर): (1) जी, नहीं। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जाता है। जिला चित्तौड़गढ़ में 184 एवं प्रतापगढ़ में 95 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया गया है। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितिवार निर्मित एवं स्वीकृत किसान सेवा केन्द्रों की सूची परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जाता है। जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ की शेष रही समस्त ग्राम पंचायतों में किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है। मैं सीधा पूरक प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्षः सीधा पूरक प्रश्न पूछना है तो आप बोलिये। माननीय मंत्रीजी, आप बैठिये। इन्होंने जवाब पढ़ लिया है, माननीय मंत्रीजी, आप विराजिये। आप पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे समय बचेगा। मेरा यह मानना है कि आप सब लोग, हम सारे सदस्य यदि सीधा-सीधा पूरक प्रश्न पूछ लें तो सारे प्रश्न आ सकते हैं।

श्री अध्यक्षः पूछिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्रों के निर्माण से किसानों को काम करने में सुविधा मिलती है? यदि हां तो शेष ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्रों के निर्माण क्यों नहीं करवाये जा रहे हैं? नम्बर एक।

नम्बर दो, यदि किसान सेवा केन्द्रों के निर्माण से किसानों को सुविधा मिलती है तो यह किसान सेवा केन्द्र कब तक निर्माण कर देंगे?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, नहीं। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जाता है। जिला चित्तौड़गढ़ में 184 एवं प्रतापगढ़ में 95 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया गया है। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितिवार निर्मित एवं स्वीकृत किसान सेवा केन्द्रों की सूची परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

जी, नहीं। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जाता है। जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ की शेष रही समस्त ग्राम पंचायतों में किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्षः यह तो उत्तर में ही लिखा है। आप तो प्रश्न का जवाब दीजिए। यह तो उसमें ही लिखा हुआ है जो आपने उत्तर दिया है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): यह तो जवाब आ गया। मैं यह पूछ रहा था, चलिये, कोई बात नहीं। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि वसुन्धराजी के शासन में यह किसान सेवा केन्द्र बन रहे थे तो पिछले पांच सालों में कितने किसान सेवा केन्द्र बनाये गये? आप तो यह बता दें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह अच्छा सवाल है। वर्ष 2013 से 2018 में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप तो अपना उत्तर दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): जैसा कि माननीय मोदीजी ने चार जातियां देश के अन्दर बताई हैं- महिला, युवा, गरीब और किसान तो 2013 से 2018 में किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की उस समय वसुन्धराजी की सरकार थी और किसान

सेवा केन्द्र निर्माण के लिए 402 करोड़ रुपये दिये गये थे और गत 2018 से 2023 के दौरान किसान सेवा केन्द्रों के लिए मात्र 24 करोड़ रुपये ही दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): यह शेष किसान सेवा केन्द्र आप कब तक बना देंगे, आप समय बता दें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): हालांकि, वर्ष 2021-22 में एक हजार किसान सेवा केन्द्र निर्माण की बजट घोषणा तो जरूर हुई थी, उक्त घोषणा के तहत एक हजार कृषि पर्यवेक्षक को नियुक्ति भी दी गयी किंतु किसान सेवा केन्द्र हेतु राशि का आवंटन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला प्रश्न। श्री गोपाल शर्मा। वैसे पूर्व सवाल कृपलानीजी का था पर माननीय सदस्य श्री अर्जुन लाल जीनगर ने पूछा है, मेरे पास लेटर आ गया था। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, आप बैठिये। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरुपूर्णिमा पर आपको बहुत-बहुत शुभकमानाएं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये। प्रश्न संख्या बोलिये।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय द्वारा मोबाइल जांच लैब की स्थापना

182. श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय का एकीकरण किया गया है? यदि हां, तो उक्त एकीकरण के पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कितने नवीन पद सृजित किए गए तथा क्या उक्त सृजित पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि एकीकरण के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण आयुक्तालय द्वारा सभी जिलों में मोबाइल टेस्टिंग लैब स्थापित की जा चुकी है? यदि हां, तो कौन-कौनसे जिले में तथा उक्त लैब के माध्यम से कितनी-कितनी जांचें की गईं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त की गई जांचों में अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण पंजीकृत हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे जिले में, किस-किस के विरूद्ध किन-किन धाराओं में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हां। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय का एकीकरण हो चुका है, जिसका आदेश परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

एकीकरण के पश्चात फूड सेफ्टी ऑफिसर के 300 पद सृजित किए गए हैं तथा 98 फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद एकीकरण से पूर्व से सृजित हैं। इस प्रकार फूड सेफ्टी ऑफिसर के

कुल 398 पद स्वीकृत है, जिन पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण आयुक्तालय के एकीकरण के पश्चात स्थापित 25 मोबाइल टेस्टिंग लैब सहित, राज्य में कुल 34 मोबाइल टेस्टिंग लैब स्थापित है, जिनका संचालन अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

खाद्य मोबाइल टेस्टिंग लैब के माध्यम से कुल 70550 जांचें की गईं जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) आमजन एवं खाद्य व्यापारियों को मिलावट के प्रति जागरूक करने के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब संचालित की जा रही है। जिसके द्वारा मौके पर नमूनों की जांच कर मिलावट के संबंध में अवगत कराया जाता है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मैंने पढ़ लिया है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि 2022 की अप्रैल से ड्रग ऑफिसर्स की भर्ती का काम चल रहा है। मैंने इसमें यह जानना चाहा कि भर्ती क्यों नहीं हुई अब तक? इसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं, नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल दो पहले अलग-अलग डिपार्टमेंट्स थे। 05.04.2022 में इनको मर्ज कर दिया गया और मर्जर से पहले खाली 98 फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट थी जो ऑक्यूपाइड थी। मर्जर के बाद 300 नयी पोस्ट क्रिएट की गई, इनमें से 200 आर.पी.एस.सी. के जरिए, करीब-करीब अभी फाइनल डाक्यूमेंट्स का वैरिफिकेशन हो रहा है तो हमारे 200 फूड सेफ्टी ऑफिसर अभी जल्दी ही आ जाएंगे और 100 जो हैं, उनका मामला कोर्ट में लम्बित है तो कुल मिलाकर यह लम्बित वाले भी हमारे साथ आ जाते हैं कोर्ट के निर्णय के बाद में तो लगभग 98 से 398 हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो जायेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी चैकिंग की जो स्पीड है और जो ज्यादा चैकिंग होगी, वह एकदम हमारी बढ़ जायेगी।

जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। 98 से 298 तो जल्दी ही हो जायेगा और 100 जो कोर्ट में लम्बित है, हमें आशा है कि उसमें भी जल्दी ही हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): यह मेरे सवाल का उत्तर ही नहीं है। मैंने यह सीधी सी बात पूछी है कि भर्ती क्यों नहीं हुई? तीन शब्द है- 'भर्ती क्यों नहीं हुई?', चार शब्द है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भर्ती का बता दिया।

श्री अध्यक्ष: उत्तर यही है। हो गया? अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम विश्नोई।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को दो पूरक प्रश्न तो

पूछने की इजाजत दो।

श्री अध्यक्षः हां, आपने दो पूछ लिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा भर्ती क्यों नहीं हुई?

श्री अध्यक्षः जवाब नहीं दिया, वह अलग विषय है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भर्ती का बता दिया कि आर.पी.एस.सी. से 200 भर्ती हो रही है और बाकी के 100 मामले कोर्ट में लम्बित है तो ये यह पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं भर्ती हो रही है, मैंने पूरा बता दिया।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है। मैंने इसमें यह जानना चाहा कि जिन लोगों के खिलाफ मिलावट के मामले दर्ज है, उनकी सूची प्रस्तुत की जाये, वह मेज पर नहीं रखी गयी है और एक भाषागत सवाल है कि इसमें लिखा हुआ है कि- 'मिलावट के प्रति जागरूक करने के लिए' यह हो रहा है। मेरा यह कहना है कि 'मिलावट के खिलाफ जागरूक करने के लिए' यह हो रहा है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेन तो माननीय सदस्य ने टेस्टिंग लैब्स के बारे में पूछा था, उन्होंने उसकी अभी कोई चर्चा नहीं की है फिर भी मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे लैब टेस्टिंग की जो मोबाइल यूनिट्स 34 है। ऑन द स्पॉट अवेयरनेस, जन जागरूकता के लिए यह हमारा जो अभियान है 15.02.2024 को सरकार का जो शुरू हुआ, 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार', यह जो है 70,550 जांचें की गईं और 6,031 एफ.एस.ओ. ने एनफोर्समेंट सैम्पल्स किये, 38,651 किलो जो अशुद्ध चीजें थीं जितनी भी खाने-पीने की उनको डिस्ट्रॉय किया गया। हमारे 11 जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अभी चल रही हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, जालोर, चूरू और सात नई लैब्स जो हैं- बारां, बाड़ेमर, धौलपुर, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा, गंगानगर इनमें बिल्डिंग्स रेडी है, इक्विपमेंट आते ही ये लैब्स भी चालू होंगी। माइक्रो बायोलॉजी जो लैब है जयपुर में वह बैक्टीरिया को डिटेक्ट करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें इस अभियान के तहत हमें पूरे देश के अन्दर फर्स्ट प्राइज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अभी 1100 मामले कोर्ट में लम्बित है और दो हजार प्लस कुल हमारे चालान हुए हैं, चार करोड़ रुपये पेनल्टी के लिये गये हैं और जो फाइन्स एक लाख से दस लाख तक की फाइन होती है और छह महीने की सज़ा या बहुत ही खराब कोई ज्यादा मिलावट हो जहरीला तो उसके अन्दर उसको आजीवन कारावास भी होता है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम विश्नोई।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों का स्थानांतरण

183. श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो

कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है।

स्थानांतरण के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित पक्षों यथा- आमजन, शिक्षाविद एवं शैक्षिक संगठनों के विचार/सुझाव आमंत्रित कर तदुपरांत विमर्श किया जाकर नीति बनाने की प्रक्रिया/कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा प्रश्न ही पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, पूछिये।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): मैं माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय लिया है कि दिव्यांग शिक्षक और कर्मचारियों को राहत देते हुए, आपने उनके घर के पास में ही पोस्टिंग देने या ट्रांसफर करने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए तो आपको बधाई। एक और आश्वासन चाहूंगा कि लम्बे समय से, पिछले कार्यकाल में डेप्यूट किये हुए, हमारे गांवों से उठाकर के शिक्षकों को डेप्यूट कर दिया गया है दूसरी जगह पर...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): उनको वापस लगाने के लिए आश्वासन चाहते हुए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बड़ा विभाग है, राज्य के आठ लाख कर्मचारियों में से चार लाख कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में है और अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2013 से 2018 के बीच में आपका कार्यकाल रहा है और उस कार्यकाल में क्या काम हुए, वह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप तो थर्ड ग्रेड का ही पूछें।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): क्या? आपने एक स्पष्ट नीति बनाई थी और उस स्पष्ट नीति के तहत अध्यापकों के स्थानांतरण किये गये थे। डार्क जोन से भी आपने स्थानांतरण किये थे 2008 से पहले वाले शिक्षक जो नियुक्त थे, उनका भी आपने स्थानांतरण किया था।

SSY/RTM/23.07.2024/11:50/1f

स्थानान्तरण के लिए अंतर जिलों के ट्रांसफर की आपने स्पष्ट नीति बनाई थी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, आप प्रश्न पूछो।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): आप किसी प्रकार की कोई नीति बनाकर, पिछले 5 साल में इनकी सरकार ने इन शिक्षकों के कल्याण के लिए, उनके ट्रांसफर के लिए कोई काम नहीं किया।

श्री अध्यक्षः यह तो शिक्षा पर बहस हो तब बोलना। प्रश्न पूछो।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): यह अपनी आपसी लड़ाई में लगे रहे। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या आप उन शिक्षकों के दर्द को समझते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण की नीति बनाकर के उनका स्थानान्तरण करना चाहते हैं या नहीं? और नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्षः हां, प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि दिव्यांगों को हम घर के नजदीक रखेंगे। इसमें आंशिक सच है। हमने सभी दिव्यांगों को नहीं कहा है। लेकिन जो 100 प्रतिशत दृष्टि बाधित हैं, 100 प्रतिशत मूक-बधिर हैं और 90 प्रतिशत आर्थोपैडिक दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने कहा है कि वह जहां चाहेंगे वहां लगायेंगे। यदि वहां रिक्त स्थान नहीं होगा तो उसके नजदीक में लगायेंगे। परंतु ऐसे सब लोगों के लिए हमने ऐसा निर्णय लिया और अभी हम लगा रहे हैं।

माननीय सदस्य की जो भावना थी, वह यह थी कि बहुत सारे डेपुटेशंस किये हुए हैं, यह सच है कि राजस्थान भर में हजारों की संख्या में अनावश्यक डेपुटेशन किये हुए थे। जयपुर में ही बड़ी संख्या में बैठाये हुए थे और वह वैसे ही बैठे हुए थे। कोई मेरे मिलने वाला है, कोई इधर का मिलने वाला है। उसका कोई काम नहीं है। उन सब डेपुटेशंस को मैंने निरस्त कर दिया है। अभी भी, इतना कहने के बावजूद भी 10 साल से भी ज्यादा डेपुटेशन पर हैं। जो लगभग 7-8 महीने पहले से डेपुटेशन पर हैं, उन सबका डेपुटेशन निरस्त करेंगे। परंतु ऐसे लोग होंगे जो दिव्यांग हैं, बीमार हैं, गंभीर बीमार हैं, ऐसों का निरस्त नहीं करेंगे। क्योंकि कई सारी संस्थाओं में डेपुटेशन पर भेजना पड़ता है। उनकी जरूरत भी होती है। लेकिन जो लंबे समय से हैं, उनका फेजवाइज डेपुटेशन निरस्त करेंगे ताकि उन संस्थाओं का काम भी चलता रहे और डेपुटेशन भी निरस्त हो जायें। अनावश्यक रूप से जो डेपुटेशन पर बैठे हुए हैं, उनको हम तुरंत ही प्रभाव से उनका डेपुटेशन निरस्त करते हैं।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री भीमराज भाटी।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न हुआ है।

श्री अध्यक्षः हो गया। आपने थर्ड में पूछा था।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): मेरा सिर्फ एक प्रश्न हुआ है। दूसरा प्रश्न है, एक ही प्रश्न है मेरा।

श्री अध्यक्षः हां, माननीय सदस्य। हो गया माननीय सदस्य, हो गया माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। माननीय भीमराज भाटी।

पाली के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

184. श्री भीम राज भाटी (पाली): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में कहां-कहां पशु चिकित्सालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों में किस-किस संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने रिक्त हैं? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधान सभा क्षेत्र पाली में स्वीकृत पशु चिकित्सालयों का स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पाली के पशु चिकित्सालयों में विभागीय कार्मिकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संवर्गवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है।

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछें।

श्री भीम राज भाटी (पाली): मुझे सिर्फ यह पूछना है कि मैंने पूछा था कि रिक्त पद हैं, उन पर कब तक भर्ती कर दी जायेगी? मुझे जवाब मिला है कि उपलब्धता के ऊपर। अब उपलब्धता का क्या मतलब है? उपलब्ध होंगे तब आप भरेंगे। उपलब्ध तो पता नहीं कब होंगे। नई भर्ती करेंगे या डेपुटेशन पर कुछ लगायेंगे? यह कब तक होगा? बाहर से कोई लायेंगे? कैसे करेंगे? मुझे सिर्फ यह जवाब चाहिये कि पशु चिकित्सालयों में पशुओं के लिए कब तक चिकित्सकों तथा अन्य के रिक्त पदों पर भर्तियां कर दी जायेंगी? स्पेसिफिक जवाब चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पाली विधान सभा क्षेत्र में कुल 93 पद स्वीकृत हैं और 45 कार्मिक कार्यरत हैं और 48 वहां रिक्त हैं। इसमें एक उप निदेशक है, 4 डॉक्टर हैं। 12 पशु धन सहायक रिक्त हैं। 23 पशु परिचर रिक्त हैं। 4 पशु धन परिचर के रिक्त हैं। 1 लैब टेक्निशियन का रिक्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टरों के सम्बन्ध में विभाग ने, पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 22.10.2019 के क्रम में दिनांक 02.08.2020 को लिखित परीक्षा आयोजित कर दिनांक 26.11.2022 को परिणाम जारी किया जा चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर से साक्षात्कार संपन्न हो चुके।

माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण परिणाम प्रकाशित होना बकाया है। इसलिए डॉक्टर अभी नहीं लग रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनके जो 4 पद हैं, वह 2 महीने में भर देंगे। दूसरा, पशु धन परिचर और पशु परिचर, इसमें भी हमने अभी 6,400 पद हैं, पशुधन परिचर के पद रिक्त हैं। 6,492 पद के विरुद्ध 4,934 पद की हमने विज्ञप्ति 12.01.2024 को जारी की है। उनके 17.02.2024 तक आवेदन ले लिये हैं। आवेदन लेने की प्रक्रिया के बाद में उसकी परीक्षा करवाई जायेगी। परीक्षा

की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी तो इनके रिक्त पद भी भर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और कुछ पूछना है?

श्री भीम राज भाटी (पाली): अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जवाब नहीं मिला कि कब तक करेंगे? प्रक्रिया कब पूरी होगी?

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया चल रही है। श्री केसाराम चौधरी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बता दिया कि डॉक्टर्स के पद जो 4 हैं, वह 2 महीने में भर देंगे। बाकी परीक्षा की प्रक्रिया के बाद में भरेंगे।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न किसी और को पूछने की अनुमति नहीं है। किसी को अनुमति नहीं है। श्री केसाराम चौधरी।

पाली में बजरी माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही

185. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में विगत पांच वर्षों में बजरी माफियाओं के विरुद्ध किन-किन पुलिस थानों में हत्या व मारपीट के मुकदमें दर्ज हुए हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार अपराधों पर रोकथाम हेतु बजरी माफियाओं पर कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) जिला पाली में विगत पांच वर्षो में बजरी माफियाओं के विरूद्ध (01 जनवरी 2019 से 30 जून 2024) तक मारपीट के 12 प्रकरण दर्ज हुए जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं। उक्त अवधि में हत्या की कोई घटना नहीं हुई है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलों में एस.आई.टी. का गठन किया गया एवं समय-समय पर संयुक्त अभियान चलाये जाकर प्रभावी कार्यवाही की गयी है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

अवैध बजरी खनन के अपराधों पर रोक लगाने हेतु समय-समय पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाती है। अवैध बजरी खनन को रोकने हेतु समय-समय पर परिपत्र जारी किये जाकर नियमानुसार कार्यवाही करवाई जाती है। जारी परिपत्रों का विवरण परिशिष्ट- स पर संलग्न है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय मंत्री जी, जवाब आ गया।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न यह है कि मारवाड़ जंक्शन में बजरी खनन के पट्टे जारी हुए। 5 साल के लिए हुए। 5 साल में उच्चतम न्यायालय ने 13 महीने 12 दिन के लिए रोक लगा दी। उस समय भी बजरी खनन होता था।

उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 13 माह 12 दिन के लिए आगे लीज को बढ़ाया। उस समय भी पर्यावरण का सर्टिफिकेट पेश नहीं करने के कारण से 26 माह 24 दिन तक लीज बंद रही। मगर उस समय भी अवैध बजरी खनन होता रहा। डिपार्टमेंट की मिलीभगत के कारण से अवैध खनन होता रहा।

मैं मांग करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, क्या यह अवैध खनन 26 महीने लीज नहीं होते हुए भी होता रहा? आज भी मौके पर सारी नदियां खुदी हुई पड़ी हैं। यह आपने पाली जिले में 12 मुकदमे बताये। मगर मारवाड़ में अवैध खनन होने के बाद भी एक भी मुकदमा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो, प्रश्न। हां, प्रश्न पूछो तो उत्तर भी आयेगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, पूछ लिया ना। मैंने यही पूछा है कि 26 महीने 24 दिन में लीज बंद रहने के बाद भी अवैध खनन होता रहा। उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: हां, यह प्रश्न है। माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, जो हमारे पास प्रश्न आया है, उसके अन्दर उच्च न्यायालय में कितने केस हैं? वह कब क्लोज हो जायेंगे? उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन इनके जो मूल प्रश्न हैं, उसका जो मेरे पास जवाब है, वह मैं आपको देता हूं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): वह तो है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ रहा है ना।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पाली जिले में 5 साल के अन्दर अवैध खनन के अन्दर मारपीट के 12 केस हुए और मर्डर का कोई भी नहीं हुआ।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय मंत्री महोदय, मैं इससे सहमत हूं। मैं हाई कोर्ट का आपसे नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि 24 महीने 26 दिन तक लीज थी ही नहीं, फिर भी खनन होता रहा। विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। आप विभाग के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? मैं यह पूछ रहा हूं। अवैध खनन के बारे में।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के बारे में।

श्री अध्यक्ष: सुनिये पहले।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो इन्होंने प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। अब न्यायालय में कितने केसेज, उनका क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष: चलिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले मैं इस मूल का जवाब तो दे दूं। इनके मूल प्रश्न का जवाब दे दूं। उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो मुझसे पूछा गया है उसका तो मैं जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष: हो गया, जवाब आ गया ना?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): खनन का है, उसकी जांच के लिए है।

श्री अध्यक्ष: वह जांच का पूछ रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब यह रोकथाम के लिए कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वह जांच का पूछ रहे हैं। जांच करवा देना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह तीसरे विधायक हैं जिन्होंने खनन के खिलाफ क्वेश्चन लगाया है। परसों ही बजरी माफिया को पकड़ने गयी पुलिस, उसमें पुलिस पर हमला हुआ है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार अवैध बजरी माफिया पर कार्यवाही करना चाहती है या नहीं करना चाहती है?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पिछली सरकार के समय आपके सदन के नेता ने कहा था कि हम कितना भी शासन, प्रशासन लगा दें, अवैध बजरी खनन पर रोक नहीं लग सकती है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो। आप दूसरी बार खड़े हो रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपके नेताजी ने कहा है पिछले सदन में। आपके नेताजी ने पिछले सदन में कहा था ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

Spp/Rtm/23.07.2024/12:00/1g

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इतना बड़ा अभियान..(व्यवधान)...

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

प्रश्नकाल के व्यवस्थित संचालन में सुस्थापित परम्पराओं के पालन की अपेक्षा

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। ..(व्यवधान).. आप फिर बोल रहे हो। आसन पाँव पर है, फिर बोल रहे हो। मैंने कल भी व्यवस्था दी थी कि जब भी आसन पाँव पर हो, सभी को चुपचाप बैठ जाना है। प्रश्नकाल में पुरानी व्यवस्था भी है और मेरी भी व्यवस्था है कि जिस माननीय सदस्य का प्रश्न होगा, उसको दो पूरक प्रश्न पूछने का हक है और तीसरा ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता हुई तो विपक्ष का नेता पूछेगा। उसके अलावा कोई भी खड़ा नहीं होगा और कोई माननीय सदस्य खड़ा होगा तो उसका अंकित भी नहीं होगा और उसका फिर प्रश्न भी आयेगा तो उसको डील करेंगे। यानी व्यवस्था की बात है। हम सब सम्माननीय हैं, रोज-रोज मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक बार जो व्यवस्था देदी, उसका अक्षरश: पालन किया जाना चाहिये। ..(व्यवधान)..माननीय मंत्रीजी, अभी कह रहा हूं कि आसन पैरों पर है और आप जा रहे हो, यह बर्दाश्त नहीं होगा। आप भी बोलोगे तो यह बर्दाश्त नहीं करूंगा।

मैंने व्यवस्था दी है कि जब भी जीरो ऑवर आये तो कोई भी सदस्य अपनी सीट से उठकर मंत्रियों के पास नहीं जायेगा। आपको यदि कोई बात करनी है तो जब 1.00 से 2.00 लंच होता है, तो आप जरूर मंत्रियों के कमरों में जाओ या जब 1.00 बजे बाद खत्म हो और मंत्री अपने कमरे में जाये उनसे जाकर कोई भी बात कर सकते हो। सदन में उठकर इस तरह का माहौल बनाते हो, सदन में आये हो। कुछ लोग पहली बार आये हैं, कुछ पुराने भी हैं, लेकिन मैंने पहली बार कहा था 269 के लिये, नहीं तो सुबह आते ही मुझे 269 को दोहराना पड़ेगा सबसे। मुझे इस बात के लिये मजबूर होना पड़ेगा। अपन मंत्री भी हैं और वरिष्ठ भी हैं। कोई यहां से सीधा उठकर वहां जा रहा है, कोई उठकर बोल रहा है। मुझे बार-बार टोकना पड़ता है। यह स्थिति अच्छी नहीं है।

जिसका प्रश्न हो, केवल वही प्रश्न पूछेगा और दो पूरक प्रश्न पूछेगा। उसके बाद विपक्ष के नेता को अनुमति दूंगा तो पूछेंगे, उसके बाद अगले प्रश्न पर जायेंगे। प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, इसको आपको कहना है तो बाद में कह देना। प्रश्न में आप जो उत्तर चाहते हो, मंत्रीजी के द्वारा वही उत्तर आये, यह आवश्यक नहीं है किसी के लिये, मैं मंत्रियों से भी आग्रह करूंगा कि वे तैयारी करके आयें और उन प्रश्नों का सही-सही उत्तर भी दें, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। अब पूरक प्रश्न पूछने वाला भी उस प्रश्न के दांये-बांये नहीं जाये, उस प्रश्न से जुड़ी हुई बात ही पूछे। पूरक प्रश्न पर भी माननीय सदस्य भाषण देना शुरू कर देते हैं। यह भी उचित नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आज एक घोषणा है। मैं अभी खड़ा हूं, मैं बैठ जाऊं फिर आपको बुलवाऊंगा।

घोषणा

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही (वर्ष 1997 से) के
विडियो अंशों की सार्वजनिक उपलब्धता

मैं माननीय सदस्यगण को अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान विधान सभा के कार्यवाही वृत्तान्त इसके प्रारम्भ वर्ष 1952 से त्वरित खोज की सुविधा के साथ इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ...(व्यवधान) आप बैठिये न माननीय। रफीक खान और माननीय मंत्रीजी, मेरा काम मैं करूंगा।

इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही, जो 10वीं विधान सभा के 8वें सत्र के समय दिनांक 6 मार्च, 1997 से तत्कालीन निर्णय अनुसार आवश्यक समयावधि की रिकार्ड की गई थी, अब तकनीक परिवर्तन पश्चात् उपयोगार्थ बना ली गई हैं एवं उन्हें राजस्थान विधान सभा के यू-ट्यूब चैनल पर उपलब्ध व वेबसाइट पर कार्यवाही वृत्तान्त के साथ लिंक कर दिया गया है। आप 1997 के बाद के कोई भी अपने यहां खोलकर आप देख सकते हो, आपको पूरा कार्यवाही वृत्तान्त मिलेगा।

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही के इन विडियो को सार्वजनिक किये जाने के पीछे उद्देश्य यह रहा है कि राजस्थान विधान सभा के गौरवमयी इतिहास से हम सजीव रूबरू हो सकें व इसकी समृद्ध संसदीय विरासतों के स्तम्भों को नमन करते हुए, संसदीय लोकतंत्र के

मूल मंत्र (1) विविधता में एकता व (2) सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मार्ग को प्रशस्त करते हुए राजस्थान प्रदेश व भारत देश के सर्वांगीण समन्वयी विकास में अपने योगदान के प्रति उत्तरोत्तर दृढ संकल्पित रहें।

मेरा आपसे आह्वान रहेगा कि आप राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही के इन विडियोज का अधिक से अधिक उपयोग करें व वाद-विवाद की बारीकियों का अध्ययन करते हुए अपने योगदान को अधिक मुखर व कारगर बनाने का प्रयास करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में वन विभाग में कार्यरत खिलाडियों को ट्रेनिंग में शिथिलता प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में आपराधिक प्रकरणों का निस्तारण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री मुकेश भाकर, सदस्य की ओर से डीडवाना-कुचामन के गांव छापरी स्थित बायोमास प्लांट को हटाने के संबंध में।

(4) श्री मोतीराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के सुकली-सैलयाड़ा बाँध से निकलने वाली नहरों की मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्रीमती गीता बरवड़, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में बीजेएस बस स्टेण्ड से बनाड़ तक बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे पर 60 किमी के अन्दर दो टोल बूथ होने से टोल टैक्स वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री टीकाराम जूली, सदस्य की ओर से 05 जुलाई, 2024 को राजस्व मण्डल अजमेर में नियुक्त किये गये राजकीय अधिवक्ताओं को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम खण्डाच में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण का विरोध करने वाले ग्रामीणों पर फायरिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के कतिपय राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के स्टेट हाईवे संख्या 20 के अन्तर्गत अधूरी सड़कों को पूर्ण किये जाने के संबंध में।

(11) श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में छात्रसंघ चुनावों पर लगी रोक नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ सहित पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं की टक्कर से राहगीरों के चोटिल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से केन्द्र सरकार की भांति आर.एस.एस. की गतिविधियों में सम्मिलित होने हेतु राज्य कर्मचारियों को छूट प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में 1995 के बाद से तीन संतान होने पर अयोग्य घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(16) डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बिजली के खम्भों से केबल चोरी होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में सी.एफ.सी.डी., आर.एन.एफ.सी.डी. एवं स्ट्रोम वाटर ड्रेस के निर्माण एवं पुनरूत्थान की डी.पी.आर. के संबंध में।

(18) श्री नरेन्द्र बुडानियां, सदस्य की ओर से कार्यालय नगर पालिका तारानगर द्वारा निदेशालय भेजी गई ई-निविदा की पत्रावलियों को वापस नहीं लौटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्रीमती शिमला देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ में गुलाबी सुन्डी के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डॉ. प्रियंका चौधरी, डॉ. सुभाष गर्ग, श्री नरेन्द्र बुडानियां एवं श्रीमती शिमला देवी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

कुछ माननीय सदस्य भी स्थगन प्रस्ताव लगाते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि स्थगन लगाते समय जो एक बार स्थगन प्रस्ताव आ गये, उनको बार-बार नहीं करके नये विषय पर लगायें तो देने में अनुमति होगी और साथ में सप्ताह में एक स्थगन प्रस्ताव सदस्य का होगा। वह बार-बार भी लगायेगा तो एक ही बार सप्ताह में आयेगा। जब सात दिन हो जायें तब वे वापस लगा सकते हैं तो जरूर उस पर कंसीडर किया जा सकता है।

MLS/RTM/23.07.2024/12:10/1h

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर की मिसिंग लिंक

सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री जसवंत सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में निर्माणाधीन चिकित्सालय का मुख्य द्वार हाईवे की ओर रखे जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री लक्ष्मण, सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर रोक हेतु टास्क फोर्स का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धौलपुर शहर में छितरिया ताल के ओवर फ्लो होने एवं सीवर लाइन के निकास की व्यवस्था न होने से कॉलोनियों में हो रहे जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में।

5. श्री संजय कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के क्षेत्रीय वन रेंज सरमथुरा में वनरक्षक द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

6. श्री शंकरलाल डेचा, सदस्य की ओर से काकरी डूंगरी प्रकरण खेरवाड़ा में दर्ज प्रकरणों की न्यायिक जांच करवाकर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।

7. डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में सोलर प्लांट हेतु लीज पर दी जाने वाली भूमि के भू-रूपान्तरण प्रक्रिया में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में।

9. श्री हाकम अली खॉ, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 के फोर लेन में परिवर्तन करने में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

10. श्री हरलाल सहारण, सदस्य की ओर से चूरू शहर में बारिश के पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

11. श्री मुकेश भाकर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में जर्जर विद्युत लाइनों से आये दिन हो रही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से जयपुर शहर के जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाये जाने के स्थान पर अण्डरपास बनाये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में निर्माणाधीन नौनेरा बांध के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा देने एवं प्रभावितों का पुनर्वास किए जाने के सम्बन्ध में।

14. डॉ. शैलेश सिंह, सदस्य की ओर से नवसृजित डीग जिले की कुम्हेर तथा रारह तहसील को भरतपुर जिले में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।

15. श्री धर्मपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की उप तहसील बबाई में नवीन पंचायत समिति का गठन किए जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 23.07.2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 54 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	पर्ची सं.	मा. सदस्य का नाम	विषय
1.	17	श्री रामस्वरूप लाम्बा	नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का पूर्व की भांति संचालन नहीं होने एवं नसीराबाद सिटी बस स्टैंड पर बसों के अंदर नहीं आकर बायपास से गुजरने से यात्रियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
2.	33	श्री हरिसिंह रावत	राजस्थान प्रदेश में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट में एक राष्ट्र, एक कर व्यवस्था किए जाने व परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही धांधली के विरुद्ध कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।
3.	5	श्री गोविन्द प्रसाद	मनोहर थाना विधान सभा की डामर सड़को से वंचित गांवो को जोड़ने, मिसिंग लिंक, पैचेबल सड़कों का निर्माण करवाने एवं उच्च स्तरीय पुलियाओं को हाई लेवल ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में चर्चा।
4.	1	श्री रविन्द्र सिंह भाटी	शिव क्षेत्र में स्थित किराडू के मंदिर, सूर्य मंदिर देवका और पौराणिक मंदिरों के संवर्धन व सरंक्षण करने तथा आवश्यक नीति बनाने के सम्बन्ध में।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हम सब आपकी व्यवस्थाओं से बंधे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मंत्री परिषद् के सभी साथी पूरी तैयारी से आते हैं, तथ्यात्मक जवाब लेकर आते हैं, पूरा जवाब देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे स्पेशल निवेदन है, आपके पास प्रश्न भी हैं, प्रश्न की विषय-वस्तु भी है और विभाग द्वारा दिया गया हमारे मंत्री जी द्वारा दिया गया आंसर भी है। उसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे मंत्री पूरी तैयारी के साथ आते हैं और सही जवाब देते हैं। अब किसी की अपेक्षा के अनुसार जवाब आये या न आये, यह अलग विषय हो सकता है। यही मेरा निवेदन था।

श्री अध्यक्ष: डॉ. प्रियंका चौधरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बाड़मेर में बिजली के खम्भों से केबल चोरी

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पिछले दो महीनों से बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण पुलिस थाने के अन्तर्गत भाडका और खारिया तला पंचायत हैं। वहां आसपास के क्षेत्र में लगातार विद्युत केबल की चोरियां हो रही हैं। इससे आमजन और किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि पिछले 6 महीने से लगातार बाड़मेर जिले में विद्युत केबल की चोरी की समस्या चल रही है। 28 जनवरी को गडरा रोड थाना क्षेत्र में विद्युत केबल चोरी हुई। 31 जनवरी को रीको थाना के अन्दर 132 केवी जीएसएस की विद्युत केबल चोरी हो गयी। 6 जून को एफआईआर दर्ज हुई खारिया तला और भाडका की। 13 जून को फिर सोलर प्लांट से चूली पंचायत में केबल चोरी हो गयी।

2 जुलाई को गोसाईराम, सत्ताराम ने एफआईआर दर्ज की। वहां खारिया तला से विद्युत केबल की चोरी हो गयी। 17 जुलाई को फिर से एक केबल चोरी हुई। बीरबाराम, पूनमाराम ने एफआईआर दर्ज करायी। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि ये जो विद्युत केबल चोरी की घटनाएं लगातार पूरे बाड़मेर जिले में हो रही हैं और बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में लगातार हो रही हैं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साहब, इन्होंने गोष्ठियां चालू कर दी हैं। आपके निर्देशों को मानते ही नहीं हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य, कोई गोष्ठियां चालू नहीं हुई हैं। माननीय सदस्य, अपनी सीट से बार-बार उठना व्यवस्था के खिलाफ है। मैं आसन से निवेदन करूंगा, ये बार-बार व्यवधान डालते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: यह मेरा काम है। बैठिये।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): जो लगातार विद्युत केबल की चोरी हो रही है, उससे आमजन को बहुत समस्या हो रही है। करीब 6-6, 7-7 दिनों तक विद्युत सप्लाई बाधित रहती है। इतनी एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आज दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरा आपसे यह आग्रह है कि इसकी जांच की जाये, पुलिस की गश्त बढ़ायी जाये और दोषियों को गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई की जाये। लगातार विद्युत केबल चोरी होने से सरकार को भी घाटा हो रहा है और आमजन और किसानों को भी समस्या हो रही है। अतः मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस पर तुरन्त ध्यान देकर पुलिस को दोषियों पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डॉ. सुभाष गर्ग।

भरतपुर में सी.एफ.सी.डी., आर.एन.एफ.सी.डी. एवं स्टॉर्म वॉटर ड्रेंस का निर्माण एवं पुनरुत्थान

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन

प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में मुख्य मंत्री बजट घोषणा 2021-22 के अन्तर्गत एक वर्षों पुरानी समस्या थी, पिछले 70 वर्षों से भरतपुर में पानी भराव की समस्या थी। आप जानते हैं कि भरतपुर की कितनी ही कॉलोनियां हैं जो 8-8, 10-10 फीट नीचे हैं। बड़ी मुश्किल से पूर्ववर्ती सरकार ने अपनी बजट घोषणा में लगभग 362 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान करके उसके टैंडर किये और वर्क ऑर्डर जारी करके काम शुरू कराया।

इसमें सी.एफ.सी.डी., आर.एन.एफ.सी.डी. एवं स्टॉर्म वॉटर ड्रेंस बननी थीं। उसमें डीपीआर के मुताबिक काम शुरू हो गया। दो वर्ष तक काम हो गये, लेकिन होता क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि 2021-22 से लेकर अब तक करीब-करीब 3 कलेक्टर्स चेंज हो गये। किसी भी कलेक्टर ने उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। अभी जो नये कलेक्टर आये, उन्होंने इस पूरी स्कीम की समीक्षा के ही आदेश करवा दिये। अनऑफिशियली मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने सीएमओ में जाकर गुमराह करने की कोशिश की।

वह तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि भरतपुर के हैं, भरतपुर के बारे में पूरी तरह जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरी सी.एफ.सी.डी. योजना भरतपुर की लाइफलाइन है, 70 वर्षों की जिस समस्या का समाधान तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने किया था, अब समीक्षा के नाम पर उस कार्य को रोका जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि उसमें करीब 4.8 किलोमीटर की पक्की ड्रेंस बनकर 40 मीटर की सी.एफ.सी.डी. को पक्का करना था, 40 फीट की उसमें सड़कें बननी थीं। यह जो योजना लागू की गयी थी, वह पूरी तरह सैल्फ सस्टेनेबिलिटी के आधार पर की गयी थी।

150 करोड़ रुपये का लोन नगर निगम ने हुडको से लिया। बाकी राज्य सरकार दे रही है। इसके तहत उस जगह मार्केट डवलप करने का प्रावधान था। मेरा आपसे आग्रह है, अभी माननीय मंत्री जी हैं नहीं, मैं उनसे जरूर यह चाहता था कि समीक्षा के नाम पर इस परियोजना को नहीं रोका जाये। यह परियोजना भरतपुर के 5 लाख लोगों की लाइफलाइन है। वहां के बाशिन्दों में काफी आक्रोश है। इसे खत्म करने के लिए इस योजना को पूरा कराया जाये।

श्री अध्यक्षः श्री नरेन्द्र बुडानियां।

तारानगर नगरपालिका द्वारा निदेशालय प्रेषित

ई-निविदा पत्रावलियों का लम्बन

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। तारानगर नगरपालिका में दिनांक 07.07.2023 को 13 कार्यों के टैंडर हुए थे। 21.08.2023 को ये टैंडर नियमानुसार खोले गये। 31.08.2023 को इन निविदाओं की टैक्निकल वित्तीय स्वीकृति जारी हुई। 27.09.2023 को इन 13 कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी हुए और 04.10.2023 इनका विधिवत

शिलान्यास भी हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 07.12.2023 को ये सभी पत्रावलियां बिना किसी लिखित आदेश के निदेशालय में भेजनी बतायी गईं। मैंने बार-बार निदेशालय में जाकर इसकी जानकारी की। मैं मंत्री महोदय से भी मिला हूं। यह फाइल वहां पर नहीं है। यह बताया गया कि फाइल मिल नहीं रही है। नगरपालिका ने कहा कि एक शिकायत हुई थी, लेकिन वह शिकायत निराधार है। सारे टैंडर्स नियमानुसार खोले गये हैं, नियमानुसार कार्यवाही हुई है। काम चालू हो गये और चालू होने के बाद सरकार बनी ही नहीं, 7 तारीख को ये पत्रावलियां आनन-फानन में किसने मंगाईं, कहां गईं, कौन ले गया, ये सारी बातें गर्भ के अन्दर हैं।

mkd/rtm/23.07.2024/12:20/1j

अध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्य चालू हुए 7 महीने हो गये हैं। सात महीने में इसकी कितनी कॉस्ट बढ़ी है? नगर पालिका को कितना नुकसान हुआ है?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच करवायेंगे? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करायेंगे? और काम शुरू हो सकें, इसलिए पत्रावलियों को तुरन्त प्रभाव से भिजवाने की व्यवस्था करवायेंगे। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शिमला देवी।

अनूपगढ़ में फसलों का गुलाबी सुन्डी के कारण क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): धन्यवाद, सर। आपने मुझे नियम 50 के तहत बोलने का मौका दिया। मेरा बहुत ही गम्भीर मुद्दा गुलाबी सुन्डी को लेकर है। सर, पिछले वर्ष भी इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ था। जो गंगानगर खंड हैं, उसके अन्दर तीन जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ जिला आता है। इस वर्ष भी हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा टीम बनाकर सर्वे किया गया था, जिसमें गुलाबी सुन्डी का प्रकोप हमारी कॉटन की फसल में देखने को मिला था।

किसानों के अन्दर बहुत भय बना हुआ है। हमारी कॉटन की फसल को लेकर। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 42 प्रतिशत हमारी बुआई कम हुई है, क्योंकि पिछले वर्ष 75 से 90 प्रतिशत गुलाबी सुन्डी के कारण किसानों को बहुत भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। कृषि विभाग के द्वारा गिरदावरी, सर्वे की सारी रिपोर्टें सब्मिट होने के बावजूद भी एक रुपया भी मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि तुरन्त प्रभाव से किसानों को मुआवजा दिया जाये। अभी जो गुलाबी सुन्डी को प्रकोप फसलों के अन्दर देखने को मिल रहा है तो किसान खड़ी फसल को नष्ट कर रहे हैं। यह गम्भीर मुद्दा है, सरकार से में मांग करती हूं कि समय रहते आप गुलाबी सुन्डी को नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठायेंगे? इसके साथ-साथ जो गुलाबी सुन्डी को नियंत्रित करने के लिए जो कीटनाशक आते हैं, वे किसानों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाये और हमारे कॉटन के उद्योग को बचाये, किसान

को बचाये, मजदूर को बचाये, क्योंकि कॉटन से हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री अमित चाचाण।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नोहर की मिसिंग लिंक सड़कों को निर्माण

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि आप आसन से व्यवस्था दें कि जीरो ऑवर में सभी माननीय मंत्री महोदय विराजमान रहें।

श्री अध्यक्ष: आप अपना 295 पढिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर): राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि नोहर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की आबादी अत्यधिक है, लगभग 200 गांव व चक नोहर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैं, निम्न मिसिंग लिंक सड़कों के अभाव में ग्रामवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों के अभाव में ग्रामीणों को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए अत्यधिक दूरी तय करके जाना पड़ता है, जिससे समय व धन की बर्बादी हो रही है।

अतः आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि ग्रामीणों के सुलभ आवागमन के लिए निम्नलिखित मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया जाये :-

पदमपुरा से जनानिया, ललाना से भोगराना, पांडूसर से बालासर, भगवानसर से नीमला, श्योराणी से खरसंडी, मन्दरपुरा से चैनपुरा, कानसर से थिराना, आपुवाला से अरडकी, दनियासर से दूधली, धानसिया से सिरंगसर, मन्दरपुरा से सांगठिया, थिराना से नणाऊ, नीमला से थिराना, ढाणी लेघान से प्रेमपुरा, धान्धूसर से मलकासर, बिडबिराना से सूरपुरा, मन्दरपुरा से नीमला, रायसिंहपूरा से लाखासर व कुलचासर से बिसरासर, धन्यवाद|

श्री अध्यक्ष: श्री जसवन्त सिंह गुर्जर। शुरू कीजिये, जो आपने सब्मिट किया है, वही पढ़ना है। उसके अलावा एक अक्षर नहीं।

बाड़ी में निर्माणाधीन चिकित्सालय का हाईवे की दिशा में मुख्य द्वार

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र, बाडी (धौलपुर) में जो नवीन अस्पताल बनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: उसमें जो लिखा है, वही पढें। उसमें एक भी वाक्य एड नहीं करें। मेरे पास भी लिखा हुआ है।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): उसे ही पढ़ रहा हूं।

उसका मेन दरवाजा कुछ व्यक्ति विशेषों को फायदा देने के लिये उनके पुराने राजनेता ने अपने होटल की तरफ खुलवाने के लिए प्रयासरत हैं। अध्यक्ष महोदय, स्टेट हाईवे पर

हॉस्पिटल बन रहा है।

श्री अध्यक्षः ये इसमें कहां है? यह जो आपने दिया है। विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में, आप तो अलग बात कर रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): जिससे उनकी जमीन के भाव आसमान छूएं। उल्लेखनीय यह है कि आम आदमी को इससे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसके कारण मरीजों को जाम इत्यादि होने से उपचार समय पर नहीं मिल सकेगा।

उल्लेखनीय यह है कि इन्हीं राजनेता ने अपने होटल की वजह से जो सिंचाई विभाग की जमीन हैं और तो और सिंचाई विभाग के द्वारा अनेकों नोटिस देने के बावजूद उक्त पर सड़क का निर्माण करा दिया गया, जबकि पीडब्ल्यूडी/नगर निगम मना करता है। हमने उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया और उक्त सड़क निर्माण ने कई किसानों की जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया गया है।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त अस्पताल का मैन गेट हाइवे की तरफ खुले, जिससे मरीजों को शहर के अन्दर नहीं आना पडे तथा उक्त होटल के सामने अवैध निर्माणाधीन सड़क को तोडा जावे एवं पुनः उस नहर को जीवित कराया जावे जिससे किसानों के खेतों की सिंचाई हो सके।

श्री अध्यक्षः श्री लक्ष्मण मीणा।

नशे की रोकथाम हेतु टास्क फोर्स का गठन

श्री लक्ष्मण (बस्सी): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत सूचना।

महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में एक गंभीर समस्या दिनों-दिन विकराल रूप लेती जा रही है। यह समस्या युवा पीढी में बढ़ती हुई नशे की लत है। कुछ वर्षों पूर्व प्रदेश के कुछ जिलों तक ही यह सीमित थी, लेकिन यह नशे की लत पूरे प्रदेश में व्याप्त है। पहले नशे के लिये अफीम, डोडा, पोस्त, गाजा आदि नशीले पदार्थों का सेवन करते थे लेकिन अब हेरोइन, कोकीन, एमडी ड्रग, सिंथेटिक ड्रग का उपयोग बढ गया है। पुलिस ने भी राज्य के 17 जिलों को एमडी ड्रग का उभरता हुआ केन्द्र माना है, ये अधिकतर जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए हैं।

नशे के आदी युवा पीढी इस लत के कारण बर्बाद हो रही है। कम उम्र में मौतें हो रही हैं। अपराधों में वृद्धि हो रही है तथा परिवारों में तनाव एवं क्लेश की स्थितियां बनी हुई हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि नशे की बढ़ती हुई इस विकराल समस्या का प्रभावी ढंग से नियंत्रण करे, विशेष टास्क फोर्स गठित कर तथा विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों को इस कार्य में लगाये। नशे के कारोबार में लिप्त हुए लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट में प्रभावी कार्यवाही कर उन्हें जेलों में भेजा जावे तथा विद्यालय, कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के नजदीक नशीले पदार्थ बेचने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की

जावे। स्वयं सेवी संस्थाओं, पुलिस तथा अन्य प्रचार-प्रसार के साधनों से युवा पीढी में नशे की लत तथा इसके कारण समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी जानी चाहिए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभारानी।

धौलपुर में जलभराव की समस्या

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रणाम। आपने मुझे 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं धौलपुर शहर की एक गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराना चाहती हूं। धौलपुर शहरी क्षेत्र के नजदीक प्राकृतिक जल स्रोत छितरिया ताल की दीवार से पानी के ओवर फ्लो होने के कारण एवं नगर परिषद क्षेत्र में जो सीवर लाइन डाली गई है, उसके निकास की उचित व्यवस्था ना होने के कारण धौलपुर शहर की 10 से 15 कॉलोनियां पानी से जल मग्न हो जाती हैं। धौलपुर शहर की भोगीराम नगर, गोकुल चंदन बिहार, मनोहर बिहार, अयोध्या कुंज, रामकुंज, पोखरा आदि कॉलोनियों में कभी-कभी 3-3 फुट तक पानी भर जाता है। जिससे कॉलोनियों की बहुत ज्यादा दुर्दशा हो चुकी है। बच्चों व राहगीरों के निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जन सामान्य अपने कार्यों पर नहीं जा पाता है। जिसके संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पहले भी बजट मांग राजस्थान सरकार से की गई थी।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस समस्या के तुरंत निदान हेतु आवश्यक बजट एवं पानी की उचित निकासी की महती आवश्यकता । जिसके संदर्भ में जिला प्रशासन को पाबंद करते हुए आवश्यक बजट राशि से तुरंत धौलपुर वासियों को निजात दिलाई जाने की कृपा करें। जय हिन्द, जय भारत, जय-जय राजस्थान।

Bhs/Rtm/23.7.24/12.30/1k

श्री अध्यक्ष: श्री संजय कुमार।

बसेड़ी के क्षेत्रीय वन रेंज सरमथुरा में वनरक्षक द्वारा की गईं अनियमितताएं

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र, बसेड़ी (धौलपुर) के क्षेत्रीय वन रेंज सरमथुरा के अन्तर्गत नाका खुर्दिया, इंदौरा झिरी में कैम्पा, नाबार्ड स्टेट प्लान के योजना के तहत कई हेक्टेयर जमीन पर प्लांटेशन, चारदीवारी, कच्ची खाई, कच्ची चारदीवारी, तालाब, ट्रेन्च आदि के कार्य सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही कराये गये हैं और जो कार्य धरातल पर मौजूद हैं वो अपूर्ण हैं।

उल्लेखनीय यह है कि रेंज सरमथुरा के अन्तर्गत नाका खुर्दिया में वर्ष 2016-17 से सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्मिक वन रक्षक के पद पर पदस्थापित है, जबकि विभागीय गाईडलाइन के अनुसार एक नाके में एक वनपाल के साथ चार वनरक्षक तैनात होने चाहिए तथा

विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार एक नाके में दो साल से ज्यादा समय होने पर उक्त कार्मिक उस नाके में नहीं रह सकता जबकि यह कार्मिक वर्ष 2016-17 से सिर्फ और सिर्फ अकेला ही नाका खुर्दिया में पदस्थापित है।

बड़ा शोचनीय विषय है कि नाका खुर्दिया के अन्तर्गत धौलपुर डिविजन के अन्दर आये हुए कार्यों का 80 प्रतिशत कार्य सिर्फ और सिर्फ नाका खुर्दिया में ही क्यों आया। उक्त कार्मिक ने विभागीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए नाका खुर्दिया में वन भूमि न होने के बावजूद भी राजस्व विभाग की भूमि जैसे कि चरागाह, सिवायचक, गोचर एवं ग्राम पंचायत की आबादी में बिना अनुमति के कार्य कराये हैं। यह भी एक शोचनीय विषय है।

वर्ष 2016-17 में पदस्थापित वन रक्षक ने कई घोर अनियमितताएं बरतते हुए सिर्फ कागजों में ही कार्य किये हैं तथा कुछ अपूर्ण कार्यों के भुगतान उठा लिये हैं जो कि कार्य मौके पर पूर्ण नहीं हैं। वन रक्षक के द्वारा अपने परिवार जनों के साथ-साथ अपने रिश्तेदारों के खातों में कई लाखों रुपयों का ग्राम वन समिति से भुगतान उठा लिया है। मेरे द्वारा उक्त कार्मिक की शिकायत सी.सी.एफ., भरतपुर को करने पर इसके खिलाफ जांच बैठाई गई तथा इसे ए.पी.ओ. कर कार्यालय उपवन संरक्षक, धौलपुर कर दिया गया, लेकिन उक्त वन रक्षक आज दिनांक तक कार्य ग्रहण न करते हुए अनुपस्थित चल रहा है।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस वनरक्षक की जांच ए.सी.बी. में मुकदमा दर्ज कराते हुए कराई जाए। सादर।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर लाल डेचा। (अनुपस्थित)

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल।

खाजूवाला में सोलर प्लान्ट हेतु लीज पर दी जाने वाली भूमि के भू-रूपान्तरण प्रक्रिया में छूट

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन है कि बीकानेर के खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में विगत 3-4 सालों से सोलर ऊर्जा प्लांट लगाये जा रहे है। सरकार ने भी इस बजट में छतरगढ़ और पूगल क्षेत्र में सोलर पार्क की घोषणा की है। निजी कम्पनी भी सोलर ऊर्जा प्लांट लगा रही है। सरकार द्वारा निजी कम्पनियों को जमीनें आवंटित की जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि वहां के स्थानीय एवं पाक विस्थापित किसान जो भूमिहीन किसान हैं, उनको प्राथमिकता से कम्पनी की दर पर ही भूमि आवंटित कर दी जाए, तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की राजस्व हानि नहीं होगी।

वहीं जमीन किसान सोलर कम्पनी को लीज पर दे सकेगा, जिससे उसके जीवन स्तर में सुधार आयेगा दूसरा मेरा निवेदन है कि टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 46ए का हवाला देकर सोलर कम्पनियां अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों की जमीन लीज पर लेने के लिए, उस भूमि का कन्वर्जन आवश्यक बताते हैं। गरीब किसानों के लिए यह प्रक्रिया जटिल होती है और जिला राजस्व अथवा उपखण्ड अधिकारी को 20 बीघा से अधिक कन्वर्जन का

अधिकार नहीं होता। इससे अधिक भूमि को राज्य सरकार से कन्वर्जन करवाना होता है, जिसमें 6 से 12 माह का समय लगता है। मध्यस्थ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, जिससे धन एवं समय दोनों ही अधिक लगते हैं।

चूंकि राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति संवेदनशील है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि लीज पर ली जाने वाली भूमि की कन्वर्जन प्रक्रिया में छूट दी जाए अथवा प्रक्रिया का सरलीकरण किया जावे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये। कोई अनुमति नहीं है। 295 चल रहा है बीच में खड़े हो गए। श्री पितराम सिंह काला।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि शिक्षा विभाग राजस्थान में जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष लगभग 550 पद स्वीकृत है, जिनमें से लगभग 330 पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संचालन व मॉनिटरिंग का ढांचा चरमरा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर डी.पी.सी. करने पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश है इस वजह से पिछले 03 वर्ष (22-23, 23-24, 24-25) की डी.पी.सी. नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में पद लगातार खाली होते जा रहे हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

1. न्यायालय का निर्णय आने तक निर्णयाधीन एडहॉक पदोन्नति से या पातेय वेतन पर रिक्त पदों को तत्काल भरा जाना चाहिए।

2. माननीय न्यायालय में विभाग द्वारा बनाई गई वरिष्ठता सूची दिनांक 15.06.2023 से वरिष्ठता के आधार पर प्रधानाचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष रिक्त पदों पर पच विरूद्ध पदस्थापित किया जाना चाहिए, जिससे माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना भी नहीं होगी तथा विभाग को कार्यव्यवस्थार्थ जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष रिक्त पदों पर अधिकारी मिल जाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हो गया आपका। यह प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य, जिसने जो लिखा है उसी को पढ़ना है उसके अलावा एक अक्षर भी न तो अंकित होगा, न ही बोला जाता है। श्री हाकम अली खान।

फतेहपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के फोरलेन में परिवर्तन में अनियमितताएं

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र, फतेहपुर शेखावटी से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (पाली-अम्बाला) के संदर्भ में हो रही अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त राजमार्ग के फोरलेन परिवर्तन का कार्य गत कुछ माह से मै. गल्फार कंपनी और सालासर हाईवे लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है किन्तु मैं अत्यन्त

खेद के साथ कह रहा हूं कि उक्त राजमार्ग के दोहरीकरण के दौरान भयंकर अनियमितता विशेष तौर से फतेहपुर परिक्षेत्र में की जा रही है।

उल्लेखनीय यह है कि चूरू और बीकानेर की तरफ से प्रवेश द्वार केवल 20-25 फुट चौड़ी सड़क प्रवेश हेतु बची है जबकि दूसरी तरफ रोड बाउंड्री पर सैकड़ों फुट जमीन खाली छोडी गई है। उक्त राजमार्ग के एक तरफ दो जांटी बालाजी मंदिर और दूसरी तरफ विनायक शिक्षण संस्थान है। रोजमर्रा आने वाले अनेक श्रद्धालु और छात्रों को धुमाव वाले अंडरपास से गुजरना होगा तथा दुर्घटना होने का डर उन पर बना रहेगा। इस पुल पर आये दिन महीने में तकरीबन 20-25 दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। यहां कैसे दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं इसके लिये उक्त राजमार्ग पर बन रहे पुल को तकनीकी इन्जीनियरों से सर्वे कराया जाये, जिससे आये दिन हो रही दुघर्टनाओं पर लगाम लग सके। मेरा कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया है, किन्तु आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देशित कर, इस मसले पर संज्ञान लेकर जनहित में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः श्री हरलाल सहारण।

चूरू शहर में वर्षा जल के निकासी की समुचित व्यवस्था

श्री हरलाल सहारण (चूरू): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन है मेरे निर्वाचन क्षेत्र चूरू जिला मुख्यालय कि एक महत्वपूर्ण समस्या पर जो कि चूरू जो देश में सर्वाधिक गर्मी व सर्वाधिक सर्दी के लिए प्रसिद्ध है।

विगत एक सप्ताह से लगातार तीन बार 70 से 80 एम.एम. बारिश एक दिन में होने के कारण चूरू शहर का विगत सरकार में ड्रेनेज के घटिया काम के कारण, घरों में तीन दिन से 1 फुट से 3 फुट पानी भरा होने के कारण अखबारों की सुर्खियों में है।

चूरू जिला मुख्यालय जिसकी आबादी 4 लाख को पार कर रही है आधी आबादी व पूरा बाजार बरसात के पानी की निकासी नहीं होने से परेशान है। चूरू के जौहरी सागर, जहां से पूरे शहर का पानी गाजसर, गिनानी में पंप द्वारा फेंका जाता है। चूरू नगर परिषद् द्वारा कांग्रेस राज में नये मोटर पंप की राशि 125.00 लाख रुपए उठाये गये परन्तु वास्तव में एक पुरानी मोटर पंप को पेंट कर जौहरी सागर में रख दिया गया जो पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है।

जौहरी सागर जल भराव समस्या विगत पांच वर्षों की अवधि के दौरान नगर परिषद चूरू की ओर से जल निकासी की व्यवस्था के नाम पर में मौजूदा पम्पिंग स्टेशन की लिए नई मोटर क्रय किये जाने एवं उनकी मरम्मत पर लगभग 74.00 लाख रुपये व्यय किए गए है।

इसके अतिरिक्त उक्त पम्पिंग स्टेशन के रख-रखाव एवं सम्पवैल सफाई व गेट वॉल

मरम्मत पर भी नगरपरिषद की ओर से 125.00 लाख रुपये व्यय किए गए है परंतु उक्त कार्य हेतु नगरपरिषद की ओर से की गई मोटर पूरी तरह घटिया क्वालिटी की होने एवं मौके पर उक्त पम्पिंग स्टेशन का रख-रखाव नहीं होने से उक्त पम्पिंग स्टेशन पूरी तरह बेहाल स्थिति में पहुंच चुका है।

शहर में बारिश का पानी से लगभग 6 वार्डों की 300 से अधिक घरों की आबादी बरसाती पानी से घिर जाती है तथा उक्त क्षेत्र में मौजूद लगभग 150 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी प्रभावित होते हैं। विगत सरकार के कार्यकाल में जौहरी सागर पम्पिंग स्टेशन का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया गया तथा इस पर खर्च किये गये सरकारी धन का पूर्णतया दुरुपयोग हुआ है, जिसकी उच्चस्तरीय जाँच करवाये जाने की मांग की जाती है।

Kas/rtm/23.07.2024/12.40/1l

श्री अध्यक्षः श्री मुकेश भाकर। (अनुपस्थित)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः बाद में, जीरो ऑवर के बाद। श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित), श्री चेतन पटेल कोलाना।

पीपल्दा में निर्माणाधीन नौनेरा बांध के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा व प्रभावितों का पुनर्वास

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के नौनेरा डैम का कार्य चल रहा है व लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण भी हो गया है। इस डैम में कई किसानों की भूमि अवाप्त की गई है व कई गाँव इस डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। किसानों की जमीन अवाप्त की गई है, उन किसानों को लगभग 90 प्रतिशत मुआवजा प्रदान कर दिया गया है। कुछ किसानों का अवाप्त जमीन का मुआवजा बाकी है, उन्हें शीघ्र ही मुआवजा प्रदान किया जावे।

इसी क्रम में नौनेरा डैम में डूब क्षेत्र में आसपास के कई गाँव हैं, जिनको सरकार ने अभी तक शिफ्ट नहीं किया है। डैम आगामी समय में आरम्भ हो जावेगा, इसी परिप्रेक्ष्य में गाँवों के निवासीयों को शिफ्ट करना अति आवश्यक है। इन ग्रामवासीयों को अन्यत्र घर प्रदान किया जावे या उनको घर बनाने हेतु पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जावे।

राज्य सरकार से अनुरोध है कि नौनेरा डैम में अवाप्त की गई शेष भूमि का मुआवजा अविलम्ब प्रदान किया जावे तथा डूब क्षेत्र में आने वाले घरों को पुनः बसाया जावे या उनको इतना मुआवजा प्रदान किया जावे कि वह अन्यत्र मकान बनाकर रह सकें, धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः जीरो ऑवर के बाद। जीरो ऑवर के समाप्त होने के बाद ही कोई इन्फोर्मेशन आती है। आप समझदार हैं, मेरे से सीनियर हैं। ...(व्यवधान)... मैंने कहा बाद में। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्षः बैठिए, बैठिए। बाद में मेरे चेम्बर में आकर बताइए। डाक्टर शैलेश सिंह।

कुम्हेर तथा रारह तहसील को भरतपुर जिले में सम्मिलन

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नवसृजित जिला डीग से तहसील कुम्हेर व रारह को भरतपुर जिले में जोड़े जाने के संबंध में विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में डीग को नया जिला बनाया गया। नवसृजित डीग जिले में कुम्हेर एवं रारह तहसील को शामिल किया गया। कुम्हेर व रारह तहसील भरतपुर शहर के आसपास बसी हुई है, जो कि नगर निगम भरतपुर के क्षेत्र से मात्र 1 किलोमीटर से 6-7 किलोमीटर है, जबकि डीग मुख्यालय 45 किलोमीटर दूर है। कुम्हेर और रारह तहसील के ग्रामीण निवासियों के ज्यादातर मकान भरतपुर शहर में बने हुए हैं। गत नगर निगम भरतपुर के चुनाव में 22 वार्डों में कुम्हेर व रारह के निवासी चुनाव लड़े थे। उनका सामाजिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं पारिवारिक समरसता भरतपुर शहर के साथ है। कुम्हेर एवं रारह में मजदूर व छोटे किसानों की संख्या अत्यधिक है और ज्यादातर लोग अपनी दिहाडी मजूदरी करने भरतपुर जाते हैं। ऐसे में उनके निजी कार्य के लिये डीग जाना सम्भव नहीं है और जाते भी हैं तो उनकी दिहाड़ी मजदूरी मारी जाती है। नवसृजित जिला डीग में अलवर जिले की कुछ तहसीलों को सम्मिलित किया जा सकता है। इन तहसीलों को शामिल करने से सामाजिक संतुलन बन सकेगा।

इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि नवसृजित जिला डीग से कुम्हेर और रारह तहसील को भरतपुर जिले में जोडा जाये जिससे कि सामाजिक, भौगोलिक संतुलन बन सके एवं यहां के निवासियों को पूर्ववर्ती सरकार की आनन-फानन में की गई घोषणाओं से निजात मिल सके।

अतः मेरा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि नवसृजित जिला डीग से कुम्हेर और रारह तहसील को न्यायोचित तरीके से जिला भरतपुर में जोडा जाये, जिससे उक्त तहसील के निवासियों को न्याय मिल सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री धर्मपाल।

बबाई (खेतड़ी) में नवीन पंचायत का गठन

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतडी का क्षेत्रफल लगभग 60 से 70 किलोमीटर में हरियाणा सीमा से लगता हुआ राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र उदपुरवाटी तक विस्तृत ऐरिया है, जिसमें कुल 44 ग्राम पंचायतों में 135 से ज्यादा राजस्व गांव और 350 से ज्यादा ढाणियां हैं। क्षेत्र की कुल

जनसंख्या लगभग 5 लाख से ज्यादा है।

इतना विस्तृत ऐरिया व अधिक जनसंख्या के चलते आमजन को एक पंचायत समिति उपयुक्त नहीं है। एक ही पंचायत समिति होने के कारण काम का दबाव अधिक रहता है, जिसके चलते सरकार की योजनाओं का लाभ व अन्य छोटे-छोटे कार्यों की जानकारी इत्यादि के लिए आमजन को लगभग 30 से 35 किलोमीटर चलकर आना होता है और काफी इंतजार भी करना पड़ता है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि खेतडी विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील बबाई, जिसमें रीको एरिया, हवाई जहाज हेतु मैदान, 400 के.वी. जीएसएस, AEN office, PHED खेतडी ग्रामीण, AVVNL AEN office. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सरस दुग्ध डेयरी, गिरदावर हल्का, पटवार हल्का तथा हर तरफ से परिवहन से जुडाव जैसे सभी मापदंड पूरे करता है।

निवेदन है कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के बबाई में एक नई पंचायत समिति बनाई जाये, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरलाल डेचा।

काकरी डूंगरी प्रकरण खैरवाड़ा में दर्ज प्रकरणों की न्यायिक जांच

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि वर्ष 2020 में वांगड़ में काकरी डूंगरी प्रकरण हुआ, जो की वांगड़ के इतिहास का काला अध्याय बन गया। जिन नेताओं और वक्ताओं ने नादान आदिवासी बच्चों को रीट भर्ती 2018 की रिक्त अनारक्षित 1167 सीटो को आदिवासी बच्चों को दिलवाने हेतु भड़काया, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव यह है कि-

1. वांगड़ में हुए काकरी डूंगरी प्रकरण खेरवाडा में दो बच्चों की मृत्यु हुई और दो प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें से एक सदर थाना डूंगरपुर में मुकदमा संख्या 197 दिनांक 26 सितम्बर, 2020 जिसमें 460 बच्चों पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो दूसरा मुकदमा बिछीवाडा थाना में मुकदमा संख्या 278 दिनांक 26 सितम्बर, 2020 जिसमे 728 बच्चों पर दर्ज हुआ। कुल मिलाकर 1201 निर्दोष बच्चों के खिलाफ कार्यवाही हुई, जबकि जिन कांग्रेस एवं बाप के नेताओं और वक्ताओं ने आदिवासी बच्चों को उकसाया, भाषण दिये, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ की इस प्रकरण की न्यायिक जाँच कर दोषियों को सजा मिले और निर्दोष आदिवासी बच्चों को न्याय मिले। क्योंकि आज इस मुकदमे के पीड़ित हमारे आदिवासी बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं एवं सरकार की विभिन्न भर्तियों में पुलिस करक्टर सर्टिफ़िकेट नहीं मिल रहा है, जिससे वे रोजगार से वंचित हो रहे हैं।

2. काकरी डूंगरी प्रकरण में शिक्षक भर्ती में 1167 अनारक्षित सीटें जो नहीं भरी गई उसका आज दिन तक कुछ नहीं हुआ, जबकी इन सीटों को आगामी भर्ती मे जोड़ कर टी.एस.पी. की सीटें बढ़ानी चाहिये थी।

मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त विषय पर सदन को अवगत कराएं एवं टी.एस.पी. के बच्चों के साथ न्याय करें।

श्री अध्यक्ष: पर्ची। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नसीराबाद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का अव्यवस्थित संचालन

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संचालन में लगातार कमी हो रही है। वर्तमान समय में नसीराबाद मुख्यालय और पीसांगन से एक मात्र बस अजमेर जिला मुख्यालय के लिये चल रही है। इसे भी कभी कटौती में डाल दिया जाता है। इससे आस-पास के ग्रामीण छात्र-छात्राएं, मरीज, कई मजदूरी करने वाले, आने-जाने वाले भी प्रभावित हो रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं।

msk/rtm/23.07.2024/1250/1m

इस समस्या को जल्दी से जल्दी दूर किया जाये। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो बसें संचालित हो रही हैं, वे भी अपने निर्धारित स्थान पर नहीं जाकर हाईवे पर उनको रोक दिया जाता है और हाईवे से ही उनको डाइवर्ट किया जाता है। इस समस्या को दूर किया जाए। जो बसें चल रही हैं और बिना फिटनेस के और बिना किसी कार्यवाही के भी चल रही हैं तो उस पर भी डिपार्टमेंट वाले ध्यान दें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें भी और बसों की भांति पूरे फिटनेस के साथ चलें तो आम जनता को सुरक्षित यात्रा करने में सहयोग मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अजमेर से नसीराबाद के संचालन बढ़ाये जायें। अजमेर-रामसर-बोराड़ा मार्ग पर जो बसें बन्द कर दी गयी हैं, उनको भी दुबारा चालू किया जाये। अजमेर-श्रीनगर-अरई बस भी पुन: चालू हो, जो कि मालपुरा जाती है। अजमेर-हाथी पट्टा, अजमेर-पीसांगन, अजमेर से गोविन्द गढ़ और जयपुर से पीसांगप, इन बसों का पुन: संचालन किया जाये, जिससे आम जनता को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

प्रदेश में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट में एक राष्ट्र, एक कर व्यवस्था की आवश्यकता व परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा कारित धांधलियां

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय परिवहन मंत्री सम्माननीय नीतिन गड़करी जी ने एक सपना संजोया कि वन-नेशन, वन-टैक्स, उसके आधार पर हमारे राजस्थान में भी केन्द्र सरकार द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एआईटीपी (All India Transport Permit) 2021 में जारी किया। जिसका सम्पूर्ण राज्यों ने इसका सम्मान किया और उसके अनुसार उन्होंने टैक्स लागू किया। उसी

टैक्स के अनुसार आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, एमपी में उसी पैटर्न पर टैक्स वसूल किया जा रहा है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की हठधर्मिता के कारण हमारे राजस्थान में वह टैक्स स्लैब लागू नहीं किया। आज हर स्टेट, चाहे अरुणाचल, एमपी देखें, वहां पर 7 हजार पर-मंथ टैक्स है, अरुणाचल का हजार रुपया टैक्स है। यूपी का 7 हजार 200 टैक्स है, लेकिन हमारे राजस्थान में लगभग 39 हजार 758 टैक्स है। आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब यहां डबल इंजन की सरकार है। केन्द्र का सपना है कि वन-नेशन, वन टैक्स, उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां भी वही टैक्स स्लैब लागू किया जाये। उसकी वजह से आज हमको कितनी हानि हो रही है। करीब 3500 बसें हमारी आउट ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड हुई हैं। जिसकी वजह से हमें कितना रेवेन्यु लॉस हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस टैक्स के इंतजार में साढ़े तीन सौ बसें तैयार पड़ी हैं। वीडियो कोच वाले यही इन्तजार कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब अगर उसी पैटर्न पर लागू हो तो वे भी हमारे यहां रजिस्टर्ड होंगी। अगर टैक्स स्लैब लागू नहीं किया गया तो वे साढ़े तीन सौ बसें भी अन्य राज्यों में चली जाएंगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर कोई विचार करें और यह स्लैब किया जाये, धन्यवाद।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): मेरा पाइंट आफ इनफोर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)... मुझे पता है, आपने स्लिप भेज दी हैं। विराजें, मैं नाम पुकार लूंगा। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में डामर सड़कों से वंचित गांव,
मिसिंग लिंक, पैचेबल सड़कों का निर्माण एवं उच्च
स्तरीय पुलियाओं पर हाई लेवल ब्रिज

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यधिक बारिश और अतिवृष्टि से 2021-22 में पूर्ववर्ती सरकार के समय मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी थीं और कई पुलियाओं की आज तक भी मरम्मत नहीं हुई और न नयी बनायी गयी। ऐसी समस्या को देखते हुए मेरे क्षेत्र में आज पुलियाओं और रोड की आवश्यकता है, जो निम्नलिखित हैं।

रोड के मामले में पायड़ा से बरूब, मनोहर थाना से हरणावदा रोड से रीचड़ी, बांसखड़ी मेवातियान से हनोतिया मेवातियान, कंवरपुरा से खजूरी होते मोहम्मद पुरा, गणेशपुरा से कोटड़ा कागला, गेहूंखड़ी रोड से देवली, बेरागढ़ से महवा खेड़ा वाया मोतीपुरा, खोली से नया गांव, लोदीपुरा से टुण्डाखेड़ा और मनोहर थाना से बुधवाड़ा, ये क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, इनमें इतने बड़े गड्ढे हो गये हैं कि उनमें चलना दूभर हो गया है।

जो पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, वे इस प्रकार हैं। इस्लामपुरा से बोरबन्द रोड के मध्य, गुराड़ी चौराहे से बामला मध्य रोड के मध्य, उमरिया से राकड़ा रोड के मध्य, सरड़ा से मानपुरा रोड के मध्य, असनावर से रातादेवी रोड के मध्य, मनोहर थाना से टोटरी जगन्नाथ

के मध्य और मनोहर थाना आदर्श विद्या मन्दिर से महाविद्यालय मनोहर थाना के मध्य, ये पुलियाएं हैं, जिनकी आज तक भी ऊंचाई नहीं की गयी है। इसके कारण छात्र-छात्राओं को और आम जन को काफी असुविधा होती है। कुछ उच्च स्तरीय पुल हैं, जिन्हें बनाना आवश्यक है। केइल कोयड़ा और घाटोली के मध्य, सरड़ा से मानपुरा रोड के मध्य और हरणावदा, मनोहर थाना मार्ग से देवलीजागीर, ये उच्च स्तरीय पुल हैं। इनको बनाने की आवश्यकता है, जिससे आम जन को सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

शिव में किराड़ू के मंदिर, सूर्य मन्दिर, देवका और पौराणिक मंदिरों का संवर्धन व संरक्षण

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शिव में स्थित किराड़ू मन्दिर, सूर्य मन्दिर के साथ ही कई सारे पौराणिक मन्दिर हैं, जिनका अभी तक किसी भी तरीके का कोई संवर्धन और संरक्षण करने की कोई नीति और कोई बजट अभी तक नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि देवका का सूर्य मन्दिर 13वीं शताब्दी में बना था, मारवाड़ में दो ही सूर्य मन्दिर हैं, एक ओसियां में है और दूसरा देवका में है। जिसका पुरातत्व विभाग के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा किसी भी तरीके का कोई संवर्धन नहीं किया गया, जिसकी वजह से वह मन्दिर पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुका है। मेरा निवेदन रहेगा कि इसको पूरी तरीके से मेंटेन किया जाये। सबसे बड़ी चीज कि इतना बड़ा मन्दिर, इतना भव्य मन्दिर, अभी बना हुआ है, पर हाईवे से सौ मीटर दूर है, पर कोई साइन-बोर्ड नहीं लगा हुआ है। चारों तरफ कंटीली झाड़ियां हैं और पूरी तरीके से यह क्षतिग्रस्त हो चुका है। मेरा निवेदन है कि इस मन्दिर का पूरे तरीके से पुनरुद्धार किया जाये।

साथ ही साथ, बाड़मेर का जो किराड़ू मन्दिर है, उसे राजस्थान को खजुराहो कहा जाता है। पांच मन्दिर हैं, पर यहां पर भी किसी भी तरीके की कोई मेंटेनेस अभी तक नहीं की गयी है। पिछले काफी लंबे समय से यह जर्जर अवस्था में है। जो मूर्तियां थीं, जो मुख्य सामान थे, वे पूरे तरीके से ले जा चुके हैं। चोरियां हो चुकी हैं, पर प्रदेश की सरकार की किसी भी तरह की कोई बजट इस पर नहीं लगा। मेरा निवेदन रहेगा कि इन मंदिरों को पूरे तरीके से डवलप करने के लिए आप विशेष पैकेज दें। पश्चिमी राजस्थान के ये जो मन्दिर हैं, देवका और किराड़ू के मन्दिर जो कि हाथमा में हैं, ये बहुत प्राचीन मन्दिर हैं। निवेदन है कि इसकी तरफ देखें। साथ ही साथ, कई सारे मठ हमारे वहां पर हैं। जिसमें ख्याला मठ है, भाडका मठ है, गरीब नाथ जी का मठ है, चंचलनाथ जी का मठ है और कई सारे पुराने मठ हैं। प्रदेश की सरकार से मेरा इनका संवर्धन करने के लिए भी निवेदन रहेगा कि आप इस ओर कोई विशेष पैकेज जारी करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूचना

मोहनगढ़ हैडवर्क्स को बाधित विद्युत सप्लाई

श्री अध्यक्षः डॉ. प्रियंका चौधरी। एक लाइन, पाइंट ऑफ इनफोर्मेशन एक लाइन में होता है।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। बाड़मेर-जैसलमेर को सप्लाई करने वाले मोहनगढ़ हैडवर्क्स का जो फीडर था, दो दिन पहले क्षतिग्रस्त हुआ था, जैसलमेर चांदन फीडर। उसको पोकरण फीडर पर शिफ्ट किया था। चांदन पोकरण फीडर है, उसके टॉवर हैं, वे भी नीचे गिर गये हैं और सप्लाई बाधित है। आने वाले दस दिनों के लिए न बाड़मेर, न जैसलमेर को पानी की सप्लाई होगी। मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी मोहनगढ़ हैडवर्क्स को अस्थायी विद्युत सप्लाई की जाए, ताकि पानी की सप्लाई बाधित नहीं हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री मनोज।

तारानगर में बाएं गांव में हत्या

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तारानगर विधान सभा क्षेत्र में बाएं गांव में एक श्याम लाल मेघवाल की कल सुबह साढ़े पांच बजे पीट-पीटकर 15-20 लोगों ने हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी अभी तक एस.एम.एस. अस्पताल में पड़ी है। उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। वह परिवार अपने आप में बहुत भयभीत है, गांव के लोगों ने उस परिवार के साथ कई बार मारपीट की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम उसकी सुरक्षा, संरक्षण और मुजरिमों को गिरफ्तार करने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रताप सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे, उस समय खड़े हुए थे। बतायें।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्तावों का
सरकार की तरफ से उत्तर का अभाव

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना-सा ही था कि हम जो 295 लगाते हैं, पढ़ते हैं, उसका जवाब सरकार की तरफ से आता है। इस सेशन में अभी तक किसी भी 295 का जवाब किसी भी माननीय सदस्य को नहीं मिला है। सभी माननीय सदस्यों की पीड़ा है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः मैं सरकार से भी आग्रह करुंगा कि व्यवस्था करे, 295 का जवाब आने की जो व्यवस्था है, उस प्रक्रिया को तेज करे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है और आपकी जो व्यवस्था है, सभी 295 के जवाब अतिशीघ्र सभी माननीय सदस्यों को, जिन-जिन ने भी लगाये हैं या जो भविष्य में लगाने वाले हैं, उन सबको विधिवत पूरे विवरण सहित जवाब मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमको कैसे पता चलेगा? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः यह पता सदस्यों को कैसे लग जायेगा, आपका कोई 295 हो तो मुझे बता देना, उत्तर आ जायेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक स्थगन लगाया नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

mdp/rtm/23.07.2024/14:00/2c

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री शंकर सिंह रावत। डॉ. शिखा मील।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चौमूं में भू-माफिया की बढ़ती आपराधिक गतिविधियां

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सदन को नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष: आप ध्यान आकर्षित कीजिए विषय पर। मंत्री जी जवाब देंगे, फिर आप बोलना।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): चौमूं में भू-माफियाओं की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर विचार रखूंगी।

श्री अध्यक्ष: आप कहिए कि ध्यान आकर्षित करती हूं, इतना पर्याप्त है।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): उस पर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के अंतर्गत चार पुलिस थाना क्षेत्र आते हैं, जिनमें पुलिस थाना चौमूं, पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम के अंतर्गत आता है तथा तीन अन्य पुलिस थाना गोविन्दगढ़, कालाडेरा तथा सामोद का क्षेत्र पुलिस जिला, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र के 4 थाना क्षेत्र चौमूं, गोविन्दगढ़, कालाडेरा तथा सामोद में जमीन सम्बन्धी धोखाधड़ी, फर्जी पट्टा तथा फर्जी एग्रीमेंट सम्बन्धी वर्ष 2021 में कुल 58 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 13 प्रकरण में चालान तथा 45 प्रकरण में एफ.आर. नतीजा दिया गया। वर्ष 2022 में कुल 68 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 8 प्रकरण में चालान तथा 60 प्रकरण में एफ.आर. नतीजा दिया गया है। वर्ष 2023 में कुल 69 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 5 प्रकरण में चालान तथा 64 प्रकरण में एफ.आर. नतीजा दिया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र के सभी चार थाना चौमूं, गोविन्दगढ़, कालाडेरा तथा सामोद में जमीनों पर जबरन कब्जा करने वाले भू-माफिया सक्रिय नहीं हैं। इस सम्बन्ध में किसी भू-माफिया के खिलाफ सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उनके खिलाफ नियमानुसार विधि सम्मत

कार्यवाही की जाएगी। डिस्प्यूट्स ज्यादा हैं, लेकिन जबरन कब्जे बिलकुल कम है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र 30 किलोमीटर दूर राजधानी से चौमूं एक क्रिमिनल, पोलिटिकल और ब्यरोक्रेटिक कोल्यूजन का केन्द्र बनता जा रहा है। कारण यह है कि जो जमीनों की कीमतें हैं वह आसमान छू रही है। भू-माफिया के गुंडों द्वारा कालाडेरा, गोविन्दगढ़, मालेरा, जैतपुरा और चारों तरफ गरीबों की अनूसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बेशकीमती जमीनों पर कब्जा हो रहा है। राजनीतिक संरक्षण में सैटलमेंट का दबाव बनाया जाता है, जो डिस्प्यूटेड प्रापर्टी हैं, उन पर। बाहुबल और प्रशासनिक बल पर उन पर अवैध कब्जा किया जाता है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि कालाडेरा थाने में एफ.आई.आर. नंबर 3980 और 106, 2024 पर इसमें सुभाष मीना नाम के एक व्यक्ति पर भू-माफिया के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया और मारपीट कर सड़क पर छोड़ दिया गया। तीस-चालीस दिन अस्पताल में इलाज चलने के बाद में यह व्यक्ति ठीक से चल नहीं पा रहा है। फिर भी जब परिवार पर दबाव नहीं बना तो उसके माता-पिता के साथ फिर से हमला किया गया। उनकी खातेदारी जमीन पर राजनीतिक संरक्षण में पुलिस की मिलीभगत से वहां तारबंदी तोड़ी गयी। विड़म्बना सबसे बड़ी यह है कि जो किंगपिन हैं, जो मुख्य भू-माफिया हैं, उनका राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव में बचाने के लिए इस फाइल को इंवेस्टीगेशन पूरा होने से पहले दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें फेयर जांच हो, एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए और एक अनुरोध है कि एंटी लैंड माफिया सेल का भी गठन किया जावे।

चौमूं में फिलहाल हालत यह है कि अपराधी बेखौफ हैं, कुछ पुलिस कांस्टेबल और प्रशासनिक कर्मचारी लाइजनिंग एजेंट से ज्यादा फिलहाल कुछ भी नहीं है। आम आदमी भयजदा है और राजनीतिक द्वेषता से लोगों पर असत्य मुकदमे दायर किये जा रहे हैं। चूंकि चौमूं के लोगों ने मुझे उनकी आवाज बनने के लिए यहां पर भेजा है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पोलिटिक्स और पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम, इस नेक्सस को तोड़ा जाए और एक सकारात्मक प्रयास किया जाए कि हम इन भू-माफियाओं से चौमूं ग्रामीण और चौमूं शहरी इलाके को छुटकारा दे सकें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्राइम किसी का भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, सरकार की ड्यूटी बनती है कि उसका निपटारा करना और जनता को फेयरली ट्रीट करना। मैं आज ही जो आपके एस.पी. हैं, उनको निर्देश देंगे कि एफ.आई.आर. नंबर 3940, 106 जो सुभाष मीना का जो इश्यू है, उसके अन्दर डिटेल में जांच करके हमें रिपोर्ट दी जाए।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सर, एफ.आई.आर. नंबर 3980 एंड 106 है।

श्री अध्यक्षः आप इनको दे देना।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सर, इसमें राजनीतिक संरक्षण है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो लोग हैं, सारी कार्यवाही को प्रभावित कर रहे हैं। उच्चाधिकारियों के भी संज्ञान में मैंने ये बात ला दी है। धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पूर्ण कार्यवाही की जायेगी और न्याय दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः श्री शंकरसिंह रावत।

ब्यावर में चीता-मेहरात व काठात समाज के मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र पर रोक

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अंतर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा नियम 131 के अंतर्गत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है-

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये। इसके अनुसार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र से तात्पर्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए समय-समय पर जारी किये गये गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचनाओं में शामिल समुदाय वर्ग को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। इसके तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 27/01/2014 द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन को नियमानुसार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जिला स्तर पर सक्षम अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दिये जाते हैं।

तत्समय माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा दिनांक 31/12/2021 के द्वारा जिला कलक्टर अजमेर को श्री जलालुद्दीन संरक्षण काठात महासभा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के सन्दर्भ में यह अवगत कराया गया कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 16/12/2019 में स्पष्ट प्रावधान है कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/01/2014 द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को अधिसूचित समुदाय का व्यक्ति होने के आधार पर दिशा-निर्देशानुसार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। इस सन्दर्भ में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा दिनांक 05/01/2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, मसूदा के द्वारा निजी सचिव,

कार्यालय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात के पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 एवं भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/01/2014 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र 26/01/2022 के द्वारा समाज कल्याण विभाग के परिपत्र दिनांक 08/11/1994 का सन्दर्भ देते हुए उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, मसूदा को यह अवगत कराया गया कि ऐसे गैर हिन्दू व्यावसायिक जातियों को जो अपने पुश्तैनी पैतृक व्यवसाय के नाम से जाने जाते हैं, जिनके हिन्दी प्रतिरूप पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर लिये गये हैं व जिनके हिन्दू व गैर हिन्दू पैतृक व्यवसाय नाम समान है, को भी पिछड़े वर्ग में माना जायेगा। अत: केवल इस आधार पर कि आवेदन अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है, उसको अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार नहीं किया जा सकता। इस तथ्य की पुष्टि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के परिवाद संख्या 23 दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 में दिये गये निर्णय से होती है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गाय है कि यदि कोई आवेदक अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात के पत्र दिनांक 16/12/19 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में बिंदु संख्या सी-4 में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के उपरांत परीक्षण कर निस्तारण करें। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ बोर्ड विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनकी पालना में जिला स्तर पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकार में तत्कालीन मंत्री महोदय सालेह मोहम्मद जी ने यह जो आदेश जारी किया है, सिर्फ एक जलालुद्दीन, एक व्यक्ति के लैटर पैड पर लेकर इसको पूरे समाज को चीता समाज, मेहरात समाज, काठात समाज को पूरे को अल्पसंख्यक घोषित कराने के लिए, क्या एक व्यक्ति करवा सकता है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, नाम नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बोलने दीजिए।

Ans/rtm 14.10 2d 23.07.2024

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): ओबीसी में भी शामिल है। आज कि ओबीसी में उकसा रिकार्ड है। राशन कार्ड, जमाबंदी का रिकार्ड, रेवेन्यू रिकार्ड में आज भी हिन्दु सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज रावत है। उसमें अल्पसंख्यक के लिए इनको कैसे घोषित किया गया। हमने पूर्व की सरकार में भी इसका विरोध किया था। तत्कालीन आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता, गुलाब जी कटारिया साहब थे, उन्होंने पूरा पक्ष रखकर किया कि शाले मोहम्मद जी बहुत गलत आदेश जारी कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, एक व्यक्ति अगर मुसलमान बनना चाहे, किसी

भी धर्म को अपनाना चाहे तो वह अपना सकता है। लेकिन पूरे समाज को अल्पसंख्यक घोषित कर दें, तो यह सीधा-सीधा धर्मान्तरण का मेटर है। आपका संरक्षण चाहिए। पिछली सरकार के टाइम ऐसे गलत आदेश के फरमान जारी हुए हैं, उसको निरस्त कराने की कार्यवाही करे। पूरे समाज को अल्पसंख्यक में घोषित नहीं कर सकते, यह मेरी प्रार्थना है। माननीय मंत्री महोदय से आदेश निरस्त कराए।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पूरे समाज का नहीं व्यक्ति का है। पर फिर भी जो बात आई, ज्ञात हुआ, आपके द्वारा जो विषय उठाया गया इसमें यह तथ्य भी आया कि 2013 से 2015 तक इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता था। फिर 2015 से 2021 बंद कर दिए गए। 2022 से पुनः प्रारम्भ किया गया। विषय जरूर यह है कि ऐसा क्या कारण रहा कि बीच में दिए गए फिर बंद किए, फिर वापिस शुरू किए गए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह विषय आपके संज्ञान में लाना चाह रहा था। आपने बात की, राज्य अल्पसंख्यक द्वारा आदेशित किया गया कि अल्पसंख्यक धर्म नहीं होने पर शपथ पत्र दिए जाने पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष जी, एक मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्षः हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः उनका तो पूरा हो जाए। बोलो।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): मेरी यह प्रार्थना है कि वह अल्पसंख्यक में पहले कभी नहीं मिले थे, 2019 के पहले यथावत ओबीसी में ही थे और हिन्दू नाम से ही थे। उनके बेटे, पोते, परिवार में सब हिन्दू नाम से थे। 2019 के बाद ही ऐसा फरमान जारी हुआ है।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी के संज्ञान में आ गया।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उस आदेश को निरस्त करवाने की कृपा करें। मंत्री महोदय, आप घोषणा करे कि आप निरस्त करेंगे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इसका विधि अनुसार परीक्षण कराकर, इस पर अग्रिम कार्यवाही कराएंगे।

अनुरोध एवं मांग

राज्य सरकार के मंत्री, शराब माफिया व आबकारी अधिकारियों की कथित वायरल रिकार्डिंग के बारे में सरकार का स्पष्टीकरण

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर इंगित करना चाहूंगा। आज पूरे मीडिया में, सब जगह माननीय गृह राज्य मंत्री जी के और शराब माफियाओं के, आबकारी अधिकारियों के बीच की एक रिकार्डिंग वायरल हो रही है। मुख्य मंत्री जी के गृह ज़िले से जुड़ा हुआ यह विषय है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर उत्तर दे और बताए कि जब माफिया, आबकारी अधिकारी, शराब माफिया और गृह मंत्री, तीनों ही मिल बैठ कर बात को सलटाने की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश किस ओर

जा रहा है? मैं इस ओर आसन का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। कुछ कहेंगे?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने कोई विषय रखा है। सरकार की ओर से मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो भी अपराधी है उसकी ना कोई जाति है, ना धर्म है वह अपराधी अपराधी ही है। चाहे वह किसी भी पार्टी को बिलोंग करे, उसको नहीं बख्शा जाएगा। शराब माफिया हो, भू माफिया हो, बजरी माफिया हो, कोई माफिया हो, अगर वह आपराधिक प्रवृति का है, अपराध करता है, तो नियमानुसार उसको सज़ा मिलेगी। हमारे मंत्री परिषद का कोई सदस्य ना किसी में इन्वाल्व था, ना इन्वाल्व रहेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठो। बता दिया इन्होंने। आपके नेता पर विश्वास नहीं है। आपके नेता ने विषय रख दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हम तो इतना ही चाह रहे हैं, जनरल आंसर नहीं चाहिए, इस विषय पर सरकार अपना रूख स्पष्ट कर दे, क्या मामला है।

श्री अध्यक्ष: रूख बता दिया। आगे चलिए, सदन की...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक सेकण्ड। इसकी जो भी होगी हम जानकारी प्राप्त करके, विधि सम्मत जो भी होगा, आपको बता दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री गोतम कुमार।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54 (14) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

दि राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का ऑडिट प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

(1) दि राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का ऑडिट प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23);

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2022-23)

(2) राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष (2022-23);

दि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2022-23)

(3) दि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2022-23);

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर के ऑडिटेड, अंतिम लेखे एवं

वैधानिक अंकेक्षण रिपोर्ट (वर्ष 2022-23)

(4) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर के ऑडिटेड, अंतिम लेखे एवं वैधानिक अंकेक्षण रिपोर्ट (वर्ष 2022-23);

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर की अंकेक्षण रिपोर्ट, वार्षिक लेखे एवं ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट (वर्ष 2022-23)

(5) राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर की अंकेक्षण रिपोर्ट, वार्षिक लेखे एवं ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट (वर्ष 2022-23);

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2022-23)

(6) राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2022-23);

राजस्थान राज्य सहकारी संघ, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2021-22) व (वर्ष 2022-23)

(7) राजस्थान राज्य सहकारी संघ, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2021-22 व 2022-23);

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2022-23)

(8) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2022-23); एवं

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2022-23)

(9) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2022-23)

श्री अध्यक्ष: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

(1) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23); एवं

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

(2) राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2010 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री अध्यक्ष: परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25

अनुदान की मांगों पर मतदान एवं विचार। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26- युवा मामले एवं खेल की प्रस्तुति

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26 युवा मामले एवं खेल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,67,04,9000 (दो अरब सडसठ करोड़ चार लाख नौ हजार)हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 26 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्ष: दूसरी भी रखनी है, 56 वाली।

मांग संख्या 56- उद्योग की प्रस्तुति

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-56 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,63,94,27,000 (छह अरब तिरसठ करोड़ चौरानवे लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 56 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्ष: डॉ. मंजू बाघमार।

मांग संख्या 32- महिला एवं बाल विकास की प्रस्तुति

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-32- महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,12,10,34,000 (बत्तीस अरब बारह करोड़ दस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 32 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री जसवंत सिंह यादव।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग संख्या 26, 32 एवं 56 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड। आज जो सबसे सहमति हुई है कि नौ बजे तक तो बहस होगी, उसके बाद दोनों मंत्री महोदय अपना जवाब देंगे। इसलिए कोशिश करे, जितना निर्धारित समय है, उसी में अपन अपनी बात रखे। माननीय निर्दलीय और अन्य दलों से भी अपेक्षा है कि रोजाना अपना नाम देने से कोई लाभ नहीं है। एक सदस्य दो बार, अपन आठ लोग हैं, रोजाना अपन दस-दस मिनट मांगेगे संभव नहीं है। 22 में से अपन जितने हैं, तो रोजाना दो सदस्यों को हम अनुमति दे पाएंगे, रोटेशन में। इतना अपने को ध्यान रहे। श्री जसवंत यादव।

मांग संख्या 26- युवा मामले एवं खेल, मांग संख्या 32- महिला एवं बाल विकास

व मांग संख्या 56- उद्योग पर विचार

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष जी, डॉ. अम्बेडकर जी के शब्द थे कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का अगर विकास हो सकता है, उन्नति हो सकती है या सामाजिक उत्थान हो सकता है तो उसकी सबसे बड़ी पूंजी है औद्योगिकीकरण। औद्योगिक विकास बढ़ने से हम रोजगार भी दे सकते हैं। गरीबी भी कम कर सकते हैं और जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं।

VPS-RTM-23.07.2024-14.20-2e

मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकरजी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जो डॉक्टर भीमरावजी की इच्छा थी, उसको पूरा करने के लिए, हमारे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो सोच थी कि उद्योग बढ़ेंगे तो ही राजस्थान आगे बढ़ेगा तो ही रोजगार मिलेंगे।

(समय: 14.20 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

अब चाइना जैसा देश जो छोटे-छोटे उद्योगों के कारण ही सब जगह पर छाया हुआ है तो निश्चित रूप से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, जिस पर मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान दिया है तो हम शायद, हमारा राजस्थान हिंदुस्तान ही नहीं और भी देशों से आगे निकल सकता है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने Ease of Doing Business और Sustainability के आधार पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2024 जो लाने की घोषणा की है, उसके माध्यम से Theme based Industrial Parks बनेंगे और Hassle Free Goods Transportation उपलब्ध होगा। रिसर्च एंड डवलपमेंट होंगे कि किस तरह का क्या होना चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लायी जायेगी। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस प्रदेश से अगर कोई माल, कोई कुटीर उद्योग लगाये, कोई कैसा भी लगाये अगर वह एक्सपोर्ट होता है तो उससे ज्यादा प्रदेश के लिए और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि आज भीलवाड़ा अपने आप में छाया हुआ है, उसको और बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी जोर दिया है कि उसको और आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से Logistic Eco-system तथा Supply Chain System को resilient बनाने के लिए Rajasthan Warehousing and Logistics Policy बनाना, ये सब चीजें अपने आप में एक अनूठा कदम है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार थी, कोई किसी की खिलाफत करना ही बड़प्पन नहीं है पर गहलोत सरकार के अन्दर मुझे भी लम्बा समय हो गया, मैंने देश के बजट में भी हिस्सा लिया, डिमांड्स में हिस्सा लिया, राजस्थान में भी बहुत बार हिस्सा लिया

है। मेरे यहां पर जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, शायद राजस्थान में उससे बड़ा कहीं पर नहीं होगा। मेरे यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी है, खुशखेड़ा है, बहरोड़ है, नीमराना है, वहां पर नया एरिया और डवलप हुआ है पर गहलोतजी सरकार ने पिछली बार एक बहुत बड़ी जोर-शोर से, इसमें काफी शोर भी मचा कि हमने इंवेस्टर बुलाये हैं, इंवेस्टर मीट कर रहे हैं। पता नहीं राजस्थान का कितना पैसा उसमें खर्च हुआ होगा? खूब उनकी आवभगत भी हुई। शायद चार हजार करोड़ रुपये के, मुझे करेक्ट फिगर याद नहीं है, एम.ओ.यू. भी हुए पर धरातल पर एक रुपया भी नहीं लगा और मेरे यहां पर तो एक भी ऐसा ग्रुप नहीं आया जो इनके उस इंवेस्टर मीट से कोई फायदा हुआ हो कि जिसमें इंवेस्टर यह कहे कि साहब, हमने आकर यहां इंवेस्ट किया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि कोई भी सरकार अगर वह यह दिमाग में जमा देती है कि हमारे यहां पर आप सुरक्षित है, हमारा वातावरण अच्छा है, हम आपको चारों तरफ से इसके अन्दर मदद करेंगे क्योंकि उद्योगपति, देसी भाषा में बनिया तो वहीं पर आयेगा जहां पर दो पैसे मिलेंगे और वह सुरक्षित रहेगा तो एक तो इनकी सरकार की ही सुरक्षा नहीं थी कि पता नहीं कब क्या हो जाये? दूसरा, इन्होंने कोई वातावरण ही तैयार नहीं किया। खाली ढिंढोरा पीट दिया कि हमने इंवेस्टर मीट कर ली लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? एकदम जीरो। वे यहां पर आराम से अपनी पिकनिक मना गये, उन्होंने यह देख लिया कि सरकार का कोई रंग-ढंग तो है नहीं, सरकार का कोई अता-पता नहीं है और ज्यादातर उन्हीं उद्योगपतियों को गुजरात ले गया, मध्यप्रदेश ले गया। उनको तो इंवेस्टमेंट करना था, उद्योग तो लगाने थे पर केवल इसलिए उन्होंने गुजरात को अपने आप में सुरक्षित माना, मध्यप्रदेश को सुरक्षित माना और राजस्थान को सुरक्षित नहीं माना। ज्यादातर इंडस्ट्री उजड़ गयी। तो आपसे मेरा तो यही आग्रह है कि माननीय भजन लालजी ने, मैं तो ताज्जुब करता हूं, जितना मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद दे सकते हो, उतना देना चाहिए, निश्चित रूप से यह भी तय है कि माननीय मुख्य मंत्री भजन लालजी ने, हमारे उद्योग मंत्रीजी ने, इन्होंने यह कहा है कि हम इंवेस्टर मीट करेंगे लेकिन जो ये इंवेस्टर मीट करेंगे तो यह तय है कि यहां पर इंवेस्टर आएंगे और अपना इंवेस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें यह यकीन है कि यह सरकार स्टेबल है।

श्री अशोक (हिण्डोली): पिछली बार अनस्टेबल किसने की थी? ...(व्यवधान)...

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): Pardon, हमारी अनस्टेबल नहीं है, आपकी अनस्टेबल थी क्योंकि भानुमति का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा आपका था तो इसलिए आपके कई मुख्य मंत्री बन गये। पिछली गहलोत सरकार ने, पिछली सरकार ने ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य। देखिये, माननीय सदस्य, आप टोकेंगे तो फिर वे भी टोकेंगे इसलिए यह परिपाटी मत बनायें। ...(व्यवधान)...

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अब क्या कारण है कि जब बी.जे.पी. की सरकार आयी तो यहां पर बड़े-बड़े उद्योग आये? ये माननीय विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं अगर ये

ईमानदारी से बात करें तो ये उसी एरिये से है जिस एरिये से मैं हूं तो जितने भी बड़े-बड़े उद्योग समूह आये, जितना भी उद्योग फला-फूला वह बी.जे.पी. की सरकार में ही फला-फूला क्योंकि उद्योगपतियों को यह विश्वास है कि यहां हम सुरक्षित रहेंगे, लूट-खसोट होगी नहीं और निश्चित रूप से जब हम कोई चीज की मांग करेंगे तो तुरंत हमारा वह काम पूरा होगा क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए।

पहले राजस्थान के बारे में यह कहा जाता था, पिछली सरकार के बारे में मैंने भी यह सुना है, मुझे यह बात कहनी नहीं चाहिए, पहले यह बात होती थी कि राजस्थान में जाओ, किसी अधिकारी से बात करो तो वह यह कहेगा कि एक महीने बाद आना। मंत्री से बात करो तो वे कहेंगे कि दो महीने बाद आना और काम करने की रुचि की बजाए उनको हैरेसमेंट करते थे, तो उसका परिणाम यह हुआ।

अब कौन ऐसा मुख्य मंत्री है, मैंने तो देखे नहीं, इतने इंडस्ट्रियल एरिये देखे हैं, मेरे तो चारों तरफ है कि कभी किसी मुख्य मंत्री ने, मैं यह ताज्जुब कर रहा था कि यह 150 करोड़ रुपये जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखे हैं, किसी ने आज तक तो नहीं रखे कि हर इंडस्ट्रियल एरिया में भी यह सुविधाएं होनी चाहिए, यह किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह भजन लालजी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री भजन लालजी ने जो कहते हैं न कि धरातल से ये मुख्य मंत्री आये हैं, जनता के बीच से आये हैं, ग्रासरूट मुख्य मंत्री हैं तो उन्होंने एक-एक चीज को जाना है, एक-एक चीज को देखा है, ऐसा मुख्य मंत्री सौभाग्य से राजस्थान को मिला है जिसकी हर एक-एक चीज के ऊपर अपनी सोच है और वह भी अलग हटकर है।

अब आपसे मैं तो यही कहूंगा कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं कि पचपदरा के अन्दर जो आपने किया राजस्थान पेट्रो जोन, यह पहले भी हो सकता था, पर अभी क्यों हुआ? पहले भी रिफाइनरी तो लग रही थी पर उसको एग्जिक्यूट नहीं किया और जो घोषणा की है, ये पहले मुख्य मंत्री हैं, घोषणाएं तो गहलोतजी के समय में भी बहुत हुईं और इतनी हुईं कि जिसकी कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सब अचंभा करते थे पर वे घोषणाएं हुई बिना सोचे समझे, इलेक्शन आ रहे हैं, बजट आपके पास है ही नहीं और घोषणाएं आप कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसा बुरा हाल हो गया, यह तो अब माननीय उद्योग मंत्रीजी, आपको बहुत कमर कसनी पड़ेगी, इन्होंने तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया को ही बर्बाद कर दिया है। न तो वहां पर जा सकते, न आ सकते। वहां पर गंदगियों का अम्बार है, असुरक्षा है, जिस पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया।

SSY/RTM/23.07.2024/14:30/2f

अब आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे काम किये हैं, कहां आज तक कोई ध्यान देता है कि अलग-अलग क्षेत्र में, जिस-जिस जिले के अन्दर, जिन-जिन चीजों की बहुतायत है उधर ही ध्यान दे देना। यह मील का पत्थर साबित होगा। यह मुख्य मंत्री जी की सोच इस राजस्थान को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। एक्सपोर्ट

बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट जितना बढ़ायेंगे उतना हमारे पास डालर आयेगा। उतनी ही हमें खुशहाली मिलेगी।

सभापति महोदय, आपसे मेरा तो यही निवेदन है कि राजस्थान अब माननीय मुख्य मंत्री के हाथ में है, यहां का उद्योग सुरक्षित है, आगे भी बढ़ेगा। जब उद्योग लगेंगे तो ही नौजवानों को नौकरी मिलेगी। तभी रेवेन्यू सरकार के पास आयेगा। उद्योग क्यों जरूरी हैं? उद्योग की जरूरत इसलिए है कि उद्योग से जो हमें रेवेन्यू मिलती है, वह बहुत बड़ी मिलती है। उसी से सरकारें चलती हैं। उन्हीं से विकास होता है।

आज हमारे यहां जापानी जोन है। आपके टाइम में कई बार आपके ही विधायकों के द्वारा उस पर अटैक हुए हैं। हमारे कार्यकाल में तो मैं भी मंत्री था, हमने तो कभी जाकर के नहीं देखा था। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या कायदे-कानून हैं। अब मैं उद्योग मंत्री से इसके बारे में कहूंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एनजीटी के द्वारा लग रहे उद्योगों को परमिशन नहीं मिल रही है। हाई वे पर जो हैं। आपके तो डबल, ट्रिपल इंजन हो गये, रोक तो हट जानी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आदरणीय जो आप एनजीटी की बात कर रहे हैं, एनजीटी वहीं पर दखलंदाजी करती है या उसी को रोकती है जहां पोल्युशन की दिक्कत होती है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एनसीआर की कहना चाह रहे हैं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एनसीआर के अन्दर अब भी लग रहे हैं। लेकिन जिनके अन्दर पोल्यूशन होगा तो जनता के हित में उस बात को रखा जायेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उद्योग लगे ही नहीं तो पोल्यूशन काहे का।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कोई आपसी बहस थोड़े ही हो रही है। आपको कोई बात करनी हो तो आप माननीय मंत्री जी से कह देना आपका जब आये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एनजीटी की रोक घिलोठ में है क्या? माननीय प्रति पक्ष के नेता जिस एरिये से आते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डवलप हो रहा है वहां एनजीटी की रोक है क्या?

श्री सभापति: ऐसे बीच में अपन बैठे-बैठे टोकेंगे तो ना आप बोल पायेंगे, ना यह बोल पायेंगे।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): पिछली सरकार थी, एनजीटी तब भी थी, लेकिन पिछली सरकार ने उन्हीं उद्योगों को बढ़ावा दिया जहां पर एनजीटी नहीं रोक सकती थी। आपसे मेरा निवेदन है कि आप जिनके अन्दर एनजीटी की बात कर रहे हो, वह आपके क्रेशर आते हैं, जो आपके यहां ज्यादातर अवैध चल रहे हैं इसलिए आपको एनजीटी याद आ रही है। क्योंकि जितना रामगढ़ के अन्दर पोल्युशन होता है उतना शायद देश में कहीं भी नहीं होता। वैसे वह वहां लागू होगा, हमारे यहां एनजीटी की कोई रोक नहीं है।

इस तरह के पिछली सरकार का तो मुझे पता नहीं, आप लोग ज्यादा जानो कि किनको परमिशन देते थे, नहीं देते थे। क्योंकि आपके यहां सबसे बड़ा हावी रहा, दिक्कत क्या है कि माननीय गहलोत सरकार के अन्दर भ्रष्टाचार और घोषणाएं हावी रहीं। अब उस चीज को आप देखना नहीं चाहते। रियल्टी कहो तो कितनी बार कहो? उसको सुनना नहीं चाहते।

अब माननीय भजन लाल जी ने भीलवाड़ा में वस्त्र, इसी तरह से बीकानेर के अन्दर सिरेमिक, बांदीकुई के अन्दर आपने इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब, सोलर पैनल पाली के अन्दर, कैमिकल मेनुफैक्चरिंग पार्क किशनगढ़ में, टाइल्स मेनुफैक्चरिंग किशनगढ़, अजमेर में, उन्होंने जो इंडस्ट्रियल एरिये भी घोषित किये तो वहां किये हैं जो इंटीरियर में हैं। यह भजन लाल जी की सोच है क्योंकि वह धरातल से गुजरे हुए हैं। आज नीमराणा में किसी इंडस्ट्रियल एरिये की घोषणा कर दो, वहां से सेचुरेटेड हो गया। उन्होंने वहां किये हैं जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जैसे कठुमर में खोला, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। इसी तरह और जगह जहां भी हुए और हमारे, नाम तो मैं लूंगा नहीं पर उद्योग मंत्री पहले बानसूर की ही थी, उन्होंने घोषणा कर दी, उस इंडस्ट्रियल एरिये का अता-पता ही नहीं है। घोषणाओं से नहीं होता है। आपने बजट नहीं रखा। आपने प्लान नहीं बनाया।

अभी आप जो कहते हो, अब मैं सुबह घूमता हूं तो हम साथ मिलकर ही घूमते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के भी होते हैं। अपने भी होते हैं। वह कहते हैं कि कमाल कर दिया। यह वहां नहीं रहते हैं। वह कहते हैं कि भजन लाल जी ने इतना जबरदस्त बजट घोषित किया है।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): बजट पर नहीं हो रही है चर्चा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं बजट की बता रहा हूं। मुझे पता है डिमांड्स पर हो रही है। पर डिमांड के लायक कुछ बचा ही नहीं। एक बचा है वह स्लेट उद्योग, वह भी बोल लेते, हमारे एक हैं जो अपने आप में जिले में अलग हैं। आदरणीय, बात तो कहनी पड़ेगी। जिस मुख्य मंत्री ने इसके अन्दर बजट रखा है, उसको पूरा करने जा रहे हैं, इससे राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान उन्नति पर जायेगा। देश-विदेशों में राजस्थान का नाम होगा।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): आपने कितने रोजगार दिलाये नीमराणा में?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरे कार्यकाल में?

श्री ललित यादव (मुण्डावर): हां।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): शायद राजस्थान में ऐसी कोई तहसील नहीं होगी जो मेरे कार्यकाल के अन्दर, जहां रोजगार मेला नहीं लगा हो, पर वह आपकी समझ में नहीं आ रहा। वह आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप रोजगार का अर्थ क्या मानते हो?

श्री ललित यादव (मुण्डावर): एक को भी रोजगार नहीं मिला।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपके मुण्डावर में भी रोजगार मेले 3 बार लगे। बहरोड में भी लगे। अब जो हमारे लोग चाहते हैं कुछ चीजें कानून से बंधी हुई हैं। कोई 25 हजार रुपये तो देगा नहीं। या तो आप उसके कैपेबल बनो। इतनी क्वालिफिकेशन लो। आपकी

सरकार पिछले बार थी, उनके कार्यकाल में भी जो वेजेज तय था, वही हमारे कार्यकाल में था। अब उसमें कोई करना चाहे, नहीं करना चाहे, वह आप कोई बात नहीं कर सकते।

आप उद्योगपतियों को यह तो कह सकते हो कि आप आइये, हमारे यहां के बच्चों को रोजगार दीजिये। पर उद्योगपतियों को यह बात नहीं कर सकते कि कानून से हटकर आप इनको वेजेज दे दो। मैं आपकी बात को ही, माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, देखो, उद्योग लगाना सबसे अच्छी चीज है। उद्योग के बिना कोई काम हो नहीं सकता, उन्नति हो नहीं सकती।

लेकिन मैंने इंडस्ट्रियल एरिये उजड़ते हुए भी देखे हैं। नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया उजड़ा। हरियाणा में धारूहेड़ा का उजड़ा। हमारे यहां का अलवर उजड़ा। उसका कारण क्या है कि उद्योगपतियों को हम सारी सुविधाएं देते हैं, उनको बिजली में भी छूट देते हैं, उनको जमीन में भी छूट देते हैं, उनको लोन भी देते हैं। उनको घर बैठे सारी सुविधा देते हैं।

उद्योग लगाना एक बहुत बड़ी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ-साथ जो लोग वहां लोकल रहते हैं, अगर हम सबको मिलकर, यह आपस के अन्दर किसी को क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा, अगर इन उद्योगों को सही चलाना है तो आपको पता है, यह जो अपने आदिवासी इलाकों में नई-नई पार्टियां आ रही हैं, उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण यह हुआ कि वहां आपने बड़े-बड़े सेठों को माइंस तो दे दी, लेकिन उन सेठों ने वहां जो लोकल लोग रह रहे थे, उनका इनवाल्वमेंट नहीं किया, उनको रोजगार नहीं दिया तो रिवोल्ट उठा कि हमारे पहाड़, हमारी खान, माल ले जा रहे हैं यह और हमको क्या मिल रहा है, धूल।

इसी तरह से उद्योग जरूरी हैं। उद्योगों को बचाने के लिए आपको मेरा निवेदन है कि जो वहां का नौजवान है, मेरे यहां का नौजवान है, आपको इन्हें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, इनका इनवाल्वमेंट करना पड़ेगा। दिक्कत क्या आती है कि जो उद्योगपति आते हैं, उनको सब कुछ देने के बाद वह जो लोकल नौजवान हैं, उनसे अपने आपको असुरक्षित मानते हैं। वह चाहते हैं कि जो यूपी का आयेगा, बिहार का आयेगा, बंगाल का आयेगा, कहीं का भी आयेगा, वह यहां दबकर रहेगा। जबकि टेलेंट में हमारे बच्चे ज्यादा हैं, अच्छे हैं। तो मैं उद्योग मंत्री से कहता हूं कि आप इसके अन्दर क्या कर पायेंगे? मुख्य मंत्री भजन लाल जी से भी निवेदन करता हूं कि आपने हर क्षेत्र में, हर दिशा में रास्ते निकाले हैं। लेकिन इन उद्योगों को बचाने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, यह भी बचें, हमारे गांव भी बचें, हमारे गांव के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार भी मिले और हमारे नौजवानों को, मेरी मांग तो यह है कि कम से कम नौजवान, अब आपका हर क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं।

Spp/Rtm/23.07.2024/14.40/2g

उनमें टेलेंट है तो कम से कम 70 प्रतिशत बच्चों को, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिये। नहीं मिलेगी तो एक दिन ऐसा आयेगा कि पता नहीं उद्योगपति तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे पर रिवोल्ट हो जायेगा, सारा माहौल खराब हो जायेगा। पूरे राजस्थान की अपनी मेहनत

खराब हो जायेगी। आपसे निवेदन है अगर कानून बना सकते हो तो अपने लोकल बच्चों को नौकरी देने के लिये आप मजबूत कानून बनाइये और कानून बनाने में पॉलिसी में कोई दिक्कत आती है तो उद्योग मंत्रीजी स्वयं जाये। माननीय मुख्य मंत्रीजी उनसे काउंसलिंग करें कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, हम हर तरह की गारंटी दे रहे हैं। अब यूनियन कोई बनाता नहीं है हम गांरटी ले रहे हैं तो आप इनको काउंसलिंग करके कैसे न कैसे उनको भागीदारी दिलवाओ और अधिक से अधिक लोकल नौजवान बच्चों को नौकरी दो, क्योंकि नौकरी नहीं देने से आज तो फर्क नहीं पड़ेगा पर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे पूर्ववर्ती क्षेत्रों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं ऐसे ही हमारे इलाकों में भी यह हालात खड़े हो सकते हैं। गांव के अन्दर ट्रक है, उसको काम न देकर बाहर का कोई आदमी आया, वह सस्ते में भर लेगा, दे दिया उसको। सामान वहां पर मिल रहा है। गांव के चारों तरफ देखते हैं, जापानी कम्पनियों में हमारे यहां सरकार चाहती थी कि जापानी कम्पनियां स्थापित रहें। पर उनके अन्दर कभी लाइट नहीं जाती थी, उनके अन्दर कभी सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं आती थी, वह अपनी मर्जी से चलते हैं। सरकार का बहुत ज्यादा अंकुश नहीं है जिससे विदेशी लोग हमारे यहां आयें, इन्वेस्टमेंट करें। पर उनसे किसी तरह काउंसलिंग करके जो लोकल बच्चे हैं, उनके लिये आप अधिक जोर दो जिससे हम सब सुरक्षित रहें और हमारा वातावरण भी ठीक रहे और हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलता रहे।

मेरा तो आपसे निवेदन है कि जब मुख्य मंत्रीजी ने जहां घोषणाएं की हैं एक्सपोर्ट हब बनाने के लिये, यह सब डवलप होंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी' के तहत जो कार्य आप कर रहे हैं इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक्सपोर्ट सेंटर होंगे। वहां पर जो मैन्युफैक्चरर है, जो वहां के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट मिलेगा। मार्केट मिलेगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे और रोजगार मिलेगा।

आप जो सबसे बड़ा काम कर रहे हो माइक्रो लेवल पर, MSME पॉलिसी 2024, जो आप ला रहे हो, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, अपने आप में यह मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिये कलस्टर बनाये..(व्यवधान)... क्या कह रहे हो? ...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप तो इधर देखिये। ..(व्यवधान).. आप तो बोलें।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपने जब बजट ही नहीं रखा, बढ़ावा ही नहीं दिया। पहला मुख्य मंत्री है जिसने जो घोषणा की है, उस पर बजट रखा है। आपके यहां तो जिले घोषित कर दिये, बजट घोषित ही नहीं किया। कोई भी घोषणा की है, उसके अन्दर घोषणा कर दी, पर उसका बजट रखा ही नहीं। पहले मुख्य मंत्रीजी हैं, जिन्होंने जो भी घोषणा की है, उसके लिये बजट का प्रावधान रखा है। बजट प्रावधान रखना ही उसको सार्थक करता है। राजस्थान के लोगों को यकीन हो चुका है, इन्वेस्टर्स को भी यकीन हो चुका है कि भजन लाल जी के हाथों के अन्दर राजस्थान सुरक्षित है और आप देख लेना जो पांच साल में आपके यहां इन्वेस्टर नहीं आया, वह इस बार की इन्वेस्टर्स समिट के अन्दर यहां राजस्थान

के उद्योगपति आयेंगे और उद्योग लगायेंगे। ..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप बिराजिये। ..(व्यवधान).. जब आपका नम्बर आये तब बोलना आप। ..(व्यवधान)..

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अब एंटरप्रिन्योरशिप के लिये जो लोग अपने माल के प्रचार-प्रसार करने के लिये जायेंगे, बजट रखा है 30 करोड़ का, मदद करेंगे। मदद करेंगे तो निश्चित रूप से बाहर विदेशों में उनका प्रोडक्ट बिकेगा तो हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। MSME के तहत 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखना, हर जगह बजट रखा है, थोथी घोषणाएं नहीं की हैं। आपके कार्यकाल में, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं, यहां पर आप सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, मेरे विपक्ष के लोग यह बता दें कि आपके कार्यकाल में, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से पूछना चाहता हूं कि अलवर जिले के अन्दर, यह मिनिस्टर भी रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है घीलोठ, नीमराणा, यह सब इन्हीं के इलाके में आता है, एक भी इन्वेस्टर नहीं आया। एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा। ..(व्यवधान).. हां बताओ ना।

श्री सभापतिः नहीं, आपका नम्बर आयेगा अभी, तब बोलना। अभी आप बोलेंगे तब बोलना आप। अभी आप बोलेंगे न। इस पर सवाल-जवाब नहीं। जब आपकी बारी आये तब कहना।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप दे दो। इसी तरह मांग संख्या 26-युवा मामले एवं खेल, हमारे खेल क्षेत्र से आये हुए, मुख्य मंत्रीजी की मैं फिर तारीफ करूंगा, क्यों तारीफ करूंगा कि उन्होंने हर क्षेत्र में ध्यान दिया है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, कंक्लूड करिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हमारे युवा मामले एवं खेल के मंत्री बनाये हैं, यह भी खेल से ही आये हैं। इन्होंने भी देश का नाम रोशन किया है, इन्होंने भी गोल्ड मैडल लिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब धरातल से आये तो उन्होंने एक-एक चीज सोच-समझकर की है और जो खेलों में आपके टाइम में हालत थी न, अब आप देखना पांच साल में अपने आप ही राजस्थान आगे बढ़ जायेगा। जिस तरह चाइना हर मैडल लेकर जाता था, इसी तरह राजस्थान अब हर जगह मैडल लायेगा। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः बैठिये, माननीय सदस्य।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इन्होंने सत्यानाश कर दिया। एक बात आप देखिये, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं ।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, अभी तो बोलना शुरू किया है। ओपनर हूं।

श्री सभापतिः आपको 30 मिनट हो गये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अभी तो मैं असली सब्जैक्ट पर आया ही नहीं हूं।

श्री सभापतिः आपको 30 मिनट हो चुके हैं। क्या है कि आप पैसेंजर में चलते हो, आप

राजधानी में चलो।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय मुख्य मंत्रीजी की नौजवानों को, हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि हमारे देश का नौजवान बहादुर हो, स्पष्टवादी हो, साहसी हो, आकांक्षी हो और साफ दिल वाला हो। इनसे ही प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। स्वामी विवेकानन्द जी नौजवानों के आइकॉन है। इसी तर्ज पर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने नौजवानों के लिये काम करने के लिये जो कोशिश की है, जो वह चाहते हैं, घोषणा की 70 हजार बच्चों को नौकरी देंगे, 6 महीने में 20 हजार को देदी। दी तो इन्होंने।

श्री सभापतिः अब आप बिराजें। श्री अशोक चांदना।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर मुझे पूरा तो बोलना दो।

श्री सभापतिः आपका पूरा हो गया।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं-नहीं, आपने कितनी देर बुलवाया है?

श्री सभापतिः 30 मिनट हो गये।

श्री अशोक (हिण्डोली): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे अनुदान मांग संख्या 26-युवा मामले एवं खेल, मांग संख्या 32-महिला एव बाल विकास, मांग संख्या 56- उद्योग के लिये बोलने का मौका दिया, मेरी पार्टी ने मुझे समय दिया, नेता प्रतिपक्ष जी का बहुत धन्यवाद एवं आपका भी बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मुझसे पूर्व में बहरोड़ से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने एक बात तो उन्होंने स्वीकार की। मेरे बात शुरू करने से पहले कहीं मैं भूल जाऊं उस बात को, कि इनकी पार्टी के पहले ही मुख्य मंत्री बने हैं जिन्होंने सभी घोषणाओं के लिये बजट रखा है। पूर्व के मुख्य मंत्रीजी शायद बजट नहीं रखते थे, ऐसा इन्होंने आज इस सदन के सामने पहले मुख्य मंत्री की इन्होंने घोषणा कर दी है कि यह पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने बोला, जिस पर बजट रख दिया, आपके पूर्व के मुख्य मंत्रियों नहीं रखा। यह आपने सदन के सामने, पूरे राजस्थान की जनता को बताने का काम किया है। ...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप बिराजें।

श्री अशोक (हिण्डोली): उद्योगों के ऊपर लोक लुभावने शब्द काम में लिये गये। माननीय उद्योग मंत्रीजी हमारे बीच में बैठे हैं। लोन देने की बात कही, इंडस्ट्रियल पार्क डवलप करने की बात कही। एक्सपोर्ट हब बनाने की बात कही, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाने की बात कही। लेकिन मैं, माननीय मंत्रीजी के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि दो-चार चीजें और हैं जिससे राजस्थान के उद्योग की शक्ति बढ़ सकेगी, राजस्थान के युवाओं की बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकेगी। उसमें पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टूल, कि पॉलिसी बिलकुल सही, पूर्व सदस्य कह रहे थे कि लोकल व्यक्ति को जब काम मिलेगा इन इंडस्ट्रीज के अन्दर, यह जो हम डवलप करने की कोशिश कर रहे हैं।

MLS/RTM/23.07.2024/14:50/2h

उसके लिए पॉलिसी लानी पड़ेगी और लोकल लोगों को जॉब पर रखने के लिए कितने प्रतिशत लोगों को रखा, उसके ऊपर यदि इंडस्ट्रीज को कोई इंसेंटिव सरकार की तरफ से मिलेगा तो निश्चित रूप से वह ल्यूक्रेटिव ऑफर होगा और लोकल लोगों को वे काम पर रखने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि आपने लोन तो ऑफर किया है, लेकिन लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है, उस पर कोई छूट दी जाये, इलेक्ट्रिक सप्लाई की प्राइसेज में कोई छूट दी जाये, टैक्सेज में छूट दी जाये ताकि व्यापारी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके और एक सस्टेनेबल मॉडल उसके सामने हो, तभी ल्यूक्रेटिव ऑफर होगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा।

सभापति महोदय, बजट में एक पैरा लिखा गया, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, "The key to economic progress and social upliftment lies in industrialization. By fostering industrial growth, we can provide employment, reduce poverty and enhance the standard of living."मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का सम्पूर्ण समाज को क्या फायदा हो सकता है, किस प्रकार से जॉब क्रिएट हो सकती हैं, किस प्रकार से आम आदमी की आमदनी बढ़ सकती है, किस प्रकार से पॉवर्टी और अनइम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो सकती है, उसके काम में भी इंडस्ट्री आनी चाहिये। उसके लिए सरकार ने जो बजट पेश किया है, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने, लोकल को जॉब देने के ऊपर किसी प्रकार का इंसेंटिव इसके अन्दर नहीं है। यदि मंत्री जी, इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी और हमारे राजस्थान के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उन्हें इसका फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जिसकी ओर मुझे लगता है कि पूरे सदन का ध्यानाकर्षण होना चाहिये, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट आज की तारीख में सभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बहुत बड़ी समस्या बन गया है। जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनके वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। भीलवाड़ा जिले से मेरा नाता है, क्योंकि पूर्व में मैं पार्लियामेंट चुनाव वहां से लड़ा, उस जिले की उस समय की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, वहां कपड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन कपड़ा इंडस्ट्री का जो वेस्ट कैमिकल है, वह भीलवाड़ा की वॉटर टेबल में मिक्स हो चुका है। ग्राउंड वॉटर में कपड़े का कैमिकल पूरे भीलवाड़ा शहर में मिल चुका है।

फ्रैश वॉटर नहीं मिलता है। वह तो भला हो कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी जी का, जिन्होंने उस समय आज से दस साल पहले साढ़े 3 हजार करोड़ रुपये की चम्बल पेयजल योजना भीलवाड़ा में लाकर गांव-गांव, शहर-शहर के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल समस्या पैदा होती जा रही है। यदि आपका विभाग इस पर ध्यान दे और इसके लिए बजट के प्रावधानों का सही इस्तेमाल करे तो बहुत सुधार होगा। लोक-लुभावनी बातें, ''वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट'', ''वन डिस्ट्रिक्ट, वन गेम'', पिछले दस सालों में कम से कम 6 बार यही बातें सुन चुका हूं। सभी सरकारों में ये बातें

होती हैं। ये बातें बजट तक ही सीमित रह जाती हैं।

आज राजस्थान में नैचुरल स्टोन की बहुत बड़ी माइनिंग इडस्ट्री है। हालांकि, उसके ऊपर कट मोशन के माध्यम से चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन पूर्व में जब से जीएसटी लागू हुआ है, उसके बाद में अभी हमारे सदस्य महोदय बता रहे थे कि क्यों इंडस्ट्रीज गुजरात जा रही हैं, लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ तो राजस्थान के नैचुरल स्टोन के साथ दोगला व्यवहार हुआ। मोरबी गुजरात में जो टाइल्स का प्रोडक्शन होता है, उनको तो कम टैक्स परसेंटेज में रखा गया 3 परसेंट के अन्दर और राजस्थान में जो नैचुरल स्टोन प्रोड्यूस होता है, उसे 28 परसेंट जीएसटी के स्लैब में रखा गया। उसकी वजह से राजस्थान की माइनिंग इंडस्ट्री, चाहे वह मार्बल की हो या ग्रेनाइट की हो या सैंड स्टोन की हो, वह बर्बादी की कगार पर है, ।

अध्यक्ष महोदय, मशीन से जो टाइल्स बन रही हैं, जिनमें लेबर भी नहीं लग रही है, जिनमें जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो रही हैं, वह सारा व्यापार गुजरात चला गया। ये तो देश के प्रधान मंत्री जी के हालात हैं।

अध्यक्ष महोदय, खेलों के ऊपर भी आज चर्चा है और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि देश के लिए मैडल लाने वाले ऐसे हमारे मंत्री हैं। हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि उन्हें खेल के बारे में नॉलेज है और उनकी जिन्दगी का एक एक्सपीरियंस है। निश्चित रूप से खेलों को उनके एक्सपीरियंस का कोई फायदा मिलने वाला है, ऐसी हमें बहुत आशा है और अभिलाषा है, लेकिन दो-चार चीजें इस बजट में मुझे लगता है कि जो रह गईं और मुझे आपको अवगत करानी चाहिये।

सबसे पहले बहुत अच्छी लगने वाली एक घोषणा हुई कि खेलों का बजट सीधा दुगना कर दिया गया है, 475 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 950 करोड़ कर दिया गया है। फिर मैंने जब इसके नीचे वाले हैड्स देखे, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 250 करोड़, सम्भागीय स्तर स्पोर्ट्स कॉलेज 500 करोड़, फिटनेस सैंटर 15 करोड़, 10 हजार से ज्यादा की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में स्टेडियम, 9 खेल स्टेडियम्स, सिंथेटिक ट्रैक। माननीय मंत्री महोदय, यह तो खेलों का बजट लगता नहीं है, यह तो पीडब्ल्यूडी का बजट लगता है। मुझे भी पूर्व में इस विभाग में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः एक भावना है, जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं।

इंजीनियरिंग यूनिट आपके विभाग की डवलप करें। चाहे एक्सईएन आपको दूसरे इंजीनियरिंग विभाग से डेपुटेशन पर लेना पड़े, मैंने भी प्रयास किये, सारे प्रयास सफल नहीं होते, कुछ प्रयास सफल हो जाते हैं, कुछ प्रयास रह जाते हैं, लेकिन खेल विभाग की अपनी इंजीनियरिंग यूनिट डवलप करें ताकि ये सारे स्टेडियम्स, यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स कॉलेज आपके खेल विभाग और उसके अधिकारियों की देखरेख में बनें और टैक्निकैलिटीज की उसमें कोई समस्या नहीं हो।

बाद में आरएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी बनाकर दे देंगे, लीपापोती हो जायेगी, मजबूरी में आपके विभाग को उनकी हैंडओवर लेनी पड़ेगी और बाद में जब तक हैंडओवर लेंगे, उनमें

आधे से ज्यादा सामान काम करने लायक नहीं रहेंगे। यह मैंने अपने कार्यकाल में देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इंजीनियरिंग यूनिट डवलप करें। ...(व्यवधान)...

मैं आपके बीच में खड़ा हो जाता, आपकी आवाज इस सदन में नहीं आती। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, अगर मैं आपके बीच में बोलूंगा, मैं अभी तक कोई नैगेटिव बात नहीं कर रहा हूं। मैं कोई नैगेटिव बात नहीं कर रहा हूं। मुझे इस विभाग से प्रेम है, इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव बातें कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... अभी राजनीतिक बातों पर भी आऊंगा। अभी रुक जाएं।

श्री सभापतिः आप बैठें। मंत्री महोदय सक्षम हैं, वे जवाब दे देंगे। आप शान्त रहें।

श्री अशोक (हिण्डोली): मैं चाहता हूं कि खेलों में जो हमारे कार्यकाल में शानदार आयोजन हुए, वे जारी रहें, बल्कि उनसे बेहतर आएं, क्योंकि जमाना आगे बढ़ रहा है। हर दिन टैक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हर दिन रिसर्च आगे बढ़ रही है, साइंस का अचीवमेंट हो रहा है तो क्यों नहीं हमारे खेलों की टैक्नोलॉजी, हमारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस भी आगे बढ़े? इसलिए एक सकारात्मक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक आपका हैड है 125 करोड़ का, उसके अन्दर इतनी सारी घोषणाएं हैं, ''वन डिस्ट्रिक्ट, वन स्पोर्ट'', ''मिशन ओलम्पिक'', ''स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम'', ''स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स'', ''सिंथेटिक ट्रैक'', ''9 खेल स्टेडियम'', ''शाहपुरा खेल अकादमी'', ''4 खेल स्टेडियम'', ''प्रदेश की 10 हजार आबादी वाले गांवों में खेल स्टेडियम'', मुझे लगता है, इतने सारे कामों के लिए 125 करोड़ कम पड़ेंगे। ऐसे में निश्चित रूप से आपको माननीय मुख्य मंत्री जी से इसे और बढ़ाने की बात करनी चाहिये।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): 10 हजार आबादी वाले में स्टेडियम नहीं है, उसमें जिम है।

श्री अशोक (हिण्डोली): इसमें खेल मैदान लिखा हुआ है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): जिम है वहां पर।

श्री अशोक (हिण्डोली): अच्छा, ओपन जिम बना देंगे? ठीक है। इस सदन में चर्चा के दौरान पिछले कार्यकाल में एक योजना हमने बनायी थी ''मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम'', क्योंकि अनेकों विधायकों की डिमांड रहती थी हमारे यहां पर स्टेडियम दे दें, तो मेजर ध्यानचन्द योजना को भी, चूंकि इसमें कोई विवरण नहीं था, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह इस सदन की चर्चा के उपरान्त ही योजना बनायी गयी। कोई भी विधायक अपने कोष से 1 करोड़ तक पैसा दे दे तो विभाग उसमें 1 करोड़ तक लगाकर जो छोटी-छोटी तहसीलें हैं, तहसील हैडक्वार्टर के लिए है, मैं मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि हमारे समय में ये तहसील लेवल तक हुई, आप इसे ग्राम पंचायतों तक लेकर जाएं तो निश्चित रूप से राजस्थान के खिलाड़ियों को, ग्रामीण प्रतिभाओं को मुझे लगता है कि इस सदन की चर्चाओं का असल फायदा मिल पायेगा।

mkd/rtm/23.07.2024/15:00/2j

हम तहसील तक लेकर गये आप ग्राम पंचायतों तक लेकर जा सकेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके अनुभव का राजस्थान के खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिलने वाला है।

सभापति महोदय, हमारे कार्यकाल में आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में अमेंडमेंट्स हुए। यह पॉलिसी 2016 में, माननीय मंत्री महोदय जी मन्द मन्द मुस्करा रहे हैं, उनकी सरकार में वे मंत्री थी, तब यह पॉलिसी बनी। मुझे बड़ा खेद है, इस बात को कहते हुए कि यह पॉलिसी पांच साल तक पड़ी रही, बनकर तैयार हो गई, लेकिन राजस्थान के एक भी उत्कृष्ट खिलाड़ी को इनकी बनाई हुई ऑउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हुई। राजस्थान के खिलाडियों को कोई फायदा नहीं मिला।

जब हमारी सरकार आई। हमारी सरकार के समय में 2020 में हमने इसमें अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करने के बाद में मुझे इस बात पर गर्व महसूस होता है कि हमारे बचे हुए साढ़े तीन साल के कार्यकाल में चार सौ से ज्यादा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को डायरेक्ट अपाइंटमेंट मिला। वे आज राजस्थान सरकार के अन्दर अपने खेलों के माध्यम से भी और अपनी दूसरी सेवाओं से भी राजस्थान सरकार की सेवा कर रहे हैं। राजस्थान के लोगों की सेवा कर रहे हैं।

साथ ही साथ, मुझे एक बात का और खेद है कि आज आपकी सरकार को सात महीने हो गये हैं। इन सात महीनों में सैकड़ों एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, लेकिन सात महीने के अन्दर एक भी ऑउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत किसी भी खिलाड़ी को नई अपाइंटमेंट नहीं मिली है।

इस बात से मैं आपको इसलिए चेताना चाहता हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा पेंडेंसी बढ़ेगी, लोगों की क्या टेंडेंसी है, आपको क्या तकलीफ है? पहली बार आये हो या कितनी बार आये हो सदन में।

श्री सभापतिः आप शान्त रहें।

श्री अशोक (हिण्डोली): आप बार-बार बीच में बोल रहे हो। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं। आपको क्या समस्या है? देखिये, मैं आपको कह रहा हूं, यदि किसी को जॉब मिलनी चाहिए और वह कई महीने से डिले हो रही है तो बीच में दलाल पैदा हो जाते हैं। कई लोग उनको अलग-अलग दरवाजा दिखाते हैं। वह उनका खास है। वह सैक्रेटरी साहब का खास है तो कई बार यह देखा है कि लोग बीच में उन खिलाड़ियों से या उनके घरवालों से पैसा लेने का भी काम कर बैठते हैं, यदि इनमें डिले होगा।

माननीय खेल मंत्री जी से आग्रह है कि इस लिस्ट की तुरन्त स्क्रूटनी की जाये। इस लिस्ट को चीफ सैक्रेटरी और आपके विभाग को मिलकर फाइनलाइज करनी चाहिए। जिनकी भी एप्लीकेशंस सही हैं, उसकी स्क्रूटनी करके जल्दी से जल्दी उन्हें विभाग अलॉट करके उन्हें जल्दी से जल्दी जॉइनिंग दिलाई जाये। वरना, बीच में कोई खेला कर जायेगा। आपकी सरकार बदनाम हो जायेगी। बाद में, हम इस सदन में इश्यू उठाने में कोई कमी नहीं रखेंगे।

हमारी सरकार ने खेल प्रबन्धक एवं सहायक खेल प्रबन्धक की विज्ञप्ति भी निकाली थी।

मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको भी जल्दी से जल्दी पूरी करें। खेल विभाग में पोस्ट खाली पड़ी हैं, कई जिला खेल अधिकारियों की पोस्ट खाली पड़ी हैं, वे पोस्ट्स इनसे भर जायेंगी। इससे राजस्थान के खिलाडि़यों को बहुत फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, इनकी सरकार ने जब चुनाव लड़ा तो अपने घोषणा पत्र में 34 नम्बर पेज पर प्रथम पॉइंट में यह लिखा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाडि़यों को सरकारी नौकरी मिले। हालांकि, सुनिश्चित तो क्या करेंगे, यह तो पहले से ही सुनिश्चित था, दो प्रतिशत में अमेंडमेंट कर दिया, ऑउट ऑफ टर्न पॉलिसी में अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन आज इनकी सरकार में उससे विपरीत व्यवहार हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय खिलाडि़यों के लिए एक नियम है कि आप अगर सरकारी नौकरी ज्वाइन भी करेंगे, अगले पांच साल तक आपको अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना पड़ेगा, उत्कृष्ट परफोर्मेंस देनी पड़ेगी, वे उत्कृष्टपरफोर्मेंस भी दे रहे हैं, वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग भी ले रहे हैं, लेकिन आपके विभाग उनको ट्रेनिंग के नोटिस दे रहे हैं।

जंगलात विभाग ने, जो खिलाड़ी अभी भी वर्ल्ड कप की तैयारी में हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी में लगे हैं, एशियन गेम्स की तैयारी में, कॉमन वेल्थ गेम्स की तैयारी में, ओलम्पिक की तैयार में, उन खिलाड़ी को ट्रेनिंग नहीं पूरी करने पर जॉब से निकालने की धमकी दी गई है। यह आज के अख़बार में आप पढियेगा।

आप समझिये, आप एक तरफ खिलाडि़यों को अपने घोषणा पत्र में वोट लेने के लिए कहते हैं कि हम जॉब देंगे, दूसरी तरफ जॉब मिले हुए खिलाडि़यों को निकालने की बात करते हैं। मैं समझता हूं, यह जो दोहरा चरित्र है, वह प्रदेश के जनता के सामने आना चाहिए।

सभापति महोदय, खेलों के ऊपर तो मैं इतना ही बोलना चाहता था, क्योंकि सकारात्मक चर्चा ही हो तो ठीक रहता है। मैं चाहता हूं कि जिस पहिये को, मुझे सदन को बताते हुए खुशी होती है कि अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि मेडल अब आयेंगे। मैं दावा कर रहा हूं, इस सदन में खुला बोल रहा हूं, आजादी के बाद में आपकी जितनी सरकारें रही हैं, उन सभी सरकारों के सारे राष्ट्रीय मेडल मिला लीजिये और पिछले पांच साल हमारी सरकार रही, राजस्थान के राष्ट्रीय मेडल, यदि उसके आधे पर भी आपकी सारी सरकार मिलकर पहुंची हो तो मैं इस सदन में पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आंकड़े पेश कीजिये।

वे कह रहे थे कि मेडल अब आयेंगे। मैं कह रहा हूं कि मेडल की बात नहीं है। हमारी सरकार ने शुरू कर दिया। हमें तो खुशी है कि एक खिलाड़ी खेल मंत्री बना है। उनके एक्सपीरियंस का फायदा मिलना चाहिए। हमसे भी दस गुणा काम होना चाहिए। हमारी यह आशा है।

श्री सभापतिः विराजियें। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अशोक (हिण्डोली): विश्वास तो है। नाई-नाई माथे में बाल कितने हैं, जजमान कटेंगे और सामने आयेंगे, ये तो अभी सामने आ जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बस दो से चार मिनट में महिला बाल विकास पर अपनी बात कहकर खत्म करता हूं। घोषणा पत्र के पेज नम्बर 29 पर, हम आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मासिक देय 13,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 7,500, आंगनबाड़ी सहायकों का मानदेय 6,500 और आशा कार्यकताओं का मानदेय 6,000 करेंगे।

उन सबके साथ में, इस सरकार ने धोखा किया है। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केवल 9,581 रुपये, आंगनबाड़ी सहायकों को 5,590 रुपये, आशा सहयोगिनी को 4,508 रुपये का भुगतान हो रहा है तो 13,000 वाला वादा, साढ़े 6,000 वाला वादा, 6,000 वाला वादा, तीन साल बाद पूरा करेंगे। या तो घोषणा पत्र में यह कह देते कि हमारा कार्यकाल पूरा होते-होते अन्त में पूरा करेंगे, ये लिख देते, लेकिन आपने राजस्थान के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी के साथ धोखा करने का काम किया है। उनके वोट लेकर पलटने का काम किया। आने वाले समय में वो भी आपको पलटने का काम करेंगी।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री अशोक (हिण्डोली): साथ ही साथ, एक लास्ट पॉइंट, हमारी सरकार में 5 अक्टूबर, 2023 को वन टाइम रिटायरमेंट पर, इनको 2 लाख रुपये से लेकर 3 लाख तक वन टाइम रिटायरमेंट पर देने का एक सरकारी आदेश निकला था और उसे अभी काम में नहीं लिया जा रहा है। ये रिटायर होती जा रही हैं। इनको रिटायरमेंट का वन टाइम सेटलमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दें।

श्री सभापतिः विराजिये, माननीय सदस्य। आपका समय समाप्त हुआ। श्री बालमुकुन्दाचार्य।

श्री अशोक (हिण्डोली): समय समाप्त, धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 26 युवा मामले एवं खेल, मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास, मांग संख्या 56 उद्योग पर बोलने का मौका दिया है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार बनने के तुरन्त पश्चात सर्वप्रथम युवाओं की समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। पिछले पांच साल में युवा वर्ग गत सरकार की कार्य प्रणाली से बहुत परेशान थे। जिसका परिणाम था कि विधान सभा और लोक सभा चुनाव में युवाओं ने बढ़-चढकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और एनडीए पर पूरा विश्वास किया और उसी का प्रमाण है कि आप और हम सब यहां पर अग्रणी विकास की ओर बढ़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, युवा मामले एवं खेल, हमारी सरकार ने जो 2024-25 का बजट रखा है, उसमें युवाओं पर पूरा फोकस रखा है। आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब और उप मुख्य मंत्री महोदया ने विशेषकर इस बात पर ध्यान रखा है कि राजस्थान के युवाओं को अग्रणी लाने के लिए किस प्रकार योजना बनाई जाये।

हमारी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, शिक्षा और खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की कौशल एवं क्षमता को निखारने के लिए, रोजगार के नये अवसर में वृद्धि करने के संकल्प को लेकर कार्य शुरू किया है।

Bhs/Rtm/23.7.24/15.10/2k

इस सम्बन्ध में हमारे राजस्थान की भजन लाल सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगामी पांच वर्षों में चार लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है और इस वर्ष पहले लेखानुदान में जो सत्तर हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की घोषणा की गई थी उसको बढ़ा कर इस वर्ष एक लाख पदों पर भर्तियां करने का जो लक्ष्य रखा है वह ऐतिहासिक है और अपने-आप में एक अभूतपूर्व कदम है। इसके अलावा हमारी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के दृष्टि से युवाओं की नीति 2024 लाने की जो घोषणा की है इस नवीन नीति के माध्यम से आगामी पांच वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर बढ़ाया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष के 475 करोड़ रुपये की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दुगुना करने का निर्णय भी युवाओं के हित में है। प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय तथा सम्भाग स्तर पर खेल महाविद्यालय की स्थापना के लिए भी बज का प्रावधान किया है। साथ ही, युवाओं में कौशल विकास कर प्रदेश में दो वर्षों की अवधि में एक लाख पचास हजार से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग कराने का भी निर्णय लिया गया है। यह ऐतिहासिक कदम है इसलिये बार-बार सम्माननीय सदस्य यह बात कह रहे हैं कि अग्रणी राजस्थान में अभी जो मुख्य मंत्री वर्तमान में हैं उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाये हैं और पूरे राजस्थान की जनता का व्यु लेकर यह कार्य किया है।

माननीय सभापति महोदय, मुझसे पूर्व अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे वे स्वयं स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और हमारे खेल मंत्री, उद्योग मंत्री भी प्लेयर हैं। 2014 का आकलन देखें, 2014 के जो पदक प्राप्त हुए हैं भारत को वो आप पूरे पदक का और पिछले का लगा कर देख लें क्या स्थिति है। बात ठीक है आपकी घोषणाएं खूब थी, घोषणाएं थोथी थी और इस क़दर आप स्वयं भी परेशान थे और आप स्वयं मंत्री होने के बावजूद भी उन बातों को लेकर निरन्तर आवाज उठाते थे, इस बात का तो समर्थन करता हूं लेकिन आज स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि पिछली सरकार में घोषणाएं थी उसके अलावा कुछ था नहीं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में एक जिला एक खेल योजना लागू कर प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पदक विजेताओं के लिए बीमा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमारे खिलाड़ियों एवं खेलों के लिए सरकार ने अनेक प्रावधान इस बजट में किए हैं जो स्वागत

योग्य है और मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में पारम्परिक खेलों को शामिल करते हुए ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर पर प्रति वर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किये जाने की घोषणा ऐतिहासिक है। पचास करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय किये जाने का निर्णय भी हमारी सरकार का सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे हवामहल विधान सभा क्षेत्र में जयसिंहपुरा खोर में एक खेल स्टेडियम के निर्माण की बजट में घोषणा की गई है, जिसके लिए मैं हमारे मुख्य मंत्री महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदय का एवं खेल मंत्री महोदय का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में लगभग पचास से साठ हजार की आबादी रहती है जहां पर स्टेडियम बनने पर वहां युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हवामहल में चौगान स्टेडियम बना हुआ है जो बहुत पुराना है जयपुर की बसावट के समय का है। पहले इस स्टेडियम का बहुत नाम था और गत कांग्रेस सरकार ने इसकी दुर्दशा कर दी। स्मार्ट सिटी के द्वारा करोड़ों रुपये का बजट का प्रावधान रखा। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से भी कि पिछले कार्यकाल का जो काम हुआ है उसकी जांच भी करे और जो आज चौगान स्टेडियम की दुर्दशा की है उन लोगों की भी सच्चाई सामने आनी चाहिये कि चौगान स्टेडियम की आज यह हालत है वहां आने वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहां तक की स्थिति यह कर दी कि वहां शौचालय और उनके गेट तक भी नहीं है। वहां कोई सुविधा है नहीं, घास है नहीं और जो पत्थर लगे हुए हैं वो गिर चुके हैं। आप जयपुर के इस पुरातत्व स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए एक पैकेज जारी करे, जिससे वहां पर खिलाड़ियों के लिए सारी सुविधाओं का विकास हो सके। वहां पर खेल गतिविधियां भी शुरू की जाए। अलग-अलग खेलों के कोच भी वहां पर नियुक्त किए जाए। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी रहती है जिसके लिए सारी सुविधा यहां पर मिलने लग जाएगी तो बच्चों को बहुत फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, गत पांच वर्षों में पेपर लीक के प्रकरण से युवाओं में जो निराशा थी, उनका भविष्य कांग्रेस सरकार ने अंधकारमय बना दिया था। हमारी सरकार ने आते ही इस पेपर लीक के मामले को हल किया और पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसा गया और भविष्य में अब दुबारा ऐसा काम न हो उसके लिए कड़क कानून भी बन गया। बच्चों के हितों पर कुठाराघात अब दुबारा न हो उसके लिए एक अच्छी नीति बना दी गई। साथ में खेलों को बढ़ावा देना यह माने कि अब कहीं न कहीं युवाओं को जो खेलों के माध्यम से भी रोजगार प्राप्त हो रहा है, नौकरियां प्राप्त हो रही है, उसमें और लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह आग्रह रहेगा कि जयसिंहपुरा खोर में स्टेडियम की जो घोषणा की गई है...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह सरकार सो रही है।

...(व्यवधान)...

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): उस स्टेडियम का जल्द से जल्द काम शुरू किया जाये और इसका फायदा वहां के क्षेत्रवासियों को मिले ...(व्यवधान)... भविष्य होगा साहब, बिलकुल होगा। आप अग्रणी राजस्थान के साथ अपना योगदान दें आप सबका भी विकास तय होगा। महोदय, हमारे उद्योग की बात कहूं ...(व्यवधान)... हां आप प्रति पक्ष के नेता हमेशा बने रहें यह बात ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग की बात करूं हमारे प्रदेश का हर जिला अपने विशिष्ट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजसमन्द हो तो टेराकोटा के लिए, बाड़मेर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, कोटा डोरिया के लिए, जालोर मोचड़ी जूती के लिए, पाली मेहन्दी के लिए, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए, जयपुर जैम्स के लिए, ज्वेलरी के लिए साथ में दौसा दरियों के लिए तथा नागौर हैंड टूल्स के लिए स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के वोकल फोर लोकल के लिए की गई पहल के क्रम में राज्य के प्रत्येक जिले का एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से राजस्थान का एक जिला एक उत्पादन योजना 2024 लाये जाने की घोषणा की है जिसके क्रियान्वयन में प्रति वर्ष लगभग सौ करोड़ रुपये का भार आयेगा। साथ ही, ऐसे उत्पादनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी, कार्यशाला, सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल लगभग दो सौ करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बातों से जो अभी पिछले वक्ताओं ने कही मैं सहमत हूं हमारी यहां की इंडस्ट्री को मेरा स्वयं का अनुभव है पिछली सरकार में मैंने खुद एक बाहर से आये हुए इंडस्ट्री ग्रुप के साथ में सरकार के कई प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): लेकिन उसका आन्सर जीरो निकला, उसका कारण यह था कि वो यहां पर इतनी बड़ी असुविधा थी और रिश्वतखोरी थी कि वो इंडस्ट्री वाले कुछ तो चले गए गुजरात और कुछ चले गए बरेली और कुछ चले गए कहीं और इस प्रकार से वो जो मारवाड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो यहां पर आना चाहते थे, उद्योग जमाना चाहते थे लेकिन यहां की जटिलताएं और सरकार की फाइव स्टार का रहना कई कारण ऐसे रहे कि इंडस्ट्री वाले यहां पर अपना उद्योग लगा नहीं पाये लेकिन इस बार मुझे पूर्णत: विश्वास है कि सम्पर्ण राजस्थान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पूरी दुनिया में जहां व्यापारी वर्ग का बड़ा नाम है हमारे मारवाड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट का। गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं, गुजरात में जिस क़दर आदरणीय प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री रहते हुए और गुजरात में ऐतिहासिक इंडस्ट्रीज डवलप की, उस कारण हमारे यहां के मारवाड़ी भी अधिक संख्या में जाकर और गुजरात में अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। गुजरात आज इतना बड़ा समृद्ध बन गया और वहीं गुजरात मॉडल की वजह से सम्पूर्ण भारत ने मांग की थी कि भारत को भी अब अग्रणी लाने के लिए हमें मुख्य मंत्री नहीं अब प्रधान मंत्री मोदी चाहिये, उसी प्रकार से अब हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री

भजन लाल शर्मा साहब ने बहुत अच्छी पहल और शुरूआत की है और मुझे पूर्णतः विश्वास है। अभी कुछ दिनों पहले ही यू.के. से मेरे कुछ लोगों के फोन आये हैं कि हम लोग मुख्य मंत्री से मिल कर और यहां पर आई.टी. हब लाना चाहते हैं यहां पर इंडस्ट्री लाना चाहते हैं।

श्री सभापतिः विराजें। अंकित नहीं हो। श्री अमीन कागजी।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): 000

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 पर बोलने के लिए अनुमति दी, उसके लिए आपका और हमारे नेता, प्रतिपक्ष का बहुत-बहुत धन्यवाद।

Kas/rtm/23.07.2024/15.20/2l

आज उद्योग की डिमांड है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह जितनी भी योजनाएं और नीतियां बनाने की बजट में बात की, वह सारी नीतियां कमोवेश बनी हुई हैं। चाहे आप एमएसएमई एक्ट की बात करें, जुलाई, 2019 में, यानी हमारी सरकार बनने के 7 महीने के अन्दर-अन्दर हम यह पॉलिसी एक्ट लेकर आ गये थे, जिसकी आज हम फिर से बात कर रहे हैं कि यह एमएसएमई एक्ट लायेंगे। यह एकदम असत्य बात है, यह नीति ऑलरेडी आई हुई है। 2023 में हमने इसका एक्ट लाकर 3 साल की अवधि को 5 साल कर दिया। इसमें यह भी क्लियर कर दिया कि अगर तीन साल के लिये कोई आदमी बिजनेस लगाता है तो उसको शुरू के तीन साल में कोई लैंड कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, वह किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर बिजनेस लगा सकता है, यह पहले से डिसाइडेड है।

इसी तरीके से 2019 में औद्योगिक विकास नीति आई। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में आई। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 2019 में आई। डाक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी योजना 2019 में आई। यह नीतियां पहले से बनी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि 31 मार्च, 2024 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें यह लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक नीयत थी, जिसे दिनांक 31.7.2024 तक बढ़ाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। हम युवाओं को और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, मंत्री महोदय, आज आप यह क्लीयर कर दें कि इस योजना के बारे में आपका आगे का क्या एक्शन प्लान है, क्योंकि अब आपके पास 7 दिन ही बचे हैं, यह तो आपको करना है, तो आज ही बता दें, बहुत मेहरबानी होगी।

मैं आपके संकल्प पत्र की बात करता हूं। आपके संकल्प पत्र की कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन है। एक तरफ आपका संकल्प पत्र है, दूसरी तरफ आपका बजट है। आप संकल्प पत्र में बात करते हैं 450 करोड़ की, बजट में देते हैं 150 करोड़ रुपये। जिस बिना पर यह सरकार बनी, जिस बात पर आप लोगों ने वोट लिये, इसमें आपने एक बात की

कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की पॉलिसी लाई जायेगी। आज 7-8 महीने हो गये, आपने अब तक क्या कार्यवाही की? बजट में भी घोषणा कर दी। इसमें आपने अब तक आधिकारिक रूप से क्या किया? क्या आपकी मंशा एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये है, उसमें क्या आप इंसेंटिव स्लैब लायेंगे? आपका इसमें जो भी वर्जन है, आप बताएं।

आपने बात की कि हम केन्द्र सरकार के साथ मिलकर पाली, अजमेर, सिरोही, जयपुर मल्टी मॉडल लोजेस्टिक पास लेकर आयेंगे। क्या आपने भारत सरकार को यह प्रपोजल भेजे? नहीं भेजे, जहां तक मेरी जानकारी में है। आपने आज तक इस पर आधिकारिक रूप से कोई चर्चा नहीं की और न आपने बजट में दिखाया। अगर आपने कुछ किया था, तो बजट में तो आता। अब तो 6 महीने में आपको इसको निपटाना है। आपने अगर प्रोविजन ही नहीं किया तो आप आगे करेंगे क्या, मैं आशा करता हूं कि आप इसका जवाब देंगे।

दूसरी बात, हमारी सरकार ने जोधपुर में पहले से ही टेक्सटाइल पार्क की घोषणा कर दी है, उसका काम चल रहा है। आपने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि हम केन्द्र सरकार के साथ मिलकर 10 हजार करोड़ के निवेश से जोधपुर के पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण तेजी से पूरा करेंगे। वह निर्माण तो चल रहा है, आप क्या करोगे, वह तो पहले से ही चल रहा है। आप नया क्या कर रहे हैं? यह तो सारी पुरानी चीजें जो हमारी सरकार ने की थीं, बराए करम आप उसको भी आगे लेकर चल जायेंगे तो इस प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल लगता है। मंत्री महोदय, आप इतना ही कर लें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हैंडसम हैं, आपकी पर्सनेलिटी अच्छी है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): मेरा आग्रह है, आप मेरे जवाब के लिये यहां रुकियेगा जरूर।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): मैं आपको बजट की भी बात बता देता हूं। बजट उन्हीं अधिकारियों ने बनाया है, जिनसे आज तक हम बनवाते आये थे, कोई नये आदमी ने नहीं बनाया है आपका बजट। हां, यह जरूर है कि हमारी बड़ी-बड़ी चीजों को आपने छोटे-छोटे में तकसीम कर दिया। मतलब हम जो 500 करोड़ देने की बात करते थे, आप 5-5 करोड़ में इतना मोटा बना दिया। ...(व्यवधान)... आप सुनिए। हमीर जी, आप बात सुनिए। आपने पोने तीन घंटे मैडम को खड़ा रख दिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो बजट था, उसको 2-2, 4-4 , 50-50 लाख में बाट दिया, इसलिए पौने तीन घंटे मैडम को खड़ा रहना पडा। खैर, आज बहुत सारी बातें हैं।

मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह हमारा फर्ज है, हम जीत कर आये हैं, माने ना माने, आपकी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान का रीको 1979 में बना। मंत्री जी, आप गौर कीजिए कि 1979 से पहले जो 60-70 इण्डस्ट्रियल ऐरियाज पूरे राजस्थान में बने थे, उनका आज हाल क्या है? उस समय क्या हुआ कि जिला कलेक्टर और जिला उद्योग अधिकारी मिलकर परमिशन देते थे और सरकार का औद्योगिक वातावरण धीरे-

धीरे डवलप हुआ। उसमें हमारा झोटवाड़ा एरिया, जो शायद आपकी कांस्टीट्यूएंसी में आता है, इसलिए आपको बताना जरूरी समझता हूं कि एक आर्डर सरकार ने जारी किया और उसमें यह कहा, पता नहीं कौनसे न्यायालय का आदेश था, उसका हवाला देते हुए ऐसे सभी औद्योगिक क्षेत्र में सारी कार्यवाही जो रीको करती आई है, चाहे वह सब-डिविजन का मामला हो, चाहे वह लैंड सब-डिविजन के साथ एनओसी का मामला हो, यह सारी चीजें आज रुकी हुई हैं, उसका हवाला देकर जो इण्डस्ट्रियल एरिया, चाहे हमारा झोटवाड़ा ले लें, झोटवाड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया में आज तक अब आप कोई सब-डिविजन नहीं कर रहे, न आप उसका डवलपमेंट कर रहे हैं, न उसमें आप एनओसी दे रहे हैं, न नाम ट्रांसफर की इजाजत दे रहे हैं, तो वह सारे इण्डस्ट्रियल एरियाज डम्प हो गये और आज इतने लिटिगेशन मामले में उन इण्डस्ट्रियल एरियाज में हो गये, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, 60-70 इंडस्ट्रीयल ऐरिया ऐसे हैं जो हमारे यहां के उद्योगपति परेशान हैं, इसके बारे में आप विचार करें और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करें।

msk/rtm/23.07.2024/1530/2m

दूसरी तरफ हम बड़े उद्योगों की बात करते हैं। हमारे यहां बड़े उद्योग कैसे आयेंगे, इस पर आप विचार करें। जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी बिजली की खपत भी ज्यादा है। बिजली की खपत ज्यादा है और दूसरी तरफ आज राजस्थान में इंडस्ट्री की बिजली की जो रेट है, वह हिंदुस्तान में ज्यादा है, इसको हमको विचार करने की जरूरत है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि जिस तरीके से रीको डवलपमेंट करती है। रीको को आप खुद एम्पॉवर करें। रीको के पास पर्याप्त पैसा भी है। उसको यह कहें या उसके लिए प्लान बनायें कि रीको खुद बिजली सेल्फ जनरेट करे। हम आरएसईबी के थ्रू बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को बिजली बनाने के लिए देते हैं। सैंकड़ों बीघा, हजारों बीघा, एकड़ जमीन हमने कई मल्टी नेशनल कंपनियों को दी है और देते आ रहे हैं, आज से नहीं, बीसों साल से। सोलर ऊर्जा के लिए हम रीको को दें। रीको खुद अपना पॉवर परचेज एग्रीमेंट इण्डस्ट्रियलिस्ट के साथ करे। बिजली के खाली हॉल चॉर्जज ही तो लेने हैं, आप वे इंडस्ट्री से लें। पॉवर परचेज एग्रीमेंट खुद करें। रीको खुद बिजली का उत्पादन करे तो मैं समझता हूं कि आपका एक सपना है। सरकार यह कहती है कि हम ग्रीन कॉरिडोर के साथ इंडस्ट्रीज डवलमेंट करेंगे। जब आप यह प्लान करते हैं तो बिजली के लिए भी प्लान करें। इंडस्ट्री को बिजली कैसे सस्ती मिले। इन्वेस्टमेंट सबमिट की बात करें। इन्वेस्टमेंट समिट बहुत टाइम से होते आ रहे हैं। लेकिन लोग आशाओं के साथ आते हैं, बहुत उम्मीद के साथ हमारे राजस्थान में आते हैं। जब यहां कर पता चलता है कि इंडस्ट्री के लिए जमीन कैसे मिलेगी तो रीको कहता है कि ऑक्शन में चले जाइये। ऑक्शन में आप बिडिंग कराते हैं, बिडिंग में उसको रेट महंगी पड़ती है। जमीन महंगी, बिजली महंगी, बड़ी इंडस्ट्री क्यों आयेंगी? हरियाणा में चले जायें, इधर गुजरात में चले जाएं। यूपी में चले जाएं, वहां पर सारी की सारी चीजें, क्योंकि आपकी अब डबल इंजन की सरकार है। आप चाहें

तो भारत सरकार से इसमें सहयोग ले सकते हैं।

अभी मेरे साथी विधायक ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें। सॉलिड वेस्ट आज एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी इस बात पर गौर किया था। मैं सदन का और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपने किशनगढ़ की बजट में कोई बात नहीं की। चूंकि वहां से हमारा विधायक जीतकर आया है। एक विधायक जीतकर आया है, आप यहां से चलेंगे, यहां से जैसे ही 200 फीट रोड, जो कि ब्यावर की तरफ जाती है। राइट हैंड पर आप देखेंगे तो अपने को सफेद-सफेद जमीन दिखती है। सारा सॉलिड वेस्ट सरकारी जमीन में डम्प हो गया। वहां तो फोटो शूट होता है। वहां प्री-वेडिंग शूट हो रहे हैं। ऐसे हो रहे हैं, जैसे हिमाचल में जाकर लोग फोटोग्राफी करते हैं। यह हमारे लिए एक चुनौती है। सारे सॉलिड वेस्ट को लेकर कई बार एनजीटी ने आपको और सरकारों को चेताया है कि क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नीति है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भारी पैसा भारत सरकार सभी स्टेट को देती है। डबल इंजन की सरकार है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ओर आप ध्यान देंगे, ताकि एनजीटी का जो डंडा है, हमारे ऊपर हजारों करोड़ रुपये की पैनल्टी लगती है, उससे हम स्टेट को बचा सकें।

इसी तरीके से हम बात कर रहे थे कि एनसीआर के जो एरियाज हैं। हमारी सरकार ने अलवर, भिवाड़ी, बहरोड़ के आसपास बहुत सारे एरिया में डवलपमेंट करने के लिए प्लान किया, रीको डवलप करना चाहता है, लेकिन एनसीआर की पॉलिसी हमारे आड़े आती है। जब हम सरकार में थे तो हमने कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन नहीं हो पाये। मैं उम्मीद करता हूं कि अब डबल इंजन की सरकार है। आप इस ओर ध्यान देंगे। ये जितने भी हमारे इण्डस्ट्रियल एरिया पैंडिंग पड़े हैं, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप हो सकते हैं, सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं। रीको के पास जमीनें हैं, वे आप एनसीआर से निकाल लेंगे तो यह बहुत बड़ा काम हमारे लिए होगा।

इसी तरीके से आपने संकल्प पत्र में साढ़े चार सौ करोड़ की बात की। हैंडीक्राफ्ट के लिए आपने डेढ़ सौ करोड़ दिये। मैं डेढ़ सौ करोड़ के लिए बात करना चाहता हूं। चूंकि आप जयपुर से हैं। अभी हमारे माननीय विधायक श्री बालमुकुन्दाचार्य जी भी बैठे थे। उनके विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ा हाट बाजार बनकर तैयार पड़ा है, बहुत लंबे समय से। सारे हैंडीक्राफ्ट, बिजनसमैन, जो मैन्युफेक्चरर हैं, उनको वहां पर लाकर बैठाइये। आपका बिजनस भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। सरकारी जमीन में उस टाइम, वसुन्धरा जी के टाइम पर यह डवलप हुआ था। बहुत बढ़िया जगह है, ट्यूरिस्ट आते हैं। आप वहां पर डवलपमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से सांगानेर का इनलेण्ड कंटेनर डिपो है, जो राजसिको की सम्पत्ति है। पहले जब कंटेनर एक्सपोर्ट होते थे तो इनलेण्ड कंटेनर डिपो से होते थे, लेकिन पिछले दो-तीन साल से, जो सांगानेर इंडस्ट्रीयल एरिया में है, यह सारा कोन्कोर्न हमने शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया, आपके विधान सभा क्षेत्र में। मंत्री जी, यह जमीन कनकपुरा में आइडल पड़ी है, बेशकीमती जमीन है। इसमें आप मल्टी मॉडल बिल्डिंग बनाइये। राजसिको की हालत खराब है।

राजसिको की प्रापर्टी है। सरकार फंडिंग करे। सांगानेर में टेक्सटाइल हब है। हैंडीक्राफ्ट डवलपमेंट का काम हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक सुझाव है, मानना या नहीं मानना, आपका अधिकार क्षेत्र है। चूंकि सांगानेर में मेरा निवास है और वह जमीन राजसिको की है। अब वहां बिजनस को लेकर या एक्सपोर्ट को लेकर कोई बात नहीं होती है। उस जमीन को आप डवलप करें। चूंकि विधान सभा क्षेत्र सांगानेर है। माननीय मुख्य मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मैं समझता हूं कि इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी तरफ, आप रीको से प्लॉट ऑक्शन करते हैं। बड़े प्लॉट 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार मीटर के जो प्लॉट हैं, उनको आजकल इण्डस्ट्रियलिस्ट नहीं ले रहे हैं। रियल इण्डस्ट्रियलिस्ट नहीं लेकर, जमीनों के ब्रोकर ले रहे हैं। ऐसे लोग ले रहे हैं, जिनको इंडस्ट्री नहीं लगानी है, वे इन्वेस्टर हैं। बेसिकली में ऑक्शन में जाते हैं। ऑक्शन में जाकर उसकी बिडिंग लगाते हैं। उनको तीन साल में 75 परसेंट पैसा देना होता है। 25 परसेंट पैसा आप उनसे 90 दिन में ले लेते हैं। लेकिन होता क्या है? इसमें बड़ा खेल है। पहले वे डिजाइन कराते हैं, अपने हिसाब से 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार मीटर का प्लॉट कराते हैं। उसके चारों तरफ सड़कें बनवाते हैं। फिर उसके बाद ऑक्शन में जाते हैं। ऑक्शन में जाने के बाद उसको ऑक्शन से छुड़ाते हैं, फिर पीएमटी कराते हैं। पीएमटी के बाद सब-डिवीजन कराते हैं और सब-डिवीजन कराने के पैसे लेते हैं, दो सौ से ढाई सौ रुपये। अगर रियल इंडस्ट्री के हिसाब से आप आप अलॉट करना चाहते हैं और इंडस्ट्री बसाना चाहते हैं तो तीन साल का लॉकिंग पीरियड कर दें, जब तक इंडस्ट्री का छह महीने का बिजनस रिकॉर्ड नहीं देख लें, एक साल का बिजनस प्रोफाइल नहीं देख लें, तब तक उसको सब-डिवीजन की इजाजत नहीं हो। यह बहुत गंभीर विषय है। यह मैं इंडस्ट्री डवलपमेंट करने के लिए कह रहा हूं। इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। दलाल जो इन्वेस्टर बनकर जमीनों को व्यापार करते हैं, इनसे आप रीको को बचा लें। रीको इनसे दूर रहे। आपके सिस्टम में ये नहीं घुस पाये। मैं ऐसी व्यवस्था की आपसे उम्मीद करता हूं। आखिर में एक बात, जितने भी पुराने इण्डस्ट्रियल एरियाज हैं, जो शहर में आ गये हैं। आप मंत्री हैं। मंत्री जी, रीको का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, जो हमारे इण्डस्ट्रियल एरिया हैं, चाहे पुराने हों, चाहे नये हों, लेकिन हम सीवरेज उसमें प्लान नहीं कर रहे हैं। आपके अधिकारी बैठे हैं। एक भी इण्डस्ट्रियल एरिया में आप सीवरेज का प्लान नहीं करते हैं, सीवरेज की लाइन नहीं डालते हैं। अब हो क्या रहा है। चाहे शहर में सांगानेर इण्डस्ट्रियल एरिया हो, मालवीय नगर इण्डस्ट्रियल एरिया हो, झोटवाड़ा हो, बाइस गोदाम हो।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): दो मिनट, यह लास्ट है। मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। इन एरियाज का आप लैंड यूज तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उपयोग परिवर्तन की इजाजत दे दें। उपयोग परिवर्तन से ये यहीं के यहीं रह जायेंगे। इसमें होटल आ सकती है, कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती हैं। होस्टल बन सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट बन सकते हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन फ्री हैं। पॉल्यूशन बचेगा और इनको नगर निगम को ट्रांसफर कर दें, ताकि

नगर निगम इनका डवलपमेंट करे, सीवरेज के पानी का इंतजाम हो। आपने बोलने का वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का अवसर मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

mdp/rtm/23.07.2024/15:40/2n

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की स्थापना नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के आयोजन के समय 1982 में खेल विभाग के रूप में की गयी थी। युवा अर्थात 15 से 35 वर्ष के आयु संवर्ग में आने वाले व्यक्ति। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत भाग युवा है। मैं कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे स्पोर्टस इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एनालेसिस, काउंसलिंग एवं न्यूट्रीशन का समावेश करते हुए सरकार के द्वारा जो खेल नीति, 2024 की घोषणा की है, उसके अंतर्गत राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करना और प्रदेश में कोच एवं स्पोर्टस स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है। प्रत्येक जिला स्तर पर जो खेल अकादमी स्थापित की है, इससे भी युवाओं को काफी लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि ब्लॉक स्तर पर अगर अकादमी खोली जाए तो इससे युवाओं को और ज्यादा लाभ होगा। टीओपी योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। स्पोर्टस लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत 25 लाख तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज भी बजट में दिया गया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और खेल मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। विद्यालय तथा महाविद्यालयों में पीटीआई कोच की समुचित व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से करना, यह व्यवस्था भी आपने बजट में की है। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनाए जाएंगे जिसमें खेल इंडिया की तर्ज पर प्रदेश में ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 'खेलों राजस्थान' आयोजित किया जायेगा, जिससे युवाओं को खेलों में विशेष लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में काफी बच्चे राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर खेलते हैं। राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा खिलाड़ियों को टीए, डीए दिया जावे। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामी राशि भी दी जानी चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है। राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाडियों को दिया जाने वाला महाराणा प्रताप पुरस्कार और प्रशिक्षकों को दिये जाने वाला गुरु वशिष्ठ पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। यह 100 दिवसीय कार्य-योजना में लिया जाना चाहिए। खेलों से सम्बन्धित 100 दिवसीय कार्य-योजना में खिलाड़ियों की नौकरी, खिलाड़ियों की इनामी राशि, खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार, खिलाड़ियों को टीए/डीए को लिया जावे। खिलाड़ियों की नौकरी, खिलाड़ियों की इनामी राशि, खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार, खिलाड़ियों का टीए/डीए काफी समय से रुका हुआ है। इस पर ध्यान दिया

जाना चाहिए।

वर्ष 2023-24 में राज्य खेल संघों और संस्थाओं को टूर्नामेंट आयोजन के पेटे जो अनुदान था, वह भी काफी समय से रुका हुआ है। अनुदान के लिए आवेदन कर रखा है, प्रतियोगिता के लिए कर रखा है। सरकार को अनुदान देना चाहिए। मौखिक निर्देशों से खेल विभाग की समस्त फाइलें अनधिकृत रूप से कार्मिक विभाग में कार्यरत खेल अधिकारी के माध्यम से जाती है। इनकी व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से खिलाड़ियों के काम रुके हुए हैं। उनको भी तीव्र गति दी जावे। तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति से तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा अनुमोदित फाइल होने के बावजूद खिलाड़ियों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। आउट ऑफ टर्न स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत पदक विजेताओं और खिलाड़ियों को नौकरी नहीं दी जा रही है, उन्हें तुरंत प्रभाव से दी जावे। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि 200 खिलाड़ियों की पत्रावली आज भी लंबित है। खिलाड़ी एक साल से चक्कर काट रहे हैं। खिलाड़ियों की समस्याओं का तुरंत प्रभाव से निवारण किया जावे। सीएमओ की नोटिंग को पूरी तरह से घुमा दिया गया है।

उपखण्ड क्षेत्र मनोहर थाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में खेल मैदान उपलब्ध है। परंतु ब्लॉक के किसी भी स्कूल में खेल स्टेडियम नहीं है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, समरोल, सरेड़ी तथा चंडीपुर में स्टेडियम बनाया जा सकता है।

अब मैं महिला एवं बाल विकास की बात करता हूं। परियोजना मनोहर थाना में लम्बे समय से सीडीपीओ का पद रिक्त है, इससे विभागीय कार्य प्रभावित होता है। परियोजना मनोहर थाना में 5 सेक्टर हैं, जिनमें एक महिला पर्यवेक्षक है। चार महिला पर्यवेक्षक के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण विभागीय योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। महिला पर्यवेक्षक नहीं होने की वजह से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण भलीभांति प्रकार से नहीं हो पाता है। अकलेरा में 14 किराये के भवनों में आंगनबाड़ी चल रही हैं, जबकि 46 विद्यालय के भवन में आंगनबाड़ी चल रही हैं और 18 सामुदायिक भवनों में आंगनबाड़ी चल रही हैं, इसलिए नये भवन की स्वीकृति दी जावे।

भवन निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए हरिपुरा, जावर, ताजपुरिया, सैदखेडी, सरेडी, खूरी, जूनापानी, सेमलाबय, मनोहर थाना पट्टी, रवासा और गोड़ाखेड़ा, नये आंगनबाड़ी भवन दिये जावे। जीर्ण-शीर्ण भवन इतने हैं कि वे अभी गिरने के कगार पर है। पाटलियालोडान, बांसखेडीलोडान, पचोला, बासोदा, बोरखेड़ीलोडान, काजल्या, पथरया, घाटोली, सरड़ा, बावड़ीखेड़ा, बिलोनिया भवनों में आंगनबाड़ी चल रही है। इनको नवीन भवन बनाकर चलवाया जाए। कभी-भी हादसा हो सकता है। बाल विकास परियोजना कार्यालय संचालन हेतु भवन की आवयश्कता है। पौष्टिक भोजन में क्वालिटी और क्वांटिटी की मात्रा बढ़ाई जावे। गर्भवती व धात्री महिलाओं को उच्च क्वालिटी का भोजन दिया जाए। लम्बे समय से रिक्त चल रहे

अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों को भर जावे। उपनिदेशक का पद काफी लम्बे समय से रिक्त चल रहा है। कार्यकर्ता व सहायिका के पद स्वीकृत हैं, 39 पद रिक्त चल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में आबादी बढ़ने के कारण नगर पालिका अकलेरा में 20 नये व ग्रामीण क्षेत्र में 50 केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है। भामाशाहों के भरोसे ही ये आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं।

उद्योगों की जहां तक बात है, कच्चे धागे की मिल, कोटड़ा जागीर अकलेरा जो कि लम्बे समय से बंद पड़ी है, इसको सरकार तुरंत प्रभाव से चालू करवाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उद्योग स्थापित होने से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन रुकेगा। उपखण्ड क्षेत्र मनोहर थाना में रीको नहीं है। कहीं पर भी किसी प्रकार के उद्योग नहीं चल रहे हैं। उपखण्ड क्षेत्र मनोहर थाना के ग्राम लाडपुरा बलराम पटवार हलका कोलूखेड़ी माल्यान के आराजी खसरा संख्या 305 रकबा 13.7917 हैक्टेयर किस्म चरागाह तथा खसरा संख्या 307 रकबा 3.1565 किस्म चरागाह कुल किता तुकी 16.9482 हैक्टेयर में नया रीको क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है। पहले भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी। आज तक जमीन आवंटन नहीं हुई है। मेरे मनोहर थाना क्षेत्र में लोग पलायन करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपको भी मालूम है आपके क्षेत्र में मेरे मनोहर थाना के कितने मजदूर आते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 65 ग्राम पंचायतों में से 40 ग्राम पंचायतें पठारी क्षेत्र पर है, वह वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई के साधन न होने के कारण, पानी की कमी न होने के कारण उनको बाहर पलायन करना पड़ता है। अगर छोटे-मोटे उद्योग स्थापित हो जाए और क्षेत्र में रीको द्वारा कुटीर उद्योगों, बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए तो वहां पलायन रुक सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की मेन समस्या पलायन है। वहां का मुख्य उद्देश्य यह है कि पलायन अगर रुक जाएगा तो उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से यही निवेदन करता हूं कि वहां उद्योग स्थापित किए जाए ताकि पलायन रुक सके। जय हिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रोहित।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, सभापति महोदय। मंत्री जी, मैं जितने भी पाइंट आज आपको रेज कर रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस समझ कर ये पाइंट मैं रेज नहीं कर रहा। मेरा बड़ा इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक रूख है। मैं आपसे सिर्फ इतना-सा कहना चाह रहा हूं, let us not make RIICO, a land selling agency. आप मुझे एक चीज बता दें, पूरे जयपुर जिले में और मैं ये चेलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी आदमी राजस्थान का एक टाइनी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जयपुर जिले में नहीं लगा सकता,because of the land prices.

Ans/Rtm 15.50 2o 23.07.2024

हमारा सिस्टम क्या है कि हम लैंड ऑक्शन करते हैं। हम अंडरस्टेंड करते हैं कि आपने लैंड परचेज की है, रीको की कॉस्टिंग है, रीको को लैंड बेचनी पड़ती है। बट कुछ सिस्टम अपने का अपनाना पड़ेगा, कुछ लैंड जो रीको के आपके इण्डस्ट्रियल एरियाज बनते हैं, कुछ लैंड उसमें से हम ऑक्शन करे, कुछ गरीब तबक़े के, पिछड़ी जाति के, एससी के जो उद्योग लगाना चाहते हैं, कुछ को अपन अलॉट भी कर सकते हैं, यह पिछली बार हमने इंडस्ट्रियल नीति में डाला भी था। मैं कहता हूं कि आप इसमें एक राइडर लगा दीजिए कि जब तक आप इसको दस साल नहीं चलाओगे, आप इसको बेच नहीं पाओगे। अगर सिक इंडस्ट्री है, as RIICO, you can take back the land. आप अपने पास लैंड वापस ले लीजिए। जिससे कोई भी लैंड माफिया आकर उस लैंड को नहीं ले। जो अभी तक होता आया है, इतने सालों से होता आया है। यह अपने को कुछ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं यह चेलेंज से कहता हूं कि थोड़े दिन बाद आप कोई एमएसएमई भी जयपुर ज़िले में नहीं लगा पाएंगे, इतनी लैंड प्राइसेस यहां पर है।

दूसरी चीज। आपकी एक नीति है, एक एसएसओ आईडी जनरेट होती है, जिससे रीको अपने चार्जेज लेती है। मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि, due to lack of staff. स्टाफ आपका करता नहीं है। हम लोग खुद आपके सर्विस चार्जेज जमा करना चाहते हैं। बट, आपके रीको में एसएसओ आईडी, क्योंकि वह रीको वाले बनाते हैं, हमें 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है, for which we are paying interest and, for no fault of ours. हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। आपके बाबू वहां पर एसएसओ आईडी जनरेट नहीं करते। बाबूओं की इतनी चलती है कि एसएसओ आईडी जनरेट नहीं होती, उससे हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे।

आपने एक और चीज यहां कर दी, क्या हम एक्चुअली चाहते हैं कि इंडस्ट्री नहीं आए राजस्थान में। आपने अभी क्या कहा, अंडरग्राउण्ड वॉटर दिया। आप यदि उसमें डालोंगे तो आपको जाकर अंडरग्राउण्ड वॉटर वालों से एनओसी लेनी पड़ेगी, तब आप करोंगे। जब आप रीको का एरिया का डवलप करते हो,आज आपने बगरू डवलप कर रखा है, आप जरा पता कर लो कि पानी आता है क्या। गंदगी के लिए वहां कोई सिस्टम है क्या, पता कर लो। उसके लिए हम आपको सब सर्विस चार्जेज दे रहे हैं। ना गंदगी उठाने वाला, ना पानी देने वाला।

आपने फिर एक राइडर और लगा दिया। फायर की एनओसी लेने के लिए आपने सब इंडस्ट्रीज को बाध्य कर दिया कि फायर की एनओसी लो। आज के दिन आपको एक फायर एनओसी लेने के लिए कम से कम 6 से 7 लाख रुपये चाहिए। फिर आपने इंलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंडस्ट्रीज के लिए कर रखी है, उससे आपका पूरा राजस्थान सब्सिडाइज होता है। Our electricity tariff is one of the highest in the Country. How will industries survive here? क्या अपन लोग नहीं चाहते कि इंडस्ट्री सरवाइव करे। आपको बैठ कर इस पर मनन करना पड़ेगा कि क्या किया जाए।

आपकी रिप्स है। आपने रिप्स बनाई और रिप्स बनाने में पिछली सरकार ने इतनी मेहनत की, इतना दिखाया, ढाक के तीन पात क्या हुआ। 4-4 क्वाटर से रिप्स का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। आपने यह कहा कि एमएसएमई में हम दस करोड़ रुपये तक जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको देंगे। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरा बिजनेस बढ़ा, मैंने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और ले ली। जब बिजनेस बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल मुझे चाहिएगी ही चाहिएगी। Without working capital, I cannot survive. अब आपका उद्योग विभाग क्या कहता है कि दस करोड़ से ऊपर इंवेस्टमेंट हो गया, इसलिए हम आपको इंटरेस्ट सब्सिड़ी नहीं देंगे। अरे भाई, जब मैंने आपका प्रोजेक्ट डाला था, तब मेरी दस करोड़ की कॉस्ट थी। If I have been able to increase my business, यदि मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपको मुझे पुराना पैसा तो देना पड़ेगा और नया पैसा भी देना पड़ेगा। दस करोड़ तक तो आप मुझे पैसा देंगे। How can you stop this? आप पुरानी चीजों को नये परिप्रेक्ष्य में कैसे ले सकते हो। प्रोस्पेक्टिवली आप चीजों को कैसे कह सकते हो। रेट्रोस्पेट में जब मैंने पैसा लगाया है अपनी इंडस्ट्री में, जब मेरी इंडस्ट्री चली, मैंने आगे इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप उस पैसे को किस तरह से रोक सकते हो।

इसी तरह से जयपुर के जितने पुराने, उद्योग विभाग ने यहां इंडस्ट्रियल एरियाज डवलप किए थे, उनका आज का स्टेटस क्या है। ना तो आप उसमे डवलपमेंट करते हो, क्योंकि आपको हैंडओवर हो गए, रीको को and, RICCO is not able to do this. Because, इतने सारे कोर्ट कैसेज फंसे हुए हैं। तो इसमें अच्छे खासे एक एएजी को लगाइये, जिससे यह प्रॉब्लम सॉल्व हो। प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही है, किस तरीके से आदमी करेगा, आप बताइये।

मुख्य मंत्री वाला, इंटरेस्ट सब्सिडी वाला मुद्दा है, यह पूरे राजस्थान का मुद्दा है। जिन-जिन ने इंडस्ट्री लगाई है, उनको इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिल रही। Let s forget Interest Subsidy. सिर्फ राजस्थान में है इंटरेस्ट सब्सिडी और कहीं नहीं है। आप गुजरात देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, let us come up with a new Industrial Policy and say, we will not give you any Interest Subsidy. इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं देंगे, हम आपको देंगे तो कैपिटल सब्सिडी देंगे। आज आप कैपिटल सब्सिडी देते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम चालू की है, आप उस तरीके से सब्सिडी देते हो, यहां लोगों की लाइन लग जाएगी इंडस्ट्री लगाने के लिए। आपको देनी चाहिए कैपिटल सब्सिडी । हम लोग क्या करते हैं बैठे हुए है एयरकंडीशन ऑफिस में, without even going into reality. कट, कॉपी, पेस्ट किया और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दी। आपने इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई फीडबैक लिया क्या,आज तक नहीं लिया। बजट में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई फीडबैक लिया क्या कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ नहीं होता है। सक्सेवल गवर्नमेंट से किसी ने कुछ नहीं किया। I can challenge it, कि किसी ने कुछ किया हो तो।

उस दिन स्पीकर साहब ने क्या कहा कि प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, रिसाइकलिंग बैग को यूज करो। भई क्यो? Can you avoid plastic? आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हो? पूरे वर्ल्ड में आप प्लास्टिक अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, recycle of plastic industry, करनी पड़ेगी। जब तक आप प्लास्टिक को रिसाइकलिंग नहीं करोंगे, आप प्लास्टिक को अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। जूट का कितना मैन्युफेक्चरिंग है, क्या आप रोजमर्रा की जिंदगी में जूट बैग, क्या कपड़े के बैग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हो, इम्पॉसिबल है। कहां करेंगे। डस्टबीन में जब कचरा डालना होता है तो कचरे में रोज जूट के बैग डालोंगे क्या। You can t put it. Please, focus on recycling of plastic. मंत्री महोदय, यह सजेशंस मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह सजेशंस हैं जो पूरे वेस्ट में भी है। आज वेस्ट क्या कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है जो प्लास्टिक, मैन्युफैक्चरिंग... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सर, पांच मिनट और लूंगा, प्लीज।

श्री सभापतिः जो आपका समय है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इन्द्रा जी वाला टाइम मुझे दे दें। जो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक है, यदि हम रिसाइकल नहीं करेंगे तो हम पूरे राजस्थान में कचरे के ढेर लगा देंगे।

मेरा एक सजेशन और था। मेरी कांस्टीटयूएंसी का है। लास्ट टाइम मुझे रीको इंडस्ट्रियल एरिया राजाखेड़ा के लिए मिला। मैं आपके एमडी से मिल लिया, तीन-चार बार इनसे मीटिंग कर ली, लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वहां प्रोवाइड करा दी, गवर्नमेंट आफ राजस्थान की लैंड है, जो फ्री। बट, उसमें काफी खाँचें बने हुए हैं जिनको समतलीकरण करना पड़ेगा। मेरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वह यूपी से बिलकुल लगा हुआ है। 15 किलोमीटर पर यूपी लगती है। Taj Trapezium (TTZ) की वजह से इस वक्त धोलपुर शहर- Rajakhera can become an Industrial Hub for Pharmaceutical Industry. धौलपुर में, लास्ट दो साल के कांग्रेस राज में कम से कम 100 Pharmaceutical Units.

मैंने उस दिन भी आपके एमडी साहब को कहा था कि मैं चेलेंज करता हूं कि आप इस इंडस्ट्रियल एरिया को बना दो, आपकी एक लैंड नहीं बचेगी, if you want to auction it, you will be ready to auction. क्योंकि यूपी में इतना बुरा हाल है, ease of doing business है ही नहीं। वहां कोई आपको नहीं पूछता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को कलक्टर से मिलने के लिए पांच महीने लग जाते हैं। हमारे यहां इतना बुरा हाल नहीं है। We are much better off. बुरा है पर, we are much better off. मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि राजाखेड़ा को रीको इंडस्ट्रियल एरिया दी है, यह red tapism का शिकार नहीं हो, यही मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, शीघ्र समाप्त करे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपसे एक रिक्वेस्ट और है। आपने आरएफसी बना रखी है। आपने 100 करोड़ रुपये दिए, it s a sick unit. हम 100 करोड़ रुपये में क्या करेंगे। आप पर एम्प्लाई अगर काउंट करोंगे कि कितना बिजनिस पर एम्प्लाई आता है तो मेरे ख्याल से पांच लाख रुपये का भी नहीं आता है, जबकि एनबीएफसी कोई भी अपन चलाते हैं, you need per employee business of at least 5 to 6 crore of rupees. You need to put money, if you really want RFC to run. Otherwise, don t even waste this 100 crore. There is no point wasting this 100 crore. They will only go for salaries, nothing else! क्योंकि आरएफसी से अब कोई लोन नहीं लेना चाह रहा। As compare to commercial banks, आप लोन बहुत महंगा देते हो, as compare to commercial banks.

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): दो सैकण्ड और। रीको में आपके कई बैड लोन्स है, मैं चाहता हूं कि आप बजट में अनाउंस कराओ, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आओ। रीको में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की बहुत बड़ी जरूरत है। जब तक आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम नहीं लेकर आएंगे,क्या करेंगे।

VPS-RTM-23.07.2024-16.00-2p

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): और एक चीज और जिससे कि राजस्थान के लोग मर रहे हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब, यह आपको करना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक में कोई सिस्टम नहीं है, जहां मर्जी आती है वहां पर गार्बेज डाल देते हैं, लेड का कंटेंट लोगों में हो रहा है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है, आपके खुद के माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है तो मैं आपसे यह विनती करता हूं कि आदमियों को आपको जीवित रखना है तो हिंदुस्तान जिंक के ऊपर एक्शन लें, जिससे कि आप और हम मिलकर राजस्थान को एक सुंदर राजस्थान बना सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जब से मुझे विधायक बनकर इस पवित्र सदन में आने का मौका मिला है तो यह तीसरा बजट मैंने देखा है और वाकई में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भजन लालजी की सरकार को कि उनके नेतृत्व में जिस तरीके का बजट पेश हुआ है, जिस

तरीके के संकल्प लिये गये हैं कि 350 खरब रुपये की अर्थव्यवस्था हम इस राजस्थान को बनाएंगे। हम बनाएंगे, क्योंकि इस राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को हमारे मोदीजी की गारंटी पर भरोसा है, हमारे संकल्प पत्र पर भरोसा है और हमारे दृढ़ निश्चय, हमारी सरकार की कार्य-शैली पर भरोसा है।

इस सदन के अन्दर अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं द्वारा बहुत सारी बातें रखी गयी हैं। किशनपोल से आने वाले माननीय विधायक, हिंडोली से और अभी-अभी राजाखेड़ा से भी पधारे हुए माननीय विधायकों ने अपनी-अपनी बात रखी और इस तरीके से उन्होंने यह संवेदना जारी की। रीको में रोजगार के लिए अलग-अलग बातें कही गईं कि हमें रोजगार के लिए ऐसा करना चाहिए, रीको में इस तरीके से सुधार करना चाहिए। पिछले पांच साल से जब बेरोजगारी भत्ते की बात हुई थी, जब युवाओं को रोजगार की बात हुई थी, जब हम लोग चिल्ला-चिल्ला कर इस सदन में यह बोल रहे थे कि आप जो भी कार्य करें, वह युवाओं के लिए करें, उनके रोजगार के लिए बात करें और जब यहां पर एक बड़ी बात कही गयी थी कि एम.ओ.यू. हमने इतने करोड़ के साइन करे, शायद 1500 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. साइन हुए थे और उस समय से आज तक इंवेस्टमेंट नहीं आया है। सॉलिड वेस्टेज पर काम नहीं हुआ तो ये बारबार अब सजेशंस दे रहे हैं। हम तो काम करके दिखाएंगे, यह भारतीय जनता पार्टी का ही संकल्प पत्र है जिसको बारबार ये घोषणा पत्र बोल रहे हैं। घोषणा तो हम करते नहीं, हम संकल्प लेते हैं और इस संकल्प पत्र के 45 प्रतिशत कार्य ऑलरेडी हो चुके हैं, यह है भजन लालजी की सरकार और यह है उनका दृढ़ निश्चय। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से अनुदान की मांग पर चर्चा थी, घोषणा पत्र पर यह चर्चा नहीं थी लेकिन बारबार हमारे संकल्प पत्र की बात इस सदन में की जाती है इसलिए मेरा भी कर्तव्य था कि मैं इस बात को जरूर कहूं।

जिस तरीके का बजट हर वर्ग को लेकर पेश किया गया है, वाकई में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो हमने छोड़ा हो लेकिन क्योंकि हम उद्योग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, यह एक गम्भीर समस्या है। मैं कुछ सजेशन अपनी तरफ से रखना चाहूंगी।

रोजगार और आई.टी.आई. कॉलेजेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजेज, इन सबको यह कह सकते हैं कि यह एक तरह से माला है जिसमें ये सब पिरोये हुए हैं। उद्योग की बात करते हैं तो जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, माननीय सभापति महोदय, राजसमन्द मार्बल इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ी हमारे यहां पर मार्बल को लेकर समस्याएं भी होती है और यह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। सबसे पहले तो मैं यह धन्यवाद देना चाहूंगी मंत्री महोदय को उन्होंने हमारे यहां पर मार्बल मंडी बनाने की सौगात दी है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और तहे-दिल से राजसमन्द के मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद लेकिन मार्बल मंडी के साथ-साथ यहां पर मार्बल के प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। मार्बल की मूर्तियों से लेकर, मार्बल की डाइनिंग टेबल से लेकर मार्बल के अलग-अलग आर्ट्स के आइटम्स, मैं

आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगी कि ऐसे एक्सपोर्ट मेले लगाये जाये राजसमन्द के अन्दर जिससे यहां के सारे स्टोन इंडस्ट्री वालों को यह मौका मिले, यह एक प्लेटफार्म मिले जिसके ऊपर वे अपने प्रोडक्ट्स को रख सके और पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश के अन्दर भी अलग-अलग जगह इनका एक्सपोर्ट और बढ़ सके।

माननीय सभापति महोदय, मार्बल अभी जिस तरीके की मंदी में है और कोरोना के बाद से ही अभी तक भी मार्बल इंडस्ट्री उस मंदी से उबर नहीं पायी है, लोन के इंटरेस्ट रेट को भी देने में बहुत समस्या और तकलीफ आती है तो उनको प्रमोट करने के लिए अगर ऐसे कुछ स्टेप्स लिये जाएंगे तो यह हमारे यहां की मार्बल मंडी के साथ-साथ एक बहुत बड़ी सौगात हमें आपके द्वारा मिलेगी।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको सभापति महोदय के माध्यम से एक बात और रखना चाहूंगी और अलग-अलग विधायकों ने भी इस बात का कन्सर्न रखा है कि रोजगार लोकल लेवल पर होना चाहिए। आप लोग यह जो पॉलिसी लेकर आये हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट- वन प्रोडेक्ट, उसकी भी मैं सराहना करती हूं लेकिन उसके साथ-साथ जो उद्योग आप उसके आस-पास डवलप करेंगे, उसमें जो रोजगार है, वहां पर भी लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाये, यह हम सबकी, हर विधायक की एक बहुत बड़ी समस्या है।

पलायन राजसमन्द में ही नहीं, हर जगह पर हो रहा है। हर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विधायक यह बात जरूर कहेंगे कि पलायन की समस्या हम लोग देखते हैं और झेलते हैं और उन बच्चों के मां-बाप हमारे सामने आते हैं, माननीय सभापति महोदय, रोते हुए वे कहते हैं प्लीज, हमारे बच्चे को यहीं कहीं नौकरी दिलवा दो, यह हमारा इकलौता बच्चा है तो हमारे पास उनको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं इसलिए चाहे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो या चाहे कोई भी बड़ी यूनिट हो वहां पर आप सुनिश्चित करिये कि जो रोजगार है वह करीबन 70 से 75 प्रतिशत रोजगार वहां के लोकल लोगों को मिले, उनके लिए अलग-अलग ट्रेनिंग सेंटर्स बने, जिससे कि वे यह नहीं कह सके कि इनको काम नहीं आता है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगी कि यह वह ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, जहां पर इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर से, अफ्रीका के बहुत लोग यहां पर काम करते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग के अन्दर काम करते हैं और हमारे लोगों को यह कहकर नकार दिया जाता है कि नहीं, इनके पास ट्रेनिंग प्रोपर नहीं है तो आप ट्रेनिंग करवाइये। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी आज, भारतीय कहीं पर भी जाता है तो वह अपना नाम कमाता है। नासा तक अगर हम पहुंच सकते हैं तो ऐसी कोई कमी नहीं किसी भारतीय में कि वह यहां पर काम नहीं कर सकता लेकिन ट्रेनिंग की जो कमी है, उस ट्रेनिंग की कमी को पूरी करते हुए मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि ऐसे उद्योगों को आप पाबंद करें कि वे ट्रेनिंग भी करवाये और ट्रेनिंग देने के बाद में 75 परसेंट टू 80 परसेंट रोजगार वहां के लोकल लोगों को, वहां के आस-पास के क्षेत्र के लोगों को, वहां के इफेक्टेड लोगों को दिया जाये, यह मेरी आपसे एक मांग है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा रीको द्वारा कुरज में रीको क्षेत्र बनाया गया है। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, यह समस्या रीको के द्वारा हमारे यहां पर भी है कि लैंड अलॉटमेंट हुए कुरज में एक लम्बा समय हो गया है लेकिन आज तक भी एक भी इंडस्ट्री वहां पर नहीं आयी है। कहीं न कहीं हमें अपनी पॉलिसी में वापस देखकर उसको करेक्ट करने की जरूरत है कि क्यों नहीं यह इंडस्ट्री हमारे यहां पर आ रही है? राजसमन्द बहुत अच्छे से हाईवे से कनेक्टेड है, बड़ी सिटीज से कनेक्टेड है, कहीं न कहीं पानी, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट सिस्टम, इन सिस्टम्स को अगर हम और डवलप करेंगे तो हम इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से लेकर आ सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मोरबी गुजरात के अन्दर एक बहुत बड़ा टाइल्स का हब बन चुका है। राजसमन्द में ऐसी कोई कमी नहीं है। गैस पाइप लाइन का भी काम चालू हो गया है तो मैं यह चाहूंगी कि उस गैस पाइप लाइन के काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये और राजसमन्द तक वह गैस पाइप लाइन चालू की जाये ताकि टाइल्स इंडस्ट्री का डवलपमेंट यहां पर हो सके। रॉ-मैटीरियल राजसमन्द के आस-पास की बहुत जगहों से जाता है, राजसमन्द से भी जाता है तो यहीं पर टाइल्स इंडस्ट्री बन जाये तो यह पूरे राजस्थान में एक अलग तरीके की नई पहचान बना सकेगा राजसमन्द और राजस्थान में भी उसी तरीके का एक्सपोर्ट और हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, रोजगार के उत्थान के लिए जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, युवाओं को जिस तरह से आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक कॉलेजेज इतने एजुकेशन देने के लिए, स्किल्ड डवलपमेंट करने के लिए बनाये गये हैं लेकिन आज भी अगर हमारे यहां पर मैं स्टोन इंडस्ट्री या गैंगसा एसोसिएशन से बात करती हूं तो वे कहते हैं कि हमको स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती है। वे यह कहते हैं कि हमारे पास तो स्किल्ड लेबर की कमी है तो कहीं न कहीं यह जो गैप है यानी, उन कॉलेजेज में वह प्राथमिकता से स्किल डवलपमेंट की कोशिश की जाये जिससे रोजगार यहां के लोकल लोगों को मिल सके। आर्गेनाइज्ड वे में इन युवाओं को रोजगार के लिए प्रमुखता से उनकी आसपास की चीजों को लेकर, उनके आसपास के एरियाज को लेकर अगर हम उनको ट्रेनिंग दें तो उससे इनका भी गैप कम होगा और कहीं न कहीं रोजगार की जो समस्या है, उससे भी हम कुछ निदान पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट और वन स्पॉट पॉलिसी लेकर आये हैं उसका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं। राजसमन्द, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं, वहां पर एथलेटिक्स, भले ही खेलों में रनिंग की बात की जाये, भले ही कुश्ती की बात की जाये तो बहुत सारे खिलाड़ी नेशनल और स्टेट लेवल पर भागीदारी रखते हैं और खिताब भी जीतकर आते हैं लेकिन कहीं न कहीं आज भी ट्रेनिंग के लिए कमी है। चार हजार रुपये भत्ते की बात आपने जो इस बजट में रखी है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहती हूं लेकिन फिर भी भले ही सी.एस.आर. फंड के माध्यम से हो या भले ही आसपास के भामाशाहों के माध्यम से इन

बच्चों को स्पेशल चीजों की जो कि बहुत महंगे आते हैं, रनिंग शूज जो कि 12 हजार, 13 हजार, 15 हजार रुपये से नीचे नहीं आते हैं, इनके प्रोटीन सप्लीमेंट्स की हमारे पास बात आती है कि मैम, इन सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं।

SSY/RTM/23.07.2024/16:10/2q

Because they all are very expensive, आप खुद इस बात को जानते हैं कि खेल में ये सारी चीजें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे अभी 2 मिनट और लगेंगे। अभी महिला बाल विकास पर भी मुझे बोलना है।

श्री सभापति: शीघ्र समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उसमें भी आप जरूर से दिखवायें कि उसको हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं और इन लोगों को इन सप्लीमेंट्स को और इन बेसिक नेसेसिटिज को हम प्रोवाइड करा सकते हैं।

मेरे राजसमन्द के बारे में भी मैं यह मांग रखना चाहूंगी कि ब्लॉक स्तर पर आप इस तरीके के एथलेटिक्स को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए सेंटर्स बनायें ताकि यहां पर और बच्चों को मोटिवेशन मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, भजन लाल जी की सरकार जब से बनी है, सबसे पहले तो मैं फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए तृतीय श्रेणी में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। यही नहीं, 15 लाख लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है, जब हम ग्रामीण क्षेत्र की औरतों के बीच में, कुछ-कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां पर महिलाएं आज भी घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। उन महिलाओं के लिए समूह इतने लाभकारी हैं और वह खुद कहती हैं कि आप हमें इन समूहों के द्वारा, हम घर बैठे किस तरीके से रोजगार कर सकते हैं, किस तरीके से स्वावलंबी हो सकते हैं? उसके लिए यह जो आपने स्कीम्स बनाई हैं, इसका हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन फिर भी कामकाजी महिलाओं की कुछ-कुछ समस्याएं हैं। वूमन हॉस्टल्स, आज भी बहुत से शहरों में नहीं है। मेरे राजसमन्द में ही मैं चाहूंगी कि एक वर्किंग वूमन हॉस्टल मिले। ताकि यहां पर जो महिलाएं गांव से आती हैं शहर में काम करने के लिए, उनको एक सुविधा मिले। उनको कम दरों में, कम रेट में वहां पर रुकने की एक अच्छी जगह मिले। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी।

आंगनबाड़ी की समस्या यहां पर हर सदस्य को है। मैं 2 मिनट और लूंगी।

श्री सभापति: विराजिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): और बाकी का सब मैं टेबल करना चाहूंगी। आंगनबाड़ी के अन्दर जिस तरीके के इश्युज हो रहे हैं, जो वहां के केन्द्रों के हालात हैं, उसके

अन्दर कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाये कि भले ही 50 परसेंट स्टेट दे और 50 परसेंट हम एमएलए लेड से दे सकें, लेकिन उन आंगनबाड़ी केन्द्रों को सही करना बहुत जरूरी है। यही नहीं, उनके नवीनीकरण के साथ-साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी हैं, उनके रिटायरमेंट के प्लान की बात हमारे सामने बैठे सदस्यों ने भी की, मैं भी कहूंगी कि आशा सहयोगिनी अपना पूरा जीवन हमारे लिए आंगनबाड़ी में देती हैं। लेकिन इनके रिटायरमेंट के लिए अभी तक नहीं सोचा। उसमें भी हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है।

आंगनबाड़ी केन्द्र, डीएमएफटी फंड के द्वारा भी हर जिले में सरकार के द्वारा यह तय कर दिया जाये कि 25 आंगनबाड़ी हम हर साल सही करेंगे तो आंगनबाड़ियों की समस्याएं दूर हो जायेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक लास्ट पाइंट कहते हुए मैं अपने सारे विषय, मांगों को टेबल करना चाहूंगी।

शहरों में प्रमुख जगहों पर आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। वहां पर डे केयर सेंटर्स भी बनाये जा सकते हैं। उन डे केयर सेंटर्स से यह होगा कि जो कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को रखना चाहती हैं, वह उधर रख सकती हैं। उन बच्चों की भी अच्छी तरह से पोषाहार की व्यवस्था हो सकेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी मांग टेबल करना चाहूंगी।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती अनिता जाटव।

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 32 महिला और बाल विकास पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरी विधान सभा हिन्डौन के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरिटी की करीब 40 प्रतिशत महिलाएं विधवा हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि इनके जीवन यापन के लिए अलग से व्यवस्था की जाये तथा उनको रोजगार देने के लिये संसाधन उपलब्ध कराये जायें।

सभापति महोदय, बजट के बिन्दु संख्या 91 में आपने लखपति दीदी योजना का जिक्र किया था। मैं चाहती हूं कि इन विधवा महिलाओं को भी लखपति दीदी योजना में भी लाया जाये। इन महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के अन्दर लाकर रोजगार दिया जाये।

सभापति महोदय, मेरी विधान सभा हिन्डौन में आये दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, दिन दहाड़े लूटपाट, मारपीट होती रहती है। पुलिस प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था खराब है। बार-बार पुलिस प्रशासन को कहने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने पुलिस गश्त लगाने का आग्रह भी किया था। लेकिन आज तक हिण्डौन में पुलिस गश्त की व्यवस्था नहीं की गई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य

चौराहे, बाजारों में पुलिस गश्त की स्थाई व्यवस्था कराई जाये। महिलाओं की सुरक्षा हेतु बयाना रोड चुंगी नाका, हिण्डौन शहर पर एक पुलिस चौकी की आवश्यकता है। चुंगी नाका नंबर 5 बयाना रोड पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने शराब का ठेका चल रहा है। जिसे वहां से हटवाने के लिए मैं पहले भी आपको अवगत करा चुकी हूं। आपके द्वारा महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। निवेदन है कि बयाना रोड चुंगी नाका 5 पर शराब के ठेके को वहां से हटाने एवं एक स्थाई चौकी लगाने की कृपा करें। हिण्डौन के सभी चौराहों पर एवं बाजारों में पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाये। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मार्केट में महिलाएं बहुत दूर-दूर से आती हैं। वहां उनके लिए शौचालय की व्यवस्था भी की जाये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री गुरवीर सिंह जी।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आज आपने हमें मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज मेरे से पहले बहुत ही सार्थक चर्चा दोनों तरफ से हुई। जितने भी सदस्य बोले उन्होंने आज बिना दलगत राजनीति के बहुत अच्छी बातें सदन के सामने रखी। यह भारत युवाओं का देश है। इसमें युवाओं की जो आबादी है वह 65 परसेंट है जिनकी उम्र आज 35 साल से कम है। किसी पार्टी में हो सकता है कि युवा नेता 50 से ऊपर के हों, पर आज 65 परसेंट जिस देश की आबादी 35 से नीचे है, तो निश्चित तौर पर यह हमारी डयुटी बनती है कि चाहे वह राजस्थान की सरकार हो, केन्द्र की सरकार हो, कि हम युवाओं को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। हम उनके लिए क्या भविष्य बनाना चाहते हैं। यह देश किस ओर अग्रसर हो। यह चिंता हमारी हर सरकार को होनी चाहिए।

हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो इनिशिएटिव्ज हैं, जो युवाओं के लिए उन्होंने फिट इंडिया, खेलो इंडिया के माध्यम से जो योजनाएं लेकर आये, उनका असर आज हमें देश भर में देखने को मिल रहा है। सरकार के गठन के बाद पहला विभाग स्किल डवलपमेंट का बना। आप सब लोग समझदार हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। लगातार स्किल डवलपमेंट के अवसर पैदा हुए। आज जिस तरीके से अनएम्पलायमेंट रेट पिछले 20 साल का कंपेयर करें तो डे बाई डे डिक्रीज हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिर भी चुनौती बनी हुई है। लेकिन पिछले 20 साल के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो हमने इसको काफी हद तक चुनौती को स्वीकार किया और उसका फायदा हमें मिला है।

मुझे खुशी है कि जो बजट आज युवाओं के लिए दिया गया है, जो युवा नीति बनाई गयी है, इसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी बधाई के पात्र है। आज उन्होंने युवाओं की चिंता की। युवाओं के बारे में सोचा और दिल खोलकर उनके बजट में जिस तरीके से दुगुना बजट दिया गया, मैं उसके लिए उनकी जितनी सराहना करुं वह कम है।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो चाहे डिविजनल हैड क्वार्टर पर 50-50 करोड़ के स्पोर्ट्स कॉलेजेज हो, इसका निश्चित तौर पर राजस्थान के युवाओं को फायदा मिलेगा। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के नाम पर, कोई स्पोर्ट्स हो, इंडस्ट्री हो, आज हम सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। जितनी भी पॉलिसिज बनी हैं, वह मेट्रो सिटी ऑरियेन्टेशन से बनी हैं। सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा ध्यान यूनिवर्सिटीज हों, स्पोर्ट्स हों, सब फैसेलिटिज राजधानियों तक सीमित रह गयीं। जिला हैडक्वार्टर, तहसील हैडक्वार्टर और हमारी सरकार ने पंचायत हैड क्वार्टर तक पहुंचने का संकल्प आज इस बजट में लिया है। यह बहुत स्वागत योग्य है।

Spp/Rtm/23.07.2024/16.20/3a

स्पोर्टर्स लाइफ इंश्योरेंस की बजट में घोषणा की गयी है कि इंटरनेशनल मेडलिस्ट विनर्स को दिया जायेगा। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से स्पोटर्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी नेशनल प्लेयर्स को भी, जो गेम विनर्स हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को इसका फायदा मिले। आज जो नेशनल, स्टेट प्लेयर्स हैं, उनकी डाइट की चिंता पहले भी की। हमारे मंत्रीजी खुद स्पोटर्स से जुड़े हुए हैं और इन्होंने देश का नाम रोशन पूरी दुनिया में किया है। स्पोटर्स पर्सन की जो जरूरतें हैं, अभी हमारे गंगानगर से एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा टूटे हुए जूते लेकर उसने नेशनल रिकार्ड को मीट किया, उसके बाद सारा शहर जगा और उसकी डाइट और जूतों की चिंता की। मैं ऐसी बहुत सी चीजें हैं, वे बच्चे कोचेज पर निर्भर हैं, वे एकेडमीज पर निर्भर हैं। जिन बच्चों में टेलेंट है, आज सरकार बहुत से पैसे खर्च कर रही है, कोई सड़क छोटी या बड़ी बन जायेगी, पर उन बच्चों का हमें ध्यान रखना चाहिये। उनकी डाइट का, उनकी फैसेलिटीज का, आज हमारा यह फर्ज बनता है।

आपने ओपन जिम प्ले ग्राउंड्स की आपने बात कही। मुझे एक शंका है कि 10 हजार पापुलेशन वाला बैरियर आप तोड़कर उसको सभी पंचायत मुख्यालय पर कर दीजिये ताकि हर युवा को मौका मिले। 10 हजार की आबादी वाले गांव पंचायतें बहुत कम हैं। ज्यादा से ज्यादा पंचायतें इसमें जुड़ पायें। आपको अगर पंचायतों में फण्ड देने का इश्यू है, तो निजी तौर पर मैं मेरी पर्सनल राय आपको बताता हूं। पहले मेरे दादाजी विधायक रहे तब भी हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बॉलीबाल के ग्राउण्ड और ट्रैक्स बनाने का काम किया। आज भी हमें MLA लेड पर जितना भी पैसा मिलेगा, वह ज्यादा से ज्यादा युवाओं के काम आये, यह हमारा टार्गेट हमने लिया है। सरपंचों की मांगें इंटरलॉकिंग टाइल्स दे दीजिये, वह अपनी कमाई की सोचते हैं। मेरा यह मानना है कि हम स्पोटर्स के ऊपर, युवाओं के ऊपर MLA ,MP लेड का कोई रेशो सरकार सैट कर दे, जिससे कि हम उसको वहां पर युटिलाइज कर सकें। हमारी सरकार ने बजट में सादुलशहर को स्टेडियम और माडर्न फैसेलिटीज डवलप करने की घोषणा की है। 2013 से लेकर 2018 तक जब हम सरकार में थे, वसुन्धरा राजे जी की सरकार में हमने उस टाइम काम किया। उससे पूर्ववर्ती सरकार ने वहां कॉलोनियां काटने के लिये

आरक्षित कर दी थी। दो-तीन साल तक उसके पीछे पड़े और वह जगह ग्राउण्ड के लिये आरक्षित की। पांच साल बीत जाने के बाद भी एक पैसा भी वहां नहीं लगा। आज हमारी सरकार ने पहले बजट में वहां पर सिंथेटिक ट्रेक और इनके लिये जो प्रस्ताव हमने भेजे हैं, हमारे मंत्रीजी उनको मंजूरी देंगे। ऐसी आशा मैं आपसे करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, लालगढ़ गांव का मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि हमारा लालगढ़ गंगानगर जिले का सबसे बड़ा गांव है। पूरे राजस्थान का एकमात्र गांव होगा जिसमें इंटरनेशनल स्तर के 32 खिलाड़ी हैण्डबॉल के दिये हैं। इसमें नेशनल के 125 खिलाड़ी दिये हैं और इस गांव ने अकेले लालगढ़ गांव के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वह 60 इस गांव के युवाओं ने जीते हैं और महाराणा प्रताप अवार्ड पर्टीकूलर एक गांव से आये हैं। हमारी पिछली सरकार ने लालगढ़ में हैण्डबॉल एकेडमी बनायी, कांग्रेस की सरकार ने आते ही, इनका कोई कुर्सी बचाने के चक्कर में किसी का वोट चाहिये होगा, वह हैण्डबॉल की एकेडमी उठाकर जैसलमेर पटक दी। वहां पर न तो खिलाड़ी हैं, हमें जैसलमेर से एतराज नहीं हैं, पर आप हमारे लालगढ़ को दुबारा एकेडमी मिले। मैंने इसके विषय में एक क्वेश्चन भी लगाया था। आज भी बजट उसका लालगढ़ एकेडमी के नाम से बोल रहा है, पर हमें एक पैसे का भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। उसी गांव का आज से पांच दिन पहले, जयपुर में जो अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर हैण्डबॉल का टूर्नामेंट हुआ, वह जो कैप्टन इंडियन टीम को लीड कर रहा था जसप्रीत सिंह, वह भी हमारे लालगढ़ गांव का है। मंत्री महोदय, आप दुबारा कृपा करें और आज जो सरकार ने जो सेन्टर 10 10 जिलों को दिये हैं, यह गंगानगर जिला पाकिस्तान और पंजाब की सीमा पर है। पंजाब वह प्रदेश है जिन्होंने सदियों से जितने भी इस देश पर आक्रमण हुए हैं, उसको अगर सबसे ज्यादा अपनी छाती पर किसी ने झेले हैं, तो वह पंजाब है। आपके पड़ोसी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर होने की नाते ड्रोन के माध्यम से वहां नशा गिराते हैं और वहां हीरोइन, चिट्टा और न जाने क्या-क्या नाम से नशे बिक रहे हैं। मां-बाप चिंता में है। नौजवान पीढ़ी विदेशी ताकतों के हत्थे चढ़कर आज वह ड्रग माफिया, नारकोटिक्स का जो भय है, वहां पर पूरा बिजनैस चल रहा है। उसकी जो टर्न ओवर आंकी गयी है, वह तकरीबन 17 से 18 हजार करोड़ की है। हमें उन युवाओं को पटरी पर लाना है और उसके लिये मैंने प्रधान मंत्रीजी से निवेदन किया, पर्सनली एक बार बोलने का मौका मिला। हमने चिट्ठी लिखी और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पहले क्वार्टर में इस पर एक्शन लिया है। चाहे आज एण्टी नारकोटिक्स स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे डि-एडिक्शन सेंटर हो, यह जो मुहिम हमने गंगानगर में छेड़ी, जिस दिन मैं विधायक बना सादुलशहर की जनता की कृपा से, अभी तक पिछले 6 महीनों में 260 NDPS के केस दर्ज हो गये और करोड़ों की स्मैक और चिट्टा, जो नौजवानों की जिन्दगी लील रहा था, आज उनके ऊपर केस किये हैं। 11 फर्जी नशा केन्द्र चलाने वालों को जेलों की सलाखों में बन्द कर दिया है। चार सेक्रेटरी सेंटर्स को बन्द कर दिया है। मेडिकल स्टोर्स की जांच हो रही है। मैं इसके लिये सरकार का और प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। इनकी कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी अपने एम एल एज

को बचाकर रखना था। 11-11 सेंटर्स एक मंडी में चलाना और नौजवानों को नशे की भेंट चढ़ाना, इन्होंने नौजवानों के साथ उन पर कुठाराघात किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं खेल मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्पोटर्स क्लब को आप मान्यता दे दीजिये। उसके आप नियम-कायदे बना लीजिये, पर उनको हम डायरेक्ट फैसेलिटी दे सकें। किसी गांव में आर्चरी के प्लेयर हैं, किसी गांव में हॉकी के प्लयेर हैं, कहीं कबड्डी के मैट की जरूरत है, कहीं जेवेलियन थ्रो और उनके स्टिक की जरूरत है, इसके लिये मैं आपसे मांग करूंगा। लेबर वेलफेयर सेस में जो स्कीम्स मिलती थी, करोड़ों रुपये का फण्ड वहां पडा है और उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप उद्योग मंत्री होने के नाम इसके लिये सुचारू रूप से काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही स्टूडेण्ट्स कौंसिल के जो इलेक्शन है, दोनों पार्टियों और पूरे सदन में बहुत से सदस्य वह उस प्राइमरी स्कूल, जो पॉलिटिक्स का है, वह उस इंस्टीट्यूशन से निकलकर आये हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दुबारा आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में उस टेलेंट को निखारिये, जो हमारे इस सदन में आयेगा, पार्लियामेंट में जायेगा। उनके चुनाव कराइये ताकि इस सदन को नये नेता मिलें। इस समाज को नई आवाज उठाने वाले नेता मिलें। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा, इंडस्ट्री पर बोलूंगा।

हम देहाती इलाके से आते हैं पर हमारी भी कुछ छोटी-छोटी मांगें हैं क्योंकि जितनी भी सरकारें आती हैं, इनका कोई न कोई पता नहीं क्या लालच रहता है, यह सारा का सारा फण्ड मैट्रो सिटीज को ही देना चाहते हैं। आज हमारी सरकार ने एक पहल की है। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के नाम से जो पहले की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। आपने एक्सपोर्ट हब बनाने की बात कही है। नोर्थ ईस्ट में अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो पूरे नोर्थ-ईस्ट आज एक्सपोर्ट का हब बन गया है। आर्गनिक फार्मिंग को उन्होंने अडाप्ट किया और देश-दुनिया में छा गये हैं। आप हर जिले को कोई न कोई प्रोडक्ट दीजिये। उनको मार्केटिंग का, उनको स्टोरेज का, उनको प्रमोशन का एक पोर्टल के माध्यम से आप मदद करिये। उद्योग विभाग के कर्मचारी ए.सी. लगाकर नहीं बैठें और दुनिया की मार्केट को तलाशें कि क्या मार्केट में चल रहा है। हमें टार्गेट मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिये कि हमें जरूरत कहां है। ऐसे ही हमें उसको, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा देना है तो इन सब चीजों पर हमें पहल करनी होगी।

माननीय सभापति महोदय, लोकल फोर वोकल की प्रधान मंत्रीजी ने बात की। ईज ऑफ डूइंग बिजनैस की बात यहां हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनैस जब होगा, जब उनको एक ट्रांसपेरेंट हम पोर्टल बनायेंगे। मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो छोटी-छोटी नगरपालिकाएं हैं और आज इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे से पहले जीते हुए आपके विधायकों ने उनके सामने यह कंडीशन रख दी कि कांग्रेस का पटका पहनो तो MSME की परमिशन मिल जायेगी। यह दो साल तक धक्के खाते रहे। मैं उद्योग मंत्रालय

से विनती करता हूं आप हरेक टेबल का टाइम निश्चित कर दीजिये। अगर उसकी फाइल डिजर्व करती है तो सैंक्शन कर दीजिये और अगर नहीं करती है तो 15 दिन में उसको रिजेक्ट करके उसको रीजन के साथ बताइये। उसको नेताओं के और आफिसर्स के धक्के नहीं खाने पड़ें। उनके पीछे फाइलें और पैसे लेकर घूमना नहीं पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मेरी विनती है और मेरी आपसे मांग हैं गंगानगर को फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स देने का काम करिये। आज होर्टीकल्चर के नाम पर किन्नू, अमरूद, अनार राजस्थान में हो रहा है, इसका फायदा हम ले सकें। एथनॉल का फार्मास्युटिकल कम्पनी की अभी बात हुई। हिमाचल के छोटे-छोटे गांव, जिसमें बद्दी, नालागढ़, उत्तराखंड का कालाअम्ब, उन्होंने फार्मास्युटिकल कम्पनीज के लिये ऐसी घोषणा की, आज पूरे नोर्थ इंडिया की फार्मास्युटिकल कम्पनीज वहां पर ट्रांसफर हो गयी। हम राजस्थान में ऐसी पहले क्यों नहीं करते? हम राजस्थान के ऐसे चार-पांच शहर, हमारे पास जमीन की कमी नहीं है, हाईवेज की कमी नहीं, रेलवे की कमी नहीं है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये। आई टी इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मांग करता हूं पूरे सदन से, हम भी राजस्थान का हिस्सा है। पूरे शहरों में, हर संभाग में यूनिवर्सिटीज हैं। आज 75 साल के बाद भी गंगानगर-हनुमानगढ़ में, डिविजनल हैडक्वार्टर हमसे 250 किलोमीटर दूर है। मेरी सदन से मांग है कि 200 के 200 एम एल एज इस पर सहमत हों और गंगानगर-हनुमानगढ़ जिले को भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दी जाये, ताकि हमारे बच्चे भी विदेशों में जाने से हम रोक सकें। आज उनके मां-बाप चिंता में हैं। आज मां-बाप अपने बच्चों को फ्लाइट्स पर चढ़ाने के लिये जमीन बेचने और गिरवी रखने तक के लिये तैयार हैं।

MLS/RTM/23.07.2024/16:30/3b

हर कोई यह सोचता है कि मेरा बच्चा नशे से बच जाये। वे ऐसा क्या विदेशों में देख रहे हैं कि सब कोई अपना जी-जान लगाकर, अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर बाहर भेजना चाह रहे हैं? इन सब चीजों पर हमें चिन्ता करने की जरूरत है। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग की छोटी सी मांगें रखना चाहूंगा। पंजाब ने एक नयी पहल की है। पंजाब ने किन्नू पोषाहार में देना शुरू किया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि राजस्थान में तो अपार सम्भावनाएं हैं। हर जिले के पास अपना प्रॉडक्ट है। गंगानगर में किन्नू हो रहा है कहीं अमरूद हो रहा है, कहीं अनार हो रहा है, कहीं खजूर हो रहा है, आप लोकल किसानों को प्रोत्साहन दीजिये। जिस जिले में जो मौसमी फल हो रहे हैं, उन्हें पोषाहार में जोड़ा जाये।

मैं विनती करूंगा, हमारे सादुलशहर में महिला एवं बाल विकास विभाग की खुद की न तो कोई जगह है, न कार्यालय है। राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के पोषाहार वितरण का काम बीजेपी की सरकार में एसएसजी के माध्यम से होता था। पिछली सरकार ने उसे सैंट्रलाइज करके कुछ चन्द कम्पनियों को फायदा दे दिया। मान्यवर, लोकल लोगों को प्रोत्साहन

दीजिये, स्टार्टअप्स बनाइये। नये युवा आगे आएं, उनसे आप माल खरीदिये। युवाओं को नौकरी मिलेगी, उनकी जेब में चार पैसे जाएंगे। अच्छा अनाज सही समय पर मिले। आप सबने मुझे सुना, मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः डॉ. शिखा मील बराला।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का अवसर दिया।

''बालिका अहम् बालिका नव युग जनिता अहम् बालिका।
नाहमबला दुर्बला आदिशक्ति अहमम्बिका।।''

अर्थात् मैं एक लड़की हूं, आधुनिक समय की लड़की हूं। मैं कमजोर या शक्तिहीन नहीं हूं, मैं अम्बिका हूं, मैं ही आदि शक्ति हूं। बालिका सशक्तीकरण की दिशा में हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सैकंडरी स्कूल हो, यह सुनिश्चित किया था, परन्तु U-Dise के डेटा के अनुसार मात्र 66 परसेंट लड़कियां ही बारहवीं कक्षा में नामांकित हो पाती हैं। आज भी हर चार में से एक विवाह 18 साल से कम उम्र का हो रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्य मंत्री राजश्री योजना शुरू की गयी थी, पर किशोरियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। सरकार के बजट में राज्य की इस बड़ी चिन्ता से निपटने के लिए कोई भी तैयारी परिलक्षित नहीं हो पाती।

महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाओं में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। हालांकि, हर पंचायत स्तर पर 'साथिन' नियुक्त है, राज्य सरकार का यह साथिन कैडर अपने आप में अनूठा है, पूरे देश में अनूठा है, परन्तु कम मानदेय और सरकार की अनदेखी के चलते इनकी भूमिका स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से रिक्वेस्ट करूंगी कि सरकार इस दिशा में विचार करे।

हमारी सरकार ने ''उड़ान योजना'' शुरू की, जिसमें 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की हर महिला को फ्री सैनेटरी नैपकिंस दिये गये थे। खेद का विषय है कि इस सरकार में उड़ान योजना के सैनेटरी नैपकिंस ट्रकों में भर नोएडा के बाजारों में बिकने जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इसमें सरकार स्ट्रिक्टली संज्ञान ले, क्योंकि मैंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिला स्वास्थ्य के लिए। मैं चोमूं ही नहीं, पूरे राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात उठाऊंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनियों की मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाये। अभी जो बजट आया, उसमें जो उनका मानदेय बढ़ाया गया, वह नाकाफी है।

संविदाकर्मियों को हम नियमित करने की बात करते हैं, पर क्या सरकार इस दिशा में विचार रखती है कि ऐसा ही कुछ हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनियों के लिए करें, क्योंकि यही वे लोग हैं, जिनके जरिये सरकारी योजनाएं धरातल पर लागू हो पाती हैं। स्कूलों में एमडीएम में कुक कम हैल्पर, जो एक दिन में 50 से 75 बच्चों का खानी बनाती हैं, उनका मानदेय मात्र 2173 रुपये प्रतिमाह है। सरकार इसे भी बढ़ाने पर विचार करे।

अगर हम युवा एवं खेल मामलों की बात करें तो राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार

ने इस तरह के काम किये कि युवा शिक्षा, रोजगार और खेल, तीनों में ही आगे बढ़ सकें और उनका सर्वांगीण विकास हो। राज्य की 50 परसेंट से अधिक जनसंख्या युवाओं की है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि राजस्थान में देश की सबसे बड़ी बेरोजगार जनसंख्या है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों, दोनों में प्रयास किये। पेपर लीक पर 10 करोड़ रुपये जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा का कानून हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बनाया, परन्तु अगर हम केन्द्र सरकार की बात करें तो जो युवा हमें सुबह प्लेग्राउंड्स के ट्रैक्स पर, सड़कों पर दौड़ करते दिखते थे, आज उनके कैरिअर के साथ एक मजाक किया गया अग्निवीर योजना के नाम पर।

खेल मैदान हमने बनाये, पर वहां हम इंडोर स्टेडियम्स भी विकसित करें, क्योंकि इंडोर खेलों के लिए युवाओं के पास अपनी प्रतिभाओं को डवलप करने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार जरूर ग्रामीण खेल ओलम्पिक्स को यथावत जारी रखेगी। युवाओं के साथ ही, हम इंडस्ट्रीज की बात करें, रीको की बात करें तो चोमू के साथ शायद सारे राजस्थान में यही स्थिति है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स स्थानीय लोगों को रोजगार देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। एयर, वॉटर और हर तरह का प्रदूषण स्थानीय लोग सहन करते हैं, पर उन्हें वहां रोजगार नहीं मिल पाता। कोई नियम ऐसा बनाया जाये कि कम से कम 60 या 65 परसेंट नौकरियां हमारे स्थानीय सक्षम युवाओं और महिलाओं को दी जाएं।

वेस्ट डिस्पोजल के नियमों को स्ट्रिक्टली इम्पोज किये जाने की दिशा में कार्य होना चाहिये। रीको में बहुत सारे लोग यही एक चिन्ता व्यक्त करते हैं कि पहले जो 90 परसेंट लैंड अलॉटमेंट के थ्रू दी जाती थी और 10 परसेंट ऑक्शन की जाती थी, पहले अलॉटमेंट ''फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व बेसिस'' पर किया जाता था। आज भी एमपी में एक रुपये की लीज पर लैंड दी जा रही है। पंजाब में अलॉटमेंट के थ्रू दी जा रही है। क्या राजस्थान में रीको इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करना चाहता? सरकार कम से कम इस पर अपने विचार रखे।

अगर हम ऑक्शन करते हैं तो जिन्हें इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने की कम जरूरत है, उन्हें ऑक्शन में लैंड मिलती है तो रीको में धीरे-धीरे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बन जायेगा। जिन लोगों को इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं करनी हैं, वे लोग दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को किराये पर अपनी लैंड देंगे। रीको एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और मेरे ख्याल से सरकार के लिए यह कमाई का साधन नहीं है, क्योंकि इनके पास जो 90 परसेंट लैंड होती है, वह तो गोचर या सिवायचक होती है। हमारा ध्येय इंडस्ट्रीज को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का होना चाहिये। ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'' की हम बात करते हैं, पर रीको में जिस तरह के अभी लैंड अलॉटमेंट के नियम हैं, उससे कहीं न कहीं हम फेल हो रहे हैं।

सरकार को इस पर अपने विचार रखने चाहिये। इंडस्ट्रीज के जो नियम हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनमें कुछ बदलाव करने चाहिये। सभापति महोदय, आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री सभापति: श्री जीवाराम चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, महिला एवं बाल विकास के बारे में आज सदन में चर्चा हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में तो महिला एवं बाल विकास की जो जमीन सरकार ने आवण्टित की थी, वह जमीन ही भू-माफियाओं ने छीन ली। मैं उसका रिकॉर्ड सदन को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सांचोर में महिला एवं बाल विकास विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने शहर सांचोर में जमीन का आवण्टन किया था, जिसका खसरा नं. 35-65/13-19 रकबा 0.12 हैक्टेयर। इस जमीन का जिला कलेक्टर जालोर के आदेश क्रं. 12-3-25 राजस्थान/37-1924/30 दिनांक 19.05.1997 के द्वारा बाल विकास परियोजना सांचोर के नाम 19.05.1997 को आवण्टन हुआ। सांचोर के श्रीमान् तहसीलदार के पत्र क्रं. 985 88 2024 दिनांक 10.07.2024 से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में खसरा नं. 35-65/13-19 रकबा 0.12 हैक्टेयर पर श्री खंगाराराम पुत्र श्री प्रभु राम जी का कब्जा है। उक्त सम्बन्ध में उचित विभागीय कार्रवाई की जायेगी, ऐसा माननीय तहसीलदार जी ने रिपोर्ट में लिखा है।

mkd/rtm/23.07.2024/16:40/3c

सभापति महोदय, इस प्रकार अगर सरकार की जमीनें भूमाफिया हड़प कर वहां बिल्डिंग, दुकानें, गोदाम बनाकर बैठ जाये और सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं करे तो यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि इस खसरे को, इस आवंटित भूमि को तुरन्त प्रभाव से खाली करवाकर महिला और बाल विकास परियोजना विभाग को सुपुर्द करे, ताकि इस विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए भवन बने। उस विभाग का हमारे वहां के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले।

सभापति महोदय, दूसरी बात हमारे राजस्थान में वर्तमान में उद्योग की नीति, ये हमारे अधिकारी महोदय एयर कंडीशनर में बैठकर बना रहे हैं। आज वर्तमान में व्यापार पूरे संसार में किस प्रकार से चल रहा है, उसकी इनको बिलकुल चिन्ता नहीं है। लोग कहां से कहां प्रोग्रेस करते जा रहे हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गुजरात में कच्छ का रण कई सालों से खाली पडा था, बंजर पडा था। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 15 साल के लिए उस एरिये को टैक्स एग्जेम्प्टेड किया। आज वहां पर हजारों फैक्ट्रियां लग गईं और करोड़ो-अरबों का रेवेन्यू गुजरात गवर्नमेंट को मिल रहा है। आज अगर तीन सौ, पांच सौ करोड़ का कोई प्रोजेक्ट हो तो गुजरात को दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, इतना रेवेन्यू वहां से आ रहा है।

आज हम रीको से जो ऋण ले रहे हैं, वर्तमान ऋण का जो बाजार का भाव है, वर्तमान में रीको हमसे लेता है, उतने ऊंचे ऋण लेकर कोई व्यापारी व्यापार में सफल नहीं हो सकता

है।

सभापति महोदय, हमारे ये अधिकारी इतने चक्कर कटवाते हैं कि आदमी बेचारा थककर भाग जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में दाड़िम की खूब खेती होती है, हजारों टन दाड़िम की पैदावार होती है। लोग महाराष्ट्र, कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा से, दूर-दूर से वहां आकर खरीद कर ले जा रहे हैं।

मेरा माननीय उद्योग मंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां पर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट डालें, ताकि वहां के हमारे किसानों को उसका पूरा लाभ मिले। हमारा किसान समृद्ध होगा तो ही हमारा राजस्थान समृद्ध होगा। हमारा किसान समृद्ध होगा तो ही हमारा भारत समृद्ध होगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अरूण चौधरी।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 युवा मामले एवं खेल विभाग, मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास विभाग और मांग संख्या 56 उद्योग विभाग पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, आज का युवा कल का भविष्य है। इस अवधारणा को वास्तविक रूप में चरितार्थ किया तो हमारे मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी की सरकार ने किया है। साथ ही, महिलाओं और व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, आज इस सदन में अनुदान की मांगे रखी गई हैं, उसके लिए मैं पूरी कैबिनेट का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

परम आदरणीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और उनके कैबिनेट ने इन तीनों मांगों को विश्वास में लेकर जिस प्रकार इस बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

युवा मामले और खेल विभाग के तहत हमारे मंत्री महोदय जी को मैं अपनी ओर से एक निवेदन करता हूं कि मेरा पचपदरा विधान सभा क्षेत्र एक सुदूर जिले के तहत है। यहां पर जब भी कोई बजट आवंटित होता है तो वह यहां से बाड़मेर बॉर्डर तक पहुंचते-पहुंचते बीच में ही खत्म हो जाता है। मेरा निवेदन है कि यदि हमेशा हमको मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि यह भजनलाल जी की सरकार है और यह भजनलाल जी सरकार हमको आश्वासन नहीं, बिलकुल यह बजट धरातल पर उतरेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं एक मांग रखना चाहता हूं कि मेरे बालोतरा में स्टेडियम आधा अधूरा पड़ा है। मेरा बालोतरा जिला स्तर का है और जिला स्तर पर एक स्टेडियम होना चाहिए और एक इंडोर स्टेडियम की भी मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पास जमीन तो बहुत है। हमारे यहां स्टेडियम तो क्या, हम तो कई स्टेडियम बना सकते है, लेकिन बस जरूरत है तो आपके बजट घोषणा करने की। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इसे आप बजट घोषणा में जरूर करवायें। मेरे

बालोतरा शहर के अन्दर स्टेडियम तो है ही, इसके अलावा खेल की जो भी क्रीड़ा परिषद वगैरह हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिला स्तर का होने के कारण यहां क्रीड़ा परिषद का कार्यालय खोलने की व्यवस्था करावें।

माननीय सभापति महोदय, मैं भजनलाल जी शर्मा और हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय और उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बजट के अन्दर मेरे बालोतरा शहर के आसपास में पेट्रोलियम हब की घोषणा की है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

साथ ही, इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी आधारित इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाने की घोषणा की। साथ ही, मंत्री महोदय आपने प्रदेश में टेक्सटाइल से सम्बन्धित उद्योगों को ऊंचाई पर ले जाने हेतु गारमेंट और अपैरल पॉलिसी की घोषणा की है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमेशा राजस्थान के प्रवासियों के हित की बात करता हूं। जिस प्रकार आपने इस बजट के अन्दर पहली बार यह घोषणा की है कि जो इंवेस्टर्स समिट होंगी, उसके अन्दर हमारे राजस्थानी प्रवासियों की सहभागिता होगी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर रंगाई, छपाई के उद्योग हैं और रंगाई, छपाई के उद्योग होने के नाते वहां रीको के भी कार्यालय हैं। पहले भी हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि रीको के कार्यालय में जो बाबू होते हैं, उनकी रेड फीताशाही होती है, किसी भी एक कार्य को करने में सालों लगा देते हैं। यहां कई अधिकारी एवं मंत्री महोदय भी बैठे हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में रीको की जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए मंत्री महोदय आप तत्काल प्रभाव से एक कमेटी बनाकर उनको जल्दी से जल्दी दूर करायें। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि रीको में जिस प्रकार से कई इंडस्ट्रियां होती हैं। वहां कई बार किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। मेरे यहां पर भी औद्योगिकीकरण होने के कारण, मुझे भी इस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। जब किसी श्रमिक की मृत्यु होती है तो वहां जो श्रमिक एसोसिएशन वगैरह होती हैं, वे लेन-देन के लिए उस डेड बॉडी को लेकर बैठ जाती है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक इस तरह का फंड बनायें, जिसके अन्दर उन फैक्ट्रियों की भी सहभागिता हो और रीको की भी सहभागिता हो। इस प्रकार करके, यदि किसी परिवार से किसी की मृत्यु होती है और वह फैक्ट्री वाला उसको पांच लाख या दस लाख देता है तो उससे पार नहीं पड़ती है। मैं चाहता हूं कि कोई अच्छा-सा, हैंडसम अमाउंट उसको दिया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा।

साथ ही, जैसा कि हमारे पूर्व कई सदस्यों ने भी बताया कि फायर एनओसी की भी समस्या है। उस पर भी आप सही ढंग से कोई न कोई घोषणा करें ताकि हर व्यापारी का

इसमें हित हो सके। साथ ही, जिस प्रकार इंडिया स्टार्ट-अप हुआ, उसी प्रकार राजस्थान स्टार्ट-अप के नाम से भी कोई घोषणा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सपने नहीं हम हकीकत को बुनते हैं, तभी तो हम लोग मोदी जी को चुनते हैं। इसी बात को लेकर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा राजस्थान आने वाले समय में उद्योग में पुनः अग्रणी श्रेणी में गिना जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं महिला एवं बाल विकास विभाग की भी अपनी ओर से मांग रखता हूं कि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो कि सरकार के छोटे-छोटे स्तर पर काम करती हैं, आशा सहयोगिनी कार्य करती हैं, इनका मानदेय बढ़ाने की सभी सदस्यों ने मांग रखी है। वह बढ़ाया भी गया है। मैं मानता हूं कि इनको अगर हम सम्मान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

माननीय मंत्री महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप तो हमेशा, डबल इंजन की सरकार कहें तो इसमें गलत नहीं है।

Bhs/Rtm/23.7.24/16.50/3d

क्योंकि आपने तो दिल्ली का भी राज किया है और राजस्थान का भी राज किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है चाहे ये सामने विपक्षी लोग हमारी मजाक उड़ाते हो, उस डबल इंजन की सरकार को वास्तव में चरितार्थ करके कि राजस्थान के अन्दर डबल इंजन की सरकार किस तरह काम करती है और उद्योग को किस प्रकार बढ़ावा देती है ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें पूरा सहयोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 - युवा एवं खेल, मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास एवं मांग संख्या 56 - उद्योग के विषय में बोलने का मौका दिया, मैं आपको तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने खेल-कूद को लेकर एक बहुत ही बढ़िया योजना चलायी थी और गांवों में राजीव गांधी ओलम्पिक खेल खेले गए थे। अब वो राजीव गांधी ओलम्पिक खेल हर गांव और ढाणी के अन्दर, हर शहर के अन्दर छोटे-बड़े के अन्दर एक बूढा दादा अपने पोते के साथ खेल खेला। एक जवान युवा अपने दोस्त के साथ खेला, महिलाओं ने महिलाओं के साथ खेल खेला चाहे क्रिकेट हो, खो-खो हो, कबड्डी हो, इस तरह से हमारी सरकार ने खेल-कूद के सिलसिले में बहुत ऐतिहासिक अभियान चलाया था, जिसमें गांवों में एक बहुत ही बढ़िया भाईचारा बढ़ा था। लोगों में मेलमिलाप होता था, रात-रात भर तक ये खेल-कूद चलते थे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं बाल विकास जो आज सब्जेक्ट है उसके लिए भी हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जनाधार कार्ड बनाया और उस जनाधार

कार्ड में महिला को मुखिया बनाया गया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की थी पूर्ववर्ती सरकार ने और जिस तरह से मोदी जी कहते हैं 33 परसेंट आरक्षण की बात करते हैं कि महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण दिया जायेगा और आज देखो राजस्थान की विधान सभा में मात्र दो महिला मंत्री बनी है जो 33 परसेंट आरक्षण की बात करते हैं। यह महिलाओं के साथ एक छलावा हो रहा है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार में उद्योग मंत्री महिला थी जो पिछड़े वर्ग की थी श्रीमती शकुन्तला रावत, बाल विकास मंत्री महिला थी श्रीमती ममता भूपेश वह दलित परिवार से थी, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा थी जो अल्पसंख्यक समुदाय से थी और चीफ सेकेट्री भी महिला थी श्रीमती उषा शर्मा इस तरह से हमारी सरकार ने महिलाओं को पूरा महत्व दिया था।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि उड़ान योजना जिसमें पन्द्रह वर्ष की आयु से लेकर 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को फ्री सेनेटरी नेपकिन दिया जा रहा था और बड़े खेद की बात है कि यह सेनेटरी का सामान जो बचा हुआ था यह ट्रकों में भर कर नोएडा बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे जहां पुलिस ने उनको पकड़ा जो राज्य सरकार का सामान था। रोडवेज बसों के अन्दर भी तीस परसेंट छूट को बढ़ा कर पचास परसेंट हमारी सरकार ने किया था और सभी जो चिरंजीवी से जुड़ी हुई थी महिला मुखियाओं को एक करोड़ पैंतीस लाख स्मार्ट फोन माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी सरकार में दिया था और स्मार्ट फोन देने के बाद में वो स्मार्ट फोन आज जो गांव के गरीब के परिवार की जिन महिलाओं ने लिया, जिनके बच्चे इन्टरनेट से जुड़ रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, जयपुर आने-जाने का खर्चा नहीं था, आज स्मार्ट फोन का वो सहारा ले रहे हैं। जैसे ही सरकार बदली स्मार्ट फोन भी आप लोगों ने बन्द कर दिया और आगे कुछ इसके लिए आप लोगों की कोई योजना नहीं है कि स्मार्ट फोन दिया जायेगा कि नहीं दिया जायेगा। यह जो महिला की बात करते हैं आज महिलाओं की आपकी कोई ऐसी विकास योजना नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं क्योंकि खान का इस बार डिमाण्ड में नहीं आया है और मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र में माइनिंग का कार्य ज्यादा है और वह उद्योग से सम्बन्धित ही माइन्स का काम होता है क्योंकि इस बार आधे से ज्यादा विभागों की डिमाण्ड नहीं है जिसमें माइन्स भी नहीं है तो मैं उसमें आपको यही कहना चाहता हूं कि मकराना में जो रॉयल्टी का मामला है, आप खान विभाग को भेज दें, उद्योग से जुड़ा हुआ मामला है, मकराना में जो रॉयल्टी ली जाती है माल पर उसमें हमारे साथ दोहरा भेदभाव हो रहा है। एक तो सरकार रॉयल्टी भी लेती है और किराया भी हमारे से लेती है और दूसरी जगह रॉयल्टी जो होती है मकराना के अलावा वहां रॉयल्टी भी लेते हैं और किराया भी लेते हैं, लेकिन उसका किराया समायोजित किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, अभी जिस तरह से रॉयल्टी हमारे मकराना में ले रहे हैं

तैयार माल की 560 रुपये ले रहे हैं जबकि ब्लॉक की रॉयल्टी 558 रुपये है। पूरे प्रदेश में मकराना को छोड़ कर ब्लॉक पर रॉयल्टी लगती है और मकराना में तैयार माल की रॉयल्टी लगती है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए लेकिन सरकार की एक पुरानी कमेटी है तीस परसेंट वेस्टेज मान कर रॉयल्टी को लेने के लिए लेकिन तीस परसेंट मानने की बजाय 56 परसेंट वेस्टेज मान कर 200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो रॉयल्टी 558 रुपये वसूल किया जा रहा है और जो 30 परसेंट रॉयल्टी वेस्टेज है उसमें भी जिस तरह से बड़े ब्लॉक में कंडे निकलते हैं उस कंडे की रॉयल्टी 182 रुपये प्रति टन ले रहे हैं, पाउडर की रॉयल्टी 134 रुपये प्रति टन ले रहे हैं, चिप्स की रॉयल्टी 123 रुपये प्रति टन ले रहे हैं, और कलर कंडे की रॉयल्टी 39 रुपये प्रति टन ले रहे हैं तो यह रॉयल्टी हमारे जो ज्यादा ले रहे हैं इस रॉयल्टी का समाधान करा जाये, क्योंकि मकराना में रॉयल्टी ब्लॉक पर नहीं ली जा सकती। मकराना की खानें 3-4 सौ साल पुरानी खानें हैं उसका लीकेज जगह-जगह पर है और अन्य जगह रॉयल्टी, आप चाहे जैसे ले सकते हैं तो वहां तैयार माल पर रॉयल्टी मिलती है और वेस्टेज की भी रॉयल्टी ली जा रही है। एक बात यह है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात यह है, उद्योग के मामले में आपसे यह कहना चाहता हूं मकराना क्षेत्र में विश्व में उच्चस्तरीय मार्बल का खनन किया जाता है, जिस मार्बल से गढ़ाई, खुदाई, मन्दिर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है अतः मकराना क्षेत्र के कारीगरों को, दस्तकारों को मशीनरी एवं आधुनिक संसाधनों से प्रशिक्षण दिलाने की सख्त आवश्यकता है ताकि मकराने के दस्तकारों को, कारीगरों को दक्ष किया जा सके। दूसरी बात यह है कि मकराना में गढ़ाई के कौशल प्रशिक्षण हेतु आई.टी.आई. जैसी संस्थाओं के मार्फत विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाये।

तीसरा यह था कि मकराना में विश्वस्तरीय गढ़ाई का कार्य किया जाता है अतः एस.ई.जेड. की तर्ज पर मार्बल आर्थिक विकास क्षेत्र में निर्माण किया जाता है। मकराना में खनन के साथ-साथ वहां गढ़ाई का काम होता है वहां मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरीजाघरों का काम होता है जैसे राम मन्दिर बना, स्वर्ण मन्दिर बना, अमेरिका में मन्दिर बना, दुनिया में जहां कहीं मन्दिर बनता है मकराना के पत्थर से मन्दिर बनता है और मूर्ति तो वहां के पत्थर की ली जाती है, उनके कारीगरों के लिए आप स्पेशल योजना बनायें, ताकि वो लोग वहां पर उसके लिए ज्यादा उत्थान कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, चौथी बात यह है कि मकराना मार्बल में कैल्शियम की अधिकता होने की वजह से मकराना क्षेत्र में पेंट, सिरेमिक टाइल्स, टूथ पेस्ट, टेलकम पाउडर जैसी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती है, अतः इस प्रकार की इकाई के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए, जिससे इस क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 99 कैल्शियम जिस मार्बल में है वह मार्बल मकराना का है उसके बाद सारा दूसरा मार्बल है, चाहे वियतनाम का हो, इटली का हो जो भी हो वह बात अलग है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात यह थी उद्योग को लेकर कि हमारे मकराना विधान

सभा क्षेत्र में रीको कहीं पर भी अलॉटमेंट नहीं है तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मकराना में रीको अलॉटमेंट किया जाये ताकि वहां पर इंडस्ट्री और लग सकें और मकराना मार्बल में जो तैयार माल स्लेब, पाटिया, चिप्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत लगता है यह जीएसटी बहुत ही ज्यादा है। किशनगढ़ में पूरे मार्बल में 18 प्रतिशत है उसको 5 प्रतिशत लेकर आइये, क्योंकि मकराना की ज्यादातर इकाइयां एक करोड़ से कम टर्नओवर की है उसका स्लेब भले ही बनता है तो यह 18 प्रतिशत जो जीएसटी हो रहा है वह कम करें और मकराना के मार्बल के बन्द उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए पांच वर्षों के लिए ब्याज रहित ऋण दिया जाये। मकराना मार्बल उद्योग के लिए आर.एफ.सी. का लोन का ब्रांच ऑफिस खोला जाये। किसी समय मकराना में पहले आर.एफ.सी. का लोन ऑफिस था वो किशनगढ़ शिफ्ट हो गया।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों को आर.एफ.सी. का लोन लेने के लिए किशनगढ़ जाना पड़ता है तो वापस मकराना में आर.एफ.सी. का ऑफिस खोला जाये और मकराना में नयी इंडस्ट्री खोलने वाले को कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाये।

Kas/rtm/23.07.2024/17.00/3e

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खेल के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे मकराना क्षेत्र में किलरीनाड़ा में खेल स्टेडियम की हालत बहुत ही खराब है, उसमें कम से कम 50 लाख रुपये दिये जाये। ग्रामीण क्षेत्र में बाजोली, हुडिया, मोएड, गेलासर में खेल स्टेडियम की घोषणा करें, ताकि वहां के गांव के लोगों को खेल स्टेडियम का फायदा मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जसवंत जी।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मेरे बाड़ी विधान सभा क्षेत्र के रीको क्षेत्र बिजोली में रीको ऐरिया घोषित तो कर दिया, लेकिन इस ऐरिये में न तो रोड है, न पानी की व्यवस्था है और न ही बिजली की व्यवस्था है, इस कारण से वहां कोई इंडस्ट्री वाला आता नहीं है। जहां पत्थर का सबसे बड़ा व्यापार है, उसकी एक इंडस्ट्री भी उसमें नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस रीको क्षेत्र पर ध्यान दें। आज धोलपुर जिले का सबसे बड़ा उद्योग पत्थर व्यवसाय है, लेकिन आपकी डबल इंजन की सरकार का पत्थर व्यवसाय की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इससे हजारों परिवार पलते हैं, फिर भी कोई ध्यान नहीं है। सभापति महोदय, आज बाड़ी, बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पत्थर व्यवसाय है। दोनों ही विधान सभा क्षेत्र में वन क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वन क्षेत्र का डाइवर्जन करते हुए नई माइंस की लीज दी जाये, जिससे पत्थर व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। नई माइंस देने से सरकार को राजस्व

भी मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी 21 जुलाई, 2024 को अखबार में खबर छपी थी कि सरकार राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सैंक्चुअरी को कोटा शहर के विकास की बाधा बताकर डिनोटिफाई करना चाह रही है। हम भी चाहते हैं कि हमारे धोलपुर में बह रही चंबल नदी का कुछ भाग डिनोटिफाई कर दिया जाये, जिससे बजरी की लीज मिल सके, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल सके। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वहां बजरी के भंडार हैं। वहां कई बार पुलिस से बजरी वालों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अब तक 12 से ज्यादा नौजवान पुलिस की गोलियों द्वारा मारे गये। वहां घड़ियाल क्षेत्र के ऐरिये की नाप कराई जाये कि आखिर कितना ऐरिया घड़ियाल का है। उसके अलावा भी काफी चंबल रेता है। जैसे और जगह लीज हो रही है तो वहां भी लीज हो सकती है।

सभापति महोदय, क्रीडा परिषद की ओर से आयोजित ग्रामीण ओलंपिक खेल घोटाला हुआ था, जिसकी जांच करने के लिये जनवरी, 2024 में सदन में आश्वासन दिया था। उसका अब तक क्या हुआ, बताने का कष्ट करें। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री रामविलास (अनुपस्थित)। श्री ताराचन्द।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56, युवा मामले, महिला एवं बाल विकास एवं उद्योग पर बोलने का दिया। महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी व खेल मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया। पूर्व में 475 करोड़ का बजट था, उसको बढ़ा कर 950 करोड़ कर बजट कर दिया, इसके लिये मैं उनका बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय, युवाओं को ऊर्जावान बनाये रखने के साथ-साथ चरित्र निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास के लिये जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये और सकारात्मक सोच का विकास करने हेतु खेल जीवन में अत्यावश्यक है, खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है।

सभापति महोदय, श्री डूंगरगढ़ क़स्बा एक लाख से अधिक आबादी वाला क़स्बा है तथा 100 से अधिक गांवों का मुख्य केन्द्र है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों खिलाड़ी विभिन्न खेलों से राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होते हैं। क्षेत्र से बहुत से युवा खेलों के माध्यम से भारतीय सेना, पुलिस विभाग सहित विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित भी हुए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतना विकसित क्षेत्र होने के बावजूद आज भी श्रीडूंगरगढ़ क़स्बे में एक भी खेल स्टेडियम कि सुविधा नहीं है। खेल स्टेडियम व रनिंग ट्रेक के अभाव में बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ता है तथा बहुतों को प्रतिभावान होने के बावजूद अपने लक्ष्य से वंचित रहना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ कि श्रीडूंगरगढ़

विधानसभा क्षेत्र में सुविधाओं युक्त मल्टीपरपज स्पोर्ट स्टेडियम खोला जाए, ताकि क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को क्रिकेट, सॉफ्ट बॉल, फुटबाल, आदि खेलो को खेलने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है, जो मेरे क्षेत्र की बड़ी पूंजी है, लेकिन इन युवाओं के कल्याण के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ असत्य वादे किये और इनके कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यहां तक कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, उसका परिणाम क्षेत्र के युवाओं को भी भुगतना पड़ा। आज भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किस प्रकार से बेरोजगारी भत्ते के नाम पर गुमराह किया गया, ऐसे ठगे से महसूस करने वाले सैकड़ों युवा गांवों में प्रतिदिन पिछली सरकार को कोसते हैं।

सभापति महोदय, देश भर में जिस प्रकार अग्निवीर को लेकर युवाओ को गुमराह करने का काम किया है। उनकी हताशा और युवाओं को गुमराह करने के प्रयास को सबने देखा है। सच्चाई सबके सामने लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य दूरगामी है। देश के प्रत्येक युवा सेना के अनुशासन को जान कर विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कर एक अनुशासित देश का निर्माण कर सकें। जब देश का युवा अनुशासित हो जाएगा तो देश अपने आप समृद्धि के रास्ते पर चल पड़ेगा। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जब खड़ा होगा तो हमारे अनुशासित युवाओं की भी उसमें भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी।

सभापति महोदय, प्रदेश भर के स्कूल/महाविद्यालयों में अग्निवीर को लेकर भ्रांति दूर करने के लिए काउंसिलिंग कार्यालय खोले जाने चाहिए।

मेरे से पूर्व अभी हमारे गुरवीर सिंह जी नशे की हालत के बारे में बोल रहे थे। आज का युवा वर्ग काफी संख्या में नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है, उसको नशे से मुक्ति दिलाने का प्रयास भी किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, हमारे महापुरुषों के जीवन पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, विवेकानंद, आदि सभी किसी न किसी प्रकार की शारीरिक विद्या एवं कौशल के विशेषज्ञ थे। सभापति महोदय, प्राचीन भारत में खेलों की समृद्ध परंपरा रही है, जो कि हमारी संस्कृति और इतिहास को परिलक्षित करती है। हमारे पुराने खेल तो प्रायः लुल्प ही हो गये, जैसे गिल्ली-डंडा, पल्लकुंझी, चौपड़, पच्चीसी, कलानी-बेलानी, काला हाथी, सफेद हाथी, कांचा, आदि अनेकानेक प्राचीन भारतीय खेल अब लुप्त प्रायः हो गये हैं। कुश्ती तथा पहलवानी, यह तो सबसे पुराने खेल हैं। इनका इतिहास तो 4000 वर्ष पूर्व का है।

सभापति महोदय, समय का पहिया घूमता रहा, आज क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, मुक्केबाजी, मोटर स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल जैसे खेल लोकप्रिय होते गये और क्रिकेट तो सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। सभापति महोदय, राजस्थान में भी पूर्व में अनेकानेक प्रतिभाएं रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम पदक दिलाने वाले राजस्थान के महाराजा श्री करणी सिंह जी, जो हमारे बीकानेर के महाराजा थे, उन्होंने सबसे

पहले मेडल जीता था तो फिर आज हम क्यों पिछड़ रहे हैं?
msk/rtm/23.07.2024/1710/3f

यदि युवा खिलाडियों को पर्याप्त सुविधा और प्रशिक्षण मिलता है तो हमारे राज्य के खिलाड़ी पूर्व की भांति नित्य नये कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सभापति महोदय, आपसे अनुरोध है कि राजस्थान में खेलों को पाठ्यक्रम का आवश्यक रूप से हिस्सा बनाया जाना चाहिए। युवाओं में शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने से समाज से प्रतिभावान खिलाड़ी निकल कर आएंगे। साथ ही, युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु यथोचित पुरस्कार और सम्मान देना चाहिए। मान्यवर, खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और इसीलिए खेल भावना को शिक्षा के साथ विद्यार्थियों, युवाओं में संपुष्ट करने हेतु सरकार को भी आवश्यक प्रयास करने चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया का सपना साकार होगा ।

महोदय जी, अब मैं उद्योग पर आता हूं। उद्योग के बारे में हमारी स्थिति ऐसी है। सभापति महोदय, मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि हमारे क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए श्री डूंगरगढ़ में जमीन अधिग्रहण कर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र काटा जाए। महोदय, डूंगरगढ़ में रीको द्वारा आज से 45 वर्ष पूर्व छोटा-सा औद्योगिक क्षेत्र काटा गया था, जिस समय शहर की आबादी 15 हजार थी। अब हमारे शहर की आबादी एक लाख के लगभग हो गई है।

सभापति महोदय, अगर श्रीडूंगरगढ़ में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र आवंटित होता है तो यहां कृषि से संबंधित बड़ी तादाद में यूनिट्स लग सकती हैं, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में लगभग 30 हजार ट्यूबवैल हैं और मूंगफली की रोजाना सालाना 50 से 60 हजार बोरी आवक होती है। इसके अलावा अन्य कृषि उत्पादन चना, ग्वार, मोठ, सरसों आदि बहुत-सी एग्रीकल्चर फसलें आती हैं। सभापति महोदय, डूंगरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने के कारण यहां कृषि उत्पादन पास की अन्य कृषि मंडियों में विक्रय के लिए जाता हैं, जिसके कारण राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथ ही, किसानों को कृषि उत्पादन अन्य जगह ले जाने से समय की बर्बादी के अलावा अतिरिक्त आर्थिक व्यय भी उनको उठाना पड़ता है।

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ कृषि पर निर्भर क्षेत्र है और राज्य की अर्थव्यवस्था भी कृषि आधारित है। कृषि आधारित लघु उद्योग प्रदेश में रोजगार का बड़ा आधार हैं। सभापति महोदय, मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में कृषि आधारित लघु उद्योगों से जुड़े कौशल विकास संबंधित योजनाओं का केंद्र स्थापित किया जाये। साथ ही, कुछ आधुनिक प्रकल्पों जैसे ड्रोन प्रशिक्षण, नैनो यूरिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मोदी जी लेकर आये थे। लोगों को कहा भी कि खेतों के अन्दर नैनो यूरिया छिड़कनी चाहिए। उनका छिड़काव करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए ड्रोन प्रशिक्षण द्वारा छिड़काव,लखपति दीदी, सोलर से जुड़े प्रोजेक्ट आदि संभावनाओं को लेकर

कौशल विकास केंद्र के साथ संबंधित एनजीओ संस्थाओं पर कार्य किया जाना अपेक्षित है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): साथ ही, सोलर से जुड़े प्रोजेक्ट, वाहन रिपेयर आदि के कोर्स से युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर पाएंगे तथा इसमें अन्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की स्थिति में आयेंगे।

सभापति महोदय, 2022 में राजस्थान सरकार के राजस्थान माइन्स विभाग ने जानकारी दी कि श्री डूंगरगढ़ विधान सभा के लखासर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिनरल्स पोटाश के विपुल भण्डार खोजे गए हैं। यह सतह से 500 मीटर की गहराई पर है। सभापति जी, सरकार द्वारा इस पर काम करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, पोटश का उपयोग कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाली खाद बनाने के लिए किया जाता है। पोटश के खनन से भारत की बड़ी निर्माता कंपनियां इस क्षेत्र में कार्य कर सकेंगी, जिससे क्षेत्र के विकास के साथ साथ समृद्धि भी आएगी व युवाओं को रोजगार अवसर प्राप्त होंगे।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे डूंगरगढ़ में रीको द्वारा जमीन अवाप्त करके रीको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र काटा जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद, मांग संख्या 26- युवा और खेल पर बोलने का मुझे मौका दिया। पिछली सरकार में माननीय अशोक जी गहलोत ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत-सी स्कीमें चलायीं।

श्री सभापति: और नया क्या कर सकते हैं, आप यह बतायें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): और नया, आप यह करें कि जो उन्होंने खेल मैदान स्कूलों में काटने का काम किया था, वे बहुत-सी स्कूलों में कट गये, कुछ बाकी हैं। बहुत-से स्डेडियम उन्होंने स्वीकृत किये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी दो स्टेडियम स्वीकृत किये। एक बालाजी की धाम सालासर में, जिसका निर्माण तो शुरू हो गया और दूसरा, सुजानगढ़ शहर में एक स्टेडियम स्वीकृत किया था, जिसके डेढ़ करोड़ रुपये आ गये और अभी भी पीडब्ल्यूडी में पड़े हुए हैं। पूर्व में उसकी जमीन नहीं मिल पायी थी। दो-तीन महीने तलाश के बाद नहीं मिली तो सुजानगढ़ का भामाशाह सिंघवी परिवार आगे आया। उन्होंने उसके लिए जमीन उपलब्ध करवायी। उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से दान पत्र लिख कर विभाग को दे दिया कि आप इसमें स्टेडियम बनायें, कुछ भी करें। उसमें शर्त स्टेडियम की थी कि आप जल्द से जल्द स्टेडियम का निर्माण करें। पर राजस्व विभाग आज तक उस जमीन का नामान्तरण चढ़ाकर खेल विभाग को नहीं दे पाया है। उसमें कोई अड़चन, कुछ विवाद नहीं है। सिर्फ पहले यह बात आयी कि आचार संहिता लग गयी, इसलिए हम नहीं कर पाये। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी कामों पर रोक लगी हुई है। हालांकि नामान्तरण करने में और स्वीकृत काम में रोक नहीं थी, फिर भी उन्होंने करते-करते समय निकाला। उसके बाद लोक सभा चुनाव

की आचार संहिता में समय निकाल दिया। अब सारे हट चुके हैं, इसलिए उस जमीन का नामान्तरण खेल विभाग पर चढ़ाया जाये और पीडब्ल्यूडी को समर्पित कर दें, ताकि वहां पीडब्ल्यूडी स्टेडियम का निर्माण कर सके। उनके पास एक-डेढ़ साल से पिछले बजट का पैसा पड़ा हुआ है। ताकि युवा जो कि बहुत लंबे समय से स्टेडियम की मांग कर रहे थे, वह जल्द पूरी हो सके और उनको खेलों के लिए एक स्थान उपलब्ध हो सके, जिसकी वहां पर एक बहुत बड़ी कमी है।

एक दूसरा स्टेडियम सुजानगढ़ शहर में है, नयाबास में स्थित है, वह काफी पहले का है। उसमें सुविधाएं नाम मात्र की हैं जगह छोटी होने के कारण, अगर उसका भी विकास किया जाता है तो शहर के दूसरे हिस्से में, बच्चों के खेलने में और बहुत-से बड़े-बुजुर्ग सुबह-शाम वहां घूमने की गतिविधियों में काम में लेते हैं तो उनके यह काफी काम आ सकता है। वह स्टेडियम बहुत अच्छी जगह बनाया हुआ है। उससे भी बच्चों को खेलों में बहुत फायदा हो सकता है।

मैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की उद्योग विभाग की मांग सीधे ही रखता हूं। सुजानगढ़ शहर में करीब 40-42 साल में रीको एरिया काटा गया था और उद्यमियों को उस समय प्लॉट उपलब्ध कराये गये थे, पर उस समय आज से 40 साल पहले आबादी भी कम थी। उस क्षेत्र में उद्योगों का व्यवसाय नहीं था कि ज्यादा उद्यमी आ सकें, कर सकें, उस समय ज्यादा आवश्यकता भी नहीं थी। समय के साथ उद्योग-धंधे भी बढ़ रहे हैं, कारोबार भी बढ़ रहा है। आज के समय में उद्यमियों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है कि वे कहां उद्योग लगायें, उसके लिए जरूरी है कि नया एरिया काटा जाये और उस रीको के एरिये में विशेष तौर से दो ब्लॉक स्पेशिफाई किये जाएं। एक ब्लॉक तिरपाल उद्योग के लिए, क्योंकि हिन्दुस्तान की तिरपाल की सबसे बड़ी मंडी सुजागढ़ में है, जहां तिरपाल बनते हैं और पूरे देश में सप्लाई होते हैं। विशेष तौर से खेतों में डिग्गियों का जो तिरपाल बनता है, हर डिग्गी का जो तिरपाल आता है, वह सुजानगढ़ से बनकर जाता है। उसके लिए जरूरी है कि उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए रीको में उनका एक स्पेशिफाई एरिया बने, ताकि वहां पर वे अपने गोदाम बना सकें, वहां पर अपना कारोबार चला सके। क्योंकि डिग्गियों के तिरपाल के लिए उन्हें बड़ी-बड़ी जगहों की जरूरत पड़ती है, जब तक रीको का एरिया काटकर उनको प्लॉट उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक यह नहीं हो सकता।

दूसरा रंगाई-छपाई का बहुत बड़ा करोबार मेरे सुजानगढ़ में है जो वर्षों से चल रहा है, उनके लिए भी उस रीको में अलग स्पेशिफाई एरिया दिया जाये, जहां सिर्फ उन्हीं का कारोबार हो, क्योंकि उनके लिए पानी की दिक्कत रहती है। वह एरिया उनको काट दिया जाये तो उन उद्योगों को फायदा हो जाये, वे बढ़ सकें। राजस्व की भी बात है। सरकार को बहुत बड़ा राजस्व तिरपाल उद्योग से मिल रहा है, उसमें सरकार की और वृद्धि हो सके, उससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। एक स्पेशिफाई योजना, जो इस बजट में वोकल फोर लोकल की बात की है कि हर जिले में एक उद्योग को बढ़ावा दिया जाये, तो उसमें मैं आपके माध्यम से मंत्री जी

से मांग करूंगा कि चूरू के लिए उन्होंने कोई स्पेशिफाई नहीं लिखा है। यह जो तिरपाल उद्योग है, उसकी इंडिया की सबसे मंडी सुजानगढ़ में है।

mdp/rtm/23.07.2024/17:20/3g

उसको आप शामिल करें ताकि उद्योग को बढ़ावा मिले, राजस्व बढ़े। एक जिले का जो उत्पाद है, उसमें त्रिपाल उद्योग आता है। इससे किसानों को भी फायदा होता है, क्योंकि किसानों को भी बहुत बड़ी जरूरत त्रिपाल की होती है। अन्य इंडस्ट्रीज में भी जरूरी है। आपको वोकल फोर लोकल, जो आप लोगों ने बजट में अनाउंस किया है, उसमें इसको लेंगे तो फायदा होगा। बोलने का मौका दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द।

श्री सभापतिः रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय। अभी युवाओं की बात चल रही थी, खेलों की बात चल रही थी।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

राजस्थान जो भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा राज्य है। युवाओं की अगर मैं बात करूं, युवाओं के रोजगार की बात करूं तो पूरे देश में लगभग 8 से 9 प्रतिशत तक बेरोजगारी है, वहीं हमारे राजस्थान में वह बेरोजगारी दर 27 परसेंट है। आज के समय में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं हैं तो वह हमारे राजस्थान में। थोड़े समय पहले मेरे साथी विधायक साहब कह रहे थे कि जो युवा हैं, नशे की ओर जा रहे हैं। नशा कर रहे हैं। चिट्ठा फैल रहा है, स्मेक, पता नहीं क्या-क्या नशों के नाम ले रहे थे। साहब, उनको रोजगार तो दीजिए। सुबह हम लोग यहां पर 9 बजे आकर बैठते हैं, रात को 9 बजे तक निकलते हैं, नशा तो दूर खाने का ही पता नहीं चलता। आप अगर उनको रोजगार देंगे तो कोई नशा नहीं करेगा। रोजगार देने के लिए हमने क्या पॉलिसी बना रखी है? कोई यूथ पॉलिसी है क्या?

आपने अभी कहा कि हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैं स्वागत करता हूं। मैं टेबल बजाकर आपके इस फैसले का स्वागत करता हूं। परंतु 4 लाख युवाओं को रोजगार कैसे देंगे? वर्गीकरण किया आपने? आज के समय में हमारे यहां पर ढ़ाई करोड़ के आसपास, 18 साल से कम युवा है। 88 लाख तो पहले से ही बैठे हैं और आने वाले 5 साल में 70 लाख की एक भीड़ और तैयार हो जायेगी। डेढ़ करोड़ जो बेरोजगार होंगे, उन डेढ़ करोड़ में 4 लाख नौकरी, क्या यह ठीक है? कह्या करे के, साहब, ऊंट रे मुंह में जीरा हाली स्थिति हो जाय। हमें नये संसाधन डवलप करने पड़ेंगे, हर क्षेत्र में। उसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा।

मेरा निवेदन है कि यूथ पॉलिसी बनाई जाए। यूथ पॉलिसी पर हम सब मिलकर काम करते हैं। मैं तो प्रदेश की सरकार से, हमारे खेल मंत्री जी से, युवा मंत्री जी से निवेदन करना

चाहूंगा कि अगर यूथ पॉलिसी में अगर कोई समस्या आ रही है, यहां पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आप यह जिम्मेदारी हम पर छोड़े, आने वाले 7 दिन में यूथ पॉलिसी बनाकर आपके सामने रखेंगे। इस सदन के सामने रखेंगे, ये विश्वास के साथ कह रहा हूं।

अभी खेलों की बात हो रही थी। आज से ठीक तीन दिन बाद पेरिस में ओलंपिक गेम हो रहे हैं। पूरी दुनियाभर से 10 हजार 500 खिलाड़ी उस ओलंपिक में भाग लेंगे। साहब, देश के 117 खिलाड़ी वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन 117 में से हमारे राजस्थान के कितने हैं? राजस्थान के हैं मात्र 2 लोग। जो 2 लोग जा रहे हैं राजस्थान की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक रुपया उनके प्रशिक्षण के लिए नहीं लगाया। वह खुद के खर्चे से वहां तक पहुंचे हैं।

हम बात करते हैं कि हम खेलों में आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे आगे? मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक खेल परिषद, जो यहां पर खेल संचालन का काम करती है, उसके अन्दर कुल 41 रजिस्टर्ड गेम हैं। 50 जिले हैं, अगर एक जिले में 41 लोग लगाए जाएं तो लगभग 2050 के आसपास प्रशिक्षकों की हमें जरूरत है। बड़ा दुःख होता है कि 248 प्रशिक्षकों की स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन वहां पर 66 प्रशिक्षक ही लगाये हुए हैं। लगभग 182 पद खाली पड़े हैं। एक भी अपने पास कोच नहीं है। खेलों की बहुत गंभीर स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे रजत विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी साहब से, जो कि खेल मंत्री हैं, साहब, बिना द्रोणाचार्य के अर्जुन तैयार नहीं हो सकते।

मैं आज इस मौके पर सादुल स्पोर्टस की भी बात करूंगा। सादुल स्पोर्ट्स, जो एकमात्र आवासीय स्पोर्ट्स सेंटर है, आज वहां पर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। मेरा निवेदन है कि उन बच्चों की ओर भी ध्यान दें। उन खिलाडियों की ओर भी ध्यान दें। पिछले 16 साल से उन खिलाडियों को भोजन भत्ते के रूप में एक रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। 16 साल में महंगाई तो बढ़ गयी, परंतु आज भी उनका भोजन भत्ता वैसा का वैसा है। आप देखेंगे कि 50 डिग्री टेम्प्रेचर में भी वे खिलाड़ी, वे हमारे छोटो भाई, जो आने वाले समय में राजस्थान का, भारत का नाम रोशन करेंगे, वह एक पंखे के नीचे बैठे हैं। हम तो बड़े-बड़े एसी में बैठे हैं। उन खिलाडियों की बात कौन करेगा? वह बीकानेर जिला है, खेल मंत्री जी, वह आपका खुद का जिला है। मेरा निवेदन है कि उस सादुल स्पोर्ट्स की तरफ आप विशेष ध्यान दें।

साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि तमाम युवाओं के रोजगार के लिए आप नये संसाधन लाएं। मुझे समय दिया, इसके लिए सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।

श्री सभापतिः सुभाष जी।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): एक मिनट, सभापति महोदय।

श्री सभापतिः नहीं, सुभाष जी मील।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): एक मिनट साहब। मैं सदन के संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि जब मैं 2004 में स्पोर्टस का मिनिस्टर था।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नियमों में आना।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): बात तो सुनिए। बात तो सुन लीजिए।

श्री सभापति: आप मंत्री जी से मिल लेना।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सभापति जी, बात तो सुन लीजिए। राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ 2004 में, जब ओलंपिक के 100 साल हुए थे, उस समय इंडिया में एक ही मेडल आया था, वह आया था हमारा उस समय शार्ट गन में फ्लाइंग ट्रैप में, डबल ट्रैप में, वह राज्यवर्धन जी लाये थे। मैं सदन को कहूंगा जोरदार तालिया बजाकर इनका स्वागत करें।

श्री सभापति: आप लिख कर दे देना। सुभाष जी मील।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 युवा मामले एवं खेल, मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास और मांग संख्या 56 उद्योग के लिए आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, युवाओं की जहां बात आती है, युवाओं के रोजगार की बात आती है तो सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी शर्मा और हमारी सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं कि गंभीरता से युवाओं की समस्या पर अगर किसी ने गौर किया है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने किया है। सरकार बनते ही जो बजट आया, बजट में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गयी और इस साल के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की गयी, जो वास्तव में हमारे बेरोजगार युवाओं के जख्मों पर एक मरहम लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सर्वप्रथम युवा नीति, 2024 बनाने की घोषणा की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 10 लाख युवाओं को स्किल अपग्रेडेशन से 10 लाख रोजगारों के अवसर देने का बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज केन्द्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर 2 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन करके देश के 4.1 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर, कौशल का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को और उनकी सरकार को, केन्द्र सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जब हम रोज अख़बार पढ़ते थे तो युवाओं के रोज सपने टूटते थे। हर रोज खबर आती थी कि आज ये पेपर लीक हो गया, आज ये पेपर लीक हो गया। आज आप देखेंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद में सरकार ने युवाओं की चिंता की। उनके सपनों पर कुठाराघात करने वालों को, आज अख़बार में जब हम सुबह उठते हैं तो रोज एक खबर मिलती है कि आज इस पेपर लीक के आरोपी को पकड़ा, आज इस पेपर लीक के आरोपी को पकड़ा। आज इस चर्चा में आपके माध्यम से

सरकार से एक मांग जरूर करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक स्पष्ट नीति जरूर बनाई जाए।

Ans/rtm 17.30 3h 23.07.2024

चाहे केन्द्र सरकार का उपक्रम हो, चाहे राज्य सरकार का उपक्रम हो, चाहे प्राइवेट उपक्रम हो, जहां पर उद्योग लगा हुआ है वहाँ के 70 परसेंट स्थानीय युवाओं को उसमें रोजगार मिले, मेरी सरकार से ऐसी मांग है कि इसके बारे में एक स्पष्ट नीति बने, ताकि उन युवाओं को पलायन नहीं करना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे खंडेला में एक यूरेनियम प्लांट लगा है, जो पूरा बनकर तैयार हो गया, मेरी इस सदन के माध्यम से उनसे मांग है, वहां के जो भी कार्मिक होंगे, जिनको रोजगार दिया जाएगा, खंडेला के 70 परसेंट स्थानीय युवाओं को वह रोजगार दिया जाए। अन्य युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए हमारे विधान सभा क्षेत्र खंडेला में आप एक रीको इंडस्ट्रियल एरिया देकर हमें अनुगृहीत करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं खेल के बारे में कहना चाहूंगा। जैसा कि अभी भाई रविन्द्र जी भाटी बता रहे थे। खेलों के बारे विपक्ष ने भी बातें रखी, हमारे सदस्यों ने भी बातें रखी। पिछली सरकार में भी कुछ घोषणाएं, कुछ काम ऐसे हुए जिससे खेलों को बढ़ावा मिलने का काम हुआ।

श्री सभापतिः प्लीज।

श्री सुभाष मील (खंडेला): मैं आज यह कहना चाहता हूं कि ओलम्पिक में भारत के 117 सदस्य भाग ले रहे हैं, यह जानकर बड़ा ताज्जुब व दुःख हो रहा है कि राजस्थान से मात्र दो खिलाड़ी ही यहां जा रहे हैं। अभी विपक्ष के साथी भी कह रहे थे कि हमने इतना काम किया। माननीय सभापति महोदय, हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे राजस्थान के दो खिलाड़ी ही जा रहे हैं, तो इसमें एक उम्मीद की किरण कहीं दिखाई दी है। हमारी सरकार और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने खेल नीति 2024 बनाई, इससे एक उम्मीद कि किरण दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

पिछली सरकार में 475 करोड़ का बजट आवंटन किया गया, उसको भी आपने दुगुना करने की घोषणा की है। मैं हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा को, सरकार को, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की घोषणा करके आपने 250 करोड़ का बजट प्रावधान किया है, इससे निश्चित रूप से आगे चलकर नई खेल प्रतिभाओं को तराशने का मौका मिलेगा। हर संभाग पर 50 करोड़ की लागत से स्पोर्ट कॉलेज की घोषणा की है, वह भी खेलों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

मिशन ओलम्पिक की बात हो, चाहे अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए 25 लाख का सुरक्षा

बीमा कवर करने की बात हो, या खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन की बात हो, या पंचायत स्तर पर, जो दस हजार आबादी वाली पंचायतें हैं, वहां पर ओपन जिम के साथ खेल मैदान आपने बनाने की घोषणा की है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक मांग रखना चाहूंगा, हमारे विधान सभा क्षेत्र खंडेला में एक खेल स्टेडियम बनाया जाए। चाह हॉकी की बात हो, वॉलीबॉल की बात हो, बास्केटबॉल या कबड्डी के खिलाड़ियों की बात हो, उनको एक उचित स्थान मिले, जिससे वह तैयारी कर सके। इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र खंडेला में एक खेल स्टेडियम बनाया जाए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, कई बार हम देखते है कि जो प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, वह रह जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, राज्य स्तर की हो, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी तब ही निश्चित रूप से हमारी प्रतिभाओं को उचित अवसर मिलेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। 248 पद खेल प्रशिक्षक के स्वीकृत है, जिनमें से 182 पद वर्तमान में खाली हे। निश्चित रूप से यह सोचने वाली बात है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि यह पद भरे जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को तराशने में मदद मिल सके।

मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है, वर्तमान में विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए चाहे राष्ट्रीय स्तर की हों, राज्य स्तर की हों, खिलाड़ियों को भत्ते दे रहे हैं, जैसा कि अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, एक मात्र स्पोर्ट स्कूल, जो सार्दल स्पोर्ट स्कूल है उसमें 16 साल से खिलाड़ियों का मैस भत्ता नहीं बढ़ाया। यह चिंताजनक बात है। सभी खिलाड़ियों का यात्रा भत्ता व खर्चे के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाए। सीएसआर फण्ड की जो राशि होती है, उस राशि को ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए खर्च की जाए।

मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहूंगा। आपने खेल नीति बनाकर प्रदेश के खिलाड़ियो के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में जो प्रचलित खेल है, चाहे कोई भी खेल हो, जिनको दो परसेंट खेल कोटे में शामिल नहीं किया गया, या आउट आफ टर्न पालिसी में जिनको शामिल नहीं किया गया, उन खेलों को भी शामिल किया जाए। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि रोलबॉल के खिलाडी है, उस खेल का शामिल किया जाए। अक्टूबर, 2023 में जब नेशनल गेम्स गोवा में आयोजित हुए तो उसमें राजस्थान के रोलबॉल के पुरुष खिलाड़ियों की टीम गोल्ड मैडल लेकर आई और महिला टीम रजत पदक लाई। ऐसे खिलाड़ियों को अगर हम आउट आफ टर्न और दो परसेंट कोटे में शामिल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि रोलबॉल खेल को भी आउट आफ टर्न और दो परसेंट कोटे में

शामिल किया जाए।

अंत में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वर्षों से हमारे क्षेत्र के युवाओं की मांग थी, वह बजट के अन्दर पूरी हुई, सरकारी कॉलेज रींगस में घोषणा हुई, वह पूरी हुई। मेरे क्षेत्र की चार पंचायतों को इस बजट की घोषणा से जो खेल मैदान मिले, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, खेल मंत्री जी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही एक मांग करता हूं। हमारे क्षेत्र लाखनी और कटुंदरा में खेल मैदान दिए जाए। एक मॉडल स्टेडियम हमारे खंडेला में दिया जाए, ताकि हमारे खिलाड़ियों को वहां तैयारी करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हाकम अली जी।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 युवा मामले एवं खेल, मांग संख्या-32 महिला एवं बाल विकास, मांग संख्या-56 उद्योग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, राजस्थान की 50 परसेंट से अधिक आबादी युवाओं की है लेकिन अफसोस की बात है कि देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी भी राजस्थान में है। यह हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। हम सबको इस बात पर सोचना पड़ेगा। युवा देश का आने वाला भविष्य है। सीएमआईई के आंकड़ों को देखे तो राजस्थान में 60 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं। इतनी बड़ी वर्क फोर्स का बेरोजगार होना हम सबके सामने एक चुनौती है। देश के युवाओं के लिए सोचना पड़ेगा।

हमारी पिछली सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। निजी क्षेत्रों में भी प्रयास करे। मैं तो आपको भी यही कहूंगा कि आपको भी प्रयास जारी रखने चाहिए, ताकि युवाओं को मौका मिल सके। पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में लगभग 2 लाख 25 हजार नौकरियां दी, करीब 76 हजार पदों पर प्रक्रिया चल रही थी, यानी करीबन तीन लाख नौकरियां देने का इरादा था।

ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का सबसे पहले सरलीकरण राजस्थान में किया गया, जो एक आदर्श मॉडल था। राजस्थान में ईडब्ल्यूएस में अचल सम्पत्ति की शर्त हटाई गई, इसके अलावा आयु सीमा और परीक्षा फीस में भी ईडब्ल्यूएस को बाकी आरक्षित वर्गों की तरह छूट दी गई। इसको भी जारी रखें और युवाओं को लाभ दें। हमारी सरकार में इतनी नौकरियां दी गईं, तब के नौकारी लगे युवाओं को, एक महीने पूर्व ही मुख्य मंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटकर क्रेडिट लेने की कोशिश की, परन्तु सबको सच का पता है कि आठ महीने में भाजपा सरकार कितनी नौकरी दे पाई। युवओं को प्रतियोगी परीक्षा में बार-बार फीस नहीं देनी पड़े, इसलिए वन टाइम..

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): सभापति जी, उप मुख्य मंत्री जी, मंत्री जी, यह क्या जमावड़ा लगा रखा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज विराजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप विराजे, पहले उनसे पूछा जाए वह पांचों लोग क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बोलिए। किसी को डिस्टर्ब ना करें। कृपया आप सबसे अनुरोध है कि पहले अपने आप में झांके फिर दूसरे की तरफ अंगुली करे। दूसरे की तरफ अंगुली करते है तो चार अंगुली अपनी तरफ होती है, इसलिए अनुशासन में रहते हुए सदस्य को बोलने का मौका दे ...(व्यवधान)...

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): युवाओं को खेलों में प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक आयोजित किए गए थे, जिनमें करीब 59 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे। यह एक बहुत अच्छी पहल थी।

VPS-RTM-23.07.2024-17.40-3j

माननीय मंत्री महोदय, आप तो खुद खेलों से जुड़े हुए हैं, आपको तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो हमसे ज्यादा खेलों के जानकार हैं। जैसा कि अभी डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया था और उस टाइम मैं खुद भी टीवी देख रहा था कि आप जब वह ओलम्पिक पदक लेकर भारत में आये थे तो उस समय जब भारत में आपकी एंट्री हुई थी तो आपका कितना स्वागत हुआ था और हम बहुत ही गर्वित हुए थे कि हमारे भारत को ओलम्पिक में पदक मिला है, तो आप तो हमारे से ज्यादा जानते हो तो युवाओं की तरफ बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है और युवा आपके ऊपर बहुत ही आशा लगाये बैठे हैं कि हमारे जो खेल मंत्री हैं, वे खेल से जुड़े हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने यह किया था कि जो बहुत सारे युवा थे, वे स्कूल से पास आउट हो चुके थे और उनकी उम्र हो चुकी थी कि वे खेलों में भाग नहीं ले सकते थे, तो उसको इस मकसद के साथ किया था कि उनमें भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे कि उनको मौका मिल जाये दुबारा, तो जो उनके अन्दर योग्यता है खेल की, वे दिखा सकें, चाहे वह फुटबॉल में हो, वॉलीबॉल में, चाहे क्रिकेट में और चाहे और कोई खेल में हो। जो बच्चे उम्र में ज्यादा हो गये थे तो उनके लिए यह योजना बनाई थी और आपने यह बंद कर दी तो ठीक है, वह आपकी सरकार की इच्छा है कि वह बंद कर दी लेकिन आपको यह जारी रखनी चाहिए थी। उससे बहुत सारी प्रतिभाएं निकल कर आती थीं, उस टाइम भी करीबन 59 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, सबमें तो वह प्रतिभा नहीं थी लेकिन उनमें से कुछ निकले थे। उनमें से बहुत सारे निकलकर आज आगे भी बढ़े हैं खेलों के अन्दर और बहुत सारी कम्पनियों ने उनको हायर किया है कि बहुत सारे स्टेट्स की टीम जो प्राइवेट बना रखी है खेलों के अन्दर, उसमें उनको भी लेकर गये हैं तो इसलिए मेरा तो यही निवेदन था कि अगर आप उसको जारी रखते तो बहुत अच्छा होता। मंत्रीजी, युवा आपकी तरफ बहुत आशा लगाये बैठे हैं।

बालिकाओं के लिए एल.के.जी. से पी.जी. तक की पूरी शिक्षा सरकारी संस्थाओं में फ्री की थी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज भाटी साहब, आप अपनी सीट पर जाइये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): हर जिले में 75 करोड़ रुपये की लागत से सौ आवासीय क्षमता वाले विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाये थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महिलाओं एवं बाल विकास के बारे में थोड़ा यह बताना चाहूंगा कि महिलाओं एवं बाल विकास की ओर हमारी सरकार ने एकल नारी पेंशन को पांच सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये किया था और अब कानून बनाकर हर साल 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का किया था और साल में 18.31 लाख महिलाओं को करीब एक हजार करोड़ रुपये की पेंशन दी गयी। यह भी महिलाओं के लिए एक सहारा था कि जो वृद्ध एकल महिला है, उसके लिए यह बहुत अच्छी योजना है और इसको आप जारी रखें, यह मेरा निवेदन है।

महिला के नाम रजिस्ट्री करवाने पर एक परसेंट अतिरिक्त छूट दी गयी थी। महंगाई राहत कैम्पों में सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिला है। राजस्थान देश का पहला और और एक मात्र पांच सौ रुपये में गैस सिलेंडर देने वाला राज्य बना था, वह महिलाओं को दिया था और हमारी सरकार का यह इरादा था कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनी तो हम हर आदमी को पांच सौ रुपये में सिलेंडर देंगे। उसका पीछा आपने किया, उसकी नकल आपने की और आपने अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि हम 450 रुपये में देंगे और उसमें आपने फिर यह कह दिया कि हम तो सिर्फ उज्जवला योजना वालों को ही देंगे, पर हमारी मंशा थी कि हम सबको देंगे।

महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने एवं काउंसलिंग के लिए हर जिले में एक महिला सशक्तिकरण केन्द्र खोले गये तो आप उनको सुचारु रूप से चालू रखें, यही मेरी आपसे अपील है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तुरंत प्रभावी कार्यवाही के लिए स्पेशन इवेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वूमैन का गठन किया गया है, यह भी एक बहुत अच्छी पहल थी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं अपहरण में उत्तरप्रदेश सबसे आगे है, सबसे अधिक कस्टोडियल डैथ गुजरात में हुई है, नाबालिगों से बलात्कार यानी, पॉक्सो एक्ट के मामले में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है जबकि राजस्थान बारहवें स्थान पर था, यह हमारी सरकार ने कंट्रोल किया था।

हमारी सरकार के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत ने यह घोषणा की थी कि जो लड़के बालिकाओं से छेड़छाड़ करते हैं, महिला अपराधों के आदतन अपराधी हैं, उनका रिकार्ड थानों में हिस्ट्रीशीटर की तरह रखा जायेगा और सरकारी नौकरी में उन्हें प्रतिबंधित किया जायेगा तो आप इसे और शक्ति से लागू करें जिससे हमारी बालिकाएं भय मुक्त हो सके, यह मेरी आपसे अपील है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं सभापति महोदय के माध्यम से आपसे यह निवेदन करूंगा कि

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई सरकारी स्टेडियम एक भी नहीं है। रामगढ़ शेखावाटी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है, वहां रामगढ़ में एक जमीन पड़ी हुई है नगरपालिका के पास में, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी भी बैठे हैं, वे मेरे जिले के भी हैं तो उनसे मैं यह निवेदन करूंगा कि ये आपको वह जमीन दे दें और उस जमीन में एक स्टेडियम बना दिया जाये। वह जमीन गांव से बाहर है। एक गांव है, वहां पर है और नगरपालिका अभी उसमें कचरा डाल रही है और गांव वालों का यह विरोध है कि शहर का कचरा हमारे गांव में क्यों लाकर डाला जा रहा है? वह जमीन लेकर आप वहां पर अगर एक स्टेडियम विकसित कर दें तो शहर को भी, रामगढ़ को भी और आसपास के गांवों के युवाओं को भी लाभ होगा। माननीय सभापति महोदय, वहां पर एक कॉलेज है, बहुत पुरानी कॉलेज है तो उस कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को भी उसका लाभ मिलेगा, वह कॉलेज भी उस जमीन के पास में ही है तो आपसे मेरा यही निवेदन है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि गांवों में एक बहुत बड़ी समस्या है खेल मैदान विकसित करने के लिए कि गांवों में जो जमीन है वह या तो गोचर भूमि है, उसमें बच्चे खेलते हैं, पहले स्कूल जो बनी थी वह गोचर भूमि में बन जाती थी और स्कूलों के खेल मैदान भी गोचर में बना दिये जाते थे, अब सरकार उसमें कोई विकास नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता है, सुप्रीम कोर्ट की यह बैन है कि आप गोचर भूमि में या वन विभाग की भूमि में नहीं कर सकते तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि न केवल आप फतेहपुर में बल्कि राजस्थान लेवल पर एक सर्वे करवाकर कि जिस-जिस स्कूल के पास खेल मैदान नहीं है, उस स्कूल के खेल मैदान की जितनी जमीन लगे, पूरा राजस्थान का टोटल करके और कहीं पर जो सिवायचक की जमीन है, उस सिवायचक से इनकी क्षतिपूर्ति करके स्कूलों को खेल मैदान दे दिया जाये तो युवाओं के लिए खेल मैदान के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। मंत्री महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा डिपार्टमेंट लिया और युवा आपके ऊपर नजरें गड़ाये हुए बैठे हैं कि हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंहजी हैं और इसमें बजट की बात अगर कहो तो आप तो दिल्ली से आये हो। माननीय मंत्री महोदय, आपने तो दिल्ली में देखा है। हमने यह सुना है कि लोग राजस्थान से जाकर दिल्ली में देखते हैं कि बजट तो पूरा दिल्ली में ही पडा है, पूरा बजट तो दिल्ली से आता है तो आपको तो सारे रास्ते पता है कि बजट कहां से आता है तो राजस्थान के युवाओं के लिए आप दिल्ली में भी बात करके और अच्छा बजट लाकर राजस्थान के युवाओं को अच्छा मौका दें। आपको धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री लालाराम बैरवा।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, युवाओं के मामले में मैं दो पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहता हूं कि-

न जीतना जरूरी है, न हारना जरूरी है,

जिंदगी एक खेल है, उसको खेलना जरूरी है।

माननीय प्रधान मंत्रीजी ने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनको संवारने के लिए व प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से खेलों का प्रोत्साहन किया जा रहा है तथा खेल मैदानों के निर्माण की भी स्वीकृति दी जा रही है और राज्य सरकार भी इसके लिए कदम से कदम मिलाकर चल रही है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के ग्रामीण जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो खेल मैदान स्वीकृत हुए हैं, उन खेल मैदानों पर आधे से ज्यादा अतिक्रमण है और वह अतिक्रमण इसलिए है कि उन खेल मैदानों पर चारदीवारी नहीं है, वह खुले हैं इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी खेल मैदान जो स्वीकृत हैं उनमें चारदीवारी करवाकर विद्यालय को सुपुर्द किया जाये।

ऐसे ही मैं माननीय खेल मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जो युवा है, वह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए कार्य करना चाहते हैं। व्यायाम और खेलकूद के माध्यम से वे अपने शरीर को दुरुस्त रखने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं लेकिन वहां पर सुविधा के अभाव से वे पिछड़ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हर ग्राम पंचायत के अन्दर ओपन जिम की स्थापना की जाये जिससे ग्रामीण युवाओं को अपनी शरीर और अपनी स्टैमिना बढ़ाने के लिए उनको सुविधा मिल सके।

SSY/RTM/23.07.2024/17:50/3k

अभी यहां पर मेरे पूर्व सदस्यों ने भी इस विषय का जिक्र किया कि आज की हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर आगे बढ़ रही है। जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, उन बच्चों को नशे की लत लगाने के लिए ऐसा गिरोह हर शिक्षण संस्थाओं के बाहर पनप रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे सीकर हो, जितने भी बड़े इंस्टीट्युट जहां पर चलते हैं, हमारी युवा पीढ़ी वहां पर पढ़ती है, वहां पर ऐसे नशे के बड़े व्यापार होते हैं, उन बच्चों को नशे की लत लगाने के लिए वह तत्पर रहते हैं। उन पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करके पाबंदी लगाई जाये। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा, वह काम में व्यस्त रहेंगे। अभी माननीय सदस्य भाटी जी ने कहा कि उनके पास अगर रोजगार होगा, काम में व्यस्त रहेंगे तो निश्चित रूप से वह इन बुरी आदतों से दूर रहेंगे। गांवों में छोटे-छोटे लघु उद्योग पहले चलते थे। अपने परिवारों के कामकाज वर्ण व्यवस्था के अनुसार वह करते थे। लेकिन आज

हर व्यक्ति नौकरी लगना चाहता है। सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूर्व में गांवों में जो छोटे-छोटे लघु उद्योग चलते थे, जिनके माध्यम से परिवार का रोजगार चलता था, उनको कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। ऐसे छोटे-छोटे रोजगार को उत्पन्न कर वहां पर वापस सरकार की सुविधा के माध्यम से उनको प्रारंभ किया जाये, जिससे युवा पढ़-लिखकर अपने ही स्थान पर रोजगार के लिए साधन जुटा सके।

सभापति महोदय, पिछली सरकार में विवेकानंद हॉस्टल की स्थापना की गई थी। मेरा शाहपुरा जिला, शाहपुरा बनेड़ा विधान सभा नया जिला बना है, मैं माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भी विवेकानंद हॉस्टल की स्थापना की जाये। जिससे वहां बच्चे उसका लाभ उठा सकें, जिससे विद्यार्थी वहां पर परीक्षा की तैयारी कर सकें। शाहपुरा हाल में जिला बना है। वहां पर आपने अभी हमें खेल अकादमी स्विमिंग की दी है। आपने 2 स्टेडियम भी दिये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और खेल मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं।

मेरे वहां पर वालीबॉल और स्विमिंग में प्रति वर्ष राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्य परिवार के बच्चे प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर थोड़ा उधर ध्यान देंगे तो स्विमिंग के और वालीबॉल के मेरे यहां बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर उनको सुविधा मिलेगी तो निश्चित तौर वह लोग मेरी शाहपुरा विधान सभा का ही नहीं, पूरे राजस्थान का और देश का नाम रोशन करेंगे।

सभापति महोदय, मैं बाल विकास के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। शाहपुरा में वर्तमान में 349 आंगनबाडियां संचालित हैं। अभी भी वहां पर 30 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की और आवश्यकता है। अभी जो आंगनबाडियां चल रही हैं, वह ज्यादातर किराये के मकानों में चल रही हैं। सरकार की तरफ से जो मकान किराया दिया जाता है, वह मात्र 250 रुपये दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 250 रुपये में गांवों में कोई मकान किराया नहीं देता है। जितनी भी किरायों के मकानों में आंगनबाडियां चल रही हैं, उनका किराया बढ़ाया जाये और उनको पूर्ण सुविधा दी जाये।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मेरी शाहपुरा विधान सभा में नये आंगनबाड़ी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में 30 की और डिमांड है। शहरी क्षेत्र में 26 केन्द्रों की और जरूरत है। जो आंगनबाडियां मेरे वहां पर संचालित हैं, उसमें से 62 केन्द्रों पर जो आंगनबाडियां चल रही हैं, वह जर्जर अवस्था में हैं, उनको मरम्मत कराने की आवश्यकता है, इसलिए उनकी मरम्मत कराई जाये। बहुत सी आंगनबाडियों में, 127 केन्द्रों पर विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, जिससे आंगनबाडियों में आने वाले बच्चे बिना लाइट के वहां पर रहते हैं। ऐसे 127 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाइट की व्यवस्था कराई जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा विधान सभा में औद्योगिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की

कोई इकाई नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शाहपुरा जिले में रोजगार के लिए कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं होने के कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए दूरदराज के शहरों में जाना पड़ता है। यहां के निवासी केवल कृषि के रोजगार पर निर्भर हैं। वर्षा नहीं होने पर घर-परिवार छोड़कर अन्य जिलों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शाहपुरा में घोषित रीको क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु किन्हीं कंपनियों से एमओयू आदि कर स्थापना करवाने की कृपा करें। जिला मुख्यालय पर उद्योग क्षेत्र भी स्थापित करवायें।

जिला शाहपुरा में भविष्य में रोजगार व उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं। जिला उद्योग केन्द्र छोटे व्यवसायों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। देश के प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का प्रावधान है ताकि जिला मुख्यालय पर लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए केन्द्र बिन्दु बनाया जा सके। एक ही आधार पर छोटे और ग्रामीण उद्यमियों को आवश्यक सभी सेवाएं और सहायता प्रदान की जा सके।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तीन घंटा और बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: इक्ट्ठा ही बढ़ा लो ना। इक्ट्ठा ही बढ़ा लो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): हां, तीन घंटा।

श्री अध्यक्ष: तीन घंटे? कितना बढ़ाया है अभी?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): तीन घंटा।

श्री अध्यक्ष: एक?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): तीन, तीन।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय तीन घंटे बढ़ाया जाता है।

श्री घनश्याम। (अनुपस्थित) श्रीमती इन्द्रा। (अनुपस्थित) बैठिये, एक मिनट।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26- युवा मामले एवं खेल, मांग संख्या 32- महिला एवं बाल विकास व मांग संख्या 56- उद्योग पर विचार

श्री अभिमन्यु (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का मौका दिया।

हमारा देश नौजवानों का देश है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान हमारे देश में हैं। राज्य का नौजवान, राजस्थान का नौजवान सरकार से पूरी आशा और उम्मीद रखता है।

अपने विकास में, रोजगार में जिस प्रकार से युवाओं के लिए 4 लाख रोजगार की घोषणा की गई।

Spp/Rtm/23.07.2024/18.00/3l

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने घनश्याम का नाम पुकारा था, आपको थोड़े ही बोलने के लिये कहा।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): सर, वह हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: मैंने अभिमन्यु कहा क्या?

श्री अभिमन्यु (संगरिया): आपने ही कहा तो बोला।

श्री अध्यक्ष: किसने कहा? मैंने आपका नाम पुकारा थोड़े ही। अभिमन्यु नाम नहीं कहा। बार-बार घनश्याम कह रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षा में तो एवज में बैठते थे, यहां भाषण भी एवज में देने लग गये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य होगा तो उसकी एवज में कोई दूसरा सदस्य बन जायेगा, नो। आप बैठिये। श्री घनश्याम। आप बोलिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): पांच साल की आदत पड़ गयी न एवज में बिठाने की।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खेल, उद्योग और महिला बाल विकास पर प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेलों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। खेल जो खेले जाते हैं, उससे एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। गांवों में जो खेल पहले खेले जाते थे, उससे भाईचारा पैदा होता था और समाज में एक नया माहौल पैदा होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण खेल जो चालू किये थे, उनको पुन: चालू करवाया जाये। उससे गांवों में एक नया उत्साह पैदा हुआ। महिला, बच्चे, बुजुर्ग सबमें इस तरह की भावना पैदा हुई उससे प्रेम भाव पैदा हुआ। गांवों में छोटी-मोटी बातों को लेकर वैमनस्यता पैदा हो जाती है। खेतों के या और किसी मामले को लेकर झगड़े हो जाते हैं तो खेल के माध्यम से गांवों में प्रेमभाव पैदा होता था। मेरा मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि ग्रामीण खेलों का जो एक अच्छा स्वरूप निकलकर प्रदेश में आया, तो उसको आप पुन: चालू करवायेंगे तो उससे निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज सरकार का जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ उद्योग की बात मैं करना चाहूंगा। ग्रामीण एरिये में उद्योग लगाने की जो व्यवस्था सरकार ने की थी, हमारे यहां टोडाभीम में रीको की जमीन अलॉटमेंट नहीं हो पायी है और सरकार ने रीको लगाने का प्रावधान रखा था और वह जमीन अभी तक एक्वायर नहीं हो पायी। मेरा आपसे निवेदन है कि टोडाभीम में रीको की जमीन को एक्वायर कर वहां पर इंडस्ट्रीज लगाने की कृपा करेंगे।

इसके साथ-साथ उद्योगों के लिये कहना चाहूंगा कि आज हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। बेरोजगार रह रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को अगर हम उद्योग से जोड़ेंगे तो उसमें प्रदेश में एक नया स्वरूप पैदा होगा।

राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने इसी तरह से काम किये जिसमें युवा शिक्षा, बेरोजगार आगे बढ़ सके और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। राजस्थान की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या युवाओं की है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि देश में सबसे बड़ी बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सी एम आई के आंकड़ों को देखें तो राज्य में 60 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं। इनका बेरोजगार होना हम सभी के सामने एक गंभीर चुनौती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में प्रयास किया था। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लगभग 2 लाख 25 हजार नौकरियां दीं। इसके साथ ही 75 हजार की प्रक्रिया चल रही थी यानी करीब 3 लाख सरकारी नौकरियां दी गयीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, EWS के आरक्षण का सरलीकरण सबसे पहले राजस्थान में किया गया। राजस्थान में EWS की अचल सम्पत्ति की शर्त हटायी गयी। इसके अलावा, आयु सीमा में भी EWS को बाकी आरक्षित वर्गों की तरह से छूट दी गयी थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हमारी सरकार ने इनको इतनी नौकरियां दी गयीं तब के समय के नौकरी लगे हुये युवाओं को मुख्य मंत्रीजी ने नियुक्ति पत्र बांटकर उनको क्रेडिट लेने की कोशिश की, परन्तु युवाओं की 8 महीने में भाजपा सरकार एक भी नौकरी नहीं दे पायी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाना शुरू किया गया। 14 जिला मुख्यालयों पर 21 मेगा जॉब फेयर आयोजित हुये। इसमें हजारों स्किल्ड और अन-स्किल्ड युवाओं को रोजगार के मौके दिये गये थे। बेरोजगारों को सम्बल देने के लिये युवा सम्बल योजना में पुरुषों एवं महिलाओं को 4 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया। करीब 6.40 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने में सरकार ने 23 हजार करोड़ रुपये का व्यय किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज महिला बाल विकास की जो योजनाएं हैं, वे भी हमारे प्रदेश में एक सुचारू रूप से चालू करें। जैसे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उनमें भी आपने जो सहयोगिनी लगा रखी हैं, उनके अलावा एक-एक और आपको लगाने के लिये निवेदन है। उससे जो बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था सरकार से आप करवायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज महिलाओं में बेरोजगारी का आलम है, आज महिलाओं को शिक्षित करने के लिये, उनको ट्रेनिंग देने के लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इस तरह की व्यवस्था की जाये कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको पुनः वहां स्किल

डवलपमेंट के लिये इस तरह का आयोजन किया जाये, उनको ट्रेनिंग दी जाये जिससे उनको रोजगार मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पिछली सरकार ने आयोजन किये, चाहे खेल का हो, युवाओं का हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। आपके नौ मिनट हो गये। 9.00 बजे खत्म ही करना है। श्रीमती कल्पना देवी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 एवं 56 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री भजनलाल जी, एवं माननीय उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी को तहेदिल से धन्यवाद देती हूं, क्योंकि इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण हमारे कोटा के सभी वासियों के लिये जो आपने घोषणा की है, वह एयरपोर्ट की घोषणा की है जिससे हमारे औद्योगिक क्षेत्र में बहुत फर्क पड़ेगा और साथ ही हमारे लोक सभा के अध्यक्ष, माननीय ओम बिरला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं जिनके अथक प्रयास के कारण आज हमारा यह सपना पूरा होने जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे बजट में पेज 45 में जब कोटा का इंट्रॉडक्शन किया गया है तो वहां लिखा है औद्योगिक नगरी कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा एक औद्योगिक नगरी के नाम से विख्यात है। कोटा में बिजली, पानी, सड़क, रेल एवं औद्योगिक वातावरण होने के उपरान्त भी आज हम पिछड़े हुये हैं। कमी थी तो केवल एयरपोर्ट की थी, जो अब वह कमी भी नहीं रहेगी। फिर हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लिये हम सबको चाहे वह प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक, हम सभी के लिये यह चिन्तन करना आवश्यक है कि राजस्थान के कई औद्योगिक क्षेत्र कोटा के बाद बने हैं लेकिन फिर भी कोटा में औद्योगिक वातावरण होने के बावजूद भी कई बड़ी फैक्ट्रियां यहां की कमी कहें या क्या कारण हैं, बन्द हो गयी हैं जिनमें प्रमुख हैं - जे.के.फैक्ट्री, सेमकोर, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, केशवरायपाटन शुगर मिल एवं अन्य ऐसी छोटी-छोटी फैक्ट्रियां लुप्त हो गयी हैं। इन फैक्ट्रियों से रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते थे, परन्तु अब वह भी बन्द हो गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के गांव-गांव में स्थानीय रोजगार के लिये हर गांव में कुटीर उद्योग थे जिससे गांवों में स्थानीय रोजगार के साथ-साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी पर भी नियन्त्रण था। गांवों में शहरों से पलायन जितना इस अवधि में हुआ है, इससे पूर्व कभी भी नहीं हुआ है। औद्योगिक विकास के लिये काश्तकारों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण भी एक बहुत बड़ा कारण है। उद्योग लग नहीं रहे लेकिन उद्योग के नाम पर किसानों को भूमिहीन कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में आज औद्योगिक वातावरण होने के उपरान्त भी

राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार ने औद्योगिक नीतियां बनायीं लेकिन लगता है कि उनके क्रियान्वयन में कुछ न कुछ त्रुटियां रह गयी हैं और शायद हम किसी कारण उद्योगपतियों को रूचि तो दिखायें लेकिन धरातल पर वातावरण तैयार नहीं होने के कारण औद्योगिक रूप से हम पिछड़े हैं और हम इसको मेनीफेस नहीं कर पाये हैं।

MLS/RTM/23.07.2024/18:10/3m

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि उद्योगों को स्थापित किये जाने के पूर्व उद्योगपतियों को पर्यावरण संरक्षण एवं इंडस्ट्रियल वेस्ट और कचरा प्रबन्धन के लिए ताकीद किया जाता है कि वे जिस क्षेत्र में अपने उद्योग स्थापित करेंगे, वहां पर्यावरण संरक्षण एवं औद्योगिक अपशिष्ट कचरा प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इस कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक फैक्ट्रियां मौजूद हैं। कई फैक्ट्रियों एवं कम्पनियों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने की लगातार शिकायतें स्थानीय स्तर पर हो रही हैं। इन कम्पनियों- फैक्ट्रियों के पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी चिमनियां व नाले बनाये गये हैं, क्या वे मापदण्ड के आधार नहीं होने के कारण प्रदूषण फैला रहे हैं? इनकी जांच करायी जाये।

कैमिकल युक्त पानी नालों से कॉलोनियों के बीच से होते हुए जा रहा है। क्षेत्रवासी लगातार इसकी शिकायत करते हैं। हमने सुना है कि गिरगिट रंग बदलता है, परन्तु यहां हमने यह भी देखा है कि मगरमच्छ का रंग बदल गया है और मगरमच्छ सफेद हो गया है। इसके कारण बोरिंग के पानी पर भी प्रभाव पड़ा है और सिंचाई का पानी भी प्रभावित हो रहा है। इससे फसल कैमिकल युक्त हो जाती है। जमीन भी बंजर हो जाती है। सरकार ऐसे उद्योगों को चिह्नित करके उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही भी करे। साथ ही, सम्बन्धित अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाये।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के समक्ष अपने क्षेत्र की मांग रखना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, इन उद्योगों को आप डायरेक्शन दें कि सभी क्षेत्रवासियों को प्राथमिकता से रोजगार दें। आपने बजट में पेज 39 के पॉइंट 30 पर कहा है कि आप नयी एमएसएमई पॉलिसी लाने जा रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। कोटा में आपने स्टोन मण्डी की घोषणा की है, परन्तु पहले भी दो बार यूआईटी द्वारा यही घोषणा की गयी थी और वह सक्सेसफुल नहीं हो पायी थी। स्टोन मण्डी के बदले मैं आपसे मांग करती हूं कि आप कोटा में ही एक स्टोन पार्क की घोषणा करें ताकि इनके आर्टिकल्स का क्रय-विक्रय किये जाने से उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे, जिसका 1/3 हिस्सा राजस्थान से जा रहा है, हमें इसका बैनिफिट लेना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्च्युनिटीज को एक्सप्लॉइट करना चाहिये। मैं कोटा के लिए सोलर हब एवं फार्मा हब के साथ-साथ एक आईटी हब की भी मांग करती हूं। आपने ''वोकल फॉर लोकल'' में कोटा डोरिया को सिलेक्ट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती

हूं। कोटा डोरिया के लिए हम प्रसिद्ध हैं, पर इसके साथ हम कोटा स्टोन, कोटा कोचिंग एवं कोटा कचोरी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) माननीय अध्यक्ष जी, दस मिनट का समय लिखा था।

श्री अध्यक्षः सबके 8 मिनट कर दिये हैं।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): एक जो अननोन चीज है, कोटा वैल्डिंग रॉड्स के लिए भी देश में सबसे बड़ा हब है। इस पर भी आप ध्यान दें। रीको इंडस्ट्रियल एरिया हमारे देश में बन गया है, पर वहां कोई भी मूलभूत सुविधा वहां नहीं मिलती है, चाहे वह पानी की पाइप लाइन का अभाव हो या सीवरेज की पाइप लाइन का अभाव हो। यहां तक कि उद्योगपति मुझे बताते हैं कि वे पीने का पानी भी घर से लेकर जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वे इस चीज पर ध्यान दें।

ऋण की बात करें तो मैं देख रही थी, राजस्थान वित्त नियम द्वारा उद्योगपतिगपतियों को ऋण दिये जाते हैं, लेकिन 3 वर्षों से आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं। 2020-21 में 300 करोड़ थे और अब 175 करोड़ दिसम्बर तक दिये हैं। प्रतिवर्ष ऋण देने का लक्ष्य घटता जा रहा है। क्या कारण है, ब्याज ज्यादा ले रहे हैं, क्या है, इसे आप देखें। एक सजेशन है, जो इंडस्ट्रीज से ट्रीटेड वॉटर निकलता है, इसे अगर आप डायवर्ट करके स्टोन प्रोसेसिंग यूनिट्स में दें तो दोनों को पानी का लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्षः कुमारी रीटा चौधरी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): अन्त में मैं मांग संख्या 32- महिला एवं बाल विकास में माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने 5-5 नवीन आंगनबाड़ियों की घोषणा की। साथ ही, मैं अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक वर्किंग वीमेंस हॉस्टल की मांग करती हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का मुझे मौका दिया।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): 000

श्री अध्यक्षः आप टेबल कर दें।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री खेल से जुड़े हुए हैं। युवा मामले एवं खेल विभाग पर मैं अपनी चार-पांच बातें रखना चाहूंगी। सभापति महोदय, विगत तीन वर्षों में जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2023 तक हमारी सरकार थी तो तकरीबन साढ़े पांच लाख अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले 6 महीनों में आपने कोई भी नया आवेदन नहीं लिया है। हालांकि, बेरोजगारी भत्ता सात महीनों से रुका हुआ था, आपने वह तो रिलीज कर दिया है, लेकिन नया आवेदन नहीं लिया है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, आपसे निवेदन है कि आप इसे वापस चालू करें और बेरोजगारी भत्ते के आवेदन लेना शुरू करें ताकि युवाओं को

मदद मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने खेलों के प्रति खिलाड़ियों का रुझान बढ़ाने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी थीं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि वर्तमान में इनके पास 182 खिलाड़ियों की नियुक्ति की फाइल पैंडिंग पड़ी है। उसे निकालने की कृपा करें। दूसरी बात, उस समय घुड़सवारी में जो पदक विजेता थे, उन्हें शामिल नहीं किया गया था। इस सदन में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जो घुड़सवारी के अन्दर पदक विजेता थे, उन्हें भी आउट ऑफ टर्न नौकरियों के लिए शामिल करते हुए नियुक्तियां दें।

तीसरी बात, 2022 और 2023 में राजस्थान की सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक्स का आयोजन किया था। उससे प्रदेश में खेल का माहौल बना था। उसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों, सभी ने खेलों में भाग लिया था। मैंने इस बजट में देखा, ''खेलो इंडिया'' की तर्ज पर आप ''खेलो राजस्थान यूथ गेम्स'' आप लोग चालू करेंगे, लेकिन उसमें और इसमें अन्तर है। उसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने भाग लिया था और उससे हमारे यहां हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा था। आपसे निवेदन है कि यूथ की तरफ तो आप ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन यह एक तरह से भाईचारे के सन्देश को ध्यान में रखते हुए आपस में लोगों में मेल-जोल बढ़े तो जो ग्रामीण और शहरी ओलम्पिक शुरू किये थे, उन्हें आप कंटीन्यू रखें।

अध्यक्ष महोदय, अभी खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद दिया था महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए। मैं भी धन्यवाद दूंगी जिसकी इन्होंने घोषणा की, लेकिन 2011-12 में जब बीजेपी की सरकार थी तो आपने झुंझुनूं में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी और 2013 में राज्यपाल ने उसे अनुमति दी थी, लेकिन आज दिनांक तक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी झुंझुनूं कहीं भी नजर नहीं आ रही, उसमें दो साल तो वीसी नियुक्त किया, पर उसका अता-पता नहीं है। जमीन जरूर उसकी अलॉट हो गयी। माननीय मंत्री महोदय, इस पर ध्यान दें, क्योंकि शेखावाटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। वहां जमीन अलॉट होने के बाद धरातल पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आप कृपा करके उस पर विचार करके उसे भी बजट दें ताकि वहां यूनिवर्सिटी डवलप हो सके। ...(व्यवधान)... हां, हमने नहीं किया, पर यह नहीं होता कि आपने की और हमने नहीं की।

एक सुझाव है, दे रही हूं, मानें या न मानें आपकी इच्छा है। आपके जो प्रभारी मंत्री हैं, वे थोड़े दिन पहले बजट से पूर्व झुंझुनूं गये थे तो इनके सामने मांग रखी गयी थी। बजट के बाद ये गये तो इन्हें पता है, इनकी झुंझुनूं में क्या स्थिति हुई। उस बात को ध्यान में रखें आप लोग। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत् कहना चाहूंगी, क्योंकि हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा नीति ला रहे हैं और 4 लाख रोजगार देने की आपने बात की, उसका तो स्वागत है, लेकिन जो 5 हजार राजीव गांधी युवा मित्र अभी तक बैठे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, उनकी भी पुन: नियुक्ति की जाये।

आप चाहे नाम बदल दें, राजीव गांधी के नाम से आपको तकलीफ है तो आप मुख्य मंत्री

युवा मित्र योजना लाकर उन 5 हजार लड़के बैठे हैं, उन्हें नौकरी पर रख लें। इस पर आप लोग ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की 3 मांगें रखना चाह रही थी। कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4 स्टेडियम की घोषणा की गयी। उसके लिए बजट भी अलॉट हुआ था और उसमें बहुत कुछ काम भी हो गया, लेकिन पूरा काम नहीं हुआ, अधूरा है, इसलिए आपसे मैं मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलसीसर, मलसीसर, मंडावर, बिसाऊ के जो खेल स्टेडियम हैं, उनके लिए आप बजट अलॉट करें ताकि पूरे तरीके से उनका निर्माण हो जाये और वे उपयोग में आ सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

mkd/rtm/23.07.2024/18:20/3n

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खेल के बारे में पहले चर्चा करूंगा। सबसे पहले राजस्थान में प्रारम्भिक खेलों को पुन: शुरू करना चाहिए, क्योंकि कबड्डी, खो-खो ये जो भी प्रारम्भिक खेल थे। उन पर यदि हम वापस ध्यान देंगे और ये खेल जाग्रत होंगे तो ग्रामीण इलाके में अच्छे युवा उभरकर आयेंगे और वे देश और राजस्थान में अपना बड़ा नाम करेंगे।

मंत्री महोदय विराजे हुए हैं। स्कूल में एक अनिवार्य पीरियड खेल के लिए करें तो वास्तव में अच्छे बच्चे गांव में से निकलकर आयेंगे। यह अच्छा होगा। आठवीं तक के स्कूल में फिजिकल पीटीआई नहीं है। फिजिकल पीटीआई दसवीं, बारहवीं में तो हैं ही, लेकिन आठवीं स्कूल तक अनिवार्य करें तो खेलों को बढ़ाया मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ओपन हो, ग्रामीण हो, स्कूल के बच्चे हों, जब वे खेलने जाते हैं तो उनको टीए-डीए बहुत कम मिलता है। आज की तारीख में कोई भी बच्चा कहीं भी खाना खाने जाता है तो सौ रुपये प्लेट से कम में खाना नहीं मिलता है। इसलिए उनको टीए-डीए पूरा मिले, इसके लिए सरकार व्यवस्था करें। ओपन के हों, स्कूल के हों, ग्रामीण के हों, जो भी टूर्नामेंट हों, उनको अच्छा पौष्टिक भोजन मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी रिक्त पद हैं। चाहे कोचेज के हों, चाहे जिला कोचेज के हों, उनको भरने की आप कोशिश करें तो खेलों को बढ़ावा मिलेगा। पहले सरकार ने हर पंचायत में खेल मैदान की बात की थी, पर वह नहीं हो पाया है। अबकी बार डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार भी है। भजनलाल जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है। मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि अनिवार्य रूप से हर पंचायत हैड क्वार्टर पर खेल मैदान की घोषणा करें। सभी तरह की बाउंड्री वगैरह बनाकर अच्छा खेल मैदान बनाया जाये।

मेरे वहां चित्तौड़गढ़ में क्रिकेट एकेडमी, कबड्डी, फुटबॉल एकेडमी अच्छी बन सकती है, उसके लिए भी आप थोड़ी व्यवस्था कराये। ओपन खेल, जो कांग्रेस सरकार में चालू हुए थे,

उनको यदि हम रेगुलर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छा फील्ड मिला था। उसको भी हम चालू रखें।

युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाये। माननीय मंत्री महोदय, पहले कांग्रेस ने बहुत घोषणाएं की थीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय नहीं। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री को सम्बोधित करते हुए कोई बात नहीं कहनी है।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाये। युवा को कौशल प्रशिक्षण दिया जाये। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाये। सरकारी एवं अर्द्धसरकारी निगम, बोर्डों आदि में रिक्त पदों पर अभियान चलाकर भर्ती की जाये और रोजगार देने की व्यवस्था है। खिलाड़ी चाहे स्टेट का हो या नेशनल का हो, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत भत्ता मिलना चालू हो जायेगा तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी व्यवस्था कराने की कोशिश करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का हब भी है और हिन्दुस्तान जिंक भी है और वहां काफी अच्छे उद्योग हैं। इसलिए सरकार यह फिक्स करें कि कुशल और अकुशल, 50 परसेंट कुशल और 75 परसेंट अकुशल, वहां के युवा बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पाती है, इसलिए युवा बेरोजगार इधर उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी से हमारे वहां के लोकल लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हमारे यहां काफी युवा बेरोजगार हैं, वहां सीमेंट का हब है, हिन्दुस्तान जिंक है और काफी नई फैक्ट्रियां भी आने वाली है, इसलिए वहां उद्योग में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की आप कोशिश करें।

चित्तौड़गढ़ में रीको की आवश्यकता है। सरकार निजी उद्योगकत्ताओं को भी उसी प्रकार की सुविधाएं दें, जैसे पानी, बिजली और रोड की रीको को देती है। इससे भी इंडस्ट्रियल एरिया काफी डवलप हो सकता है। मेरे चित्तौड़गढ़ में मार्बल का हब भी है, मेरे वहां एक बहुत बड़ी जमीन मादलदा पड़ी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मेरे वहां मादलदा में पांच सौ, सात सौ हेक्टेयर जमीन पड़ी है। उसको यदि रीको डवलप करे तो वहां अच्छे उद्योग आ सकते हैं। राजस्थान से कच्चा माल सिरेमिक जाता है। वह सारा माल गुजरात में जाता है। वह सारा माल चित्तौड़गढ़ में उपलब्ध हो सकता है। चित्तौड़गढ़ में अच्छी सिरेमिक की टाइलें बन सकती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको वहां पर उद्योग डवलप कर सकता है। इसलिए आप व्यवस्था कराये और नये उद्योग के लिए जमीन उपलबध करायेंगे तो अच्छा रहेगा। हम कई बार माइंस अलॉट कर देते है, उद्योगों को अलॉट कर देते हैं, डम्पिंग की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए सरकार उसकी भी व्यवस्था कराये।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका होती हैं, उनको बहुत कम मानदेय मिलता है। इसलिए मानदेय बढ़ाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में बहुत हो गया। आप टेबल कर दें, दस मिनट हो गया है। श्री उमेश मीणा। आठ मिनट से ज्यादा किसी को नहीं।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): पोषाहार की गुणवत्ता भी देखें। आंगनबाड़ी में पानी बिजली की भी व्यवस्था करावें। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मैं सबसे पहले खेल विभाग पर बात करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उदयपुर सम्भाग और टीएसपी एरिये की बात करूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, मेरे डूंगरपुर जिले की बात करूं तो हमारे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, जो जिला स्तर, स्टेट स्तर व अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी गये हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जिला मुख्यालय पर उन्हें प्रेक्टिस में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। मेरी खेल मंत्री महोदय से मांग है कि हमारे जिला मुख्यालय पर एक खेल स्टेडियम खोला जाये।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

मेरे आसपुर विधान सभा क्षेत्र में तीन ब्लॉक हैं, दोवड़ा, साबला और आसपुर, इन तीनों ब्लॉक में खेल के मिनी स्टेडियम खोले जायें।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे प्रदेश में क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी लोकप्रिय है। उसके लिए मैं चाह रहा हूं कि हमारे एरिये के अन्दर कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, जो खेलना तो चाह रहे हैं, लेकिन हमारे गांवों एवं ग्राम पंचायतों के अन्दर मैदान उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायत स्तर पर मैदान उपलब्ध कराये जायें। इन मैदानों को न्यूनतम राशि दस से पन्द्रह लाख रुपये दी जाये, ताकि अच्छा-सा मैदान बन सके।

हमारे कई गांवों में बुजुर्ग कहते हैं कि आज युवा भटक रहा है, शाम होते ही दारू के ठेके पर मिलते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर मैदान मिलेंगे तो शाम होते ही पांच बजे युवा दारू के ठेके पर नहीं मिलेंगे, खेल के मैदान में मिलेंगे। यह मैं आपसे कहना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, आज मैं उद्योग की बता करूं। सभापति महोदय, जो हमारा डूंगरपुर जिला है, वह बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है। वहां से कई युवा बाहर गुजरात, मध्य प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे डूंगरपुर जिले के अन्दर एक बड़ी मिल है, वह पुरानी मिल अभी बन्द पड़ी हुई है, उसको चालू करवाया जाये ताकि पांच हजार से ज्यादा लोगों को वहां रोजगार मिल सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर निठाउवा के अन्दर, जो एक बड़ा व्यापार हो सकता है,

तेंदू पत्ते वाला।

Bhs/Rtm/23.7.24/18.30/3o

जो हमारी महिलाएं हैं, पूरा दिन काम करने के बाद उनके पास जो टाइम बचता है उसमें वो तेंदू पत्ता इकट्ठा करके बेचने का काम करती हैं तो उसका जो ठेकेदार होता है वह पूरी मूल राशि नहीं देता है जबकि सरकार की राशि साढ़े पांच हजार है लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से दो हजार रुपये भी नहीं मिलते हैं तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि एक तो उनका साढ़े पांच हजार रुपये जो है उसको दस हजार रुपये किया जाये और वहां पर ऐसी व्यवस्था बनायी जाये कि वहां पर स्थानीय टेन्डर हो, स्थानीय ठेकेदार हो ताकि वास्तविक जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब महिला है उसकी जेब में पैसा जाये। ऐसी व्यवस्था बनायी जाये।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन है कि हमारा जो जंगल एरिया है... (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट चाहूंगा, अभी मेरे चार मिनट भी नहीं हुए हैं। हमारे यहां शादी-विवाह में पत्तल दोने चलते हैं वो प्लास्टिक और कागज के बनते हैं तो उससे काफी साइड इफेक्ट होता है और शरीर के लिए नुकसानदायक है तो वो पत्तल दोने जो हमारे पत्ते के बनाये जाते हैं खाकरे के पत्ते और महुए के पत्ते से तो वहां पर ऐसी स्कीम चलायी जाये और उस पत्तल दोने की एक रुपया कीमत की जाये तो उसका हमारी महिला एवं बुजुर्गों को बड़ा रोजगार भी मिलेगा यह मेरा मानना है।

मैं महिलाओं पर बात करना चाहूंगा महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत तो हमारे यह मंत्रालय 1985 में बना है और कहीं न कहीं बालक और महिलाओं को शारीरिक रूप से और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने के लिए यह बनाया गया है लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे एरिया के अन्दर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो पोषाहार दिया जा रहा है वह पोषाहार एक नम्बर घटिया दिया जाता है, कहीं न कहीं इस सामग्री के अन्दर मिलावट की जा रही है इस कारण से कई सारे कुपोषित व्यक्ति हो रहे हैं तो उसकी जांच की जाये पूरी तरह से ताकि हमारे वहां व्यवस्था सही हो सके। यह मैं आपको कहना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, आंगनबाड़ी की जो महिला कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा सहयोगिनी है उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि कोरोना काल में भी उन्होंने चौबीसों घंटे काम किया है और एक योद्धा के रूप में काम किया था फिर भी उनको भत्ता भी नहीं मिला और कोई राशि भी नहीं मिली है और उनको जो मानदेय दिया जा रहा है बहुत कम दिया जा रहा है राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उनकी राशि जो मिल रही है केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से उसको 18 हजार रुपये किया जाये ताकि उनका घर व्यवस्थित रूप से चल सके और जो उनकी सेक्टर मीटिंग होती है मीटिंग में जाने का उनको जो भत्ता मिलना चाहिये वह भत्ता भी नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त जो कार्य दिया

जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। चुनाव की ड्यूटी, स्कूल के कार्यक्रम, पंचायती राज आदि में ड्यूटी लगाई जाती है उसका उन महिलाओं को भत्ता नहीं मिलता है तो मांग करना चाहूंगा कि महिलाओं को भत्ता दिया जाये और आपकी अनुमति हो तो यह मैं पूरा टेबल कर दूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री कुलदीप जी।

श्री कुलदीप (विराटनगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26,32 और 56 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, 2024-25 का जो बजट राजस्थान की विधान सभा में पेश हुआ है इतना शानदार और जानदार बजट है कि राजस्थान के साथ-साथ देश के अन्य प्रान्तों में भी राजस्थान के बजट की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की ओर से प्रदेश के यशस्वी नेता आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसान से लेकर, नौजवान से लेकर, महिला शक्ति से लेकर हर ऐसे वर्ग को आपने जोड़ने का प्रयत्न किया है।

सभापति महोदय, आज यूथ एंड स्पोर्ट्स और उद्योग के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। मैं बिना भूमिका के आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मैं ऐसे विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जहां पर मेरे ऐसे-ऐसे खिलाड़ियों ने जन्म लिया है जिन्होंने हमारे राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे भारत राष्ट्र का नाम रोशन करने का काम किया है, उनका जिक्र मैं जरूर आपके माध्यम से आज इस सदन में लेना चाहता हूं। मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्र आदरणीय श्रीराम सिंह शेखावत जी जो बड़नगर गांव के रहने वाले हैं मेरे गांव के पड़ोस में ही गांव है इनका और एशियाड में पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम किसी ने किया तो माननीय श्रीराम सिंह शेखावत जी ने किया। मैं बधाई देना चाहता हूं ऐसे ही एक हमारे खिलाड़ी जो नौकायन में श्री सतीश चन्द्र शर्मा जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाजे कलां पंचायत हमारी आती है वहां के रहने वाले हैं, गोल्ड मेडल जीत कर आये। ऐसे ही एक हमारे नौजवान खिलाड़ी जो मेरे पड़ोसी गांव मढ़ा के रहने वाले हैं जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय स्तर हमारे भारत की बास्केटबॉल टीम का नेतृत्व किया। ऐसे-ऐसे खिलाड़ियों ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जन्म लिया है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं खेल मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे खेल मंत्री महोदय भारत सरकार में मंत्री भी रहे, जयपुर ग्रामीण से सांसद भी रहे। आप इन सारे खिलाड़ियों को जानते हैं। आप भी एक खिलाड़ी हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जिन खिलाड़ियों ने हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया ऐसे खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि इनके गांव श्रीराम सिंह जी का गांव बड़नगर है, सतीश शर्मा जी का जाजे कलां है, जयराम जी का गांव मढ़ा है तो मैं इतना आग्रह सरकार से करना चाहता हूं कि आपने एक जनसंख्या के आधार पर तो खेल

अकादमी बनाने की घोषणा की है, बहुत सारे ट्रेक भी वहां खिलाड़ियों के लिए बनने हैं लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं मंत्री महोदय, कि ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान तब और ज्यादा बढ़ेगा जिन्होंने हमारी इस मिट्टी का सम्मान बढ़ाने का काम किया ऐसे खिलाड़ियों के गांवों का आप खेल की दृष्टि से विकास करिये। वहां ओपन जिम बनाइये। वहां ऐसे जिन खिलाड़ियों ने जिन खेलों में हमारे राष्ट्र का नाम आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है ऐसे खेलों में हमारे उन गांवों का विकास करना बहुत अच्छा लगेगा। खिलाडियों का मान-सम्मान भी बढ़ेगा और उन गांवों में और भी अधिक प्रतिभाशाली जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इससे प्रेरित भी होंगे।

सभापति महोदय, सरकार ने जो घोषणा की है कि दस हजार की आबादी की जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं जो बड़े स्थान हैं उनको विकसित किया जायेगा आपके स्पोर्ट्स अकादमी के माध्यम से। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे मेरे पांच-छः स्थान है विराटनगर में मेरे पावटा, प्रागपुरा जिनकी पापुलेशन पच्चीस हजार से ज्यादा है। ऐसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में जो प्रोपर अरबन एरिया लगता है वहां पर नगरपालिका है वहां बहुत बड़ी पापुलेशन हमारे उस क्षेत्र की है। साथ ही हमारे कूड़ला क्षेत्र जो बहुत बड़ा इलाका है जहां पर देश की सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन का काम होता है ऐसे ही मेड़कूरला क्षेत्र है उसकी पापुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पर खेल अकादमी यदि स्थापित होती है तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों को और नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे सारे स्थानों को, ऐसा ही स्थान मेरे एक बीलवाड़ी का स्थान भी है उसको यदि विकास की दृष्टि से अगर हमारी सरकार विकास करायेगी तो निश्चित रूप से मेरे पूरे इलाके में खेलों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, मैं ऐसा नहीं मानता कि केवल मेरे ही इलाके में खेलों के प्रति प्रेम है लेकिन ऐसे-ऐसे खिलाड़ियों ने हमारे यहां जन्म लिया है जिन्होंने हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग का जिक्र भी चल रहा है। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पिछली सरकार में सरकार की ओर से एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया लेकिन न तो भूमि आवंटन का काम हुआ और न कहीं रीको दिखा इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर जो जयपुर दिल्ली हाईवे के बीच में आता है शाहपुरा के बाद नीमराना को सब लोग जानते हैं हमारी सरकार में जब हमारी सरकार थी 2013 से 2018 के बीच में तब हमारी सरकार ने बहुत सारा वहां विकास करवाया था और हाईवे के ऊपर हम पड़ते हैं। हमारे यहां उद्योग भी स्थापित नहीं हैं इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र विराटनगर में हाईवे के ऊपर जहां भी, जमीन हमारे पास बहुत उपलब्ध है, जमीन हम देंगे लेकिन सरकार औद्योगिक क्षेत्र घोषित करे। कांग्रेस ने जो पाप कमाने का काम किया, जनता को जो ठगने का काम किया मैं स्पष्ट रूप से सदन के सामने अपना विषय रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, ऐसे ही मेरे एक शिल्पकारों का गांव है जहां पर मूर्तियां बनाई जाती है और केवल देश में ही नहीं पूरे संसार में हमारे यहां से मूर्ति बन कर जाती है। शिल्पकारों का

बहुत बड़ा गांव छीतोली गांव है वहां पर एक बहुत बड़ा हब है। अपनी ही मेहनत से हमारे शिल्पकार भाई मूर्ति बना कर और पूरे देश और दुनिया में भेजने का काम करते हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको स्पेशल रूप से उन शिल्पकार भाइयों को सुविधाएं मिले इसलिये लघु उद्योग के रूप में मेरे छीतोली ग्राम पंचायत को स्थापित करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं उद्योग मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपका भी बहुत प्रिय गांव छीतोली गांव रहा है अगर उसमें सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित रूप से विकास की दृष्टि से शिल्पकार भाइयों का मनोबल और बढ़ेगा, ऐसी मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं एक ऐसा विषय रखना चाहता हूं सरकार के सामने जो बड़ा सेंसेटिव बिन्दु है, हमारे अल्ट्रा टेक सीमेंट का प्लांट चल रहा है मोहनपुरा जोधपुरा में और बहुत लम्बे समय से एक समस्या वहां के किसानों की बनी हुई है उसमें कई गांव शामिल होते हैं ...

Kas/rtm/23.07.2024/18.40/3p

अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट लगने के बाद सभी गांवों का पुनर्वास किया गया, उसमें हमारे दो-तीन गांव छूट गये। एक कुजूदा और एक जोपला गांव छूट गया था। माननीय सभापति महोदय, आज वहां की हालत यह है कि वहां ग्रासिम की ओर से एक अवैध रुप से क्रेशर स्थापित किया गया है और बार-बार शिकायत करने के बाद, उन्होंने कलेक्टर कोटपूतली को भी कहा, अन्य अधिकारियों से भी कहा है, इसके बावजूद आज तक उस समस्या का समाधान हो नहीं पाया। आज वहां श्वास लेना भी दूभर हो रहा है। पिछली कांग्रेस के समय से लगातार वहां पर पांच साल तक धरना चलता रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को भी अवगत कराना चाहता हूं, पांच साल लगातार धरना चला, लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने जाकर यह नहीं कहा कि आप यहां धरना क्यों दे रहे हो और धरने को समाप्त क्यों नहीं करते हो। सभापति महोदय, यह बहुत सेंसेटिव बिन्दु है, इसलिए मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि तत्काल प्रभाव से उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो और जो अवैध रूप से, बिना किसी एनओसी के वहां पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेशर लगाया गया है, उसकी जांच होनी चाहिये। उस गांव का पुनर्वास किया नहीं किया गया है। वहां ग्रासिम सीमेंट वालों ने कांग्रेस पार्टी के कुछ दलाल पकड़ रखे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिये और पुनर्वास किस प्रकार से हो सकता है, इतने वर्ष क्यों लगे? जब जमीन एक्वायर हो गई, किसानों को पैसा दिया नहीं गया। आज पुनर्वास किया गया होता तो मैं समझता हूं कि हमारे उन किसानों का और ज्यादा विकास हो सकता था। आज खाना, खाना तो बहुत दूर की बात है, वहां श्वास लेना दूभर है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं अल्ट्राटेक के खिलाफ जांच बैठाकर इस पूरे विषय की जांच कराई जानी चाहिये

और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही हो और जो लगातार पांच साल से हमारे किसान भाई धरने पर बैठे हैं, उनको उठाकर उनका सम्मान होना चाहिये।

सभापति महोदय, बहुत सारे विषय अभी मेरे छूट गये हैं, लेकिन मैं समय की बाध्यता को समझता हूं। आपको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ललित यादव।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका और प्रतिपक्ष के नेता का धन्यवाद करता हूं।

आज यहां सभी साथियों ने अपनी-अपनी बात रखी है। नौजवान पर भी बात हो रही है, महिला विकास पर भी बात हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के अनुसार 15-29 आयु के नौजवनों को युवा माना और आबादी का 27.5 परसेंट हिस्सा उनका इस देश में है। माननीय सभापति महोदय, हमने बड़ी-बड़ी चर्चा की, लेकिन आज नौजवान के ऊपर चर्चा का विषय है कि हम जवान को रोजगार कैसे दे सकते हैं? 4 लाख नौजवानों को रोजगार की बात आपने यहां कही है कि हम पांच साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। वह 4 लाख नौकरी कहां देंगे, किसको देंगे, प्राइवेट देंगे, सरकारी देंगे, गैर सरकारी देंगे, इसका आपने कहीं अभी तक जिक्र नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार के लिये ईको सिस्टम विकसित करें, जिससे कि नौजवान को रोजगार मिल सके। बेरोजगारी के हालात आज किस प्रकार के देश में और प्रदेश में बने हुए हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज 60 परसेंट से ज्यादा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार में बहुत सारे निजी क्षेत्र में मेगा फेयर का आयोजन किया गया, जिनसे बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिला और बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिला। आज शासन में भारतीय जनता पार्टी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के रोजगार फेयर लगवाये जाएं ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके।

राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक हम लोगों ने पिछली सरकार में चालू किया, जिसमें 59 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा आंकड़ा है। इस प्रकार के कार्यक्रम अगर चालू हो, भले ही आप नाम अपनी मर्जी के अनुसार रखें, लेकिन इससे प्रदेश में एक फ्रेंडली वातावरण बनेगा और हमारा नौजवान आगे बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नीमराना औद्योगिक जोन है, इसमें देशी-विदेशी कंपनियां वहां लगी हुई हैं। गिलोट में भी औद्योगिक जोन है। मेरे वहां शाहजहांपुर में औद्योगिक जोन है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां लोकल नौजवान को रोजगार नहीं

मिलता है। मैंने पहले भी सदन में इस बात की चर्चा की है कि सबसे बड़ी चिंता किसी बात की है तो आज वह नौजवान के रोजगार की है। एक माता-पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है कि पढ़-लिख कर यह नौकरी करेगा और परिवार चलाने का काम करेगा। अपने खून-पसीने की कमाई अपने बेटे पर न्योछावर करता है और जब पढ़-लिख कर वह आता है तो सरकारी नौकरी तो नहीं मिल पाती, लेकिन सभापति महोदय, जब वह निजी कारखाने में जाता है तो उसको यह कह कर बाहर भेज दिया जाता है कि आप यहां के स्थानीय नौजवान हो, इसलिए आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि कोई नीति बने, जिस नीति में लोकल नौजवान को रोजगार मिले, जिससे वह नौजवान अपना पेट और अपने परिवार को पाल सके। आज नीमराना में औद्योगिक जोन लगा है, वह पूरा इलाका प्रदूषित हो रहा है, वह हम लोग झेल रहे हैं। हमारी बिजली काम में ली जा रही है, हमारा पानी खतम हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं ,जो कंपनी के गंदे पानी को जमीन में बोरिंग करके वापस डालने का काम कर रही हैं। इससे बड़ी बीमारियां फैल रही हैं, वह भी हम लोग झेल रहे हैं और फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा। इसलिए मैं पुरज़ोर तरीके से आपसे मांग करता हूं कि सरकार कोई कानून बनाये और उस कानून के तहत हमारे इलाके के नौजवान को रोजगार मिल सके।

सभापति महोदय, एक सीएसआर का फंड है, अगर मेरे इलाके में कंपनी लगी है तो वह सीएसआर का फंड भी मेरे इलाके में खर्च हो, जिससे वह इलाका डवलप हो सके। लेकिन सीएसआर फंड लगाने के नाम पर बंदरबाट होती है और न जाने वह पैसा कहां जाता है। मेरे इलाके में 200 कंपनी लगी हैं, लेकिन आज वहां बद से बदतर हालात हो रहे हैं। स्कूलों में काम करने की डिमांड करते हैं तो वहां भी काम नहीं करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाये। आपने थीम बेस पार्क डवलप करने की बात की है। वह पार्क जहां हम लोग लगायेंगे, उन पार्कों की जमीन जिन काश्तकारों से लेंगे, उसके बारे में हम लोग चिंता करें कि उसका संरक्षण कैसे करेंगे, कहां उसको सुविधा उपलब्ध करायेंगे?

सभापति महोदय, मैं महिलाओं के बारे में दो बात कहना चाहता हूं। आज जिस प्रकार की पुरुषवादी सोच इस प्रदेश और देश में है, महिलाओं का स्थान कहां है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। भले ही सदन में आकर हम बड़ी-बड़ी बात करते होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो उनको अधिकार मिलना चाहिये, वह अभी तक भी नहीं मिल पाया है। मैं महिलाओं के लिये कहना चाहता हूं:-

कोमल है तू कमजोर नहीं, सख्ती का नाम ही नारी है,
जग को जीवन देने वाली नारी है, मौत भी तुझसे हारी है।
सतियों के नाम पर तुझे जलाया गया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा भी तेरी हुई
बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है।
कोमल है तू कमजोर नहीं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र बने हैं, उन केन्द्रों की प्रोपर हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। हमने घोषणा तो कर दी कि 5-5 हम नये केन्द्र बनायेंगे, लेकिन जो पुराने केन्द्र जर्जर हालत में हैं, उनके बारे में हम लोगों ने चिंता नहीं की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके बारे में हम चिंता करें। आज जिस प्रकार का वातावरण प्रदेश में बना है, महिला अपराध किस प्रकार से बढ़ रहा है, उस पर भी हमें चिंता करनी चाहिये। माननीय खड़गे साहब ने लोकसभा में एक कविता पढ़ी थी, वह मैं पढ़ना चाहता हूं:-

बेटी दी है रब ने, बेटी का हिसाब क्या देते
सवाल सारे गलत थे, तो तुम जवाब क्या देते।
आज जिसकी आवाज को तुमने कदमों तले दबा दिया
रुख मोड़ दे आंधी का वो, तुम अधिकार तो देते।

msk/rtm/23.07.2024/1850/3q

अधिकार मिले तो महिला निश्चित रूप से इस देश के अन्दर बड़ी क्रान्ति ला सकती है। मणिपुर की हालत आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार के हालात मणिपुर में हो रहे हैं।

श्री सभापति: श्री अंशुमान भाटी।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): सभापति महोदय, केवल आधा मिनट चाहूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले आपने 128वां संशोधन कर महिला आरक्षण विधेयक, 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और आपने कहा कि महिलाओं को आरक्षण का काम करें।

श्री सभापति: श्री अंशुमान सिंह भाटी। अंकित नहीं होगा।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): 000

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं सर्वप्रथम हमारे मुख्य मंत्री श्री भजन लाल का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस बजट घोषणा में हमारे बीकानेर को सेरेमिक हब बनाने की बात रखी। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत के अन्दर बोलक्ले, फायरक्ले, वाइट क्ले का अथाह भण्डार है। पर यहां पर मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण यहां पर जो खनिज, क्ले पाया जाता है, उसको पकाने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा के माध्यम नहीं है। इसी कारण प्रतिदिन तकरीबन 400 ट्रक 750 किलोमीटर दूर मोरवी जाते हैं और हमारी इसी क्ले को वहां पर मौजूद सैंकड़ों फैक्ट्री गैस के माध्यम से पकाकर उनसे वैक्ट्रिफाइड टाइल्स बनाती हैं और सेनेटरी वेयर बनाती हैं। हमारे कोलायत के अन्दर सभी परिस्थिति अनुकूल है। हमारे पास खनिज भी है, नहर का पानी भी है। हमारे युवा मेहनती भी हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों उद्योग लगाने के लिए आधारभूत मूल सुविधाएं देनी हैं। इसी क्रम में मैं मांग रखता हूं कि मोरवी की तर्ज पर कोलायत में भी एक गैस पाइपलाइन बिछायी जाये। जिससे

हमारा सेरेमिक उद्योग बढ़ सके।

(समयः)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

मैं एक और मांग रखता हूं। एक सुझाव देता हूं कि कोलायत क्षेत्र लगातार सोलर हब के तौर पर विकसित हो रहा है तो क्यों न एक डेडीकेटेड सोलर पार्क ही बना दिया जाये, जिससे जो भी बिजली उत्पन्न होती है, उस बिजली को हम रियायती दरों पर उन तमाम उद्योगों को ऊर्जा दें, जिससे उनको पर्याप्त और निर्बाधित बिजली मिले। इससे निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में निवेश आयेगा और व्यापार-व्यवसाय बढ़ेगा, विकास भी होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

हमारे बीकानेर जिले का तकरीबन 70 प्रतिशत खनिज उत्पादन मेरे विधान सभा क्षेत्र से आता है। हमारे बीकानेर के अन्दर खनन गतिविधियों से तकरीबन 25 करोड़ का डीएमएफट फंड आता है। इस डीएमएफटी फंड में से तकरीब 17 से 18 करोड़ तो हमारे कोलायत विधान सभा क्षेत्र का योगदान है। परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कोलायत के विकास की बात की जाती है तो हमें मात्र 8 से 10 करोड़ रुपये थमा दिये जाते हैं। जो विधान सभा क्षेत्र 70 प्रतिशत डीएमएफटी को योगदान दे रहा है, उसको मात्र 30 से 40 प्रतिशत डीएमएफटी का फंड दिया जाता है। कई बार तो जिला प्रशासन व राजनीतिक दबाव के कारण डीएमएफटी उन क्षेत्रों को दे दिया जाता है, जहां पर कभी किसी प्रकार का खनन कार्य हुआ ही नहीं हो। मेरी राज्य सरकार से यह मांग है कि जिन ग्रामीणों की जमीनें, चरागाह छीन लिये गये, जो बेरोजगार हुए, जिनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो दिन-रात खनन क्षेत्र में होने वाले धुएं, शोर-शराबे के अन्दर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन प्रभावित लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए डीएमएफटी फंड का उपयोग किया जाए। जिस ग्रामीण क्षेत्र में खनन हुआ, पर्यावरण को नुकसान हुआ, जहां पर रोडें टूटीं, पानी की पाइपलाइन टूटी, उन गांवों के विकास के लिए अपन को बात करनी चाहिए, वहां डीएमएफटी का फंड खर्च किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 8 से भी अधिक 200-300 मेगावाट पॉवर के सोलर प्लांट लगे हुए हैं, दो बड़े थर्मल प्लांट लगे हैं, सैंकड़ों 2-3 मेगावाट के प्लांट लगे हुए हैं। इनके थ्रू करोड़ों का सीएसआर फंड बनता है, परन्तु हमको ये सीएसआर फंड पूर्ण रूप से नहीं देते। जब हम कभी दबाव देते हैं तो औपचारिकता निभाते हुए खुद की कंपनी की सीएसआर की जिम्मेदारियों से भागते हुए, उनसे पल्ला झाड़ते हुए, वे कोई डेढ़-दो लाख रुपये एक विधान सभा क्षेत्र को देते हैं, उसमें भी कोई टिफिन, कोई पेंट, कोई शर्ट, कोई प्याऊ बनाकर खुद की जिम्मेदारियों से हाथ धो लेता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो क्षेत्र सालाना करोड़ों का राजस्व देता है, क्या उनके लिए दो लाख रुपये कोई रेवड़ी से कम हैं? यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है। जिला प्रशासन और राजनीतिक दबाव के कारण सीएसआर और डीएमएफटी फंड गैर-जरूरी अनावश्यक कार्यों के उपयोग में लिया जाता है। जब हम पूछते हैं

कि साहब हमारे सीएसआर, डीएमएफटी का क्या हुआ तो वहां जिला प्रशासन यह बात कहता है कि हमने तो जिला मुख्यालय के अस्पताल और शिक्षा के लिए आपका डीएमएफटी और सीएसआर फंड इस्तेमाल कर लिया। हमने ऐसा गुनाह किया कि आजादी के 77 साल बाद भी हमको 200 किलोमीटर दूर जाकर खुद के बच्चों का, बहन-बेटियों का इलाज कराने के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। क्यों न, वहां पर ही गांव में, तहसील स्तर पर, उप खण्ड स्तर पर इस सीएसआर और डीएमएफटी से एक ऐसी व्यवस्था की जाये, जिससे गांवों के अन्दर पलायन भी रूकेगा और हमारे सभी बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, उनको बढ़िया व्यवस्था मिल सकेगी। इन सारी मूलभूत सुविधाओं पर हम सभी ग्रामीणों का भी बराबर अधिकार है।

इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कहने को गजनेर रीको और बज्जू रीको कार्यरत है, परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हकीकत में वे सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण यहां इतने सालों में एक भी उद्योग नहीं बना और अगर अपन उम्मीद करते हैं कि बिना कोई सुविधा दिये कोई उद्योगपति यहां उद्योग लगायेगा तो यह बिल्कुल गलत है। रीको ने बेशकीमती आबादी के विस्तार वाली भूमियां रोक रखी हैं। रीको ने चरागाह जमीन भी नहीं छोड़ी। उनको अवाप्त करके रोक रखा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि रीको बज्जू और रीको गजनेर में सड़क, पानी, रहने जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, इससे क्षेत्र में निवेश आयेगा, विकास होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

हमारे क्षेत्र के अन्दर योग्य प्रतिभाशाली युवाओं की कोई कमी नहीं है। उनकी खेल में रूचि भी बहुत है। परन्तु मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण वे अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। कोलायत और बज्जू मुख्यालय में अत्याधुनिक खेल मैदान तैयार किया जाये, जिससे युवा राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभा सकें। जो युवा फौज में जाना चाहते हैं और राष्ट्रीय खेलों में भगा लेना चाहते हैं, उनकी सभी प्रतिभा को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे युवाओं का शारीरिक, मानसिक और आत्मीय विकास भी होगा। साथ ही, युवा बेहतर मनुष्य बन पायेंगे। अंत में, मैं यह बात कहूंगा कि हमारा बीकानेर जिला पूर्व में एशिया की सबसे बड़ी ऊन उत्पादन की मंडी थी। यहां का कालीन उद्योग तो विश्व में अलग ही पहचान रखता था। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक मगरा ऊन है, जो कि विश्व विख्यात है। इस मगरा ऊन की खासियत यह है कि इसका जो फाइबर है, इसका जो रेशा है, इसकी व्हाइटनेस, सॉफ्टनेस विदेश न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया की ऊन के बराबर है।

पशुपालन राजस्थान का सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। हम लगातार सोलर के नाम पर, इंडस्ट्रीज के नाम पर, हमारे खुद के गोचर, ओरण, हमारे चरागाह इन सभी इंडस्ट्रीज को देते आ रहे हैं। चाहे ऊंट हो, भेड़ हो, चाहे बकरी हो, इनको स्टॉल फीडिंग करके कोई भी गरीब आदमी नहीं पाल सकता है। इनको चरने के लिए चरागाह भी चाहिए, खुला क्षेत्र भी चाहिए। चरागाह का क्षेत्र लगातार घट रहा है और ऊंट, भेड़, बकरी की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, जिससे उलटा क्षेत्र के अन्दर रोजगार कम ही हो रहा है। आये दिन सरकार

कहती है कि हम पशुपालन केन्द्र खोल रहे हैं, जब भविष्य में ये ऊंट, भेड़, बकरी नहीं बचेंगे तो इन पशुपालन केन्द्रों और ऊन मंडियों का क्या औचित्य रह जायेगा? (समय समाप्ति सूचक घंटी)

हम चाहते हैं कि ऐसी औद्योगिक नीति बने और ऐसी ऊन नीति बने, जिसमें अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान से, ग्रामीण से, पशुपालक से व छोटे-मोटे सभी उद्योगपतियों से वार्ता करके, उनके सुझाव लेकर एक नीति बनायी जाये, न कि एसी में, एक हॉल में बैठकर निर्णय लिया जाये।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर पश्चिमी राजस्थान को पूरे देश का सोलर हब बनते हुए हम देख रहे हैं। सोलर लगना अनिवार्य भी है, ग्रीन एनर्जी आनी भी चाहिए। परन्तु हमको यह बात देखनी पड़ेगी कि जब सोलर लगता है तो उसकी भूमि जब तैयार की जाती है तो अशिक्षित लोग या तो जमीन बेच देते हैं या लीज पर दे देते हैं। जब उन युवाओं के पास जमीन नहीं बचती है तो उनके पास कृषि कार्य भी नहीं बचता। जब कृषि कार्य नहीं बचता तो वे मजबूरन आकर बेरोजगार हो जाते हैं और वे गलत संगत में पड़कर इन नशों में पड़ जाते हैं। नशे के कारण वे चोरी और आपराधिक गतिविधियों में भाग लेने लग जाते हैं। इसी प्रकार हम देखते आ रहे हैं कि हमारी धरोहर खेजड़ी है, जो हमारे राज्य का पेड़ है। हमारे जाल, हमारे कुमट, हमारी कैर ऐसी जितनी भी स्थानीय वनस्पति हैं, उनको लगातार सोलर वाले काटते आते हैं। नियम में यह बात कही भी है कि एक की जगह तीन पेड़ लगाने हैं। कई कहते हैं कि एक की जगह दस पेड़ लगाने हैं। परन्तु मेरा चैलेंज है, हकीकत में एक भी जगह, आठ-दस सालों के अन्दर एक भी सोलर प्लांट ने पेड़-पौधे नहीं लगाये। एक तरफ हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम मूकदर्शक बनकर देखते हैं और हमारी आंखों के सामने पेड़ काट दिये जाते हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। इसी प्रकार से हाइटेंशन लाइनें भी लगातार देखता आ रहा हूं। हर एक के खेत में लगा दी जाती है। उनकी इच्छा के विपरीत लगा दी जाती है।

श्री सभापतिः विराजिये।

mdp/rtm/23.07.2024/19:00/4a

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): हुकम, बस आधा मिनट।

मैं कहता हूं कि हमारे से रोजगार छीन लिया जाता है। हमारी जमीनें हमसे छीन ली जाती हैं। हमारा भाईचारा खतम हो जाता है। भाई को भाई का दुश्मन बना दिया जाता है। सामाजिक समरसता खतम हो जाती है। हमें अपराधी बना दिया जाता है। परंतु जब रोजगार की बात आती है, तब हमारे गांव वालों को, गांव के बच्चों को रोजगार के लिए यहां से 1000-1500 किलोमीटर पलायन के लिए रोजगार देखना पड़ता है। आपने रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः विराजिए। धन्यवाद। श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, महिला एवं बाल विकास मांग संख्या 32 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महिलाओं का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है, जब वे खुद का रोजगार स्थापित करें। हमारी महिला बहिनों में एक से बढ़कर एक हुनर छिपे हुए हैं। वैसे तो इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं है, क्योंकि उन योजनाओं की जानकारी हर महिला तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। कुछ महिलाओं तक पहुंच भी जाती है तो जो सीधी-साधी गांव की महिलाएं हैं, वे खुद का व्यापार कैसे शुरू करें, इसकी जानकारी नहीं होती।

माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है कि महिलाओं के लिए हर जिले में जिला हैडक्वार्टर पर महिला रोजगार केन्द्र खोले जाए। उसमें महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिनके तहत महिलाओं को तरह-तरह के रोजगार के बारे में अच्छी तरह से समझाया जाए। उनकी रुचि के अनुसार उनका खुद का रोजगार स्थापित करने में उनकी मदद करने के लिए अधिकारी नियुक्त किये जाएं। अधिकारियों को पाबंद किया जाए एक फिक्स टारगेट के साथ कि महीने में कम से कम हजार महिलाओं को, सभी तरह की योजनाओं की जानकारी देकर उनका रोजगार शुरू कराया जावे, जिससे गांव में रहने वाली सीधी-साधी, अनपढ़ महिलाएं भी अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। तभी महिलाओं का विकास हो सकता है और हमारी माता बहनें, ज्यादातर गांव में रहती हैं, उनके अन्दर बहुत-से हुनर छिपे हुए हैं। मैं चाहती हूं कि अनपढ़ महिलाओं और पढ़ी लिखी महिलाओं के अलग-अलग तैयार कराया जाए ताकि वे आगे काम कर सकें। अलग-अलग प्रशिक्षण दिया जाए। उनकी सही तरीके से आर्थिक मदद की जाए और उनको सरल तरीके से जल्दी से जल्दी लोन दिलाया जावे।

मैं यह भी निवेदन करूंगी कि प्रशिक्षण लेकर भी महिलाएं सुरक्षा की दृष्टि से अन्य जगह काम करने नहीं जा पातीं। मैं यह चाहती हूं कि गांव की महिलाओं को गांव में ही प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जावे और शहर की महिलाओं को शहर में प्रशिक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री लादु लाल पितलिया।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): खजुरिया श्याम की जय। सभापति महोदय, मांग संख्या 32 व 26 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी विधान सभा क्षेत्र में 3 बाल विकास परियोजनाएं आती हैं, रायपुर, सहाड़ा, सुवाणा। तीनों परियोजनाएं मिलाकर विधान सभा क्षेत्र में कुल 453 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। इसमें सरकार ने इसी वर्ष 44 मिनी केन्द्रों को पूर्ण केन्द्रों में क्रमोन्नत किया है। मिनी केन्द्रों को पूर्ण केन्द्रों में क्रमोन्नत करने पर कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। इसके लिए राज्य सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद। मिनी केन्द्रों पर पहले एक मानदेय कार्यकर्ता थी, अब दो होगी। यानी

महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार एवं मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार।

सभापति जी, मैं राज्य सरकार का ध्यान आंगनबाड़ी केन्द्रों पर होने वाली समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जो कार्यकर्ता, सहायिका के रिक्त पदों को भरने हेतु कुंवारी लड़कियों को फार्म भरने की पात्रता दी है, श्रीमान यह न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि इसकी योग्तया 12वीं क्लास पास है। 12वीं के बाद लड़कियों का विवाह अन्यत्र होने से आंगनबाड़ी केन्द्र पर पद रिक्त हो जायेगा। पुनः चयन प्रक्रिया में समय व धन दोनों लगता है। श्रीमान इस पर पुनः विचार फरमावे। इससे आंगनबाड़ी का उद्देश्य एवं सेवाएं बार-बार बाधित होंगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तीनों परियोजनाओं में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद रिक्त हैं एवं महिला पर्यवेक्षक के लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं। अगर मूल मॉनिटरींग के पद रिक्त रहते हैं तो आंगनबाड़ी केन्द्र सुचारु रूप से चलना संभव नहीं है क्योंकि एक कहावत है कि भय बिना प्रीत नहीं। अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि रिक्त पदों को भरा जाए।

सभापति जी, रिक्त पदों को भरने हेतु मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि दस वर्ष अनुभव वाली कार्यकर्ता, परीक्षा के बाद महिला पर्यवेक्षक पद हेतु पात्र हो जाती है। ये भर्तियां निरंतर आयोजित करवाई जाएं, जिससे महिला पर्यवेक्षक के पद के लिए रिक्तियों में कमी आयेगी। महिला पर्यवेक्षक पद की नियमित डीपीसी होती रहे, जिससे सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद व बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद रिक्त रहता है, वह रिक्त पदों को भरने में बहुत सहायक साबित होगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों को निजी स्कूलों में संचालित प्ले ग्रुप की तरह विकसित किया जावे ताकि बच्चों का रूझान बढ़े। इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं के साथ केन्द्र की चार-दीवारी एवं बच्चों के खेल केलिए सामग्री उपलब्ध कराई जावे। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ता के लिए टेबल कुर्सी उपलब्ध कराई जावे।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना, जिसका समस्त कार्य ऑनलाइन किया जाता है। इस योजना में द्वितीय प्रसव में लड़का-लड़की होता है, उसको राज्य सरकार द्वारा 6 हजार रुपये तीन किश्तों में दिए जाते हैं। योजना का 90 प्रतिशत डाटा पीसीटीएस पोर्टल, चिकित्सा विभाग से प्राप्त होता है और इसको पूर्ण करने की शत-प्रतिशत जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक को दे रखी है, जो न्याय संगत नहीं है। यह पूरा कार्य चिकित्सा विभाग से करवाया जाना चाहिए। उड़ान योजना, महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित है, लेकिन इसका समस्त कार्य बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से कराया जाता है, जो न्याय संगत नहीं है। यह योजना चिकित्सा विभाग को दी जाए, क्योंकि आशा अब चिकित्सा विभाग में कार्यरत है। विभाग में विभिन्न योजनाएं जैसे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, प्रधान मंत्री मातृ वंदन योजना, उड़ान योजना आदि के

लिए सरकार ने एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की थी। वर्तमान में किसी भी कार्यालय में ऑपरेटर के पद नहीं है, जिससे योजनाओं के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। यह समस्त कार्य महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से करवाया जा रहा है। अतः कार्य को सुचारु व गतिशील बनाने के लिए ऑपरेटर लगाना आवश्यक है।

इस विभाग की नींव की ईंट एवं प्रथम कड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की इन समस्याओं का समाधान अति आवश्यक है। अगर इन समस्याओं का समाधान होता है तो प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आपको दुआएं देंगी। आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों की मरम्मत अति आवश्यक है। कई आंगनबाड़ी केन्द्र पुराने हैं, जिनमें छत, दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके खराब होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साफ-सफाई नहीं रख पाती हैं, इसलिए केन्द्रों पर अभिभावक बच्चे नहीं भेजते हैं। छत, भवन मरम्मत पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बार-बार अवगत कराया जाता है कि वर्तमान में जो पोषाहार आपूर्ति किया जा रहा है, वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से बच्चों की उपस्थिति कम रहती है। पोषाहार बदला जावे। विगत वर्षों से आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों का मानदेय दो किश्त में जमा होता है, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार, जिससे समय पर मानदेय नहीं मिल पाता। अतः भुगतान व्यवस्था अलग-अलग नहीं होकर एकमुश्त भुगतान किया जावे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आए दिन विभिन्न विभागों द्वारा एवं अन्य सर्वे, रेलियां, चुनाव, पल्स पोलियों आदि कार्य संपादित करवाए जाते हैं, जिससे इनका मूल विभागीय कार्य बाधित होता है। महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के लिए अलग से भवन बनाये जावे। महिला अधिकारिता विभाग में प्रचेताओं के अधिकांश पद रिक्त हैं, जिससे इनका चार्ज महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक को दिया जाता है, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्र का पर्यवेक्षण एवं कार्य बाधित होता है।

Ans/rtm 19.10 4b 23.07.2024

अतः महिला अधिकारिता विभाग में प्रचेताओं के सभी रिक्त पद भरे जाए। मंत्री महोदय, 100 प्रतिशत बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद भरने का ऐसा फार्मुला बताना चाहता हूं जो पूर्ण रूप से न्यायसंगत है तथा जिससे राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा तथा प्रशिक्षित अधिकारी मिलेंगे। आपके विभाग में सरकार बनने के बाद मंत्रालयिक वर्ग में निरन्तर डीपीसी के माध्यम से कई मंत्रालयिक कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं, जिससे विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों में हर्ष है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को निवेदन है कि आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि इन पदोन्नतियों से कई मंत्रालयिक कर्मचारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन अधिकारी बने हैं जो राजपत्रित हैं।

श्री सभापतिः शीघ्र पूर्ण करें।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): एक मिनट।

मेरे सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में खेलों की दृष्टि से पिछड़ापन है। साहडा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाने की आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, गंगापुर, रायपुर में बड़े स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश के ग्रामीण बालक-बालिकाओं को विभिन्न खेलों के प्रति प्रोत्साहन हेतु उपकरण व किट्स उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मेरे गंगापुर में सिथेंटिक ट्रेक बनवाने की आवश्यकता है। प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर खेल एकेडमी बनाने की आवश्यकता है। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में खिलाडियों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण ट्रेनर की आवश्यकता है, जिससे खिलाड़ी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर जाकर सहाडा विधान सभा क्षेत्र का नाम रोशन करे। मेरे रायपुर में इंडोर स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया,बहुत-बहुत धन्यवाद। जय-जय श्री राम। गो माता की जय।

श्री सभापतिः श्री अभिमन्यु।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): सभापति महोदय, मांग संख्या 26,32 व 56 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर हमें राज्य में युवा का असली मायने में विकास करना है तो सबसे पहले गांव में रहने वाले युवा को शिक्षा खेल, उद्योग के माध्यम से रोजगार युक्त करना पड़ेगा, तब जाकर राज्य व देश का युवा बेरोजगार मुक्त होगा। राज्य के बजट में चार लाख नौकरियों की घोषणा की गई। युवाओं के लिए बजट में की गई घोषणाओं, भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए, विभागवार नौकरियों का आंकड़ा जारी क्यों नहीं किया जा रहा। आपके संकल्प पत्र में पेज संख्या 34 के बिन्दु संख्या 6 में भर्तियों का कलेण्डर जारी करने की बात कही गई है

पूरे देश में, राजस्थान में पेपर लीक को लेकर अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। एनटीए देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी है, जो मेडिकल व इंजीनियरिंग की परीक्षा करवाती है। जिसके माध्यम से हमारे युवा, देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में, एम्स मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी में पढ़ रहे हैं। नीट यूजीसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबके पेपर लीक हो गए। कई गिरफ्तारियां भी हुईं। इस पर 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, परन्तु किसी भी भाजपा के नेता ने एक शब्द नहीं बोला। अब क्या हो गया, सत्ता में आते ही युवाओं की चिंता खतम हो गई।

नीट पेपर को लेकर जब मीडिया ने शिक्षा मंत्री जी से पूछा तो वह योग की बात करते है। यह समय एक दूसरे पर छींटा कसी का नहीं है। आपकी सरकार है, आप भारत सरकार को लिखो, नीट परीक्षा में 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज गांव शहर के गरीब का बच्चा आशा लिए हमारी ओर देख रहा है। यह सदन कुछ निर्णय करेगा, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय जी को अवगत कराना चाहता हूं कि सफेद पाउडर, हेरोइन में हनुमानगढ़, गंगानगर ज़िले के युवा साथी लिप्त हैं। यह घटना, इस महीने के भास्कर अख़बार की है। 75 दिन में 40 मौतें हुईं, उसमें 21 से 25 वर्ष के युवा साथी है, जो

10वीं व 12वीं के मेधावी छात्र हैं। बोर्डर का क्षेत्र होने के नाते 21 हजार करोड़ की गुजरात में हेरोइन पकड़ी जाती है। 270 करोड़ की सांचौर में पकड़ी जाती है। इस पर अंकुश कब लगेगा, कैसे लगेगा, सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। आज 25 बेड़ के नशा मुक्त केन्द्र से युवाओं का विकास नहीं हो सकता। अगर युवओं का सही मायने में विकास करना है, हमें हर पंचायत स्तर पर, खेल के माध्यम से युवाओं का विकास करना पड़ेगा। संगरिया विधान सभा में एक भी खेल स्टेडियम नहीं है। वहाँ के बच्चे, बड़े गांव हैं, डाबा हो, बोलावाली हो, लुकेरा हो, सीववाला खुर्द हो, तलवाड़ा हो, जहां पर अनेक प्रकार की भूमि पड़ी है, इर्रिगेशन की है, नगरपालिकाओं में है, मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां एक खेल स्टेडियम की घोषणा करने की कृपा करें।

श्री सभापतिः शीघ्र समाप्त करें।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का समय चाहिए।

उद्योग के नाम पर मैं यह कहना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ ज़िले में एक मात्र सरकारी उद्योग था, स्पिनिंग मिल 1980 से संचालित हुई, भीलवाड़ा में गुलाबपुरा के साथ इसको अटेच किया गया। 800 कर्मचारी इस उद्योग में थे, उसको बंद कर दिया गया। भाजपा सरकार उस समय थी, उसके बाद दस साल से इसको दुबारा चालू नहीं किया गया। टिब्बी नगरपालिका में एथेनॉल के नाम पर एक उद्योग स्थापित किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा से जो नहरें आती है, उसका पानी अशुद्ध है। कैंसर के रूप में संगरिया व टिब्बी वह पानी पी रहा है। वहां पर एथेनॉल की फैक्ट्री, टिब्बी में मात्र दो किलोमीटर पर वह फैक्ट्री लग रही है। मैं निवेदन करता हूं कि उस उद्योग को बंद करवाया जाए। वहां चावल की खेती होती हे। कपास, नरमा की खेती होती है, उसमें किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न नहीं हो।

हमारा संगरिया क्षेत्र चावल का क्षेत्र है। वहां राइस मिल, सरकारी उद्योग लगाया जाए। संगरिया व टिब्बी में एक भी सरकारी उद्योग नहीं है। जो उद्योग वहां लगे, उनमें 75 प्रतिशत नौकरी वहां के स्थानीय युवाओं को दी जाए, मैं यह सरकार से निवेदन करता हू। आंगनबाड़ी में महिलाएं सेवा देती है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राज्य सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आंगनबाड़ी कर्मचारी, सहायिका, सहयोगिनियों को 18 हजार रुपये प्रदान किए जाए। अतिरिक्त कार्य, जिसका उनको कोई भुगतान नहीं मिलता...

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): जैसे चुनाव डयूटी हो, विद्यालय सर्वे हो, पेंशनर हो, विधवा हो, पालनहार हो, उन महिलाओं का विकास तब होगा, जब हमें उन्हें उचित पेंशन देंगे, तब जाकर हम इस राज्य के विकास में भूमिका निभा सकते हैं।

श्री सभापतिः धन्यवाद। विराजे। श्री धर्मपाल।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): हमारे नौजवान मंत्री हैं। मेडल लेकर आए हैं। पूरा राज्य युवा मंत्री की तरफ देख रहा है। धन्यवाद।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 26, 32 व 56 पर आपने मुझे

बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। यहां आज पूरे दिन युवा, खेल व उद्योग के बारे में चर्चा हुई। हर व्यक्ति ने अपने-अपने हिसाब से युवा को, खेल को परिभाषित किया। उद्योग के बारे में अपनी आवश्यकताएं और वर्तमान में जो चल रहा है, उसके बारे में बताया।

सभापति महोदय, हमारे शेखावाटी में युवा की परिभाषा अलग होती है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे शेखावाटी में यह नहीं कहा जाता कि जिसकी उम्र 18 से 25 साल होती है वह युवा होता है। युवा वह भी नहीं होता जिसके सर के बाल काले होते हैं। युवा वह भी नहीं होता जो जींस की पेंट और गदर स्टाइल की टी शर्ट पहनता है। हमारे शेखावाटी में तो युवा वह होता है जिसके पैरों में गरीब आदमी को साथ लेकर चलने की शक्ति होती है, जिसके सीने में मातृ ए हिंद पर मर मिटने का जज्बा होता है और जिसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की आग होती है, उसको युवा कहते हैं। ऐसे युवा को हमारे देश में रोजगार की तलाश है।

मेरे एक मित्र ने बहुत सही बात कही। मुझे बहुत पसंद आई। हमारे देश में हर ग्राम पंचायत स्तर पर अगर खेल के मैदान बना दिए जाए, खेल के ट्रेक बना दिए जाएं, सिंथेटिक ट्रेक बना दिए जाएं, खेल के मैदान में सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएं, तो शाम के समय युवा शराब के ठेके पर जाने की बजाय खेल के मैदान में पसीना बहाते हुए नजर आएगा।

VPS-RTM-23.07.2024-19.20-4c

यह बात बहुत ही प्रसन्नता की बात है मेरे लिए और पूरे सदन के लिए और आप सभी के लिए कि एक नौजवान विधायक ने यह बात कही है तो मैं यह समझता हूं कि हमारे देश में युवा की जो दिशा और दशा भटकी है, निश्चित रूप यह रोजगार के अभाव में भटकी है और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना, चाइना की तर्ज पर जब जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या जिस रेश्यो में बढ़ती है, उस रेश्यो में चाइना का एक ही उद्देश्य होता है कि उस रेश्यो में उद्योग को बढ़ावा दे दो अगर हमारे भारतवर्ष में भी हमारी जनसंख्या के हिसाब से, हमारे रेश्यो के हिसाब से अगर उद्योग को बढ़ावा दे दिया जाये तो निश्चित रूप से इस देश का युवा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जावान, सबसे ज्यादा शक्तिवान और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक युवा है तो हिंदुस्तान का युवा है जो कर दिखाने और कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि युवा को रोजगार चाहिए और मैं एक बड़ी विडंबना के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे सदन के अन्दर अलग-अलग तरीके से लोग परिभाषित करते हैं। एक सम्माननीय विधायक ने यह कहा कि हमारे 60 लाख बेरोजगार हैं और दूसरे सम्माननीय विधायक ने यह कहा कि हमारे 80 लाख बेरोजगार हैं तो मैं एक बार सदन से यह मांग करना चाहता हूं नया विधायक होने के नाते कि इन बातों का सत्यापन करने वाला कौन है? कोई एजेंसी है क्या जो हमारी इन बातों का

सत्यापन करे और किसी भी बात का रेश्यो बताया जाता है, किसी भी बात का अगर परसेंटेज बताया जाता है तो पक्ष उसको 80 परसेंट बताता है तो विपक्ष उसको 30 परसेंट ही बता देता है तो इन बातों का सत्यापन करने के लिए कोई ऐसी एजेंसी यहां पर विधान सभा के अन्दर होनी चाहिए। हम लोग नये विधायक आये हैं, हम कन्फ्यूज हैं इस मामले में, जो बात कह दी जाती है अगर वह विपक्ष की तरफ से कही जाती है तो विपक्ष उस पर तालियां बजा देता है और यदि पक्ष की तरफ से कही जाती है तो पक्ष उस पर तालियां बजा देता है तो हम इस बात में टोटल ही कन्फ्यूज हैं तो हमें कोई ऐसी एजेंसी उपलब्ध करवायी जाये सदन के अन्दर जो उस वास्तविक आकड़े का सत्यापन करे और सत्यापन से राजस्थान की असली तस्वीर जाहिर हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि कई बातों का कन्फ्यूजन हमारे इन सात महीनों में हुआ है लेकिन मैं आज जो विषय से भटकने के लिए क्षमा चाहता हूं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मेरे खेतड़ी के बारे में विशेष रूप से कि खेतड़ी कोई राजस्थान या हमारे जिले की ही विख्यात तहसील नहीं है बल्कि खेतड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विख्यात तहसील है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा अगर कोई तांबा संयंत्र है तो वह खेतड़ी के अन्दर है और खेतड़ी के अन्दर आज भी 200 वर्ष का तांबा सुरक्षित है। अगर जिस गति से आज खनन हो रहा है, उस गति से अगर खनन चालू रखा जाये तो 200 वर्ष तक का तांबा हमारे खेतड़ी के अन्दर है। अगर हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्रोजेक्ट को ही सुचारु रूप से चालू कर दिया जाये जिसमें एक वक्त के अन्दर 12 हजार कर्मचारी होते थे और उसके पीछे 60 हजार लोग पेट पालने का काम करते थे। अगर 12 हजार कर्मचारियों की वह ही स्थिति दुबारा से आ जाये पर मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है, उन 12 हजार कर्मचारियों की जगह मात्र 500 कर्मचारी ही वहां पर काम करते हैं, बाकी सब ठेके पर दे चुके हैं और सब लोगों ने यह कहा कि स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार होना चाहिए। जो भी संयंत्र हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर का हो या चाहे प्रदेश स्तर का हो या चाहे स्थानीय स्तर का हो, उसमें स्थानीय और लोकल लोगों की जब तक भागीदारी तय नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से प्रतिभाओं का अपमान होगा।

मैं उद्योग मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर यह एच.सी.एल. के प्रोजेक्ट को ही पूर्णरूप से विकसित कर दिया जाये तो खेतड़ी की बेरोजगारी सम्पूर्ण रूप से खतम हो सकती है और दूसरा, कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में मेरे खेतड़ी के अन्दर एक रीको का औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था। चुनाव के जस्ट छह महीने पहले सिर्फ वोटों की राजनीति और चुनाव की रणनीति के तहत एक जगह जमीन पर बोर्ड लगाकर RIICO लिख दिया और दो जगह पर बोर्ड लगा दिया कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया इतने किलोमीटर लेकिन आज तक वहां पर कोई काम नहीं हुआ। भूमि अवाप्त तो जरूर हुई है लेकिन लैंड एक्वीजिशन पूरा होकर, उसके बाद कोई एन.ओ.सी. की कार्यवाही नहीं की गयी है। सेन्टर की एनवायरनमेंट एन.ओ.सी. आना भी बाकी है तो मैं उद्योग मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि रीको

का अशोक नगर के अन्दर जो प्रोजेक्ट आया है, उसकी अगर सेन्टर से एन.ओ.सी. दें तो मैं समझता हूं कि वह प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के लिए लाइफ लाइन शुरू हो सकता है और लाइफ लाइन बन सकती है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और युवा के मामले में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और शेखावाटी में युवा बड़ा एनर्जेटिक है। जो काम मिलता है उसको ईमानदारी से करना चाहता है और बेरोजगारी की स्थिति में आज जो युवा नशे की तरफ भटक रहा है, अपराध, अत्याचार की तरफ जो बढ़ रहा है, उस पर भी अंकुश लगायें। रोजगार हमारी इन कई बीमारियों को कम कर सकता है इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है और दूसरा एक महिला विकास का हमारा एक मुद्दा इस पर है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आंगनबाड़ी जो केन्द्र है, यह एक मुख्य स्रोत बन गया है हमारे महिला विकास और बाल विकास का तो इसमें अगर आप स्वच्छता से जो गरीब और परिपूर्ण रूप से दरिद्र नजर आते हैं हमारे आंगनबाड़ी केन्द्र वहां पर सुव्यवस्थित और सुसज्जित अगर आंगनबाड़ी केन्द्र होंगे तो बच्चे का स्वास्थ्य शुरू से, बचपन से ही सही रहेगा इसलिए वहां पर आर.ओ. वाटर की व्यवस्था की जाये, वहां पर गैस कनेक्शन की व्यवस्था की जाये और इलेक्ट्रिफिकेशन की भी व्यवस्था की जाये, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आप लोगों से यह आग्रह है कि आपने मुझे सुना और माननीय सभापति महोदय, आप टोकें, उससे पहले ही मैं अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। पुनः एक बार मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री संजय कुमार।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आज मांग संख्या-26, 32 और 56 पर बोलने का मौका दिया गया। मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के पाइंट टू पाइंट अपने मुद्दे रख रहा हूं, क्योंकि मैं काफी प्रभावित हूं हमारे मंत्रीजी से, वे युवा मंत्री हैं, वे खिलाड़ी भी रहे हैं, शूटर रहे हैं, तो मैं उनका काफी सम्मान भी करता हूं।

अभी हम सबने यह कहा था कि खेल मैदान, स्टेडियम तो हमारी माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे की सरकार थी तो उस समय जिला परिषद का मैं मैम्बर था और उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होता है, वहां पर एक खेल मैदान सबके लिए दिये थे, हो सकता है कुछ रह गये हो तो मेरी आप सबसे एक विनती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष से कि जो खेल मैदान है आज के समय में वहां पर क्यों न उनको डवलप किया जाये, क्योंकि वह भी तो ग्रामीण क्षेत्र में ही है। हम जानते हैं कि उसकी चारदीवारी, समतलीकरण, उसमें बेंच लगाना, ट्रैक, हो सकता है कि उसमें कोई कमरा हो तो इनडोर गैम के लिए भी व्यवस्था की जाये तो मैं यह चाहता हूं कि हमारे जो मंत्रीजी हैं युवा मामले व खेल के, यह आपके ही विभाग से उसके लिए अलग से फंड दिया जाये क्योंकि उस

पर काम न तो कोई सरपंच करवाना चाहता है और न ही कोई प्रधान या जिला प्रमुख या कोई एम.एल.ए. इतना फंड दे पाता है तो मैं यह चाहता हूं कि उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो अपना खेल मैदान है, उसका विकास आपके विभाग से अलग फंड से किया जाये तो यह बहुत अच्छा मुझे लगेगा, यह मेरे मन में विचार आये इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया।

साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी मांग संख्या 32- महिला एवं बाल विकास के लिए है, अभी प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए स्वीकृति दी गयी है तो मेरा यह मानना है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों को अगर हम जहां पर जो केन्द्र है, उसके समीप में अगर कोई विद्यालय है तो उस विद्यालय में ही अगर खोला जाये तो बच्चों का विकास और भी अच्छा होगा क्योंकि वह उनकी देखरेख में भी रहेंगे और उनका विकास और आंगनबाड़ी केन्द्र की अच्छी व्यवस्था भी होगी, यह मेरा मानना है।

साथ ही, मैं मंत्री महोदयजी से यह निवेदन करूंगा जो अपनी मांग संख्या 56- उद्योग है, उसके सन्दर्भ में निवेदन है कि मैं एक ऐसे विषम परिस्थिति वाले क्षेत्र से आता हूं बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र से, हमारे यहां पर अभी बाड़ी से आने वाले विधायक महोदय ने भी बता दिया था कि हमारे यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो व्यवसाय है, वह केवल पत्थर व्यवसाय है। हमारे यहां पर पत्थर व्यवसाय के अलावा कोई रोजगार वहां पर है ही नहीं। बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र और बाड़ी विधान सभा क्षेत्र की जो आजीविका है, वह पत्थर व्यवसाय पर ही टिकी हुई है और धौलपुर जिले का नाम है इस पत्थर व्यवसाय से, जिसे हम लाल पत्थर कहते हैं। लाल पत्थर से आगरा का लाल किला, आपके दिल्ली का लाल किला, पार्लियामेंट, नई संसद भवन, सब जगह लाल पत्थर जो गया है वह सरमथुरा क्षेत्र से ही गया है और यह आज पत्थर व्यवसाय जो है वह बिलकुल ही खतम होने के कगार पर है सरमथुरा के अन्दर, बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र और धौलपुर के अन्दर, वह अपनी पहचान खो रहा है। क्यों खो रहा है? उसने पहचान खो दी इसलिए कि क्योंकि वहां पर माइन्स विभाग की उदारतापूर्ण नीति की वजह से यह पूरा सब कुछ चल रहा है क्योंकि बीस-बीस करोड़ रुपये के प्रतिवर्ष के ठेके होते हैं, जहां पर माइनिंग लीज है उसमें पत्थर है ही नहीं और जहां से अपन परिवहन करके लाते हैं, उसको अवैध के नाम पर प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है तो पत्थर व्यवसाय की हड्डी टूट चुकी है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आप कोई स्पेशल पैकेज देकर धौलपुर के लाल पत्थर के लिए, यह धौलपुर का पत्थर है, उसके लिए कोई अलग से पैकेज देकर उस पत्थर व्यवसाय को पटरी पर लाया जाये। यह मेरा आपसे विशेष निवेदन है सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से, कि उस पत्थर व्यवसाय को क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बंशी पहाड़पुर का जो पत्थर है जो नई संसद में लगा है, वह भी फोरेस्ट एरिया में था, लेकिन उसका डायवर्जन करके वहां से पत्थर निकाला गया और जिससे नई संसद बनी है। मैं यह चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर रमधा है,

कछपुरा में माइन्स है, कछपुरा एक हमारा गांव है वहां पर माइन्स है लेकिन उस माइन्स में पत्थर बिलकुल खतम हो चुके हैं, पत्थर है ही नहीं उसके अन्दर अब तो अपना रमधा है, रिजोनी नाके के अन्दर, रिजोनी वन खंड आता है, उर्दूपुरा वन खंड है, बिलोनी है, हरलालपुरा, डोमपुरा, ऐसे हमारे पत्थर की जहां पर खदानें चलती हैं, जिस पर प्रशासन ने काफी लगाम लगा रखी है, फोरेस्ट एरिया के नाम पर अगर इसको डायवर्जन करके डी-फोरेस्ट या डायवर्जन या विमुक्त कर दें फोरेस्ट से तो मैं यह चाहूंगा कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार का, रोजगार मिलेगा और प्रशासन जो अवैध के नाम पर कार्यवाही कर रहा है, उससे राहत भी मिलेगी।

SSY/RTM/23.07.2024/19:30/4d

आप सब जानते हैं कि मेरे धौलपुर जिले के अन्दर पत्थर ही एक व्यवसाय है। अगर हम उसको नहीं बचा पायेंगे तो वहां की आम जनता सड़क पर आ जायेगी। कल मैंने इसके बारे में बोला था। पूर्वी राजस्थान से हमारे क़द्दावर नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदरणीय किरोड़ी लाल जी, वह 3 फरवरी को गये थे क्योंकि सर्व समाज ने उनका स्वागत रखा था। मैं भी उसमें शामिल था क्योंकि वह सर्व समाज का कार्यक्रम था। उसके अंतर्गत उन्होंने खुद मन से यह कहा था कि मैं तीनों विभागों के अधिकारियों को लाकर मीटिंग करूंगा, वन विभाग, राजस्व विभाग और माइंस विभाग, यहां से डिमार्केशन करते हुए इसमें राहत देंगे।

कल संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल जी ने मुझे टोका भी था। जिसकी आज मैं कटिंग भी देना चाहूंगा। कल उन्होंने मुझसे कटिंग का भी कहा कि कोई हो तो बता देना। यह इसमें बिलकुल स्पष्ट है। सर्व समाज के द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। 10 से 15 हजार जनता थी। मंत्री महोदय जी ने वहां किया था। आज आप सब लोग जो सदन में बैठे हैं, आज पूर्वी राजस्थान के अन्दर युवा की आवाज उठाई, पेपर लीक हो चाहे हमारी सरकार के समय, उन्होंने आवाज उठाकर के, आज सत्ता पक्ष उन्हीं की वजह से है। मैं उनका सम्मान करता हूं। आज हम कहने के लिए क्या कह सकते हैं उनके बारे में, आज वह छुट्टी पर हैं। आपकी सरकार में ही उनको आज यह हालत देखनी पड़ रही है। वे हमारे आदरणीय हैं। हमारे धौलपुर के पत्थर व्यवसाय को चार चाँद लगाये तो आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने ही लगाये थे।

मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पहले बहुत गरीबी और भुखमरी रहा करती थी। मैं चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, आप युवा हैं, आप हमारी बात को समझेंगे। माननीय सभापति महोदय, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिये। एक स्पेशल नीति बनाकर के सिर्फ धौलपुर स्टोन के नाम से लाई जाये। जिससे वहां का पत्थर व्यवसाय अपनी पटरी पर आ सके। उससे करीब-करीब 30 हजार लोगों की आजीविका चलती है। उससे 30 हजार लोगों का घर चलता है। यह शोचनीय विषय है कि उसको हम पटरी पर कैसे लेकर आयें क्योंकि वहां फोरेस्ट आता

है। अगर हम वन विभाग के द्वारा, सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं अगर वह चाहें तो जो एरिया वहां वन विभाग के अन्दर आता है, उसका अगर हम डायवर्जन कर दें, जैसे अभी अख़बार में 21 तारीख को निकला था कि कोटा शहर में चंबल घड़ियाल सेक्चुरी को विकास में बाधा बताया गया, तो वह भी बाधा है हमारे। हम भी तो गरीब परिवार से आते हैं। एससी, एसटी के लोग रहते हैं। हम कहां जायेंगे? सिर्फ वही हमारी आजीविका का संसाधन है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं, पूरा सदन बैठा है, एक ऐसी नीति लाई जाये जिससे वह पत्थर व्यवसाय अपनी पटरी पर आ सके और लोगों को अपनी आजीविका का संसाधन मिल सके। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा गैंगसा यूनिट सिर्फ हमारे सरमथुरा क्षेत्र में लगी हुई हैं। करीब-करीब 80 गैंगसा यूनिट हैं। उससे 30 हजार परिवारों का पेट भरता है। पेट पलता है। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि पत्थर व्यवसाय के लिये अलग से पैकेज लाकर के इसके लिए व्यवस्था की जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री डूंगरराम।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32, 56 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

युवा मामले और खेल पर, बाल विकास और उद्योग पर चर्चा है। देश का युवा आगे आयेगा, सोते हुए को आकर जगायेगा। देश का विकास खुद ब खुद हो जायेगा। देश को आगे बढ़ायेगा। देश का युवा आगे आयेगा। इस बात को चरितार्थ करने का काम मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। राजस्थान प्रदेश के अन्दर हर जिले में आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज देने का काम पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया।

राजस्थान के युवाओं में एक जागृति पैदा करने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए, राजस्थान का युवा एक-दूसरे से मिल-जुलकर रहे, इसके लिए पूरे राजस्थान प्रदेश के अन्दर मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम और शहरी ओलंपिक गेमों का आयोजन किया। जिसके अन्दर दादा-पोता एक साथ खेले। सास-बहू एक साथ खेली। उस टाइम राष्ट्र गान गाने का एक विश्व रिकार्ड राजस्थान ने बनाया।

इसके साथ-साथ मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30 हजार बच्चों को फ्री में जो प्राइवेट इंस्टीट्युट हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं, उनमें कोचिंग मिले, इसके लिए बेरोजगारी भत्ता 4 हजार बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए साढ़े 4 हजार दिया। सबसे बड़ा जो काम उस समय हुआ, वह राजस्थान की उस टाइम के, तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा जी की प्रेरणा से और मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से महात्मा गांधी स्कूल जिसने राजस्थान के हर उस मां-बाप का सपना पूरा किया, युवा का सपना पूरा किया कि वह अपने बेटे को अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इस बजट में उस महात्मा गांधी स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए या और किसी भी तरह की योजना राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान के वित्त मंत्री द्वारा नहीं बनाई

गयी है।

विश्व की उच्च शिक्षण संस्थाओं में राजस्थान के बच्चे बाहर जाकर के पढ़ें, इसके लिए 500 विद्यार्थियों को राजस्थान की सरकार छात्र वृत्ति देकर के पढ़ाने का काम करेगी। यह काम भी मुख्य मंत्री जी ने किया। 1 करोड़ 35 लाख स्मार्ट फोन बांटने का काम किया ताकि उस समय के जो बच्चे हैं, वह इंटरनेट से जुड़ सकें। इंटरनेट के माध्यम से घर बैठकर पढ़ाई कर सकें।

उस टाइम मुख्य मंत्री जी ने विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत जो लघु उद्योग हैं, जो छोटी-छोटी दस्तकार जातियां हैं, जैसे कुम्हार है, सुथार है, नाई है, लुहार है, दर्जी है, शिल्पकार है, इन जातियों को आगे बढ़ाने के लिए और इन जातियों को औजार देने के लिए इस तरह की योजना बनाई गयी। लेकिन इस बजट के अन्दर इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं किया गया।

राजस्थान प्रदेश के अन्दर माटी कला से जुड़े हुए जो आर्टिजन हैं, उनको पहली दफा विद्युत चालित चाक राजस्थान ने दिये। उस टाइम दिये। मैं अब धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है।

राजस्थान के अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने देश का पहला राज्य बनाया। जहां महिलाओं को आगे करके सिलेंडर 500 रुपये का दिया। जो पूरे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। आपने उस योजना को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। 450 में वह सिलेंडर देने का काम किया है। उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे।

मिट्टी कला से जुड़े हुए जो कारीगर हैं, आर्टिजन हैं, उसके साथ-साथ यह भी निवेदन है कि आज जिस तरह से कुपोषण के शिकार, खाने में पौष्टिकता की कमी बार-बार आ रही है, वह हमारे बर्तनों की वजह से आ रही है। पहले हमारे घरों में मिट्टी के बर्तन होते थे। मिट्टी की हांडी होती थी। मिट्टी की कढ़ाई होती थी। मिट्टी की परात होती थी। इस बात को साबित किया है डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, जोधपुर ने जिन्होंने 10-15 दिन तक कुछ परिवारों को अपने वहां रखकर के, उन पर रिसर्च किया जिसमें जोधपुर यूनिवर्सिटी के सानिध्य और दिशा-निर्देश में नींद व पाचन प्रक्रिया और पौष्टिकता में गुणवत्ता है, वह खाने के अन्दर आई है। तो हमारा यह भी निवेदन रहेगा कि जो आंगनबाड़ी हैं, आंगनबाड़ी के अन्दर यदि मिट्टी के बर्तनों के अन्दर पकाकर के उन बच्चों को खाना खिलाया जाये तो शायद उन बच्चों के खाने में और ज्यादा पौष्टिकता आ सकती है। इस बात का भी ध्यान रखने की आज बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि आज जितनी भी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है, लीवर सम्बन्धी बीमारियां हैं, मिट्टी के बर्तनों में पकाकर के खाना खाने से इन सारी बीमारियों में कमी आ सकती है। कोलेस्ट्रोल घट सकता है। पाचन क्रिया है, दिल की जो बीमारियां हैं, वह कम हो सकती हैं। इस बात की तरफ भी ध्यान हम लोगों को देना चाहिए।

Spp/Rtm/23.07.2024/19.40/4e

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): डूंगरराम जी, आपके समाज के लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने बन्द कर दिये, यह बर्तन कहां से लायेंगे?

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): जो बना रहे हैं। आज यह भी बहुत बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश की, कि जो हमारे इस तरह की छोटी-छोटी जातियां हैं, जो पुश्तैनी काम करती हैं, वे सारे के सारे काम खतम होते जा रहे हैं और यदि हम लोग लघु उद्योगों को बढ़ावा दें तो उन कामों को भी बढ़ावा मिल सकता है, उन परिवारों को भी बढ़ावा मिल सकता है और यह काम हमें करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार सरकार ने यह भी काम किया था कि यदि बाहर जाकर के इस सामान को बड़े मेलों के अन्दर बेचने का काम करेंगे तो उन्हें 10 हजार रुपया मिलेगा। इस बात को भी बढ़ावा देना चाहिये, ताकि उनका सामान भी ज्यादा से ज्यादा बिक सके।

प्रदेश के अन्दर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, साथिन है, उनका मानदेय और सुविधाएं बढ़ाने का काम की आज बहुत बड़ी जरूरत है।

प्रदेश के अन्दर सूरतगढ़ में आंगनबाड़ी के जो केन्द्र हैं, उनको और अन्य जो आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उनको प्लेइंग स्कूल की तर्ज पर चलाने की जरूरत है, ताकि वहां पर बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। सूरतगढ़ के अन्दर आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन नहीं हैं। आज वह दूसरे भवनों के अन्दर सामुदायिक भवनों के अन्दर ये सारे के सारे आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। वहां पर भवन बनाने की जरूरत है। प्रत्येक राजस्व गांव में और कच्ची बस्तियों में और ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की भी जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, आज का जो युवा है वह विशेष तौर से नशे की लत का शिकार है। जितने भी आज वक्ता बोले हैं, सारे के सारे माननीय विधायकों ने इस बात पर चिन्ता जताई है। यह पूरे प्रदेश की चिन्ता है और गंगानगर जिले की सबसे बड़ी चिन्ता यह है, क्योंकि गंगानगर के अन्दर यह ज्यादा बढ़ रहा है। उधर से पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से इस तरह के पैकेट गिराये जाते हैं, इधर पंजाब से आते हैं तो इसलिये इस नशाखोरी से बचने के लिये इस पर पाबन्दी लगाये जावे। विशेष तौर से कोई टास्क फोर्स बनाकर इस तरह से इन पर कार्यवाही करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ इस बात की भी जरूरत है कि इन बच्चों को, जो आज का यूथ है, उनको खेल से ज्यादा से ज्यादा जोड़कर देखा जाये।

गांवों के अन्दर राजियासर है, जयसर है, गुडली है, डाम्बा है, इनमें स्टेडियम और मूलभूत सुविधाओं की बढोतरी करने की जरूरत है। विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्दर पंचायत मुख्यालयों में ओपन जिम खोलने की जरूरत है। 10 हजार की जो पापुलेशन आपने

बतायी है, 10 हजार की पापुलेशन वाले गांवों के अन्दर आप जिम खोलेंगे, क्योंकि 10 हजार की पापुलेशन वाले गांव एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक-आधा गांव होगा और बहुत-से विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर ऐसे गांव होंगे भी नहीं तो मेरी इन सारी की सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भीम। जय संविधान।

श्री सभापतिः श्री राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26, 32 और 56 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह से इन तीनों मांगों पर पक्ष-विपक्ष की तरफ से सभी लोग अपने-अपने विचार रख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। आज हमारा युवा देश और प्रदेश का भविष्य है। आने वाला समय भारत एक युवा देश के रूप में जाना जायेगा। प्रदेश के युवाओं को और आगे बढ़ाने के लिये ग्रामीण इलाकों में उभरती हुई प्रतिभाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि खेलों को बढ़ाने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियमों की स्थापना होना बहुत जरूरी है। पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 05 अगस्त, 2023 को माननीय अशोक गहलोत जी ने राजीव गांधी ग्रामीण-शहरी ओलम्पिक खेलों का विधिवत रूप से उदघाटन किया था, लेकिन सरकार ने इसका राजनीतिकरण किया। प्रचार-प्रसार के नाम पर करोड़ों रुपये की टी-शर्ट बांटने का काम किया जिसमें सरकार को काफी नुकसान हुआ। हम क्षेत्र में रहते थे और कई बार पता लगता था कि फलां गांव के व्यक्ति को जबर्दस्त ही उस खेल से बाहर आउट कर दिया। बहुत जबर्दस्त पक्षपात हुआ था और सरकार ने यह भी कहा था कि इन खेलों से निकलने वाली प्रतिभाओं को आने वाले वर्षों में ओलम्पिक, राष्ट्रमण्डल और एशियाड खेलों जैसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतेंगे। लेकिन यह घोषणा केवल चुनाव तक ही सीमित रही। मेरे महवा विधान सभा क्षेत्र की मेरी खुद की ग्राम पंचायत खुर्रा मोहल्ला के अन्तर्गत आदरणीय किरोड़ी लाल जी के सहयोग से एक जबर्दस्त अभियान हमने चलाकर करीब 20 बीघा जमीन, जो सरकार ने आंवटित की, उसमें निजी सहयोग से एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य चालू है, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेना में बहुत सारे युवा भाई वहां पर सम्मिलित होते हैं। एक विशेष समाज के भाई, करीब अब तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में 32 लोग शहीद हुए हैं और उस विशेष समाज के भाई सुबह से लेकर शाम तक स्टेट हाईवे के अन्दर, गांवों की रोड़ों पर सुबह मोर्निंग वॉक करते हैं। वे प्रेक्टिस करते हैं। वे इसलिये करते हैं कि वहां पर स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे महवा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सांखा, बालाहेड़ा, बैजूपाड़ा और बाबू महाराज जी का मन्दिर नाहडा, अगर यहां पर मिनी स्टेडियम बन जायें तो निश्चित रूप से युवाओं को लाभ मिलेगा।

मैं आदरणीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि करीब 30 वर्ष पहले मेरे महवा विधान सभा क्षेत्र में समलेटी गांव, जो जयपुर-आगरा रोड पर स्थित है, वहां पर 122

बीघा जमीन सरकार ने आवंटित की थी, उसका नामान्तरकरण भी निगम के पक्ष में खोल दिया गया है। लेकिन अभी तक वहां स्थिति जैसी की तैसी है। इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस रीको एरिया को आप जल्द से जल्द विकसित करें ताकि महवा और आसपास के युवाओं को वहां पर रोजगार के अवसर मिल सकें।

इसके साथ ही, महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि विभाग के प्राचीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र जो क्षतिग्रस्त हैं, पूर्णतः खण्डहर पड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत करवायी जाये या फिर वहां पर नये भवन बनवाये जायें। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय का निर्माण हो एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

विधान सभा क्षेत्र महवा में कोरोना काल के दौरान विभाग द्वारा गर्भवती महिला व 6 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराये गये गेहू, चावल और दाल की पैकिंग का भुगतान विभाग के द्वारा मानदेयकर्मियों को नहीं दिया गया, जोकि लगभग 15 से 20 लाख रुपये की राशि का भुगतान शेष है। मैं मंत्रीजी से आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि उसका आंवटन कराया जाये, ताकि उनका भुगतान मिल सके।

मैं इसके साथ ही, माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा इन तीनों विभागों के लिये इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है और निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरे पांच वर्ष तक युवा, महिलाओं के लिये सशक्तिकरण के लिये बहुत अच्छे से काम करेगी। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि दीन, हीन,गरीब और सबसे पीछे पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिये संकल्पित होकर उसे आगे बढ़ाने का काम करते आये हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री नानालाल नीनामा।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आप ने मुझे मांग संख्या 26-युवा मामले एवं खेल एवं मांग संख्या 32-महिला एवं बाल विकास पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं।

मांग संख्या 26-युवा मामले एवं खेल के बारे में पहले कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने युवाओं को अधिक संबल प्रदान करने एवं युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने हेतु पांच वर्षों में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा बजट में की गई है। इस वर्ष की 70 हजार हजार सरकारी भर्तियों को बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार बने करीब 7 माह का समय निकल गया है, जिसमें मात्र 20 हजार नौकरियां प्रदान की गई हैं। अभी राज्य सरकार आंकडों में जुटी है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। इतनी बडी संख्या में सरकारी नौकरियां देना असंभव सा लग रहा है।

सभापति महोदय, राज्य बजट में युवा नीति-2024 अन्तर्गत 5 वर्षों में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में स्किल अपग्रेडशन में 10 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा के साथ ही स्टेट स्किल नीति के तहत 1.50 लाख युवाओं को अपग्रेड कोर्स कराने की बात की

गई है।

सभापित महोदय, राज्य सरकार के पास पहले ही मूलभूत सुविधाओं की कमी है, साथ ही राज्य के कई तकनीकी संस्थानों में कई ट्रेडों में पद रिक्त चल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में बजट में खेल नीति 2024 की घोषणा की गयी, जिसमें राजस्थान खेल आधुनिकरण मिशन की बजट राशि को दोगुना किया गया है, जिसके लिये राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं घाटोल विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, जहां लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। जिसमें दोनों जिले प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा क्षेत्र पड़ते हैं। यहां पर अनगिनत जनजाति युवा प्रतिभा छिपी हुई है, जिसको तराशने की आवश्यकता है। तीरदांजी के अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्यामलाल एवं लिम्बाराम जनजाति क्षेत्र से निकले हुए हैं।

आज भी उदयपुर एवं बांसवाड़ा संभाग के 10 युवा जनजाति तीरदांज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। 200 से अधिक तीरदांज राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण ले रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को कहना चाहूंगा कि तीरदांजी के अलावा यहां के खिलाड़ी वॉलीबाल, फुटबाल, कबड्डी एवं तैराकी में अपना विशेष हुनर रखते हैं। इन खेलों में राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा संभाग और जिले में ब्लॉक स्तर पर विशेष कैम्प लगाकर खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा।

MLS/RTM/23.07.2024/19:50/4f

इस हेतु प्रतिभा खोज प्रतियोगिता करायी जाने की आवश्यकता है। इससे प्रतिभावान खिलाड़ी राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। माननीय सभापित महोदय, बांसवाडा जिले में तीरंदाजी अकादमी एवं फुटबाल अकादमी पूर्व से ही स्थापित हैं। इन अकादमियों में मूलभूत आवश्यकतों के साथ अच्छे प्रशिक्षक की आवश्यकता है, जिसके लिए राज्य सरकार को सोचना होगा। माननीय सभापति महोदय, राजकीय/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर के अच्छे पदक विजेता खिलाडि़यों को राज्य सेवा में नियुक्ति देने का नियम राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था। साथ ही, सरकारी भर्तियों में 2 प्रतिशत खेल कोटे का आरक्षण भी हमारी पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का शुभारम्भ हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं, युवाओं एवं खेल की इन योजनाओं को बंद न किया जाये। ये स्थानीय ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाडि़यां खोले जाने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में कई आंगनबाड़ी केन्द्र भवन ऐसे हैं, जो स्कूलों के भवनों में संचालित हो रहे हैं। कई भवन किराये पर हैं। कई केन्द्र भवन रहित हैं। कई भवन ऐसे हैं, जो विभागीय भवनों में संचालित हो रहे हैं, किन्तु उनकी भौतिक स्थिति जर्जर है तथा उनमें बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल में प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आते हैं, जहां करीब 80 प्रतिशत जनसंख्या जनजाति वर्ग की है। प्रतापगढ़ के ब्लॉक पीपलखूंट, सुहागपुरा एवं बांसवाड़ा के ब्लॉक घाटोल के अन्तर्गत कुल 392 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। उनमें 41 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित हैं, जिनके भवन निर्माण की आवश्यकता है। इनमें 38 केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। इनमें 32 केन्द्र ऐसे हैं, जो राजकीय विद्यालय में संचालित हो रहे हैं। 299 केन्द्र, जो विभागीय भवनों में संचालित हो रहे हैं, उनकी भौतिक स्थिति ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पहले इनको प्राथमिकता देकर भवन निर्माण की मरम्मत एवं नये भवन बनाने की राशि को स्वीकृत करें, जिससे सरकार की भावना के अनुरूप आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में सोची गयी परिकल्पना को साकार रूप मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि राज्य के बजट में आंगनबाड़ी पर पोषाहार के लिए 3 दिन दूध पाउडर देने की जो घोषणा की गयी है, उसके स्थान पर पौष्टिक फल देने पर सरकार को विचार करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के मानदेय में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की थी। केन्द्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के रेशो में किया जाता है। आज के इस महंगाई के दौर में परिवार का भरण-पोषण सुचारू रूप से चलाने हेतु मैं इनके मानदेय में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की राज्य सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री पूसाराम गोदारा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के युवा हमारे देश के भविष्य हैं। इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए हम नीतियां बनाएं और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं। राजस्थान की सरकार ने 4 लाख भर्तियों की जो घोषणा की है, वह निश्चित तौर पर सराहनीय है। इन पांच सालों में भर्तियां की जाएं और पेपर लीक की गम्भीर समस्या इसमें नहीं आये। पारदर्शिता के साथ इन्हें धरती पर उतारा जाये। इससे युवाओं को निश्चित तौर पर रोजगार मिलेगा। इसके अलावा युवाओं को कृषि, उद्योग, उत्पादन और शिक्षा जगत में विशेष महत्त्व दिया जाये व रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराये जाएं ताकि युवा सड़कों पर भटकते नहीं फिरें।

आज मुझे बड़ा खेद है कि हमारे राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार ने 5 हजार

राजीव गांधी युवा मित्र लिये थे, भर्ती की थी। उन्हें आपकी सरकार ने एक ही बार में हटाकर युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। यह उन्हें रोजगार देने का नहीं, बल्कि उन्हें प्रताड़ित करने का काम है। उन्हें आन्दोलन करने की छूट नहीं मिलती। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जाते हैं। उन मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिये। अगर सरकार राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से नहीं करना चाहती है तो उनका नाम बदलकर भी वापस लिया जा सकता है।

हमारी सरकार ने 50 हजार महात्मा गांधी प्रेरक लेने की घोषणा की थी। चुनाव से पहले उनके इंटरव्यू हो गये। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद आपकी सरकार ने आते ही उस भर्ती और उन इंटरव्यूज को निरस्त कर दिया। पुनः महात्मा गांधी प्रेरकों की राजस्थान सरकार भर्ती करे और युवाओं को रोजगार दे। अगर वास्तव में युवाओं को रोजगार देना है तो इस प्रकार की योजनाओं को आप जारी रखें, निरस्त न करें। इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि युवाओं के बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया जाये। जो इंटर्नशिप योजना उनके लिए लागू है, उसका समय चाहे 1 घण्टे की जगह 2, 2 घण्टे की जगह 4 कर दिया जाये, लेकिन वर्तमान में जो उन्हें वजीफा मिल रहा है, उस बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया जाये।

इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि युवाओं को खेल जगत में विशेष प्रोत्साहन देने के लिए खेल नीति को सुदृढ़ किया जाये। कॉलेज और स्कूलों में जिन खिलाड़ियों में जज्बा है, जो हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उन्हें सामने लाने के लिए, उन्हें प्लैटफॉर्म दिलाने के लिए हमारी सरकार ने ओलम्पिक खेल योजना शुरू की। हालांकि, आपने ''खेलो राजस्थान'' शुरू किया है, इसमें भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उस टाइम में दादा और पोता, दोनों एक साथ खेले। पंचायत लेवल पर हुआ, जिला लेवल पर हुआ और स्टेट लेवल पर भी हुआ। निश्चित तौर से हमारे प्रदेश की जिन प्रतिभाओं को मौका नहीं मिलता था, वह उन्हें हमारी सरकार ने दिया। आप भी ''खेलो राजस्थान'' में इस व्यवस्था को लागू करें, तब हम आपको धन्यवाद देंगे।

इसके अलावा, मैं खेल जगत में यह भी कहना चाहूंगा कि आज हमारे सैकंडरी और सीनियर सैकंडरी स्कूलों के पास खेल मैदान नहीं हैं। हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान हो, उसके लिए जमीन आवण्टित की जाये। हालांकि, जोहड़ पायतन की जमीन आवण्टित नहीं की जा सकती, लेकिन गोचर में से अगोर को छोड़कर आवण्टन किया जा सकता है। इसके अलावा, आराजी भूमि में से अलॉट किया जा सकता है। गांवों में जमीन उपलब्ध है। इनके लिए लैंड आवण्टित कर उन्हें खेल मैदानों के रूप में विकसित किया जाये ताकि हमारे युवाओं को खेलने का भी मौका मिल सके।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत लेवल पर जिम, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की जाये ताकि उन्हें जिम करने का और पढ़ाई करने का भी मौका मिल सके। इसके अलावा, मैं युवाओं के लिए यह भी कहना चाहूंगा कि पारदर्शिता के साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं। इस दौरान नशा मुक्ति की जो बात चल रही है, हर विधायक ने वास्तव में सही बात कही है कि हमारे युवा नशे की प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए कड़े कानून और कड़ी व्यवस्था

बनायी जाये। हमारे खेल मंत्री युवा भी हैं और खिलाड़ी भी हैं।

इसके अलावा, मैं थोड़ा सा उद्योग पर बोलना चाहूंगा कि उद्योग नीति में निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर परपज जो होता है, उससे कृषि आधारित व्यवस्था लागू की जानी चाहिये, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, वहां उनकी फैक्टरियां डवलप हों, उन्हें सस्ती ब्याज दर पर और सब्सिडी पर लोन उपलब्ध करायी जाये और लैंड को कम से कम तीन साल में कन्वर्ट करके ग्रामीण उद्योग लगाने की उन्हें छूट प्रदान की जाये। इससे वहां एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी होगा, एग्रीकल्चरल सिस्टम बढ़ेगा, ग्रोथ होगी और वहीं उनकी इंडस्ट्रीज लगेंगी और वहीं के लोगों को धन्धा मिलेगा, और हमारे युवा बेरोजगार वहां काम कर सकेंगे। इसके अलावा, मैं एक बात अपने विधान सभा क्षेत्र की भी कहना चाहूंगा कि मेरे यहां जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वह हैंडीक्राफ्ट का हब है। वहां ग्रोथ सैंटर की आवश्यकता है। लम्बे समय से मांग चल रही है, वहां ग्रोथ सैंटर खोला जाये।

mkd/rtm/23.07.2024/20:00/4g

जब फायर ब्रिगेड का कार्यालय बना दिया और कर्मचारी के अभाव में इंडस्ट्री को लाभ नहीं मिले, यह अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां इंडस्ट्री एरिया है, उसमें सारी सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, अच्छा इंडस्ट्री एरिया है। काफी फैक्ट्रियां चल रही हैं, पाइप की फैक्ट्रियां चल रही हैं, पौषाक की चल रही है, हैण्डीक्राफ्ट की चल रही हैं। सारी सड़कें टूट पड़ी हैं, उनको मीठा पानी उपलब्ध नहीं है, पाइप डाली हुई नहीं है। हमने कई बार उसकी व्यवस्था करने की मांग की है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां बरसाती पानी की निकासी भी नहीं है, बरसाती पानी की निकासी भी करनी चाहिए, टूटी सड़कें बनाई जानी चाहिए, ग्रोथ सेन्टर खोला जाना चाहिए और फायर ब्रिगेड के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि उनको लाभ मिल सके।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, महिला और बाल विकास में, 33 परसेंट से 50 परसेंट महिलाओं को कई विभागों में आरक्षण की बात की है। इस बात के लिए तो धन्यवाद है, क्योंकि हमारी सरकार भी पहले कर चुकी है। आज बहुत-सी आंगनबाड़ियां किराये के भवनों में चल रही हैं, स्कूलों के कक्षा-कक्षों में चल रही हैं, वहां मास्टरों और आंगनबाड़ियों में तकरार रहती है। वहां गर्भवती महिला, धात्री महिला और बच्चों के उचित पोषाहार की व्यवस्था एक रूम में नहीं हो सकती है। इसलिए जहां आंगनबाड़ी नहीं बनी हुई है, वहां आंगनबाड़ी भवन बनाये जायें।

इसके अलावा जो भी हमारी ढाणियां है, जो आइडेंटिफाई ढाणियां हैं, पचास है, चालीस है, साठ हैं, वहां मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भी खोला जाये। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इन मांगों पर बोलना का मौका दिया। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री देवेन्द्र जोशी।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे उद्योग विभाग की

मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री और डायनेमिक ऊर्जावान श्री भजन लाल जी शर्मा और राज्यवर्द्धन सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने रीको को एक ट्रांसफोर्मेशन एज में डाला है। एक रियल एस्टेट कम्पनी से हटाकर उसको सर्विस प्रोवाइडर कम्पनी और अब फ्री डायमेंशनल, इन्होंने जो लैंड अलॉटमेंट का सिस्टम प्रारम्भ किया है, निश्चित रूप से राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रांति आयेगी। आज तक रीको खाली ऑक्शन ही करती आई है, लेकिन अब ऑक्शन के साथ-साथ अलॉटमेंट भी है, लॉटरी भी है और प्राइवेट बेसिस पर मेरिट के आधार पर उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप जमीन का आवंटन भी है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा का और ऊर्जावान उद्योग मंत्री भाई राज्यवर्द्धन सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने उद्योग क्षेत्र की लम्बे समय से जो मांग थी, उसको पूरा करने की दिशा में कदम उठाये, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, उद्यमशीलता, उद्यमी और उद्योग तीनों रिलेटेड शब्द हैं। जब तक उद्यमशीलता का विकास नहीं होगा, उद्यमी का विकास नहीं होगा, उद्यमी का विकास नहीं होगा तो उद्योग का विकास नहीं होगा। इसलिए आज के समय में आवश्यकता है कि उद्यमशीलता का विकास कैसे हो। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएट बाहर आते हैं, लेकिन उनको दिशा नहीं है। पहले यह व्यवस्था थी कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज से छात्र बाहर आते थे, वे जिस डिसिप्लिन में वे करके आये हैं, उस विधा में कौन-सा उद्योग स्थापित हो, उनको यह जानकारी दी जाती, सहायता दी जाती थी, लेकिन गत कुछ वर्षों से उद्योग विभाग खाली उद्योगों का, उद्योग विभाग को एंटरप्रेन्योरशिप डवलपमेंट का काम करना चाहिए। उसकी जगह खाली उद्योगों को फैसिलिटेट करने का काम करने लगा।

मेरी मांग है कि उद्योग विभाग में जितने भी उद्योग प्रसार अधिकारी हैं, उनकी जॉब फिक्स हो, उनका कार्य फिक्स हो और एक टारगेट ओरिएंटेड, हजारों की संख्या में बेरोजगार हैं, लेकिन उनको दिशा नहीं है, दिशा देने का काम उद्योग विभाग में बैठे अधिकारी करें। उनको बुलाकर करें, चाहे कॉलेज में जाकर करें। जब तक उद्यमशीलता विकसित नहीं होगी, उद्यमी विकसित नहीं होगा और उद्यमी विकसित नहीं होगा तो उद्योग विकसित नहीं होगा।

माननीय उद्योग मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के साथ एक टाइप अप करते हुए कैसे उद्यमशीलता का विकास हो और उसके माध्यम से नये-नये उद्योग प्रदेश में लगे और प्रदेश में औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत हो, इसके लिए मैं आशा करता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे।

दूसरा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है। मैं स्वागत करता हूं औद्योगिक पॉलिसी का। पॉलिसियां पहले भी आई हैं लेकिन मेरा सुझाव है कि केवल पॉलिसी ही नहीं, पॉलिसी के साथ प्रोसीजर भी आना चाहिए। जब तक उद्योग का प्रोसीजर नहीं आयेगा, उद्यमी को मालूम ही नहीं है इसमें करना क्या है। दूसरा, इंटरप्रिटेशन की प्रोब्लम होती है। एक अधिकारी से

दूसरे अधिकारी तक, एक डीआईसी से दूसरे डीआईसी तक, इंटरप्रिटेशन प्रोब्लम और फंसता कौन है, उद्यमी।

इसलिए पॉलिसी के साथ प्रोसीजर हो। उस प्रोसीजर में हर कार्य की एक समय सीमा तय हो, यह सात दिन में होगा, यह दस दिन में होगा और अगर उस दरमियान नहीं किया जाता है, उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो। तभी हम इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी ला पायेंगे। उद्योग विभाग को इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बना पायेंगे। अभी खाली बातें हो रही हैं।

मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि उद्योग विभाग जो काम कर रहा है, वह उद्यमी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है। प्रोसीजर नहीं होने की वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ इंडस्ट्रियल प्रोसीजर भी हो। हर पॉलिसी में क्या-क्या एडवांटेज हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये लिस्टेड हों। उन कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा तय हो।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन लेता है तो उसके रिपेमेंट का पीरियड 25 साल है। लैंड वही है, बिल्डिंग वही है। वह इंडस्ट्री के लिए लेता है तो उसका रिपेमेंट पीरियड 7 साल है। नैचर में कोई बदलाव नहीं है। चाहे उद्योग के लिए जमीन ली हो, नैचर वही है। उद्योग के लिए भवन बन रहा है, नैचर वही है, लेकिन उसको सात साल। इस कारण से नया उद्यमी उसमें पैर रखने से डर रहा है।

इसमें यह भी, चाहे फाइनेंसियल प्रोसीजर में चैंज करना है, फाइनेंस एक्ट में हो, चाहे केन्द्र सरकार से हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यह आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए कि आपका लैंड और बिल्डिंग का लोन रिपेमेंट 25 साल का हो ताकि नया उद्यमी जो उद्योग लगाना चाहता है, वह जमीन भी खरीद सके, उस पर भवन भी बना सके और छोटी-मोटी मशीन लगाकर अपना कार्य भी प्रारम्भ कर सके। इससे जो नया उद्यमी आ रहा है, उस पर फाइनेंसियल बर्डन बहुत कम हो जायेगा और कम होगा तो वह जल्दी से उद्योग को लगाने की ओर, उद्योग का विकास करने की ओर अग्रसर होगा।

माननीय उद्योग मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है, केन्द्र सरकार से हो या आपके स्तर पर हो, इंडस्ट्री के लिए लैंड और बिल्डिंग के लोन का रिपेमेंट पीरियड कम से कम 25 साल किया जाये ताकि नये उद्यमी को इसका लाभ मिल सके।

हम उद्योगों के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उसको सस्टेनेबल नहीं बनायेंगे। यदि हम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को राजस्थान में सस्टेनेबल बना दें और उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, आने वाले वर्षों में क्या-क्या चुनौतियां आने वाली हैं, चाहे वह जोधपुर का हैण्डीक्राफ्ट उद्योग हो, चाहे जोधपुर का ग्वार गम उद्योग हो, चाहे भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग हो, आने वाले चार-पांच सालों में, इसके लिए उद्योग मंत्रालय के अधीन एक ट्रेड इंटेलिजेंस सेंटर, जो आने वाले समय की चुनौती को पहले भांपकर आपके

उद्यमी को सचेत कर सकें कि अगले तीन साल में आपके सामने ये चुनौतियां आने वाली हैं, इसका इस तरह से समाधान करना है।

एक एडवाइजरी बॉडी, चाहे उसमें हमारे हिन्दुस्तान के अच्छे से अच्छे कंसलटेंट को हायर करना पड़े। राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की जोधपुर में क्या स्थिति हो रही है? ग्वार गम की क्या स्थिति हो रही है? अगर यह ट्रेड इंटेलिजेंस विंग राजस्थान में, यह पूरे हिन्दुस्तान में नवाचार होगा कि राजस्थान की सरकार ने ट्रेड इंटेलिजेंस विंग प्रारम्भ की है, ताकि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैं, उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके, उसको बचाया जा सके। नहीं तो आने वाले समय में यह होगा कि नई इंडस्ट्री हम लाते जायेंगे और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, वह समाप्त होती जायेगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि एक ट्रेड इंटेलिजेंस विंग उद्योग मंत्रालय के तहत गठित की जाये। उसमें हिन्दुस्तान भर के अलग-अलग विषयों के जो भी एक्सपर्ट हैं, उनको शामिल किया जाये ताकि राजस्थान की इंडस्ट्री को एक दिशा मिल सके। अभी जो उद्योगपति हैं, उनको भी दिशा मिल सके कि आने वाले वर्षों में क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं।

दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, बेसिक एमेनिटीज। रीको ने जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये हैं। आज भी मुझे मालूम है, हजारों की संख्या में जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं।

Bhs/Rtm/23.7.24/20.10/4h

लेकिन हम अभी तक उनको पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाये। मेरा निवेदन है माननीय उद्योग मंत्री महोदय से कि जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, पाइप लाइन डाली हुई है लेकिन पानी नहीं आता, कनेक्शन दे दिये लेकिन पानी नहीं आता, तो इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करते हुए आपसे निवेदन है कि औद्योगिक क्षेत्रों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो, पानी स्वयं उद्योगपति अरेंज कर लेगा लेकिन हजारों की संख्या में लेबर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी करें।

मैं एक बार पुन: आपने जो औद्योगिक क्षेत्र में नये-नये पैरामीटर स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया है उसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और आपसे आशा करता हूं ...(व्यवधान)...

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, व्यवस्था का सवाल है।

श्री सभापति: विराजें आप। बोलने दीजिये। समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): बस एक मिनट। मैं माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में सम्भागीय मुख्यालय होने के कारण से एक स्टेडियम का निर्माण करने की बजट में उन्होंने घोषणा की है। मेरा निवेदन है कि जोधपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बहुत बड़ा भूखंड है वहां पर राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम स्थापित करें। ऐसी मेरी मांग है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, जोधपुर से आने वाले ...

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजें। श्रीमती सुशीला।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 26,32 व 56 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, आभार प्रकट करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 में संशोधन कर संशोधित नियम, 2020 जारी कर प्रदेश के राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खेल-कूद प्रतियोगिताओं में पदक विजेता उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सरकार की सेवाओं में बिना पारी नियुक्ति देने की सराहनीय पहल की थी, जिसके तहत प्रदेश में कई खिलाड़ियों को उनके शैक्षिक व सह शैक्षिक योग्यता के आधार पर राज्य की विभिन्न सेवाओं में विगत सरकार द्वारा नियुक्ति भी प्रदान की गई थी। वर्तमान सरकार को भी उस पहल को आगे बढ़ाते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की राज्य सेवाओं में नियुक्ति के सिलसिले को जारी रखना चाहिये। अभी तक वर्ष 2021 के पदक विजेता उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भी राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति नहीं हो पायी है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2022 के पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार द्वारा आदिनांक तक प्रोत्साहन राशि तक नहीं दी गई है इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। हमारी सरकार कौन से खेलों को प्रोत्साहन देने की बात कर रही है? हमें पड़ोसी राज्यों हरियाणा व पंजाब की सरकार से कुछ सीखते हुए अपनी खेल नीति में वांछित सुधार कर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की दरकार है। हमारे देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है केवल उस प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार को जरूरी प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश के युवा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर की खेल-कूद प्रतियोगिताओं में पदकों का अम्बार लगा देते हैं तो सरकार को उनकी तरफ सहयोग करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को दरकार है प्रदेश में अधिक से अधिक खेल स्टेडियम बनवाने व जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े स्टेडियमों का जीर्णोद्धार करवाने की।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के श्री जेठाराम डूडी खेल स्टेडियम, नोखा की बात करूं तो यह स्टेडियम बिलकुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। मेरे ख्याल से यही हाल राज्य के अनेक कई खेल स्टेडियमों का भी रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को कहना चाहती है कि सरकार नोखा खेल स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाने का काम करे। मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के ब्लॉक मुख्यालय पांचू व तहसील मुख्यालय जसरासर में नवीन खेल स्टेडियम स्वीकृत करा कर मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए आवश्यक प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं राज्य सरकार क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 संशोधित नियम, 2020 के तहत राज्य के समस्त पदक विजेताओं खिलाड़ियों को अविलम्ब राज्य सेवा में उनकी योग्यता अनुरूप नियुक्ति प्रदान करें तथा समस्त पदक विजेताओं व उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यथासमय प्रोत्साहन राशि का भुगतान करावें। राज्य सरकार को खिलाड़ियों की हौसला अफजाही व मनोबल बढ़ाये रखने व युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यह बहुत जरूरी है। राज्य सरकार विगत सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में बिना पारी नियुक्त पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल जारी करने हेतु सामर्थ्यकारी वातावरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जारी कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.7.2022 की अक्षरशः पालना के आदेश राज्य सरकार के समस्त विभागाध्यक्षों को प्रदान करें।

श्री सभापतिः विराजियें। कॉपी टेबल कर दें। विराजिये।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापतिः श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26,32 और 56 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आज इत्तिफ़ाक़ से बड़ा दिन है। आज वैसे तो आपको छुट्टी रखनी चाहिये थी। आज केन्द्र सरकार ने भी बजट दिया है और केन्द्र सरकार ने बजट दिया और राजस्थान को कुछ नहीं दिया, जीरो बटा जीरो। एम.एस.एम.ई. इंडस्ट्री, यूथ अफेयर्स, युवा मामलात, युवाओं के रोजगार अपोर्चुनिटी जीरो बटा जीरो और किसको दिया, अपनी केन्द्र की सरकार बचाने के लिए बिहार को दे दिया, आन्ध्र प्रदेश को दे दिया और राजस्थान को कुछ नहीं। राजस्थान वह प्रदेश है जिसने दो बार 25-25 सांसद दिये और इस बार 14 सांसद दिये और मैं यह कह सकता हूं कि जब 25 सांसद दिये तो जो मंत्री महोदय आज यहां बैठे हैं और जिनके विषय की डिमांड है वो उस वक्त केन्द्र में मंत्री थे। हम तो यही चाह रहे थे कि ये अभी भी केन्द्र में मंत्री बनते लेकिन आपने इनका डिमोशन करके यहां स्टेट में मंत्री बना दिया लेकिन फिर भी मैं जब ये ओलंपिक जीते थे तो हम सबके दिल और दिमाग फख्र से ऊंचे हो गये कि जयपुर का एक आदमी जिसने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, राजस्थान का नाम रोशन किया उस आदमी को तो आपको कम से कम केन्द्र में मंत्री बनाना ही चाहिये था। तो बजट आपने दिया केन्द्र में और कुछ भी नहीं दिया तो मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं,

'सब्र हर बार अख्तियार किया, तेरे वादों का इंतजार किया,

आदतन तुमने झूठ ही बोला और भोले-भाले लोगों ने एतबार किया।'

और जनता आ गई एतबार करने, ट्रस्ट कर लिया और आज मैंने अभी बाहर जाकर बजट की कुछ बातें देखीं तो गरीब आदमी को, आम आदमी को, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया जीरो बटा जीरो और बिहार को दे दिया 40-50 हजार करोड़ रुपये, आन्ध्र प्रदेश को दे

दिये 25-30 हजार करोड़ रुपये। हम इंतजार कर रहे हैं पर्यटन के लिए आपने पांच हजार करोड़ का प्रॉविजन किया। अभी हम बात कर रहे थे कि आर.एफ.सी. के पास पैसा नहीं है बहुत सारे सदस्य बोले, डबल इंजन की सरकार है, पैसा आयेगा, तो एक इंजन दिल्ली वाला तो बन्द हो गया। अब हम कैसे बोलें कि आप आर.एफ.सी. को पैसा दो, आप रीको को पैसा दो। हम तो बोलते हुए ही शर्मिन्दा हो रहे हैं क्योंकि बजट में ही कोई प्रॉविजन नहीं है। ...(व्यवधान)... बहरहाल मैं इंडस्ट्री पर अपनी बात करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य। मंत्री जी, इधर पहुंचवा दें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): वो टेबल करना चाह रही हैं, इधर भिजवा दो।

सभापति महोदय, आपने हर जिले को एक प्रोडक्ट के लिए कहा कि हम हर जिले से एक प्रोडक्ट को लेंगे और उसका डवलपमेंट करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, जयपुर एक प्रोडक्ट की जगह नहीं है जयपुर मल्टी प्रोडक्ट की जगह है और जयपुर कुटीर उद्योगों की नगरी है और आज से नहीं है आजादी के पहले से है।

Kas/rtm/23.07.2024/20.20/4j

आजादी के पहले से जयपुर में बहुत सारे व्यवसाय पनपे हुए थे और मैं यह कह सकता हूं कि आज जयपुर में सबसे बड़ा एम्प्लायमेंट जनरेशन गार्मेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में होता है। 2-2 हजार, 5-5 हजार लोग एक-एक फैक्टरी में काम करते हैं। हम कह रहे हैं कि अपैरल पार्क बनायेंगे, अपैरल के लिये पॉलिसी लेकर आयेंगे, लेकिन आठ महीने हो गये इसका कोई जिक्र नहीं है। कब लाओगे, कब अपैरल इंडस्ट्री को प्रमोट करोगे और क्या रूपरेखा बनाई है? आप जब भी जवाब दें तो इस बात का जवाब जरूर दें, क्योंकि आपने कहा है कि हम अपैरल इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे।

दूसरा, मैं कह सकता हूं कि एक लाख करोड़ से ज्यादा का जयपुर का जवाहरात का उद्योग, जो सिर्फ जयपुर में होता है। 5-10 हजार करोड़ का कलर स्टोन का व्यापार है। सोने-चाँदी की ज्वेलरी है, जयपुर ज्वेलरी का हब बना हुआ है। आज हमें इतना समय हो गया, अभी तक हम ऐसी कोई रूपरेखा, ऐसा मॉडल नहीं लेकर आ पाये। बैंकॉक छोटी सी जगह है, वह बहुत बड़े लेवल पर दुनिया की इंडस्ट्री में अपना शेयर रखते हैं। चाइना वाले हम से आगे जा रहे हैं और जबकि कलर स्टोन में और जवाहरात में जयपुर वाले लोग और जयपुर के एक्सपोर्टर्स अपना एक स्थान रखते हैं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस पर एक पॉलिसी बनाये। इस तरह का एक मॉडल लेकर आये तो एक प्लेटफार्म पर सारी तरह की ज्वेलरी यहां मिले। रेवेन्यू जनरेशन का और एम्प्लायमेंट जनरेशन की इससे बड़ी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और सर्टेन चीजों में हम पूरी दुनिया में माने जाते हैं। आप सेंट्रल में मंत्री रहे हैं, बहुत बड़ा विजन है। आपने सूरत के लोगों को देखा होगा, वहां पर डायमंड का काम बहुत होता है, लेकिन डायमंड जहां यूज किया जाता है, वह कलर स्टोन के साथ यूज होता है और कलर स्टोन और सोने-चांदी का काम जयपुर में बहुत बड़ा है। आप अगर इसमें कोई पॉलिसी

बनायेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल जयपुर की इंडस्ट्री बढ़ेगी, एम्प्लायमेंट जनरेशन होगा, बल्कि हम फोरेन एक्सचेंज लेकर आयेंगे और जितना साइज का आपका बजट है, उतना बड़ा काम हम अकेले जयपुर में कर सकते हैं।

बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर है, मूर्तिकला उद्योग है, रज़ाई के मामले में हम बहुत पहले से फेमस हैं, बैड शीट्स हैं। हम बहुत सारी चीजों में पूरी दुनिया में विख्यात हैं। आप एक पॉलिसी ऐसी लेकर आओ, जिससे पूरी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो और एम्प्लायमेंट जनरेशन हो। आप बातें करते हो कि हम 4 लाख को रोजगार देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। 4 लाख को रोजगार देना बहुत बड़ा टार्गेट है। लेकिन अगर आपने कोई इंडस्ट्री डवलप कर ली और आपने किसी ऐरिया को प्रमोट कर दिया, तो वह लोग जरूर एम्प्लायमेंट जनरेशन कर देंगे। हमें सामूहिक प्रयास करके यह टार्गेट करना चाहिये कि हम इंडस्ट्री को यहां डवलप करें, ताकि जो पूरी दुनिया से लोग आते हैं वह जयपुर में आएं, लोगों में जयपुर का वर्षों से भरोसा है। अगर हम इसको डवलप कर लेंगे तो न केवल रेवेन्यू जनरेशन होगी, बल्कि एम्प्लायमेंट जनरेशन में भी हम आगे जायेंगे।

एक बात आज के बजट में देखने को मिली। प्रधान मंत्री जी ने बहुत बातें कीं, आत्म निर्भर भारत। अब इंपोर्ट बंद, अब हम कोई चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो सारी चीज हिन्दुस्तान में बनायेंगे। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आपने इंपोर्ट पर ड्यूटियां घटा दी हैं। आज आपने इंपोर्ट के दरवाजे खोल दिये हैं, तो किस इंडस्ट्री को मारने का प्रयास कर रहे हो? एक तरफ तो आप बात करते हो कि हम आत्म निर्भर भारत लेकर आयेंगे और हर चीज हिन्दुस्तान में बनायेंगे और दूसरी तरफ जब आप बजट पेश करते हो, अपना पहला बजट दे रहे हो, उसमें यह कह रहे हो कि बाहर के लोग आओ, हम आपकी ड्यूटी कम कर देते हैं, हिन्दुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है, यहां माल बेचो। यह विरोधाभास क्यों? आपने आत्म निर्भर की बात की, लेकिन आत्म निर्भर के मामले में आप जीरो रहे।

एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं। अभी जोधपुर से आने वाले साथी बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत ईजी कर दिया, दिन भर से इंडस्ट्रीयल ऐरिये के नाम पर चर्चा हुई। मैं दो-तीन बात आपको बताना चाहता हूं, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है और हालत क्या है, आप 500 गज का प्लॉट नहीं दे सकते। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए और आपसे कहे कि मुझे 500 गज का प्लॉट दे दो, आपके पास 500 गज का प्लॉट देने के लिये जगह नहीं है। आपसे गुजारिश करता हूं कि इंडस्ट्रियल ऐरिया जयपुर के आस-पास लेकर आओ। रियायती दरों पर भू-खण्ड दो, जिससे इंडस्ट्रीज लग सकें।

ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा, कुछ ऐसे प्रोडेक्ट हैं, जो मिनरल हमारे यहां हैं, जो चीजें हमारे यहां पैदा होती हैं, जालोर साइड में जीरा वगैरह पैदा होता है, लेकिन प्रोसेसिंग गुजरात में जाकर होती है, क्योंकि गुजरात में टैक्स कम है, हमारे यहां टैक्स ज्यादा है। इस एसिमिट्री को दूर करो। इस सबके लिये आपको कैबिनेट में एक

समन्वय समिति बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक-दूसरे से चीजें क्लैश होंगी। क्वाड पैदा यहां होता है, अजमेर से निकलने के बाद आगे तक चले जाओ आप, रॉक फास्फेट है, लेकिन प्रोसेसिंग दूसरे स्टेट में होती है। केन्या, जिम्बाब्वे, जाम्बिया जैसी छोटी-छोटी कंट्रीज यह प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे प्रोडेक्ट को जो हमारे यहां प्रोसेस करेगा, उनको प्रायोरिटी देंगे। आपके यहां बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो प्रोसेस भी यहां हो। उनकी इंडस्ट्री यहां डवलप हो, दूसरे स्टेट को क्यों फायदा मिले? एम्प्लायमेंट जनरेशन भी होगा, रेवेन्यू भी आयेगी।

रीको के बारे में दो-तीन बातें झोटवाड़ा के प्लाट्स से रिलेटेड, छोटे प्लाट्स से रिलेटेड सबने कहीं। मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, जयपुर में कुछ इंडस्ट्रियल ऐरियाज ऐसे हैं जो टाउनशिप में आ गये, उनका शहरीकरण हो गया, उनको डिनोटिफाई करवाओ, सरकार से बात करो और उनकी एवज में दूसरे नये इंडस्ट्रीय ऐरिया डवलप करो, ताकि उन ऐरियाज का यूज भी हो सके और उन सब बातों का फायदा भी लिया जा सके।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय मेजर ध्यानचंद योजना थी, मेजर ध्यानचंद योजना में हमने स्टेडियम दिये और यह प्रोविजन था कि विधायक अपने कोटे से जितने पैसे देगा, उतने पैसे सरकार देगी। बहुत अच्छी स्कीम थी, इसको आपने क्यों बंद कर दिया? मेरी विधान सभा में मैंने एक करोड़ रुपये दिये हुए हैं, उसको तो पूरी करवा दो। जब सरकार के एक करोड़ रुपये मंजूर हैं, मैं तो कहता हूं कि पूरे राजस्थान में इसको कराओ। बहुत अच्छी स्कीम है, हर विधायक करना चाहता है, आपके यहां के भी करना चाहते हैं और हम भी करना चाहते हैं। अगर यह एक अच्छी स्कीम है तो हम सबको मिलकर एडॉप्ट करनी चाहिये। अभी सब आपसे डिमांड करें उसकी बजाय आप इसी स्कीम को लागू कर दो। आपको ध्यानचंद नाम अच्छा नहीं लगता, नाम कुछ और रख दो, लेकिन उस स्कीम को चालू तो रखो।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं सिर्फ इसलिए आपको इंट्रप्ट कर रहा हूं, मेजर ध्यानचंद का नाम तो हमें बहुत प्रिय है, हमने तो राजीव गांधी खेल रत्न को चेंज करके मेजर ध्यानचंद रखा है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना हम लेकर आये हैं, आप नहीं लेकर आये हो। नाम कोई भी रख दो, चालू कर देना आप तो।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): एक मिनट, वह चालू ही है, आपको ग़लतफ़हमी है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): वह चालू नहीं है और अगर चालू है तो आप आश्वासन दे दो, चालू नहीं है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): जब खेल मंत्री कह रहा है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): चालू नहीं है, मैं एक करोड़ रुपये दे चुका हूं, अभी तक सेंक्शन नहीं हो रही है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): वह आपकी सरकार में रुका होगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अब तो आठ महीने से आपकी सरकार है, मैंने तो पैसा मेरे कार्यकाल में दे दिया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, आपने जब फरवरी में बजट दिया तो यह कहा कि जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिये रेजीडेंशियल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट बनाये जायेंगे। कब बनाये जायेंगे, आठ महीने हो गये। कहां बनाओगे, बनाओगे या नहीं बनाओगे? केवल घोषणाओं के लिये बातें मत करो, काम करने के लिये धरातल पर बातें करो और उनका एग्जीक्यूशन करो, उनका उद्घाटन करो, इम्प्लीमेंट करो, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री आदू राम मेघवाल जी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत धन्यवाद।

(समय: बजे।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन।)

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का सुअवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का, आज केन्द्रीय बजट में राजस्थान को रिफंड में 7 हजार करोड़ रुपये की अधिक सहायता दी। महिलाओं व युवाओं के लिये विभिन्न योजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये, इसके लिये भी यशस्वी प्रधान मंत्री जी और हमारी केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

msk/rtm/23.07.2024/2030/4k

माननीय अध्यक्ष महोदय, चोहटन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बाखासर रण क्षेत्र में करीब 10 हजार बीघा जमीन बंजर और लवणीय पड़ी है। विगत सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में विकास कार्यों पर बिल्कुल ध्यान न देकर हमेशा दरकिनार किया है। परिणामस्वरूप विगत सरकार की उदासीनता ने सीमावर्ती क्षेत्र को आज भी वीरान कर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चौहटन विधान सभा क्षेत्र की आम जनता द्वारा विगत लंबे समय से बाखासर विस्तृत रण क्षेत्र में नमक उद्योग को स्थापित किये जाने की मांग की जा रही है, तो मैं प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री जी एवं उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि राज्य हित में बाखासर के रण क्षेत्र में नमक उद्योग की स्थापना की जाती है तो निश्चित रूप से वर्षों से खामोशी एवं अकेलेपन को देख रही भारत की पश्चिमी सरहद की विकास की आवाज बुलन्द होने लगेगी, प्रदेश में आर्थिक उन्नति के नये प्रतिमान स्थापित होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्तृत बाखासर रण क्षेत्र में नमक उद्योग स्थापित कर नमक उत्पादन की नवीन इकाइयां प्रारंभ की जाती हैं तो प्रदेश में औद्योगिक नीति के धरातल पर क्रियान्वयन सकारात्मक दृष्टि से होगा। उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ राज्य का समग्र आर्थिक विकास भी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग हमारी प्राचीन संस्कृति धरोहर के प्रतीक हैं, जो मानव संस्कृति और सभ्यता का हमेशा संरक्षण करते आये हैं। ऐसे में यदि सीमावर्ती बाखासर रण क्षेत्र में नमक उद्योग को स्थापित किया जाता है तो पश्चिमी राजस्थान के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर आसानी से प्राप्त होंगे। सशक्त भारत, मजबूत भारत का सपना जल्दी ही पूर्ण होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत भाग्य विधाता युवा। पश्चिमी राजस्थान में और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़मेर जिला है, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने, युवाओं ने इस देश का गौरव बढ़ाया है। जैसे हमारे जितेंद्र सिंह जी भाटी ने एशियाड गेम के अन्दर 2018 में भारत को 26 साल बाद रजत पदक दिलाया। हमारे सिपाही खेतराम सिहाग ने ओलम्पिक खेल 2016 में रियो डी जनेरियो में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बाड़मेर हाई-स्कूल के खिलाड़ी महिपाल सिंह जी भाटी ने बास्केटबाल वर्ल्डकप में भारतीय बास्केटबाल का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे ही हमारे सिपाही जितेन्द्र सिंह जी राठौड़ ने एथेलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। घुड़सवार गुलाब सिंह राठौड़ ने कई बार भारतीय घुड़सवारी टीम का प्रतिनिधित्व किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो युवा हैं। चौहटन क्षेत्र के अन्दर राज्य स्तरीय स्टेडियम बने।

हमारे चौहटन क्षेत्र के अन्दर आंगनबाड़ी केन्द्र में उम्मेदाणियां मेघवालों की ढाणी, कोली प्रजापतों की ढाणी, वरगाणियों मेघवालों की ढाणी, मीठे के तला, गणपति नगर, माजूओं गोदारों की ढाणी, हुडोका, थोरियो की ढाणी। चौहटन विधान सभा क्षेत्र में लोग भौगालिक दृष्टि से ढाणियों के अन्दर रहते हैं, यदि इन आंगनबाड़ियों को नये खोलेंगे तो वहां के लोगों को। आने वाले समय के अन्दर हमारे वहां ऐसे 36 नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायें। मैसूर की ढाणी, मेघवालों की ढाणी की स्वीकृति कराने बाबत, तखत सिंह की ढाणी, आकोड़ा, भामुओ का तला, लिजड़ो की बस्ती, गंगुपुरा में आंगनबाड़ी, सुरतान की ढाणी, पूनियों की ढाणी, भीलों का हाथला, दीनगढ़, नाइयों की ढाणी, आदर्श बासड़ऊ, ऊपरला पाड़ा सिंहार, मनोणियों-जाटों की ढाणी, वनार भीलों का पाड़ा, रते का तला, नवां तला बाखासर, भोजावास, गोड का तला, देवाणी कोलियों की ढाणी, रामदेव मन्दिर तालसर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चौहटन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, बाड़मेर जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में खेल कोच की नियुक्ति करने की अति आवश्यकता है। यदि खेल कोचों की नियुक्ति की जाती है तो निश्चित रूप से उन्नति और प्रगति के आयाम स्थापित होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं विधान सभा क्षेत्र की बहन-बेटियों की आवाज बनकर सदन में नेतृत्व करने आया हूं। वहां आज भी मानवीय

मूल्यों और सामाजिक कृत्यों को सर्वोच्च शिखर पर रखा जाता है। सीमावर्ती विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए जागरूकता लाने के लिए आधुनिक यंत्र प्रदान करने एवं भौतिकवादी युग की विशेष कार्ययोजना एवं नीति, प्रणाली बनाने की अति आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन के अन्दर वर्तमान में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के मौजूदा हालात अत्यन्त गंभीर हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं, आशा सहयोगिनियों आदि के समस्त पद लंबे समय से रिक्त हैं। ऐसे में राज्य हित में इन समस्त पदों को अतिशीघ्र भरा जाने की सख्त आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका पुनः आभार प्रकट करुंगा कि आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्षः डॉ. मंजू बाघमार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा व्यवस्था का सवाल है। मंत्री जी बोलेंगे, वे मंत्री जी भी बोलेंगे। इस सदन की गरिमा बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। आज 15 मंत्री गायब हैं। अगर मंत्री डिमांड के ऊपर बोल रहा है और 15-15 मंत्री अगर गायब रहेंगे तो इस सदन की गरिमा कैसे बचेगी?

श्री अध्यक्षः विपक्ष से भी केवल दस लोग बैठे हैं। 70 में से जिन 20 लोगों ने भाषण किया, वे तो बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डिमांड तो आपको पारित करानी है...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः वे तो बैठे हैं। सभी की ड्यूटी है। पक्ष और विपक्ष, दोनों को बैठना है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा एक निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे सुबह निवेदन किया था कि सदन की गरिमा की दुहाई देने वाले हमारे माननीय सदस्य बिना आपकी अनुमति से, बिना किसी कारण के, बिना किसी पुकार के, अपनी मनमर्जी से जब चाहे तब खड़े हो गये। यह सदन की गरिमा ऐसे रहती है या बिना अधिकार के, बिना परमिशन के बोलने से सदन की गरिमा रहती है। यह पहले बताना पड़ेगा। ऐसे बिना आसन की अनुमति के बोलते हैं और वे सदन की गरिमा की दुहाई देते हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, उतने तो हमारे मंत्री यहां उपस्थित हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः चर्चा नहीं। मैंने नाम पुकार लिया। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री गायब हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मैंने व्यवस्था दे दी है। बीच में आपने एक मिनट कहा, लेकिन पहले अपना घर संभालें, फिर इधर का देखना ...(व्यवधान)... मुझे दोनों को संभालना है, आप भी कम नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री ही गायब हैं।

श्री अध्यक्षः बैठे हुए हैं, जितने आवश्यक हैं, उतने बैठे हुए हैं। बैठिये, माननीय मंत्री डॉ. मंजू बाघमार।

mdp/rtm/23.07.2024/20:40/4l

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रदेश में ऊर्जावान मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब तथा हमारी उप-मुख्य मंत्री जो विभाग की केबिनेट मंत्री भी हैं, आदरणीय दिया कुमारी जी को और अध्यक्ष महोदय, आपको भी, जिन्होंने सदन में महिला एवं बाल विकास की अनुदान मांगो पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा दिये गये बहुमूल्य सुझावों का भी सम्मान करती हूं और सभी माननीय सदस्यों को और सदन को यह विश्वास दिलाती हूं कि आप द्वारा जनहित में जो सुझाव दिये गये हैं, उसको हमारी सरकार पूरा करने का पूर्ण प्रयास करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य में महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। विभाग का कार्यक्षेत्र राज्य के सभी जिलों में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक फैला हुआ है। राज्य की लगभग आधी आबादी को ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सेवाएं दे रहा है। किसी समय राजस्थान प्रदेश की जो छवि थी, वह रूढ़िवादी प्रदेश, बालिका अशिक्षा, भ्रूण हत्या और बाल विवाह से ग्रसित प्रदेश के रूप में थी। सभी के अथक प्रयासों और विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं की दशा बदलने के साथ-साथ उनके कार्य को करने की दिशा भी बदल गयी है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार का संकल्प है कि,

प्रदेश में विकास की नींव पर एक नया पत्थर लगाना है,
चुनौतियों से बाहर निकल कर प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने, उन्हें विकास की मुख्य धारा में समान रूप से जोड़ने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग का विभाजन कर महिला अधिकारिता निदेशालय एवं समेकित बाल विकास सेवाओं का गठन किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों के विकास के लिए मैं कहना चाहूंगी मुझे जान एफ. केनेडी की कोटेशन याद आ रही है, “Children are the living messages we send to a time we will not see.” इसी की तरह बच्चों का विकास करने के लिए वर्तमान में राज्य में 365 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन 62 हजार 20 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वास्थ्य की जांच और सन्दर्भ सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से ही विभिन्न

सेवाओं में राज्य में लगभग 42 लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं व 6 वर्ष तक के बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी नई सरकार के गठन होने के उपरांत विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से, उनका आमजन तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि उनके मार्गदर्शन में 100 दिवसीय कार्य योजना बनायी गयी। उसी के परिणामस्वरूप हमारी इस 100 दिवसीय कार्ययोजना के अन्दर राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों के अन्दर पोषण पंचायतों का गठन किया गया, जिससे महिला एवं बच्चों के कुपोषण के कारणों की जांच की जाए और उसमें सामूहिक सहभागिता निभाई जाए ताकि महिला और बच्चों के कुपोषण से उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। इसी की तर्ज पर जो आंगनबाड़ी केन्द्र थे, उन्होंने पिछले चार सालों में बच्चों के लिए चार वर्ष से अधिक के पुराने ग्रोथ मॉनिटरिंग इक्यूपमेंट थे, जो काफी पुराने हो गये थे, उनको बदलकर उनके स्थान पर करीब 31 हजार 694 स्टेडियोमीटर, 31 हजार 694 इंफेंटोमीटर तथा 21 हजार 367 वज़न मशीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये गये हैं।

इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत जो हमारी पात्र महिलाएं हैं, करीब 50 हजार पात्र महिलाओं को, लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से नगद लाभ हस्तांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में 85 हजार 500 पात्र लाभार्थी महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है। इस योजना में अब तक 26 लाख 35 हजार लाभार्थियों को लगभग 959 करोड़ 70 लाख की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के 7 माह के कार्यकाल के दौरान ही लगभग 3 लाख 40 हजार 600 लाभार्थियों को राशि 91 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

इसी तरह राज्य मद से संचालित योजना आईजीएमपीवाई के अंतर्गत द्वितीय बालक के जन्म पर राज्य सरकार के सात माह के कार्यकाल के दौरान ही 2 लाख 35 हजार 243 लाभार्थियों को लगभग 74 करोड़ 67 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

हमारी जो 100 दिन की कार्य योजना थी, उसी के अन्दर राज्य सरकार द्वारा 6 हजार 204, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र जो राज्य में संचालित किये जा रहे हैं, उनको मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र के अन्दर क्रमोन्नत किया जा रहा है। उसमें पहले एक ही मानदेय कर्मी कार्य करता था। अब दो-दो मानदेय कर्मी वहां रहेंगे। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस विभाग की सेवाएं दी जा रही हैं। इन क्रमोन्नत केन्द्रों के लिए 6204 मानदेय कर्मियों का चयन किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से केन्द्र की 2023-24 की जो हमारी बजट घोषणाएं थी, उसमें प्रधान मंत्री जनजाति आवासीय न्याय अभियान, पीएमजनमन जो योजना थी, उसके अन्दर 12 जिले की आदिवासी बाहुल्य परियोजनाओं में 12 नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाकर संचालित किये जा रहे हैं।

मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने अल्पकाल में ही ये उपलब्धियां हासिल की हैं।

आगे भी सरकार बालिकाओं और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। हमारी यही भावना हमारे बजट में भी परिलक्षित हो रही है। जो हमारी बजट घोषणा थी 2024-25 की, उसकी पालना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 1 अप्रैल, 2024 से 10 प्रतिशत वृद्धि कर दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा आगे भी क्रमिक रूप से मानदेय में वृद्धि की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में विभाग की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाते हुए महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए कुछ बजट घोषणाएं भी की गयी है। जैसे कि प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाएगा, हमने अपने लेखानुदान में इसकी घोषणा की थी। अभी प्रदेश में 365 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने बताया था, उसी आधार पर मैं बताना चाहूंगी कि जो ये आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बनाए जा रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक के अन्दर, इसके अन्दर गरीब तबके के जो बच्चे हैं, उनको भी प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर उस स्तर की सुविधा प्राप्त हो, इसलिए हम इन आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उनको उस स्तर की सुविधाएं देना चाहेंगे ताकि वे प्री-प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर प्राइवेट स्कूल से भी उनका कॉम्पीटीशन हो सके। हम आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों के अन्दर जो सुविधाएं देंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का कार्य, वॉल पेंटिंग करवाई जाएगी। साथ में सोलर पॉवर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उसमें दिया जायेगा। चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उसमें लगाया जायेगा। साथ ही ड्रिंकिंग वॉटर के लिए आर ओ वॉटर प्यूरिफाई भी लगाया जायेगा। टॉयलेट मेकओवर बनाएं जाएंगे, उसके लिए इलेक्ट्रिक आइटम लगाएं जाएंगे, जैसे फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब और भी जो आइटम्स वगैरह हैं, एलईडी टीवी, सीसीटीवी, वाई-फाई, पेन ड्राइव जो भी लगाए जाएंगे। पोषाहार कंटेनर भी नये खरीदे जाएंगे। पोषण वाटिका भी बनायी जायेगी। लाइब्रेरी कॉर्नर भी बनाए जाएंगे। इस तरह से आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किए जाएंगे।

इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्दर जो आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जो बाकी हमारे बचे हुए केन्द्र हैं, उनमें भी चरणबद्ध रूप से प्रत्येक आंगनबाड़ी के अन्दर शुद्ध पेयजल, बिजली एवं बच्चों को गरम पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में 2 हजार केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। इससे प्रत्येक विधान सभा के अन्दर कम से कम 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में विकसित किया जायेगा। हमने करीब 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको क्रमोन्नत करने के लिए। इसके अन्दर भी कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग का कार्य किया जायेगा, वॉल पेंटिंग की जायेगी, आर.ओ. वॉटर प्यूरिफाई लगाया जायेगा, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट बनाये जायेंगे, इलेक्ट्रिक आइटम लगाए जाएंगे, किचन स्लैब को मोडिफाई किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमारी मातृ वंदन योजना, पीएमएमवीवाई योजना है, वह राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के द्वारा प्रथम बच्चे के जन्म पर कुल भुगतान राशि जो 5 हजार रुपये दी जाती थी, उसमें 1500 रुपये की वृद्धि करके अब उसे 6 हजार 500 रुपये देने की घोषणा की गयी है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत जो दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को राशि 6 हजार 500 रुपये के स्थान पर 10 हजार रुपये दिये जायेंगे। मैं यह बताना चाहूंगी कि उक्त अतिरिक्त राशि शत-प्रतिशत राज्य मद से वहन की जायेगी।

Ans/rtm 20.50 4m 23.07.2024

साथ ही काफी समय से स्कूलों के अन्दर बच्चों के समान आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी बच्चो को दूध उपलब्ध किए जाने की मांग को देखते हुए करीब 36 लाख बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सप्ताह में तीन दिन उन्हें दूध उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए प्रथम चरण में ही राज्य मद से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगर समाज में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका की बात करूं तो मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर का एक कथन याद आ रहा है, मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन वहां की महिलाओं की स्थिति से करता हूं। हमारी बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने के लिए महिला अधिकारिता द्वारा कई योजना भी संचालित की जा रही है, जिसमें विवाह में होने वाले अनावश्यक खर्च, बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने के लिए सामूहिक विवाह अनुदान योजना संचालित है। इसके तहत प्रति जोड़ा राज्य सरकार द्वारा 25 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1 हजार 546 नव विवाहित जोड़ो को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है,एवं 2 करोड़ 40 लाख रुपये इस पर व्यय किए गए हैं।

इसी तरह राजस्थान राज्य की किशोरी तथा महिलाओं के स्वास्थ्य में जागरूकता के लिए नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन हेतु उड़ान योजना संचालित की जा रही है। इसमें वेस्ट मैटेरियल के लिए डिस्पोज करने के लिए मैन बात है, वह सेनेटरी नैपकिन अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य सेनेटरी नैपकिन अपशिष्ट प्रबंधन नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट से अनुमोदन के उपरांत शीघ्र ही इस नीति को लागू कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच और उनके शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए मुख्य मंत्री राजश्री योजना भी लागू की गई थी और इस

योजना के तहत बालिका के माता-पिता व अभिभावक है, उनको कुल 50 हजार रुपये का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक इस योजना में 1 लाख 74 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

इसी तरह से बालिकाओं का सशक्तीकरण की दिशा में एक नई योजना भी लागू करने का सरकार का विचार है, जिसमें लॉडो प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जा रही हे। इसके तहत बालिकाओं का विभिन्न चरणों में 1 लाख रुपये तक दिए जाने का वित्तीय प्रावधान किया गया है, तथा उनको सेविंग बॉड भी दिए जाएंगे, यह योजना शीघ्र राजस्थान राज्य के अन्दर लागू की जाएगी।

इसी तर्ज पर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री द्वारा शिशु लिंगानुपात में सुधार करने के लिए और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। इसके तहत विभाग द्वारा 2023-24 में विभिन्न स्तरों पर 1 लाख 8 हजार बेटियों का जन्मोत्सव मनाया गया तथा कन्या वाटिका के तहत 70 हजार पौधे लगाए गए हैं। इस योजना के माध्यम से समाज में बालिकाओं के प्रति एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है जिससे बेटियों का लिंगानुपात भी सुधरा है। मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थान का 947 हैं, जो कि इंडिया के एवरेज से ज्यादा है।

इसी तरह से सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर हिंसा से व्यथित और पीड़ित महिलाओं को उन्मूलन, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए, हिंसा के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए हमारे यहां 246 पुलिस सर्किलों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं और अब तक इसमें 80 हजार से अधिक प्रकरणों में पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान की जा सकी है।

इसी तरह राज्य में महिलाओं को शोषण से, उत्पीड़न से बचाने के लिए, उन्हें समुचित संरक्षण प्रदान करने के लिए महिला हैल्प लाइन 181 स्थापित की गई है, जो 24X7 घंटे कार्य करती है। महिला हैल्प लाइन पर अब तक 47 हजार से अधिक रेफरल प्रकरणों में राहत दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि भारत सरकार द्वारा 2015 में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना प्रारम्भ की गई थी। राज्य में जो जिला मुख्यालय है, करीब 37 जगह पर भी इन महिलाओं को एकल खिड़की योजना के तहत 24 घंटे चिकित्सकीय, पुलिस, विधिक, परामर्श सहायता, अस्थायी आश्रय की भी आवश्यक सुविधा प्रदान की जाती है। इसके तहत वन स्टॉप सेंटर, सखी केन्द्रों पर अब तक 28 हजार से अधिक प्रकरणों में पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान की जा सकी है।

अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम साथिनों का मानदेय सेवा का पद स्वीकृत है। साथिनों महिलाओं को भी आत्मनिर्भर एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक

करने और सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों, योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलवाने के लिए, जो कार्य कर रही है इसलिए माह अप्रैल, 2024 में साथिनों का मानदेय भी 5 हजार 313 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 5 हजार 844 रुपये अर्थात 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि उद्यम प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत हमारे विभाग द्वारा कई प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते है। इसके अन्दर महिलाओं को 50 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। यदि कोई जनरल महिला है तो उसे 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। अगर एससी,एसटी, परित्यक्ता है तो उसको 30 परसेंट की सब्सिड़ी दी जाती है। एसएजी ग्रुप है, उन्हें करीब 1 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाता है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 7 करोड़ 63 लाख रुपये के 125 ऋण आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं।

इसी तरह से शिक्षा सेतु योजना जो विभाग द्वारा चलाई जा रही है शिक्षा से वंचित महिला, बालिकाएं हैं जो ड्रॉप आउट हो गई है, जिन्होंने किसी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। पूरी फीस विभाग द्वारा उसको रिएम्बर्स कर दी जाती है। योजना के अन्तर्गत अब तक 2 लाख 82 हजार महिलाएं व बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। इसी तरह से निःशुल्क बेसिक कम्प्यूटर आरएस सीआईटी प्रशिक्षण योजनाओं के तहत महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क आरएस सीआईटी प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक इसमें 3 लाख, 54 हजार बालिकाएं और महिलाएं इससे लाभान्वित हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी, स्वयं सहायता समूह हैं, उनके द्वारा निर्मित प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रमोशन करने के लिए उनका सवंर्द्धन करने के लिए, उनके अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शन के लिए, उनके उत्पादों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, उनको अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अमृता हाट बाजार का आयोजन किया जाता है। उन महिलाओं को जो यहां आकर अपना स्वयं सहायता समूह की महिला जो अपने समूह द्वारा निर्मित प्रोडक्ट को वहां पर रखती है। उनके आने जाने का किराया, भोजन, ठहरने की व्यवस्था और उनकी दुकान भी निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। अब तक 90 हॉट बाजार आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें करीब 6 हजार 784 स्वयं सहायता समूह द्वारा भाग लिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि अनुदान माँगों पर चर्चा के दौरान मुझे माननीय सदस्यों के विभिन्न योजनाएं एवं गतिविधियों के सम्बन्ध में कुछ कटौती प्रस्ताव भी प्राप्त हुए थे, उनका जवाब माननीय सदस्यों को भिजवा दिया गया है। शेष प्रस्तावों के सम्बन्ध में, जो कि अभी मुझे काफी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य प्रस्ताव दिए थे, उसके अन्दर अपने सुझाव भी दिए थे, उसके अन्दर नये आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने के लिए, भवन निर्माण, मरम्मत के लिए, रिक्त स्टाफ को भरने के लिए, कुछ में किराया बढ़ाने के लिए आंगनबाडी केन्द्र को।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26- युवा मामले एवं खेल, मांग संख्या 32- महिला एवं बाल विकास व मांग संख्या 56- उद्योग पर विचार

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए, पोषण में गुणवत्ता सुधार के लिए, पोषाहार की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, कई सारे बहुमूल्य सुझाव मुझे दिए गए हैं, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि विभिन्न विभागीय योजनाएं एवं गतिविधियों के सम्बन्ध में मुझे सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनका समुचित परीक्षण करवाकर नियमों के अधीन व्यावहारिक सुझावों को विभागीय योजनाएं एवं गतिविधियों में सम्मिलित कराये जाने के प्रयास किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार के गठन होते ही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय और हमारी उप मुख्य मंत्री महोदय, बच्चों, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि राज्य के विकास के लिए उनकी भावना और प्रयासों के सम्बन्ध में मैं कुछ लाइनें कोट करना चाहूंगी। इस प्रकार का उन्होंने 10 जुलाई को बजट पेश किया

VPS-RTM-23.07.2024-21.00-4n

जिसकी सब जगह पर सराहना की जा रही है और हर विभाग को हर क्षेत्र के अन्दर उन्होंने बजट में प्रावधान किया है, जिससे निश्चित रूप से हमारे यहां कि बालिकाएं और महिलाएं सशक्त होंगी। इसके अलावा भी कई विभाग की कई सारी योजनाएं भी हमारे अलग-अलग विभागों द्वारा चलायी जा रही हैं। जैसे अभी कई सुझाव मुझे दिये गये थे उनमें यह बताया गया था कि साहब, इसमें वर्किंग वूमैन के लिए भी हॉस्टल वगैरह बनाइये तो जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से अलग-अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा इस प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं और हमारे बजट घोषणाओं के अन्दर हमने यह कहा था कि सैनिक स्कूल भी हम, बालिकाओं के सैनिक स्कूल भी खोलेंगे, इस तरह की कई सारी घोषणाएं बजट में की गईं तो

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय आदरणीय भजन लालजी शर्मा साहब का और हमारी उप मुख्य मंत्री महोदया आदरणीय दिया कुमारीजी की राज्य के विकास के लिए उनकी भावनाएं हैं और बजट में जो उनके प्रावधान किये गये हैं और उनके लिए जो प्रयास किये गये हैं, उनके सन्दर्भ में यह कहना चाहूंगी कि-

हम चलेंगे तो आंधियां, तूफान खुद ही चल पड़ेंगे,
सागरों की क्या बात है, हिमगिरी सरीखे ढल पड़ेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): तूफान आ गया।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हो गया?

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): एक मिनट।

हम चलेंगे तो आंधियां, तूफान खुद ही चल पडेंगे,
सागरों की क्या बात है, हिमगिरी सरीखे ढल पड़ेंगे,
यह दिशाएं पथ हमारा रोक लेंगी,
हम चलेंगे तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उद्योग मंत्री।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पारित करने का प्रस्ताव तो करवाइये।

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड। मैंने सोचा बाद में रखवाते हैं। हां, आप करिये।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 32- महिला एवं बाल विकास पारित की जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के दूसरे सत्र में अनुदान मांगों पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया जा रहा है, उससे मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान और केन्द्र दोनों का लक्ष्य एक है कि राजस्थान विकसित हो और पूरा भारत विकसित हो और एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं कि 2047 तक, हम हमेशा अपने लिए तारीख तय करते हैं, हर काम के लिए तारीख तय करते हैं, 2047 तक हमारे को भारत को, राजस्थान को विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनाना, यह हमारा लक्ष्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह बजट भी हुआ और आज अनुदान की मांगें हुईं।

मैं इस सदन के पटल पर यह कहना चाहूंगा कि आज की चर्चा बड़ी शानदार चर्चा थी। अनेकों विधायकों ने अपनी-अपनी बात रखी और सब तथ्यात्मक बहुत शानदार सुझाव दोनों पक्ष की तरफ से आये। मैं एक बार धन्यवाद के रूप में नाम लेना चाहूंगा- डॉ. जसवन्त सिंह यादव, श्री अशोक चांदनाजी, श्री बालमुकुन्दाचार्यजी, श्री अमीन कागजी जी, श्री गोविन्द प्रसादजी, श्री रोहित बौहराजी, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरीजी, श्रीमती अनीता जाटवजी, श्री

गुरवीर सिंहजी, डॉ. शिखा मील बरालाजी, श्री जीवाराम चौधरी जी, श्री अरूण चौधरीजी, श्री जाकिर हुसैन गैसावत साहब, श्री जसवंत सिंह गुर्जरजी, श्री ताराचन्दजी, श्री मनोज कुमारजी, श्री रविन्द्र सिंह भाटीजी, श्री सुभाष मीलजी, श्री हाकम अली खां साहब, श्री लालालामजी, श्री घनश्यामजी, श्रीमती कल्पना देवीजी, कुमारी रीटा चौधरीजी, श्री चन्द्रभान सिंह चौहान साहब, श्री उमेश मीणाजी, श्री कुलदीप धनखड़जी, श्री ललित यादवजी, श्री अंशुमान सिंह भाटीजी, श्रीमती शोभारानी कुशवाह, श्री लादु लाल पितलियाजी, श्री अभिमन्युजी, श्री धर्मपालजी, श्री संजय कुमारजी, श्री डूंगररामजी, श्री राजेन्द्रजी, श्री नाना लालजी, श्री पूसारामजी, श्री देवेन्द्र जोशीजी, श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडीजी, श्री रफीक खान साहब एवं श्री आदू राम मेघवाल साहब, आप सभी ने बहुत ही बढ़िया पाइंट दिये हैं। हालांकि, मुझे यह ताज्जुब हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जिस आत्मीयता से, जिस जज्बे से, जिस जोश के साथ, जिस बारीकी से मेरे कांग्रेस के साथी सुझाव दे रहे थे, जो कमियां थीं, मुझे यह लगा कि जैसे इनकी सरकार तो कभी रही ही नहीं लेकिन सुझाव अच्छे आये हैं।

आज की सदन की चर्चा तो अच्छी हो गयी। पिछले पांच दिनों में क्योंकि अनुदान की मांगें मेरे विभाग की आज पहली बार आयी हैं तो मुझे बोलने का मौका आज पहली बार मिला है। पिछले कुछ दिनों में यह बजट की चर्चा और उनके अनुदानों की मांगों की चर्चा का बहाना लेकर कुछ समाज विरोधी बातें बोली गईं, जिससे बड़ा कष्ट हुआ। 'पधारो म्हारे देस', राजस्थान की परम्परा है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की परम्परा वाला हिंदुस्तान और यहां पर बांटने की बातें हुईं, तोड़ने की बातें हुईं, भड़काने की बातें हुई और जब मैंने यह देखा कि हमारे कांग्रेस के साथी टोक भी नहीं रहे, रोक भी नहीं रहे अपने साथियों को तो यह आपकी इच्छा के ऊपर, आपकी जो इंटेंशन है, भावना है, उसके ऊपर फिर शक होता है। हम विपक्षी हो सकते हैं विचारधारा में लेकिन राष्ट्र हमारा एक है और हमारे पूर्वज भी एक हैं। जब एक समाज के पूर्वजों के लिए यहां पर बात की गई तो पूरे राजस्थान को उससे कष्ट हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैनिक हूं और जीवनभर सैनिक रहूंगा और मैं एक खिलाड़ी भी हूं और जीवनभर खिलाड़ी रहूंगा और आज मैं एक जन सेवक भी हूं और क्योंकि जन सेवक हूं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। एक कविता यहां पर पढ़ी गयी जो समाज को बांटने वाली कविता थी। मैं समाज को जोड़ने वाली कविता पढ़ना चाहता हूं, मैं अपने योद्धाओं को नमन करने वाली कविता पढ़ना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अनुमति है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): कविता है- प्रश्न है सम्मान का, सम्मान किसका? आपके और हमारे पूर्वजों का।

प्रश्न है सम्मान का, सम्मान है बलिदान का, बलिदान है जवान का, उन्होंने पूरी जवानी कुर्बान कर दी। सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जवानी।

प्रश्न है सम्मान का,
सम्मान है बलिदान का,

बलिदान है जवान का,
और जवान है हिंदुस्तान का।

सभी योद्धा हर जाति के होते हैं और पूजनीय होते हैं। हम योद्धाओं को अगर बांटने लग गये तो फिर यह देश कहां पर जाएगा?

प्रश्न है सम्मान का,
सम्मान है बलिदान का,
बलिदान है जवान का,
और जवान है हिंदुस्तान का।
किसी ने छोड़ी रियासत,
किसी ने दी शहादत,
तब ही यह बना मजबूत भारत,
कांग्रेस को है बांटने की आदत,
इनके सपने में नहीं एक भारत।
कांग्रेस को है बांटने की आदत,
इनके सपने में नहीं एक भारत,
बस, मोहब्बत की यह नेम प्लेट लगाते हैं,
मोहब्बत की नेम प्लेट लगाते हैं,
पर दुकान नफरत की चलाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जो कविता यहां पर पढ़ी गयी थी, उसके अन्दर केवल जहर था। रोकना चाहिए था पर रोका नहीं।

बस मोहब्बत की यह नेम प्लेट लगाते हैं,
पर दुकान नफरत की चलाते हैं।
बोर्ड मोहब्बत की दुकान का,
सौदा नफरत के सामान का,
इनको फर्क नहीं नुकसान का,
क्योंकि नुकसान हिंदुस्तान का।

यह आप और हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी जातियां योद्धाओं की, योद्धाओं की कोई जाति नहीं होती है, सभी पूजनीय होते हैं। खासतौर से महाराणा प्रताप, उनकी सेना में तो छत्तीस कौम ने उनका साथ दिया था और मेरे साथी आज यहां पर नहीं हैं विपक्ष के, शायद हो सकता है कि टी.वी. पर देख रहे हो, उनके पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ अकबर की सेना के दाँत खट्टे किये थे, वे भी ध्यान से सुनें। ध्यान से सुनें वे क्योंकि उन्होंने राजस्थान को बांटने की बात की थी।

सभी जातियां योद्धाओं की,

योद्धा थे महाराणा प्रताप के,
महाराणा प्रताप राजस्थान के,
और राजस्थान हिंदुस्तान का।

माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं की बात हो रही है। आज युवाओं से ही शुरू करते हैं। खेल, स्पोर्ट्स, युवा। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार सभी खिलाड़ियों को जिनके नाम यहां पर आज आप सबने लिये, उन्हें आमंत्रित किया गया था, युवाओं के अन्दर स्टार्टअप जो चला रहे हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया था और उनसे बात करके कि किस तरह की युवा नीति बननी चाहिए, किस तरह की स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हुई। मैं इस शुरूआत के लिए मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं।

SSY/RTM/23.07.2024/21:10/4o

मैं फिर बधाई देता हूं मुख्य मंत्री जी को और हमारी वित्त मंत्री जी को, कि खेल के अन्दर 475 करोड़ के बजट को चरणबद्ध तरीके से दुगुना किया जायेगा ताकि युवाओं के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके।

अब नई खेल नीति बनाई जायेगी। नई खेल नीति आपके लिए नई बात नहीं है। वह चांदना जी चले गये यहां से। चांदना जी खिलाड़ी हैं, ऐसे हट्टे-कट्टे मजबूत हैं। लेकिन उनके सामने एक रुकावट डाल दी थी। अब मनोज जी मुस्करा रहे हैं, वह जानते हैं रुकावट क्या है। आप भी जानते हैं रुकावट क्या है। उनको बैठा तो दिया था खेल मंत्री की कुर्सी पर, लेकिन उनके साथ एक रुकावट भी लगा दी थी। उसकी वजह से उन्होंने 2020 में यहां सदन के अन्दर बोला था कि हम एक नई खेल नीति लेकर आयेंगे। यह उनका कोट है। लेकिन 2020 निकल गया, 2021 निकल गया, 2022 निकल गया। हम नई खेल नीति लेकर आयेंगे।

जब हम युवाओं की बात करते हैं तो बड़ा मंथन करके एक अच्छी नीति बननी चाहिए जिसमें आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। टार्गेट ओलंपिक पोडियम, हम अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर लेवल का खेल होना चाहिए। ग्रास रूट लेवल का खेल होना चाहिए। जैसा कुछ हमारे साथियों ने बोला है कि आत्मीयता बनती है। अमेरिका के अन्दर जहां पर गैंग्स वार होते हैं, वहां पर खेलों के माध्यम से उन युवाओं को जोड़ा जाता है, एक पॉजिटिव रास्ते के ऊपर। आत्मीयता बढ़ाने के लिए, लोग आपस में मिलें उसके लिए खेल ग्रास रूट भी होने चाहिए और एक्सीलेंस के लिए भी होने चाहिंए, ओलंपिक्स के लिए भी होना चाहिए।

प्रधान मंत्री मोदी जी ने टार्गेट ओलंपिक पोडियम शुरू किया था। मैं संक्षिप्त में बताऊं तो उस समय के खिलाड़ी ऐसे होते थे जो सुबह चलते थे तो अपने साथ 2 टिफिन लेकर चलते थे। 2-3 जोड़ी कपड़े लेकर चलते थे। क्योंकि सुबह ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग करने के बाद,

पसीने बहाने के बाद शर्ट, पैंट पहनकर खेल मंत्रालय जाते थे। वहां पर अपनी फाइल को धक्का लगाते थे। 4-5 घंटे वहां बिताने के बाद फिर वापस कुछ भोजन करके, कपड़े चेंज करके फिर वह वर्जिश करने जाते थे। इस तरह से वह होता था। टार्गेट ओलंपिक पोडियम के अन्दर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, उनके लिए अलग से फंडिंग है। उनके लिए अलग से ऐसे मैनेजर्स उनके साथ लगाये हुए हैं, जो उनकी सारी समस्याओं का हल करके देते हैं। हम राजस्थान के अन्दर भी केन्द्र की तरह टार्गेट ओलंपिक पोडियम यहां शुरू करेंगे जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे उनके लिए स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवलेबल हो, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अवलेबल हो।

पेरिस ओलंपिक्स के लिए 117 खिलाड़ी रवाना हो चुके हैं। उसमें से 2 खिलाड़ी हमारे राजस्थान के हैं। सभी हमारे हैं बिलकुल सही बोला। सभी हमारे हैं लेकिन उनमें से 2 राजस्थान के हैं, अनन्तजीत नरुका और माहेश्वरी चौहान। सदन में मेरे छोटे भाई ने कहा कि उनको राजस्थान से कुछ नहीं मिला, रविन्द्र जी भाटी ने कहा उनको राजस्थान से कुछ नहीं मिला। उन्हें पता नहीं है। अनन्तजीत और माहेश्वरी दोनों को मैंने बचपन से ही देखा है। बड़े होते देखा है। दोनों ने राजस्थान की भाजपा सरकार की बनाई हुई जो शूटिंग रेंज हैं, वहां से अपना पूरा बचपन, वहां अपनी ट्रेनिंग की, वहां से उनका पूरा कैरियर स्टार्ट हुआ। उन दोनों के पिताजी वहां आते थे। यूनुस खान जी मुस्करा रहे हैं, आप खेल मंत्री थे शायद उस समय।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सुबह तो सुनना नहीं चाह रहे थे। आपने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम किया है। आपके लिए जोरदार तालियां।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माहेश्वरी चौहान हमारे जालौर जिले से है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): बधाई हो। राज्य क्या करता है? राज्य एक नर्सरी है। उस नर्सरी में वह खिलाड़ियों को तैयार करता है ताकि वह अंतरराष्ट्रीय लेवल के हो जायें, फिर उसके बाद देश की सरकार उनको संभालती है। हमने यहां से उनको तैयार करके भेजा। यहां पर हजारों कारतूस उन दोनों ने शूटिंग रेंज में चलाये हैं। हमें गर्व है, हमें फ़ख़्र है। मुझे उम्मीद है वह वहां पर जरूर पदक जीतेंगे। हम सारे के सारे कंटीन्जेंट को, सदन जोरदार ताली बजाकर, मेजें थपथपाकर उनको बधाई दे कि हमारे खिलाड़ी वहां पर जीतकर आयें।

खेलों को प्रमोशन करने के लिए खेलो राजस्थान यूथ गेम्स हम शुरू करेंगे। जैसे प्रधान मंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया वहां पर शुरू किया है, उसी तरह खेलो राजस्थान यूथ गेम्स हम शुरू करेंगे। कोचेज और स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट, गुरू बहुत जरूरी होते हैं। गुरुओं को सही ट्रेनिंग मिल पाये उसी के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 250 करोड़ लगाकर हम बना रहे हैं। केवल एक ही जगह बन जाये, उससे काम नहीं चलेगा। उसके अलग-अलग संभाग के अन्दर, कॉलेजेज हों, यह हमारा विजन है। इसको हम पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपके अजमेर के अन्दर, बोराज काजीपुरा के अन्दर कलेक्टर ने जमीन भी चिह्नित कर ली है। बाकी जगह भी हम जमीन चिह्नित कर लेंगे। इसको जल्द ही बनायेंगे। यहां पर सभी कोचेज को बार-बार ट्रेनिंग के लिए भेजा जायेगा ताकि उनकी जो नॉलेज है वह हमेशा अपडेटेड रहे। हम कोशिश यह भी करेंगे कि जो पीटीआईज हैं, क्योंकि विभाग मदन

जी का है, जो पीटीआईज हैं, जो स्कूल में टीचिंग करते हैं, क्योंकि स्कूल, जैसे उस दिन डोटासरा जी बता रहे थे, स्कूल एक बैडरॉक है, फाउंडेशन है, स्कूल में अगर सही शिक्षा मिलेगी खेलों की भी तो वह आगे बढ़ेंगे। मैं मदन जी से रिक्वेस्ट करुंगा कि वे भी अपने पीटीआई वहां पर ट्रेनिंग के लिए भेजें। इस तरह से हम साइकिल पूरे साल भर चलाते रहेंगे।

वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, हम सब बातें करते हैं कि एक समय ऐसा था जब राजस्थान बास्केटबॉल के अन्दर शानदार था। फुटबॉल के अन्दर बहुत शानदार था। हमें अभी से संकल्प लेना है कि हम ऐसे-ऐसे जिलों को जहां स्पेशलाइज्ड खेल हैं, वहां उस पर फोक्सड ट्रेनिंग दें। इसको हम करवायेंगे।

स्टेट ऑफ दा आर्ट, फिटनेस सेंटर हाल ही में जैसे ही हमारी सरकार बनी, मैं एक दौरे पर एसएमएस स्टेडियम में गया तो पता चला कि डेढ़ करोड़ का एक जिम बन रहा था। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसके अन्दर एसएमएस स्टेडियम वाला हिस्सा और डेढ़ करोड़ की लागत से कोई जिम बने, यह तो नाइंसाफी है। पूरे राजस्थान के लिए एक आइकॉनिक प्लेस होना चाहिए। उसको हम 10 करोड़ की लागत से शानदार फिटनेस सेंटर बनायेंगे।

हमारे पैरा एथलीट्स हमें गौरवान्वित करते हैं। बाहर बहुत पदक जीत रहे हैं। उनके लिए भीहर तरह के विशेष प्रावधान करवाये जायेंगे। गांव के अन्दर, असली जो टैलेंट है, पोटेंशियल है, वह गांवों में बसता है। वहां पर उनके पेट में एक लगन है। अध्यक्ष महोदय, कोई खिलाड़ी रिसोर्सेज से, साधनों से नहीं जीतता। अगर कोई खिलाड़ी जीतता है, कोई चैंम्पियन बनता है तो अगर उसके पेट में आग हो कुछ करने की, तभी जीत सकता है। इसीलिए हमारे गांवों के अन्दर हमें एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है।

प्रधान मंत्री मोदी जी ने जब फिट इंडिया कहा, हम सब स्वस्थ रहें, फिट रहें, उसका आह्वान किया है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम चरणबद्ध तरीके से ओपन जिम्स ग्राम पंचायतों के अन्दर लगायेंगे। पहले शुरू करेंगे 10 हजार से अधिक जिनकी आबादी हो, फिर धीरे-धीरे नीचे जायेंगे।

यहां पर कुछ साथियों ने यह भी बात की कि उनका जो रिक्रूटमेंट होता है, उस रिक्रूटमेंट के अन्दर एक दिक्कत आती है। वह दिक्कत होती है फॉल्स सर्टिफिकेट्स की। यह फॉल्स सर्टिफिकेट्स की जो समस्या है, इसका समाधान करने के लिए हमें केन्द्र के साथ बात करनी पड़ेगी। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके अन्दर जैसे ही कोई नौजवान किसी भी खेल में खेलता है, चाहे वह 14 वर्ष का कहीं खेल रहा हो तो उसका एक बार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वह रजिस्ट्रेशन हमेशा क्लाउड में रहना चाहिए। ताकि वह कभी बदल नहीं सकता। उसी तरह सर्टिफिकेट्स भी जो दिये जायें वह सर्टिफिकेट्स भी क्लाउड्स में पहुंचे ताकि कोई भी उसको देख सके।

यूथ डे, राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ। विदेश में जाकर एक्सपोजर का अनाउंसमेंट हुआ। आप और हम जब छोटे थे तो हमारी दुनिया बहुत सीमित

थी। आज के नौजवान के चूंकि एक हाथ में मोबाइल है, वह सीधे अमेरिका पहुंचता है। सीधे कहीं दूसरे देश में पहुंचता है। उनका एक्सपोजर और बढ़े, उसके लिए वह दूसरे देशों के युवाओं के साथ बात करें, तो बहुत शानदार रहेगा। ऐसी व्यवस्था केन्द्र सरकार ने तो की हुई है। हम राजस्थान के अन्दर भी करेंगे। हम अपने युवाओं को विदेश भेजेंगे ताकि वह दूसरे देशों के नौजवानों के साथ इंटरेक्शन कर सकें और उनका विश्वास व भरोसा और बढ़े।

यूथ डे की बात हुई। हम केवल 12 जनवरी को यूथ डे मनायें, केवल ऐसा नहीं है। ऐसा तो है ही कि एक ऐसा दिवस हो, या 3-4 दिन हों, जहां पूरे राजस्थान से, अलग-अलग जिलों से नौजवान वहां पर आयें और एक-दूसरे से सीखें। अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। उनमें भरोसा और जागे।

हम एक ऐसा पोर्टल बनायेंगे। हम एक ऐसा आईटी पोर्टल बनायेंगे जिसमें लगातार हर महीने या हर दूसरे हफ्ते में कोई अंतरराष्ट्रीय फिगर या राष्ट्रीय फिगर जो उनको मोटिवेट कर सके, हो सकता है कोई बिजनसमैन हो, हो सकता है कोई आईएएस हो, हो सकता है कोई दूसरा खिलाड़ी हो, हो सकता है कोई कम्युनिटी सर्विस करने वाला समाज सेवी हो, वह उनसे बात करे ताकि वह सब इंटरनेट के माध्यम से दूसरे लोगों का अनुभव जान सकें और उनका जो विजन है, वह बड़ा हो सके। यूथ दिवस नहीं होगा, यूथ साल होगा। लगातार इसको हम चलाते रहेंगे।

Spp/Rtm/23.07.2024/21.20/4p

न्यूट्रीशन, खाने की जो उनको एकेडमी में खाना मिलता है, तकरीबन सात हजार रुपये खर्च होते हैं पर खिलाड़ी। मेरा यह मानना है, मैंने अपने अधिकारियों से भी बोला है। हम अभी एल-वन करते हैं, टेण्डर करते हैं। वह जब टेण्डर होता है तो जो डाइट का जो पैसा है, उस पैसे में से ही कम हो जाता है। वह अपने मसालची का पैसा निकाल लेता है, अपने वेटर का, अपने कूक का, सबका पैसा निकाल लेता है उसमें से। हम अभी कोशिश कर रहे हैं और एक पायलट प्रोजेक्ट चलायेंगे। हमारे पास 22 एकेडमियां हैं। हम कोशिश यह करेंगे कि कम से कम सात-आठ-दस या जितनी भी हो सके, इंडस्ट्री विभाग भी मेरे पास ही है, हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री को इन्सेंटिव दें कि इंडस्ट्री हमसे पैरा पूरा ले उनके न्यूट्रीशन का, उसके बाद का जो ऊपर का खर्चा है, वह अपने CSR से लगा दे, ज्यादा खर्चा भी नहीं आयेगा, लेकिन उनको न्यूट्रीशन शानदार मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रफीक साहब ने बात कही कि केन्द्र से क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो रफीक साहब, केन्द्र चाहता है कि हम 'खेलो इंडिया' तुरंत आयोजित करें। हमने उनको कहा है कि हमको एक साल चाहिये। इसलिये कि हमको इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और जब इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो यही मिलेगा, आप जो इशारा कर रहे हैं, हमारे को पैसा मिलेगा तो केन्द्र हमारे साथ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि 32

जिलों के अन्दर खेलो इंडिया सेंटर स्थापित हो गये हैं, जो केन्द्र करता है। 'खेलो इंडिया' सेंटर स्थापित हैं। 17 नये जिलों के अन्दर सितम्बर, 2024 तक 'खेलो इंडिया' सेंटर स्थापित हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं को आगे बढ़ने का अगर अवसर देना है तो अभी जो रफीक साहब इशारा कर रहे थे, उसकी जरूरत है और उसके लिये इंडस्ट्रीज हैं। हमें कॉमर्स और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है और यह दोनों विषय आज बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मेरे एक साथी मुझे कह रहे थे कि यह तो बड़ी अजीब सा विषय हो गया युवाओं का और इंडस्ट्री का। मुझे तो लगता है यह एक ऐसा विषय है जिसमें आप और हम एकमत होने चाहिये। अभी हमें लक्ष्य अगले कई सालों का रखना चाहिये। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ओलम्पिक की तैयारी कर रहे हैं तो हम 2036 ओलम्पिक्स की मैन तैयारी कर रहे हैं, क्यों? आपको याद होगा चाइना ने 20 साल तक ओलम्पिक्स में हिस्सा ही नहीं लिया था। उसने 20 साल तैयारी की। 20 साल का मतलब उन्होंने 5 से 10 साल तक के बच्चों को पकड़ा और 20 साल तक उनको ट्रेनिंग देते रहे। हम 2028 के ओलम्पिक्स में भी जायेंगे, 2024 के ओलम्पिक्स में तो गये हैं, हम जायेंगे सबमें। लेकिन हम अभी एक टेलेंट हंट प्रोग्राम अभी करना चाहते हैं जिसमें 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, पूरे राजस्थान के अन्दर हम उनको एक प्रक्रिया के अन्दर चुनना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 7 फीट के कोई माता-पिता हैं, उनके बच्चों को ढूंढ लेता हूं 100-50 और उनको अभी से बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने लगते हैं तो 100 प्रतिशत वह 10-15 साल के अन्दर अमेरिका की टीम के अन्दर क्या, भारत की टीम के अन्दर खेल रहे होंगे। इतना शानदार उनका स्टेण्डर्ड हो जायेगा। हमें अभी से 10-12 साल के बच्चों का चयन करना है और उस टेलेंट हंट के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद में उनको हम एकेडमीज में भेजेंगे और वह आप और हम मिलकर, एकमत होकर चलायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं जिसमें आपको और हमारे को एकमत होना चाहिये। आप जयपुर में कई सालों से यहां रह रहे हैं, मुझे याद है मैं जब आठवीं क्लास में था तो मैं जूनियर चैम्पियनशिप के लिये किसी दूसरे शहर से जयपुर आया था। SMS स्टेडियम वैसा का वैसा है, जैसा तब था। इतना रियल एस्टेट प्रोपर्टी, हम कोशिश करते हैं, वह खिलाड़ी तो साधारण परिवार का है, वह खिलाड़ी थोड़े ही खेलने का पैसा दे सकता है। हमें ऐसा वातावरण बनाना है कि रेवेन्यू जनरेशन अलग हो और वहां से जो पैसा आये वह खिलाड़ी के लिये जाये। आगे चलकर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमें SMS स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेण्डर्ड, मतलब सिंगापुर की कम्पनी आये, यू.के. की कम्पनी आये, भारत की बेस्ट कम्पनीज आये और वह आकर बताये कि यह डिजाइन होना चाहिये जहां पर पब्लिक भी आ सकती हो, अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आ सकते हों, सीखने वाले बच्चे भी आ सकते हों, लेकिन पैसा उन बच्चों से नहीं लेकर पैसा जनरेशन अलग हो। हमें इस तरह से आगे बढ़ना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो अभी सरकार जब सत्ता में आयी तो राजस्थान की जो आर्थिक व्यवस्था है, वह 15 लाख करोड़, हमारा संकल्प है कि हम पांच साल के अन्दर इसको 30 लाख करोड़ बनायेंगे। Ease of business and low cost of business, हमारा फण्डा बिलकुल क्लियर है। हमारे मंत्रालय ने भी बिलकुल तय कर लिया है कि हमारी मानसिकता यह नहीं हो सकती कि यह पैसा बना रहा है, वह पैसा बना रहा है, हम तो डिपार्टमेंट ही हैं जहां पर हम लोगों को अवसर दें करोड़पति, अरबपति बनने का, जिससे एक माहौल ऐसा बने जहां पर एम्प्लायमेंट जनरेशन हो और पूरे राजस्थान के अन्दर एक पाजीटिव माहौल हो। लैण्ड की कोस्ट कम करनी पड़ेगी, बिजली की कोस्ट कम करनी पड़ेगी और बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। पानी लाना पड़ेगा। अभी जैसे आपने फरमाया कि केन्द्र सरकार ने क्या किया? इतना बड़ा काम किया है। लाखों-करोड़ों लीटर चाहिये होता है इंडस्ट्रीज को चलाने के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह सारा पानी ERCP के माध्यम से सभी जिलों के अन्दर पहुंचेगा। Ease of business and low cost of business.

इसके साथ-साथ हमने पिछले 5-6 महीने के अन्दर ही 3-4 बड़े निर्णय लिये। सबसे पहला, रीको के एक किलोमीटर के आसपास की जमीन होती थी, वहां पर रीको से जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, हमने उसे हटा दिया। अभी रीको से कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेना आसपास की जमीन के लिए। पहले कम्पल्सरी लैंड एक्विजिशन होता था। हम उसे बदलकर खातेदारों की सहमति से लैंड एग्रीगेशन पॉलिसी अब हम लेकर आएंगे। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स की नीति बनायी है। सप्लाई चेन का बहुत महत्त्व होता है और सप्लाई चेन राजस्थान में बड़ी मात्रा में है। एक तिहाई हिस्सा दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का राजस्थान से होकर निकलता है।

राजस्थान के अन्दर भारत का दूसरा बड़ा रेल तंत्र है। सड़कों का तीसरा सबसे बड़ा तंत्र राजस्थान में है। इसका हमें फायदा उठाना है। इसकी सप्लाई चेन हमें बनानी है। उसके लिए भी हमें पॉलिसी बनानी है। कुछ देर पहले मेरे कुछ साथियों ने बोला, मैं आऊंगा, एक-एक व्यक्ति के ऊपर आऊंगा, कुछ साथियों ने कहा था, बौहरा साहब यहां नहीं हैं, वे चले गये, उन्होंने कहा था कि फाइनेंस नहीं मिल पा रहा। उसके ऊपर आगे मैं विशेष रूप से टिप्पणी करूंगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आप क्यों भूल गये कि आपकी सरकार थी। आपकी गलती नहीं है, लीडरशिप की गलती है। पिछली कांग्रेस सरकार ने बजट में, जो इतनी महत्त्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इस बजट में घोषणा की कि 176 औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की कि 176 औद्योगिक क्षेत्र बनायेंगे, लेकिन बनाये कितने? केवल 31 औद्योगिक क्षेत्र। उसमें से 1663 भू-खण्ड आवण्टित हुए, लेकिन उनमें से प्रोडक्शन कितनों में शुरू हुआ? मात्र 43, इसीलिए तो दुःख है। यह होता है 2.5 प्रतिशत, जबकि हमने 5 महीने के अन्दर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र में 635 भू-खण्ड आवण्टित कर दिये हैं और हम एक कमिटेड तरीके से काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने रीको के

इंडस्ट्रियल क्षेत्र के डवलपमेंट के लिए 408 करोड़ रुपये खर्च किये। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र का डवलपमेंट बहुत जरूरी होता है, हम आपसे दुगनी राशि खर्च करके डवपलमेंट करेंगे। हमने 270 करोड़ रुपये तो डवपलमेंट पर खर्च कर भी दिये।

रीको का जो पैसा डवलपमेंट के लिए जाना चाहिये था, वह तो पिछली सरकार ने चुनावी घोषणाओं में लगा दिया। रीको एक हजार करोड़ रुपये जा चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं। एक हजार करोड़ रुपये कम नहीं होते, एक हजार करोड़ रुपये चुनाव की लुभावनी योजनाओं के लिए ट्रांसफर हो गये। वह पैसा नहीं आया। चुनाव भी हार गये। वह पैसा भी नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर्ड इंडस्ट्रियल एरिया की बात हुई, यह बहुत महत्त्वपूर्ण पॉइंट है। ट्रांसफर्ड इंडस्ट्रियल एरिया, यहां कुछ भी करना सम्भव नहीं था, सब-डिविजनल हुआ, ये सब करना सम्भव नहीं था। तो सरकार है, सरकार की ताकत है और इसीलिए हम ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड वैलिडेशन एक्ट लेकर आएंगे ताकि इन सारी पुरानी समस्याओं का समाधान हो सके।

MLS/RTM/23.07.2024/21:30/4q

उम्मीद है उसमें आपका हमें पूरा समर्थन रहेगा। पिछले पांच महीनों में दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जोधपुर, पाली, मारवाड़ में हमने 90 किलोमीटर की पाइप लाइन डालने का काम शुरू कर दिया है। 275 करोड़ रुपये से हम वहां पानी का प्रबन्ध कर रहे हैं। 5 करोड़ लीटर पानी वहां प्रतिदिन इंडस्ट्रीज को मिलेगा, तब जाकर इंडस्ट्रीज चलेंगी। यह काम हमने पिछले पांच महीनों में शुरू भी कर दिया।

हमने कुछ संकल्प लिये हैं। हम उन संकल्पों के माध्यम से काम करेंगे। एमएसएमई पॉलिसी मल्टीडायमेंशनल हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, बहुआयामी हो, व्यापक हो, सन्तुलित हो और समावेशी हो। उसमें हमें ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना है। हमें हमारे रीको इंडस्ट्रियल एरियाज में एससी, एसटी, विमेन एंटरप्रिन्योर्स को आगे बढ़ने का अवसर देना है। लैंड कन्वर्जन रूल्स को हमें आसान करना है। हमारी एमएसएमईज को हमें क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन प्रदान करना है। बहुत से ऐसे हमारे साथी थे, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों की बात की, कहीं स्टोन का काम हो रहा है, कहीं पत्तियों का काम हो रहा है, इन सबका डवलपमेंट क्लस्टर डवलपमेंट में होगा। उसके लिए 50 करोड़ क्लस्टर्स के लिए हमने 150 करोड़ रुपये अलग से रखे हैं।

''वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट'' की पॉलिसी पर भी हम काम करेंगे। 50 जिलों में हमने 63 प्रॉडक्ट्स को आइडेंटीफाई किया है। जैम्स और ज्वैलर्स को एक्सपोर्ट हेतु बढ़ावा देने के लिए हम बोर्ड्स भी बनाएंगे। राजस्थान इन्वैस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, यही बात थी जो बौहरा साहब बोल रहे थे कि उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। वह फायदा इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी प्रोसीजरल गाइडलाइंस ही नहीं बनीं। जब गाइडलाइंस ही नहीं बनीं तो उसमें सहायता कैसे कर सकते हैं। अब हम उसकी पूरी गाइडलाइंस बनाएंगे, ज्यादा समय भी नहीं लगाते, 15 अगस्त 2024 को ऑनलाइन पोर्टल हम स्टार्ट कर देंगे ताकि इन्वैस्टमेंट की प्रमोशन

स्कीम उपलब्ध रहे।

हम एक इन्वैस्टमेंट समिट करने वाले हैं। आपने भी की थी। बड़ी पार्टी हुई थी। करीब 50 करोड़ तो लगे ही थे, उसके ऊपर जो लगा, वह पता नहीं। आपकी जो समिट हुई थी, उसमें 12.50 लाख करोड़ के एमओयूज साइन हुए, लेकिन लगे कितने मात्र 2 लाख करोड़ से भी कम, 15 प्रतिशत। अशोक चांदाना जी ने टाइल्स की बात की थी, औरों ने भी बात की थी, हम गैस लेकर आ रहे हैं, टाइल्स के लिए गैस एनर्जी की जरूरत होती है। और भी उस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि जो टाइल्स की मैन्यूफैक्चरिंग राजस्थान में हो सके। उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग के लिए बात की और कहा कि आप इंजीनियरिंग विभाग बनाइये अपने स्पोर्ट्स के अन्दर। महकमा बड़ा करने से काम नहीं होता, लेकिन कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे।

मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम के लिए उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है, वे टीवी पर सुन रहे हों कहीं, मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम पॉलिसी, रफीक साहब भी बोल रहे थे, उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने तो तहसील तक पहुंचा दिया, अब आप ग्राम पंचायत तक पहुंचा दीजिये। मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि अभी तक 6 ही बने हैं। अभी तक 6 ही बने हैं, 5 प्रगति पर हैं। इसका मतलब अभी भी हमें तहसील पर ही काम करना है। बाल मुकुन्दाचार्य जी ने अपने चौगान स्टेडियम के लिए बोला, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं, चौगान स्टेडियम को हम करोड़ों रुपये खर्च करके उसको शानदार तैयार करेंगे।

अमीन कागजी साहब ने कहा, एमएसएमई योजना पहले से थी। पहले से थी तो फिर उसमें काम क्यों नहीं हो पा रहा था? काम इसलिए नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें कमियां थीं। कई सैक्टर्स में कमियां थीं। उन कमियों को हम दूर करेंगे। टैक्सटाइल पार्क के बारे में बात की। टैक्सटाइल पार्क के बारे में बात करने से पहले आपको पता तो कर लेना चाहिये था पूरा। पीएम मित्र योजना के अन्दर भीलवाड़ा को टैक्सटाइल पार्क मिल रहा था, लेकिन उस समय के जो मुख्य मंत्री थे, उन्हें केवल जोधपुर दिखाई देता था। वे उसे जोधपुर लेकर चले गये और जोधपुर में कपड़ा बनता नहीं है तो वहां टैक्निकली वे डिस्क्वॉलिफाई हो गये। ऐसे में न जोधपुर को मिला, न भीलवाड़ा को मिला। हम भीलवाड़ा के अन्दर टैक्सटाइल पार्क लेकर आएंगे, यह आश्वासन देते हैं।

रोहित बौहरा जी ने बोला, एक की तो मैं चर्चा यहां कर चुका हूं, दूसरा उन्होंने कहा कि एसएसओ आईडी जनरेशन विभाग के अधिकारी करते हैं, रीको के अधिकारी करते हैं, इंडस्ट्री के अधिकारी करते हैं, गलत। हर व्यक्ति अपनी एसएसओ आईडी जनरेट कर सकता है और अब अगर वह कम है तो हम मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं, जिससे फेस टू फेस इंटरैक्शन ही खत्म है, सारा काम ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने कहा कि बिजली महंगी है। 5 महीने में ही हमने 1.5 लाख करोड़ के एमओयूज कर लिये पीएसयूज के साथ। हम सोलर पावर को बढ़ाएंगे। और भी दूसरी तरह से पावर लेकर आएंगे। साथ ही, यह भी मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपकी सरकार ने एक कैप लगा रखी

है।

अध्यक्ष महोदय, अगर कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है और कहता है कि आप हमें बिजली नहीं दे पा रहे तो मैं अपनी बिजली खुद प्रड्यूस कर लेता हूं तो पिछली सरकार ने उस पर कैप लगायी हुई थी कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। मुझे यकीन है, उस पर कोई पॉजिटिव स्टैप लिया जायेगा। हम हर तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। स्पीकर महोदय के लिए बोला गया कि आपने उस दिन कहा कि प्लास्टिक यूज नहीं होगा। उनका मतलब था, सिंगल प्लास्टिक यूज नहीं होगा। प्लास्टिक तो हर जगह यूज होता है। रीसाइक्लिंग ऑफ प्लास्टिक, बहुत अच्छा सुझाव है बौहरा साहब का। रीसाइक्लिंग ऑफ प्लास्टिक हम करेंगे।

राजाखेड़ा की उन्होंने बात की। आपकी सरकार में आप नहीं कर पाये, क्योंकि वह अनड्यूलेटिंग ग्राउंड है, ऊबड़-खाबड़ जमीन है, उस पर कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। जब कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जायेगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा, लेकिन फिर भी हम राजाखेड़ा को फिर से दिखवा लेंगे। आप तो इंडस्ट्री लगाने वाले बनिये, लगाने के लिए हम पूरी तरह से समर्थन देंगे। चन्द्रभान जी ने बोला कि 100 रुपये खाने के लिए कम हैं। इसलिए हम 100 रुपये नहीं देते। हम 600 रुपये देते हैं। जो स्टेट लेवल के लिए जाते हैं, उन्हें 600 रुपये देते हैं और जो नेशनल के लिए जाते हैं, उन्हें 1000 रुपये देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे। मेरे साथियों ने बोला कि मैं सबका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक डेटा पूरा रहेगा कि कौन-से सदस्य के क्षेत्र में क्या समस्या है। मैं सभी को कहना चाहूंगा, चाहे खेल विभाग हो, चाहे रीको इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो, हम तो प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं और उसमें कहीं न कहीं आप सबकी भी मदद चाहिये। जैसे स्टेडियम्स के लिए आप सब साथी मुझसे बात करते हैं, मैं सभी को यह कहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में देखिये, कोई वहां माइनिंग का फंड हो, कोई इंडस्ट्री हो, आप कहीं से साधन जोड़िये। मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम, यह एक योजना ही है। यह केन्द्र के नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट फंड से ही प्रेरित योजना है।

वहां पर भी यह है कि जितने पैसे आप डालेंगे, उतने ही पैसे सरकार डालेगी। इसमें अभी सीमा 1 करोड़ की लगायी हुई है। उसके अन्दर भी मैं अपने विभाग से चर्चा करूंगा, मुख्य मंत्री जी से भी चर्चा करूंगा, अगर जरूरत पड़ती है तो हम उस फंड को भी बढ़ा सकते हैं, कैप को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सब जिलों के अन्दर या तहसीलों के अन्दर अगर हम स्टेडियम की व्यवस्था कर सके तो हमारा सौभाग्य होगा। साथ ही साथ, जो सिटी बेज्ड इंडस्ट्रीज हैं, वहां किस तरह के सॉल्यूशंस लाने हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ 1979 के पहले की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर रीको का कोई अधिकार नहीं है, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। एक जगह जब प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, उसके बाद रीको का अधिकार खत्म हो जाता है अगर वह प्रोडक्शन बन्द हो जाये। उस पर भी चर्चा कर रहे हैं।

हम अनेको योजनाएं लेकर आ रहे हैं ताकि राजस्थान में एक पॉजिटिव माहौल बने। मैं चाहूंगा कि आप सबका उसमें योगदान हो, साथ हो। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल तथा मांग संख्या 56 - उद्योग पारित की जाएं।

मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,67,04,09,000 (दो अरब सड़सठ करोड़ चार लाख नौ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 56 - उद्योग का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 56 - उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,63,94,27,000 (छह अरब तिरसठ करोड़ चौरानवे लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

mkd/rtm/23.07.2024/21:40/5a

मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,12,10,34,000 (बत्तीस अरब बारह करोड़ दस लाख चौतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 24 जुलाई 2024 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.41 बजे बुधवार, दिनांक 24 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल विभाग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26 - **युवा मामले एवं खेल विभाग** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं. 159)

1. ब्यावर के पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम के लिए बजट स्वीकृत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम (वि.सं. 175)

2. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू के ग्रामीण क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनवाये जाने तथा तीरन्दाजी को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं. 142)

3. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नया स्टेडियम स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं. 98)

4. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में खिलाड़ियों को मैस भत्ता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं. 10)

5. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मोडल खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान व प्रोत्साहन के लिए खेल अकादमी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. प्रदेश में युवाओं को अधिक सशक्त एवं बलिष्ठ बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जिम के उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के बालक-बालिकाओं को विभिन्न खेलों के प्रति प्रोत्साहन हेतु खेल उपकरण व किट्स उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जिला मुख्यालय सलूम्बर में खेल स्टेडियम की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं. 05)

10. सरदारशहर में खेल स्टेडियम का शीघ्र निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं. 94)

11. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के खेल मैदान में खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)

12. शेरगढ़, बालेसर, सेखाला एवं चामू तहसील एवं समिति मुख्यालय में खेल स्टेडियम स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
13. तहसील एवं समिति मुख्यालय सेखाला में खेल अकादमी स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)

14. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के लसाडिया तहसील मुख्यालय और झल्लारा तहसील में खेल स्टेडियम बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
15. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में खेल स्टेडियम स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
16. प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय व सलूम्बर जिला मुख्यालय पर तीरंदाजी खेल एकेडमिक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)

17. प्रदेश में जिला स्तर पर युवा बोर्ड का गठन करके अध्यक्षों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. जिला मुख्यालय बालोतरा पर यूथ हॉस्टल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
19. प्रदेश के जिला युवा समन्वयक की नियुक्ति एवं समन्वयक द्वारा ग्रामीण युवाओं को सामाजिक कार्यों के लिए समर्थ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को जिला स्तर पर खेलकूद की टीमों के चयन, प्रशिक्षक, कोच प्रभार के चयन की जानकारियां उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
21. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड स्तर पर युवाओं की खेल प्रतिभा को तराशने के लिए खेल स्टेडियम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं. 51)

22. चित्तौड़गढ़ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं. 138)

23. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में नव स्वीकृत खेल स्टेडियम के आधे-अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)

24. विधान सभा क्षेत्र बून्दी में विभिन्न खेलों के प्रोत्साहन के लिए खेल अकादमी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र बून्दी में क्रिकेट/बास्केटबॉल/फुटबाल इत्यादि के खण्ड स्तर पर खेल मैदान के निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
26. युवा मामले एवं खेल विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं. 61)</u>

27. बहरोड़ स्टेडियम में सिंथेटिक टैंक (Synthetic) का निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
28. बहरोड़ में जिला खेल-कूद कार्यालय (DS0) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
29. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कब्बडी और बालीबॉल की अकादमी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
30. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ओपन जिम खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)</u>

31. विधान सभा क्षेत्र आहोर उपखण्ड पर खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित करके विभिन्न इन्डोर ग्राउण्ड तैयार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
32. विधान सभा क्षेत्र आहोर के साकरणा के खेल मैदान का चिन्हिकरण कर चारदीवारी बनाने व स्टेडियम को विकसित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)</u>

33. विधान सभा क्षेत्र भीम के युवाओं को खेल-कूद हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में स्टेडियम का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं. 13)</u>

34. खेलों के विकास एवं ओपन खेलों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
35. प्रदेश में प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालयों पर खेल एकेडमी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)</u>

36. प्रदेश में उच्चस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खेल स्टेडियम एवं खेल अकादमी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं. 158)</u>

37. युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह एवं रूचि बढ़ाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदानों का विकास एवं स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कान्ति प्रसाद (वि.सं. 29)</u>

38. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में बजट भाषण 2023-24 की घोषणा अनुसार खेल स्टेडियम स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं. 141)

39. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उपखण्ड मुख्यालय मेड़ता पर राजकीय खेल अकादमी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
40. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उपखण्ड मुख्यालय मेड़ता में खेल मैदान (स्टेडियम) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)

41. प्रदेश में राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण-पत्र प्राप्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान व नौकरियों में वरियता देने तथा क्रीड़ा परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं. 50)

42. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
43. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्रामीण विद्यालयों में खेलों के विकास हेतु खेल ग्राउण्ड बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री यूनुस खान (वि.सं. 121)

44. नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना के राजकीय खेल स्टेडियम में जिला खेल अधिकारी, कर्मचारियों के पद स्वीकृत कर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
45. राजकीय खेल स्टेडियम डीडवाना में खेलों के संचालन के लिए मल्टीपरपज इण्डोर हॉल, स्विमिंग पूल, हॉकी, हैण्डबॉल, कब्बडी तथा टैनिस ग्राउंड की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
46. राजकीय खेल स्टेडियम डीडवाना में खेलों के संचालन के लिए खेल सामग्री की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
47. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं. 150)

48. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में ग्राम पंचायत कसेरू, बारवा व जाखल में खेल मैदान एवं नवलगढ़ मुख्यालय पर आवासीय स्पोर्टस स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं. 04)

49. अजमेर में अन्तर्राष्ट्रीय बॉस्केटबॉल खिलाड़ियों की पर्याप्त मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए एक नई बॉस्केटबॉल एकेडमी स्थापित कि‍ये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में उल्लेखित ऐथलीट एकेडमी को अजमेर दक्षिण में स्थित चन्द्रवरदायी खेल मैदान में स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
51. अजमेर दक्षिण में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से बने हॉकी एस्ट्रोट्रफ मैदान पर अन्तर्राष्ट्रीय मैच कराये जाने हेतु आवश्यक रख-रखाव कार्य के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट से आवश्यकता अनुरूप राशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
52. प्रदेश में निजी खेल एकेडमियों की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान सम्मिलित करते हुये एक नयी पॉलिसी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)</u>

53. राजसमंद जिला स्तरीय स्टेडियम ग्राम-भाणा में निर्माण कार्यों में विलम्ब एवं समय सीमा में पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
54. राजसमंद जिला स्तरीय स्टेडियम ग्राम-भाणा में 50 मीटर लंबाई के तरणताल निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
55. राजस्थान युवा बोर्ड एवं जिला युवा बोर्डों को पर्याप्त धन राशि उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
56. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर क्रीड़ांगन (स्टेडियम) निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)</u>

57. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास उपखण्ड में खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
58. विधान सभा क्षेत्र बयाना में खेल स्टेडियम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं. 31)</u>

59. भवानी मंडी या डग में बड़ा खेल स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)</u>

60. प्रदेश में आउट ऑफ टर्म पॉलिसी के तहत एक वर्ष से लम्बित पदक विजेताओं को नियुक्ति अविलम्ब दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोरधन (वि.सं. 47)</u>

61. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं के खेलने की अन्य सुविधाएं भी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)

62. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति रानी के ग्राम रानी कलां में खेल स्टेडियम का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
63. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी पंचायत समिति के ग्राम खिवाड़ा में खेल स्टेडियम का निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
64. मारवाड़ जंक्शन नगरपालिका क्षेत्र में खेल मैदान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं. 19)

65. प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न स्थानों पर खेल कोच की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
66. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में चौहटन मुख्यालय पर निर्मित खेल स्टेडियम का विस्तार कर सौन्दर्यकरण करने तथा सेड़वा उपखण्ड मुख्यालय पर आधुनिक सुविधायुक्त नवीन स्टेडियम निर्मित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
67. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
68. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन खेल मैदान व खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (वि.सं. 155)

69. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के खाजूवाला स्टेडियम में विकास कार्य एवं खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (वि.सं. 123)

70. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर कच्ची बस्ती, वन विहार, घाटगेट आदि स्थानों पर खेल मैदान नहीं होने के कारण उपयुक्त जगह खेल मैदान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं. 57)

71. विधान सभा क्षेत्र आसींद में आसींद, बदनोर तथा गुलाबपुरा में खेलों को बढ़ावा देने हेतु इण्डोर स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामबिलास (वि.सं. 135)

72. विधान सभा क्षेत्र लालसोट के रामगढ़ पचवारा में खेलों को बढ़ावा देने हेतु नवीन खेल स्टेडियम स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुलदीप (वि.सं. 33)

73. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में ओपन जिम व स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं. 22)</u>

74. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में खेल मैदान के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
75. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में खेल एकेडमी का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
76. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में ग्राम पंचायत मिरजा व दांतल में खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
77. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में करेडा व सुवाना में खेल स्टेडियम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
78. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में खिलाड़ियों के राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर चयन हेतु प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)</u>

79. प्रदेश में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर युवा पुरस्कार विजेताओं को किसी प्रकार की सहायता एवं सुविधा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं. 11)</u>

80. बालोतरा जिला मुख्यालय पर खेल परिषद एवं समस्त प्रकार के खेलों हेतु क्रीड़ा परिषद खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
81. बालोतरा जिला मुख्यालय पर युवा मामले एवं खेल विभाग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
82. विधान सभा क्षेत्र पदपचरा के ग्रामीण इलाके में समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खेल स्टेडियम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
83. बालोतरा में स्थित महात्मा ज्योति राव फूले स्टेडियम का आधुनिकीकरण कर इसको पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
84. प्रदेश में खेले जा रहे समस्त खेलों को क्रीड़ा परिषद अथवा खेल परिषद द्वारा मान्यता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं. 197)</u>

85. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में खेल स्टेडियम एवं खेल मैदान विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जुबेर खान (वि.सं. 65)</u>

86. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम साहड़ोली, बेरेबास, साधन का बास (नंगला बन्जीटका) एवं रघुनाथगढ़ में मिनी खेल स्टेडियमों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं. 112)

87. बजट घोषणा 2023 में घोषित सुजानगढ़ स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

88. सुजानगढ़ के एन.के.लोहिया स्टेडियम व नया बास स्टेडियम में मरम्मत कार्य नहीं होने से हो रही दुर्दशा के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं. 108)

89. ओसियां क्षेत्र में ग्रामीण पृष्ठभूमि की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा बढावा देने के लिए नवीन इंडोर स्टेडियम खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं. 36)

90. विधान सभा क्षेत्र बगरू की नगरपालिका वाटिका स्थित खेल स्टेडियम को विकसित कर अत्याधुनिक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र बगरू की ग्राम पंचायत अजयराजपुरा एवं मुहाना में ऑपन जिम एवं खेल मैदान विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (वि.सं. 99)

92. विधान सभा क्षेत्र वैर के भुसावर में खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)

93. प्रदेश में विभिन्न खेलों से संबंधित चल रही खेल एकेडमियों को आवंटित बजट की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र नोहर में बाल कृष्ण बिहारी स्टेडियम में फुटबाल एकेडमी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र नोहर में तहसील पल्लू, उप तहसील खुइयां, फेफाना तथा विभिन्न गांवों में स्टेडियम/खेल मैदान का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. प्रदेश में खेल कोचिंग सेंटर्स में चयनित खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं. 39)

97. नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से खेलों को आयोजन करवाने तथा ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. डूंगरपुर जिले में सभी खेलों के कोच नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. डूंगरपुर जिले में एथेलेटिक्स खेल अकादमी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर खेलों को बढावा देने हेतु मिनी स्टेडियम बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की सभी पंचायत मुख्यालयों पर खेल मैदान एवं खेल केंद्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं. 176)

102. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर, बकानी, पनवाड़ एवं रटलाई में खेल स्टेडियम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र खानपुर सहित सम्पूर्ण झालावाड़ जिले की ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अन्तर्राज्यीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (वि.सं. 171)

104. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खेल स्टेडियम का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खेल महाविद्यालय (स्पोर्टस कॉलेज) की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं. 145)

106. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के प्रत्येक गांव के खेल मैदान को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

107. जिला मुख्यालय शाहपुरा पर विवेकानंद युवा होस्टल की स्थापना की घोषणा की क्रियान्विति
किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओपन जिम की स्थापना के संबंध में
चर्चा के लिए।

109. जिला मुख्यालय शाहपुरा में एक इंडोर खेल स्टेडियम के निर्माण के संबंध मे चर्चा।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं. 62)

110. विधान सभा क्षेत्र मकराना के खिलेरी नाड़ा मकराना में निर्मित खेल स्टेडियम एवं मोरेड़ तथा गेलासर में खेल स्टेडियम के लिए बजट स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)

111. विधान सभा क्षेत्र बयाना में इण्डोर खेल स्टेडियम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं. 03)

112. उम्मेद राजकीय स्टेडियम, जोधपुर में खेल विस्तार, छात्रावास निर्माण और इण्डोर कोर्ट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. राजकीय पॉलिटेनिक कॉलेज जोधपुर में एक नवीन स्पोर्टस कॉम्पलेक्स निर्माण हेतु

विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर स्थित राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर प्रगतिरत सभी निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की उच्च स्तरीय ऑडिट एवं जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. पश्चिमी राजस्थान के सम्भागीय मुख्यालय जोधपुर में इण्डोर स्टेडियम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम को BCCI और अन्य एजेंसियों से मुक्त करवा कर स्थानीय खिलाड़ियों के खेल-प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समरजीत सिंह (वि.सं. 174)

117. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के ग्राम पंचायत दासपां में निर्मित स्टेडियम में खेल-कूद सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के शिवराज स्टेडियम का रख-रखाव नगरपालिका के अधीन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुरवीर सिंह (वि.सं. 42)

119. प्रदेश में राष्ट्रीय एवं राज्य पदक विजेताओं व खिलाड़ियों के लिए न्यूट्रिशन डाइट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. प्रदेश में राष्ट्रीय एवं राज्य खेल पदक विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पुनः शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. प्रदेश में खेल के दौरान खिलाड़ियों की चोट के इलाज हेतु सरकारी सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)

122. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में खेलो इंडिया योजनान्तर्गत बारां रोड (बोरखेड़ा) में नवीन स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में युवाओं की कोचिंग एवं कैरियर काउंसलिंग हेतु विवेकानन्द होस्टल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय को समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम 2015 में शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में बालिकाओं को बालिका फुटबाल अकादमी कोटा द्वारा विद्यालय स्तर पर कैम्प आयोजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)

126. विधान सभा क्षेत्र आहोर में तहसील स्तर पर एक खेल मैदान को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र आहोर में युवाओं के खेलने के लिए एक जिला स्तरीय इनडोर स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती इन्द्रा (वि.सं. 20)</u>

128. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में खेल स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
129. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में युवा खिलाड़ियों को राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर चयन के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं. 115)</u>

130. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्रामीण युवा खिलाड़ियों को राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर चयन के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
131. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मेजर ध्यानचन्द खेल स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
132. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं. 142)</u>

133. बारां जिले में खेलों के प्रति रूझान बढ़ाने के लिये खेल अकादमी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
134. राज्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंतर्गत पंचायतों में खेल मैदानों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
135. प्रदेश में बजट सत्र 2023-24 में घोषित युवा विकास एवं कल्याण बोर्ड के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
136. मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं. 23)</u>

137. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में खेल छात्रावास खोलने एवं स्टेडियम के निर्माण स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
138. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के दोवड़ा, आसपुर व साबला तीनों ब्लॉक स्तर पर खेल मैदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
139. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं. 153)</u>

140. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गंधेली में डंडोर स्टेडियम बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबाल, हैंडबॉल, खो-खो, कबड्डी व फुटबॉल के मैदान आदि में खेल सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गांधी स्टेडियम पीलीबंगा में इंडोर स्टेडियम जिसमें 200 मीटर सिंडर एथेलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबाल, हैंडबॉल, खो-खो, कबड्डी व फुटबॉल के मैदान एवं क्रिकेट खेल मैदान में फ्लड लाईट आदि खेल सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा) (वि.सं. 154)

142. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के बिजयनगर में खेल स्टेडियम बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के भिनाय में खेल स्टेडियम बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन देवासी (वि.सं. 122)

144. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा मुख्यालय पर पूर्व बजट घोषणा में स्वीकृत खेल मैदान के संबंध में चर्चा के लिये।

145. रानीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर खेल उपकेन्द्र स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. प्रदेश में खेल एकेडमियों के लिए विधायक कोटे से अनुशंसित बजट आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु जिला लेवल पर सम्मानित करने व हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

148. माउण्ड आबू (सिरोही) स्थित पोलो ग्राउण्ड के नवीनीकरण का कार्य शीघ्र शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

149. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खेल स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. भरतपुर संभागीय मुख्यालय पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

151. भरतपुर शहर में स्पोर्टस कॉम्पलेक्स की स्थापना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. भरतपुर मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी खेल स्कूल का निर्माण शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं. 176)

153. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी ब्लॉक, रटलाई ब्लाक, पनवाड ब्लॉक व खानपुर ब्लॉक में खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने एवं खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभ क्षेत्र खानपुर की समस्त ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं. 53)

155. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गांव तालाब एवं मोरपा में खेल मैदान की बाऊंड्री बनवाने व गांव हनोतिया के खेल मैदान की बाऊंड्री पूर्ण बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के खातोली, ईटावा व बडौद में खेल स्टेडियम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के गांवो में खेल मैदान स्वीकृत (आवंटित) करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल (वि.सं. 83)

158. प्रदेश में वन डिस्ट्रीक्ट व स्पोर्ट स्कीम के तहत नवगठित नीमकाथाना जिले में खेल अकादमी की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ऑपन जिम और खेल मैदान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम जमालपुर में सिन्थेटिक ट्रैक का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विकास चौधरी (वि.सं. 148)

161. खेल विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम एवं शहरी वार्ड में ओपन जिम बनाने व खेल मैदानों को विकसित कर पौधारोपण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

162. किशनगढ़ शहर (इन्द्रानगर) में खेल स्टेडियम का निर्माण कर मल्टी स्पोर्ट्स काम्पलैक्स बनाने व खेल मैदानों को ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार कर रनिंग ट्रैक, कबड्डी, क्रिकेट एवं वॉलीबाल आदि के मैदान तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं. 102)

163. जयपुर शहर के चौगान स्टेडियम में खेल सुविधाओं का विकास करने पर चर्चा के लिये।

164. जयपुर शहर के चौगान स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षकों के पद सृजित करने तथा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. जयपुर शहर के चौगान स्टेडियम का जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव करने के लिए बजट की आवश्यकता पर चर्च के लिये।

श्री छोटूसिंह (वि.सं. 55)

166. जैसलमेर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंडोर स्टेडियम बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
167. जैसलमेर जिले के रामगढ़ मुख्यालय झिझनियाली, न्याजलार एवं फतेगढ़ उपखण्ड मुख्यालय में खिलाड़ियों के खेलने हेतु बास्केट बॉल कोर्ट व कबड्डी मैदान बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।
168. जैसलमेर जिले के श्री मोहनगढ़ ब्लॉक मुख्यालय पर सिंथेटिक बॉस्केटबॉल कोर्ट एवं कबड्डी मैदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं. 66)</u>

169. बीकानेर में खेल विश्वविद्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।
170. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में इण्डोर स्टेडियम व खेल कॉम्पलेक्स बनाने पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (वि.सं. 185)</u>

171. प्रदेश के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति व प्रोत्साहन राशि देने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं. 72)</u>

172. प्रदेश में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए गांवों में खेलों को प्रोत्साहन देने पर विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
173. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) राजियासर, जैतसर, बीरमाना, गुडली व दाबा में स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा के लिये।
174. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) में राजीव गांधी स्टेडियम के रख-रखाव, नव निर्माण एवं सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा के लिये।
175. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की सभी पंचायत मुख्यालयों पर ओपन जिम खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भीम राज भाटी (वि.सं. 107)</u>

176. विधान सभा क्षेत्र पाली में पब्लिक पार्कों में ओपन जिम एवं बालकों के लिए स्वीमिंग पूल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।
177. विधान सभा क्षेत्र पाली के रोहट में स्टेडियम एवं पब्लिक पार्क में बच्चों के लिये तरणताल बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं. 111)</u>

178. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) में शाहपुरा के पार्कों में ओपन जिम खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
179. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में तरणताल बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के मनोहरपुर में इंडोर स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
181. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सिंथेटिक ट्रेक व खेल मैदान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
182. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के ग्राम पंचायत खेजरोली में छ:खम्भा मैदान को स्पोर्टस कॉम्पलैक्स/एकेडमी बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ललित यादव (वि.सं. 143)

183. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सिंथेटिक ट्रैक व खेल मैदान बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।
184. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के बिजवाड़ में इंडोर स्टेडियम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं. 126)

185. विधान सभा क्षेत्र शिव में 400 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक, बॉस्केटबॉल कोर्ट, इण्डोर बेडमिंटन हॉल, वॉलीबॉल ग्राउण्ड-2 एवं कबड्डी ग्राउण्ड तैयार करवाने तथा प्रशिक्षक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।
186. स्पोर्ट्स काउंसिल में प्रशिक्षकों के 66 पदों को बढ़ाकर 2100 करने के संबंध में चर्चा के लिये।
187. राजस्थान में खेल छात्रावासों, भवनों तथा अकादमियों का नामकरण राजस्थान के ही खिलाड़ियों के नाम पर करने के संबंध में चर्चा के लिये।
188. प्रदेश में शाला क्रीड़ा संगम, शार्दुल स्पोर्टस तथा आरवाईसीसी केन्द्रों पर एनआईएस डिप्लोमाधारियों को लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं. 116)

189. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में खेल मैदानों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
190. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में खेल स्टेडियम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष मील (वि.सं. 179)

191. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में खेल स्टेडियम स्वीकृत करने तथा ग्राम पंचायत खटून्दरा व लाखनी में खेल मैदान स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुकेश भाकर (वि.सं. 118)

192. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में नवनिर्मित स्टेडियम में खेल कोच लगाने एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री नौक्षम (वि.सं. 86)

193. विधान सभा क्षेत्र कामां में खेल स्टेडियम खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं. 01)

194. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के तहसील मुख्यालय बज्जू में आधुनिक खेल मैदान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के तहसील मुख्यालय कोलायत में आधुनिक खेल मैदान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ताराचन्द (वि.सं. 73)

196. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में खेल मैदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)

197. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम पंचायत समिति मुख्यालय पर प्रचलित atleast one outdoor game की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 56 - उद्योग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-56 मुख्य शीर्षक **उद्योग विभाग** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं. 159)

1. ब्यावर क्षेत्र के रीको एरिया में टूटी हुई सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित मीना (वि.सं. 142)

2. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के गवाड़ी मझारी में रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया को आवश्यक बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं. 10)

3. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में आंवल पत्तों की उपज व आंवला उत्पादन से बनने वाले आचार, रस आदि लघु उद्योगों के लिये प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, जयसमन्द, सलूम्बर, गिंगला झल्लारा एवं सेमारी में रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खनिजों से संचालित उद्योगों के विकास व वन उपज से प्राप्त कच्चे माल से औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं. 94)

6. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)

7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर सता कस्बे में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. प्रदेश में युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु बैंकों के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की नगर पालिका बालेसर सता मुख्यालय पर स्टोन मण्डी विकसित करने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. प्रदेश में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में चयनित युवाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)

11. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उद्यम स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)

12. विगत पांच वर्ष में रीको एवं उद्योग विभाग द्वारा नवस्थापित उद्योगों के लिए जारी की गई अनुदान राशि की समीक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
13. सिवाना में नवीन रीको इकाई की भूमि के आवंटन के संबंध में चर्चा के लिये।
14. जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर-बालोतरा द्वारा उद्यमियों के लिए संचालित योजनाओं को आमजन तक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बिना भूमि से संपरिवर्तन के संचालित उद्योगों के लिए नीति निर्धारण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
16. प्रदेश में मिट्टी बर्तन, लकड़ी औजार, लोहा औजार, चमड़ा निर्मित वस्तुएं, सोना-चांदी गहने आदि कार्यों को गृह उद्योग, करघा उद्योग की श्रेणी में लिये जाने तथा राजकीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं. 51)

17. चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के ग्रेनाईट उद्यमियों के लिए ब्याज अनुदान योजना पुनः शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं. 98)

19. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में गिर्वा क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)

20. प्रदेश के रीको विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
21. प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु स्टार्ट-अप धारक को अधिक सहयोग व सरलीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।
22. प्रदेश में एम.एस.एम.ई. उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सस्ते ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
23. प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु आमजन को प्रोत्साहन/नवाचार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं. 61)

24. प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिलाने हेतु नीति निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
25. प्रदेश में उद्योगों से सी.एस.आर. से मिलने वाले फण्ड का उपयोग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)

26. विधान सभा क्षेत्र आहोर में एम.एस.एम.ई. के लिए योजना स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र आहोर में रीको की इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)

28. रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया भीम बगड़ में तत्काल पयेयजल एवं अन्य संबंधित व्यवस्थाओं हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायतों में हस्तकर्घा व मिट्टी बर्तन कुटीर उद्योगों को उन्नयन एवं प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (वि.सं. 139)

30. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में नवीन रीको इकाई की स्थापना व प्रदेश में रीको एरियाज में साफ-सफाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगेलाल मीना (वि.सं. 117)

31. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की तहसील रैणी के धौराला में रीको द्वारा चयनित भूमि को विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं. 13)

32. प्रदेश में उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए आसान किस्तों पर ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन कागजी (वि.सं. 9)

33. प्रदेश में प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालयों पर रीको एरिया बनाकर उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)

34. प्रदेश में रीको क्षेत्रों को विकसित करने तथा लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं. 158)

35. प्रदेश के वागड़ क्षेत्र में रीको इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं. 96)

36. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में औद्यागिक विकास को गति प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय के आस-पास नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर स्थित रीको के उप-इकाई कार्यालय को इकाई कार्यालय में परिवर्तित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर स्थित औद्यागिक क्षेत्रों के लिए उचित पहुंच मार्ग सुनिश्चित करने के लिए चामुण्डा चौराहे से सिणधरी रोड़ के समीप रिंग रोड़ तक लगभग 04 किमी. की लम्बाई एवं 10.00 मीटर चौड़ाई की सड़क का निर्माण करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)

39. प्रदेश में रीको इकाइयों का विकास एवं उद्योगों की स्थापना हेतु सरलीकरण किये जाने आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (वि.सं. 50)

40. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में लघु उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में रीको इकाई स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यूनुस खान (वि.सं. 121)

42. नव गठित जिला मुख्यालय डीडवाना में जिला उद्योग कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. नव गठित जिला मुख्यालय डीडवाना में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित लवण इकाई को राजकीय उपक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित लवण इकाइयों को विकसित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं. 150)

46. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में प्रस्तावित दुर्जनपुरा-नवलगढ़ एवं डूंडलोद-मुकुन्दगढ़ रीको क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं. 04)

47. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के औद्योगिक संस्थान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, कायड़ द्वारा सी.एस.आर. फण्ड का निर्धारित 2 प्रतिशत सामाजिक सरोकारों पर व्यय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. अजमेर-ब्यावर रोड़ पर रीको को आवंटित भूमि पर उद्योग विकसित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. अजमेर की माखुपुरा, एच.एम.टी., पालरा एवं गेगल औद्योगिक इकाइयों में सोलर विद्युत प्लांट लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कोई ठोस नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. अजमेर जिले में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध केटसपार को गुजरात जाने से रोकने तथा सैरमिक टाईल्स उद्योग से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु नई नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश में नये स्थापित उद्योगों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों को निश्चित प्रतिशत में नियोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)

52. प्रदेश के मार्बल उद्योगों में मन्दी हेतु विभागीय विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के उद्योगों के लिए पाईपलाईन द्वारा गैस आपूर्ति हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. राजसमन्द के ग्राम कुरज औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाओं का विकास नहीं होने एवं वहां औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने के विभाग की विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. प्रदेश में सेन्टर फॉर डवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (सीडोस) द्वारा लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं तकनीकी सहायता देने, मार्बल खण्डों के उपयोग एवं पत्थर उद्योग में नवीन तकनीकी में किये गये कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

56. प्रदेश में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) प्राधिकरण की गतिविधियों एवं उपलब्धियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (वि.सं. 60)

57. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बिजोली में रीको द्वारा विकास कार्य नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)

58. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास उपखण्ड में रीको की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. भरतपुर जिले को ताज त्रेपेजियम जोन एवं एन.सी.आर. से हटाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (वि.सं. 31)

60. विधान सभा क्षेत्र डग में नवीन रीको इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं. 19)

61. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में रीको (उद्योग) की स्थापना कर स्थायी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. बाड़मेर जिले में संचालित निजी कम्पनियों एवं औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को योग्यतानुसार रोजगार प्रदान करने एवं कौशल प्रशिक्षण के लिए नवीन नीति बनाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के बाखासर रण-क्षेत्र में नमक उद्योग को स्थापित किये जाने हेतु नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोरधन (वि.सं. 47)</u>

64. प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)</u>

65. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के न्यू मारवाड़ जंक्शन फ्रेट-कॉरीडोर-स्टेशन के पास औद्योगिक एरिया स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (वि.सं. 155)</u>

66. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के सत्तासर में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं. 123)</u>

67. जयपुर के ट्रेडिशनल उद्योगों को प्रोटेक्ट करने, नये इण्डस्ट्रियल एरिया स्थापित करने व उद्योगों हेतु रियायती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रामबिलास (वि.सं. 135)</u>

68. विधान सभा क्षेत्र लालसोट के लालसोट कस्बे में नवीन रीको वुड पार्क (हैंडीक्राफ्ट) स्वीकृत कर, कोथून ऱोड़, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज के पास स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री कुलदीप (वि.सं. 33)</u>

69. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं. 22)</u>

70. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में संचालित उद्योगों के उन्नयन के संबंध में चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में उद्योगों से प्राप्त सी.एस.आर. फण्ड से ग्रामों के विकास संबंधी कार्य करवाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संजय कुमार (वि.सं. 169)</u>

72. धौलपुर जिले में पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं. 11)

73. रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स, 1979 में IT & ITE's संबंधी संशोधन कर रीको क्षेत्र में ऑनलाईन परीक्षा का केन्द्र या अन्य आई.टी. अथवा कम्प्यूटर संबंधित समस्त प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. प्रदेश में प्रवासी राजस्थानियों को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में सोलर सिस्टम लगाये जाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र हेतु एच.पी.सी.एल. रिफाइनरी से निकलने वाले पेट-कॉक के उपयोग की अनुमति दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. बालोतरा शहर की औद्योगिक इकाइयों में कलस्टर के रूप में कपड़ा बुनाई के लिए पावरलूम क्षेत्र और ओटोलूम क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं. 112)

78. सुजानगढ़ शहर में नया रीको एरिया स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (वि.सं. 65)

79. अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्र एम.आई.ए. के यातायात का दबाव कम करने हेतु एम.आई.ए. से भरतपुर हाईवे (बिलाई वाला) तक 5 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. जिला अलवर में प्रस्तावित नौगावां एवं बगड़ राजपूत में रीको द्वारा उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)

81. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में लाइम/सीमेन्ट स्टोन की प्रचुरता के कारण रीको इकाई की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के मसाला उद्योग के प्रसंस्करण हेतु औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने व रीको तथा अन्य स्रोतों से ऋण दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के कापरड़ा स्थित 'सेज' क्षेत्र में किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (वि.सं. 99)

84. प्रदेश में भुसावर के अचार एवं मुरब्बा उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं. 145)</u>

85. जिला शाहपुरा में नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

86. जिला शाहपुरा में उद्योग केन्द्र की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के सभी निजी औद्योगिक उपक्रमों में योग्य स्थानीय युवकों को प्राथमिकता से रोजगार दिलाये जाने की अनिवार्यता किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं. 62)</u>

88. मकराना (मार्बल मण्डी) में औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)</u>

89. बयाना में सरसों तेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिग्रहण कर व्यापारियों को सुविधाएं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. बयाना में रीको औद्योगिक क्षेत्र के अपशिष्ट को डालने के लिए डम्पिंग यार्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गुरवीर सिंह (वि.सं. 42)</u>

91. श्रीगंगानगर में दलहन एवं तिलहन से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु 'एस.ई.जैड.' घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. सादुलशहर के बनवाला एरिया में कन्टेनर लोडिंग-अनलोडिंग हेतु यार्ड स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. श्रीगंगानगर में इथेनॉल उत्पादन कारखाने को स्थापित करने के लिए विशेष छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)</u>

94. रीको औद्योगिक क्षेत्र नोहर में औद्योगिक इकाइयों के बेहतर संचालन एवं उद्यमियों की समस्याओं के निवारण हेतु भूखण्ड संख्या एच1-10(जी) से भूखण्ड संख्या एच-6 तक की वर्तमान 12 मीटर सड़क की चौड़ाई को बढ़ाकर 15 मीटर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. प्रदेश में गत 2 वर्षों में रीको विभाग की सक्षम समितियों द्वारा भूखण्डों के निलामी से पूर्व पूर्ण समीक्षा कर न्यूनतम नीलामी दर निर्धारण करने के बावजूद न्यूनतम नीलामी दर से अधिक राशि के एकल प्रस्तावों (सिंगल बिड्स) को उद्यमियों के हितों और औद्योगिक विकास के विपरीत एकल दर प्रस्तावों के निरस्तीकरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. प्रदेश में रीको औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में औद्योगिक आवश्यकताओं एवं औद्योगिक विकास हेतु स्थापित धर्म-कांटों को रीको विभाग द्वारा नियमितीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
97. प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश में स्थित विभिन्न रीको इकाई कार्यालयों व जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
98. हनुमानगढ़ जिले की भौगोलिक स्थिति के मध्येनजर व जिले के उद्यमियों के हितार्थ एवं औद्योगिक विकास के लिए रीको उप-इकाई कार्यालय हनुमानगढ़ को इकाई कार्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)</u>

99. विधान सभा क्षेत्र आहोर में एन.एच.-325 पर रीको एरिया खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं. 142)</u>

100. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नवीन रीको क्षेत्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
101. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
102. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
103. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के गुवाड़ी रीको औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं. 153)</u>

104. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर, उन उद्योगों में क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा) (वि.सं. 154)</u>

105. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के बिजयनगर रीको में अवैध अतिक्रमण हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
106. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के भिनाय में रीको स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रतन देवासी (वि.सं. 122)</u>

107. जिला जालोर-सांचौर-सिरोही के प्रवासियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं. 178)

108. भरतपुर में शहद (हनी) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें देने हेतु विभाग द्वारा कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. भरतपुर जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. भरतपुर को शहद एवं सरसों की दृष्टि से विशेष उद्योग का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. भरतपुर के बृज एवं नये औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों, नालियों एवं बिजली की निरन्तर आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. भरतपुर जिला मुख्यालय को आई.टी. हब के रूप में विकसित करने के लिये आई.टी. सेज की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं. 176)

113. झालावाड़ जिले के कोटा स्टोन (लाईम स्टोन) के खनन क्षेत्रों, आरोलिया रूंझी, भिलवाड़ी, पिपलिया, कनवाड़ा, मान्दियाखेड़ी मेहरावत में छोटे-छोटे स्टोन औद्योगिक क्षेत्र कलस्टर के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के पनवाड़ में रीको द्वारा राईस मिल औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. झालावाड़ जिले में औद्योगिक विकास के लिये बारां-झालावाड़ मेगा-हाईवे से कनेक्टेड ग्रामीण इलाकों में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. झालावाड़ जिले में छोटे औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल (वि.सं. 83)

117. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम श्री अशोक नगर (बबाई) में स्थापित नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक इन्वायरमेंट क्लीयरेन्स (ई.सी.) जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल (वि.सं. 83)

118. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में मिट्टी के बर्तनों/वस्तुओं के व्यवसाय से जुड़े कारीगरों यथा कुम्हार/प्रजापत आदि को इलेक्ट्रीक चाक एवं मिट्टी गुदने के लिए मशीन उपलब्ध करवाने या उक्त मशीनों के लिए सस्ती दरों पर लोन/लोन पर सब्सिडी दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के बंद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में उद्योग क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हैण्डलूम और हैण्डीक्राफ्ट क्षेत्र का क्लस्टर विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन व लोन पर सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं. 62)

122. मकराना मार्बल उद्योग में तैयार माल (स्लेब, पाटिया, पाऊडर, चिप्स) पर लगने वाला टैक्स जी.एस.टी. 18 प्रतिशत को कम कर 5 प्रतिशत करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. मकराना मार्बल उद्योग के लिए खोले गये उद्योगों को संरक्षित करने हेतु 5 वर्षों तक के लिए ब्याज रहित ऋण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. मकराना उद्योग इण्डिस्ट्रीज को कम ब्याज पर ऋण देने के संबंध में चर्चा के लिये।

125. मकराना मार्बल उद्योग के लिए आर.एफ.सी. लोन ऑफिस मकराना में खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विकास चौधरी (वि.सं. 148)

126. किशनगढ़ में मार्बल, पावरलूम व हैण्डीक्राफ्ट हेतु नई नीति बनाकर कॉम्पलेक्स की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. किशनगढ़ में रीको द्वारा नवीन क्षेत्र चिन्हित कर नवीन इकाई खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह (वि.सं. 55)

128. जैसलमेर में लाईम-स्टोन से निकलने वाली लाईम-डस्ट का उपयोग की संभावनाएं तलाश कर नये उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. जैसलमेर जिले में महिला शिल्पकारों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. जैसलमेर शहर में पीले पत्थर के नक्कासी के केन्द्र खोलने व शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)

131. कोटा जिले के सी.एस.आर. (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) में कम्पनियों द्वारा किये गये निवेश राशि का सी.एस.आर. समिति की अनुशंसा के आधार पर व्यय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. कोटा जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में वायु, जल फिल्टर एवं अग्नि उपकरणों की नियमित जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. कोटा में IT Industries Hub एरिया विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. कोटा में स्थित डी.सी.एम. एवं श्रीराम फैक्ट्री से केमिकल, जिंक एसिड, अमोनिया गैस एवं फ्लाईऐश की नियमित जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. कोटा के रीको इंडस्ट्रीयल एरिया में मूलभूत सुविधाओं (सड़क/पानी/बिजली/सिवरेज/ ड्रेनेज) की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं. 72)</u>

136. प्रदेश के गांवों में बेरोजगारी को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक लोन व सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के राजियास, बीरमाना एवं जैतसर कस्बों में रिको के तहत प्लॉट देकर उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. प्रदेश में दस्तकारों को रियायती दर पर ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. प्रदेश में लघु उद्योग को बढ़ावा देने एवं लघु उद्योग में लोन सब्सिडी को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. राजस्थान प्रदेश में लुप्त होती कुम्हारी कला एवं मिट्टी कला को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भीम राज भाटी (वि.सं. 107)</u>

141. विधान सभा क्षेत्र पाली में सी.एस.आर. फन्ड के तहत राशि के व्यय की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र पाली में नामित सी.एस.आर. कमेटी में स्थानीय विधायक को मनोनीत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र पाली में प्राईवेट उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को नौकरी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं. 172)</u>

144. कोटा में भारत माला प्रोजेक्ट के एक्जिट पॉईंट के आस-पास औद्योगिक क्षेत्र हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. कोटा के रानपुर औद्योगिक क्षेत्र की अप्रोच रोड को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं. 111)</u>

146. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के रीको औद्योगिक क्षेत्र शाहपुरा में डंपिग यार्ड सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के बिशनगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित यादव (वि.सं. 143)

148. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना में लगे उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना रीको के सी.एस.आर. में कंपनियों द्वारा किये गये निवेश का सी.एस.आर. समिति की अनुशंसा के आधार पर व्यय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में रीको एरिया स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना रीको इंडस्ट्रीयल में मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं. 162)

152. प्रदेश के रीको एरियाज में भूखण्ड ऑक्शन द्वारा न देकर अलॉटमेंट द्वारा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. जयपुर के जैतपुरा/कालाडेरा रीको एरिया में क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं. 126)

154. बाड़मेर जिले के बाखासर में सूखा बंदरगाह स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र पर सुविधाएं विकसित करने एवं रीको क्षेत्र का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

156. विधान सभा मुख्यालय शिव पर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र पर सुविधाएं विकसित करने एवं रीको क्षेत्र का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं. 116)

157. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में उद्योगों के विस्तार हेतु कार्य-योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष मील (वि.सं. 179)

159. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के कस्बे के पास औद्योगिक क्षेत्र (रीको) विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुकेश भाकर (वि.सं. 118)

160. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में रीको क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री नौक्षम (वि.सं. 86)

161. विधान सभा क्षेत्र कामां में उद्योगों के लिए दिए जाने वाले अनुदान के बकाया प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र कामां में नये औद्योगिक क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र कामां के सुरहरा स्थित रीको में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं. 01)

164. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के रीको गजनेर एवं रीको क्षेत्र बज्जू का विकास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

165. राजस्थान में लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु कार्य-योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. बीकानेर ऊन मण्डी के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य-योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में सेरेमिक्स उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ताराचन्द (वि.सं. 73)

168. श्रीडूंगरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र की सभावनाएं तलाशने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–32 महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

1. ब्यावर जिले में प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन बनाए जाने एवं नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम (वि.सं.175)

2. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

3. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में महिला कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनियों की राशि बढ़ाने तथा नये भवन व जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं.10)

4. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों की भौतिक स्थिति का सत्यापन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता जांच हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर कमेटी गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बालकों को प्रोत्साहन के लिए विशेष कार्यक्रम "बाल गोपाल" की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. आंगनबाड़ी केन्द्र पर नामांकित बालकों का आधार लिंक करवाने एवं दोहरे नामांकन की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

9. छबड़ा व छीपाबड़ौद तहसील में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)

10. बाल विकास परियोजना कार्यालय शेरगढ़, बालेसर, सेखाला एवं चामू में महिला पर्यवेक्षक सहित विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
11. बाल विकास परियोजना कार्यालय शेरगढ़, बालेसर, सेखाला एवं चामू के भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
12. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों के जर्जर भवनों की मरम्मत करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
14. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री थावर चन्द (वि.सं.75)

15. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में आंगनबाड़ी भवनों में पेयजल, शौचालयों व बाउंड्रीवॉल एवं भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
16. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग में आदिवासी महिलाओं एवं किशोरियों में हीमोग्लोबिन की कमी एवं कुपोषण की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. प्रदेश की आंगनबाड़ियों में तीन दिन पाऊडर के दुग्ध की जगह फल या अन्य पौष्टिक आहार दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

19. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के नए राजस्व गांव/ढाणी/बस्तियों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की पंचायत समिति समदड़ी मुख्यालय पर C.D.P.O. कार्यालय पद सहित स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
21. प्रदेश में विभाग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता परखने एवं पोषाहार तैयार माल यथा पक्का भोजन, बिस्किट, मूंगफली एवं कई प्रकार के अन्य व्यंजन दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
22. ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत आशा सहयोगिनियों के कार्य का मूल्यांकन एवं आंकलन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. प्रदेश की आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों, सहायिकाओं, आशा सुपरवाईजर एवं आशा सहयोगिनियों के चयन हेतु निर्धारित वर्गवार अंक विभाजन के अनुसार चयन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

24. भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
25. प्रदेश में खाली पड़े सरकारी भवनों को आंगनबाड़ी केन्द्रों को आवंटित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
26. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक मानदेय प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)</u>

27. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बालकों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार, दुग्ध एवं फल उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं.98)</u>

28. उदयपुर में नाबालिग बालिकाओं के विवाहों को रोकने हेतु जागरूकता लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)</u>

29. महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियां करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
30. प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
31. प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य विकास हेतु नवाचार किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)</u>

32. महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, नीमराणा में भवन का निर्माण एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
33. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
34. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
35. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिए जाने वाले पोषाहार की मात्रा एवं गुणवत्ता की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)

36. प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में पिछले 5 वर्षों से रिक्त पड़े C.D.P.O. एवं अन्य पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. प्रदेश में आशा सहयोगिनियों एवं कार्यकर्ताओं के रिक्त चल रहे पदों पर अनियमितता करके नियुक्ति देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र आहोर में आंगनबाड़ी केन्द्रों के नये भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र आहोर में विभाग में भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिक का तबादला होने के बाद भी उसके कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र आहोर में महिला एवं बाल विकास विभाग के भवन निर्माण के लिए बजट आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)

41. प्रदेश में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम में सब-आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)

42. प्रदेश में आंगनबाडियों के भवनों का निर्माण एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)

43. विधान सभा क्षेत्र कपासन के आंगनबाड़ी केन्द्रों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत एवं बालकों व गर्भवती महिलाओं को पोषणयुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

44. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने तथा वर्तमान में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं.158)

45. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनियों को संविदा कार्मिक मानकर स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं.96)

46. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में विभिन्न स्थानों पर 20 नए आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

47. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

48. प्रदेश में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों को गंभीरता से लिए जाने तथा महिला कुक को न्यूनतम श्रमिक मजदूरी दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हंसराज मीना (वि.सं.188)

49. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का वितरण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
50. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, सपोटरा में कॉन्फेड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा माह सितम्बर-अक्टूबर, 2022 में पोषाहार वितरण किए बिना भुगतान उठा लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
51. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के कार्यालय बाल विकास परियोजना में पोषाहार वितरण में किए गए भ्रष्टाचार में निर्दोष अधिकारियों/कर्मचारियों को फंसाने और दोषियों को सज़ा नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
52. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं/आशा सहयोगिनियों की नियुक्ति नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

53. गंगापुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं.132)

54. विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू व निवाई में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यूनुस खान (वि.सं.121)

55. नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना पर जिला स्तरीय महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
56. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
57. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में जनसंख्या के अनुपात में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
58. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)

59. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के वंचित गांवों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)

60. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु पोषाहार की खरीद हेतु केन्द्रीयकृत व्यवस्था समाप्त कर स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
61. प्रदेश के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु विधायक मद से राशि उपलब्ध करवाने पर राज्य सरकार द्वारा राज्य मद से 50 प्रतिशत मैचिंग ग्राण्ट के रूप में उपलब्ध कराए जाने की कार्ययोजना अथवा नीतिगत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
62. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु संचालित विभिन्न स्व:रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने एवं धनलक्ष्मी केन्द्रों में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री के लिए उपयोग में लाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
63. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत मानदेय कर्मियों की सेवानिवृत्ति पर उन्हें 5 लाख रूपए प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
64. प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकों के मानदेय में 50 प्रतिशत वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

65. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सर्व सुविधायुक्त भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
66. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में समेकित बाल विकास योजना, पूरक पोषाहार, शालापूर्व शिक्षा, किशोर बालिका पोषाहार योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान आदि योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन नहीं होने एवं पात्र बालिकाओं को पूर्ण लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर पर चर्चा के लिए।
67. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, स्वयं सहायक समूहों एवं उद्यमी महिलाओं के उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए समुचित प्रयास नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
68. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्रों की स्थापना एवं इनके द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।
69. राजसमन्द जिले की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन योजना के क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जीवाराम चौधरी (वि.सं.64)

70. विधान सभा क्षेत्र सांचोर में विभाग को आवंटित भूमि के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)

71. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में नए आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना करने व रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (वि.सं.31)

72. विधान सभा क्षेत्र डग में आंगनबाड़ी का नया भवन बनवाने, पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार एवं C.D.P.O. के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

73. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत झुझार्डी के ग्राम धारेश्वर में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
74. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत बोरीमादा के ग्राम तेलपुरा में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
75. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत झुझार्डी के ग्राम सड़क मालिया में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
76. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत केसुली के ग्राम रामपुरा की ढाणी में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
77. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत भादरलाऊ में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

78. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
79. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महिलाओं एवं बालिकाओं में जागरूकता लाने एवं प्रोत्साहन हेतु विशेष कार्ययोजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
80. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन सी.डी.पी.ओ. कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
81. प्रदेश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग हेतु प्रावधान एवं क्रियान्वयन के सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
82. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में वर्तमान में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में अलग-अलग संवर्ग के समस्त रिक्त पदों को भरे जाने तथा लोकहित में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (वि.सं.123)

83. प्रदेश में महिलाओं को पुन: सेनेट्री नेपकिन्स उपलब्ध कराने तथा मिड-डे मील में पौष्टिक पौषाहार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)

84. प्रदेश में विभाग के कुक का मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामबिलास (वि.सं.135)

85. विधान सभा क्षेत्र लालसोट की ग्राम पंचायत ढोलावास के ग्राम शाहजहांपुर सहित अन्य भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

86. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के संबंध में चर्चा के लिए।
87. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
88. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
89. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले पोषाहार की पौष्टिकता के संबंध में चर्चा के लिए।
90. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत स्टाफ के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)

91. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में ब्लाऊ, आसोतरा निर्मल कुटीर, देरिया, कल्याणपुर, दुधवा, खट्टू एवं पोषाल नगर असाड़ा सराणा, पाटलू, कानाना, थोब आदि ग्राम पंचायतों में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
92. प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर अवकाश दिलाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
93. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं का भवन एवं उनमें शौचालयों की भी व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
94. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पौष्टिक पोषाहार एवं पोषाहार की निर्धारित मात्रा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
95. प्रदेश में आंगनबाड़ी के समस्त कार्यकर्ताओं का वेतन भत्ता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>**डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं.24)**</u>

96. प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन संचालित सी.डी.पी.ओ. कार्यालयों में सूचना सहायक के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के किराए के भवनों में संचालित कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों के स्थान पर स्वयं के भवन निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>**श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)**</u>

98. सुजानगढ़ व बीदासर तहसीलों में नए आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>**श्री जुबेर खान (वि.सं.65)**</u>

99. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की पंचायत समिति रामगढ़ एवं गोविन्दगढ़ (अलवर) में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. जिला अलवर की पंचायत समिति रामगढ़ एवं गोविन्दगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>**श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)**</u>

101. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित सी.डी.पी.ओ. कार्यालय में रिक्त पड़े पदों पर पदस्थापन, कार्मिकों का वेतन भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति एवं महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु लखपति दीदी योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता एवं प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं रसोईयों का मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों तक बाल पौष्टिक आहार के परिवहन के टेण्डर एवं वर्कऑर्डर प्रक्रिया तथा परिवहन में धांधली की शिकायतों का निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>**श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)**</u>

104. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में संचालित भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>**श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)**</u>

105. राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के सफल क्रियान्वयन एवं प्रगति की कार्ययोजना के संबंध में चर्चा के लिए।

106. हनुमानगढ़ जिले में लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में लाभान्वित परिवारों व लम्बित आवेदनों के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं को दी जाने वाली नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण योजना (उड़ान योजना) का संचालन एवं लाभान्वितों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र नोहर में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण व नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

110. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार को आंगनबाड़ी केन्द्र पर ही तैयार किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के नवीन भवन बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं साथिन का मानदेय बढ़ाया जाकर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों का मानदेय का भुगतान प्रतिमाह समय पर करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. जनजाति बाहुल्य क्षेत्र डूँगरपुर जिले में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

115. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खाचरोद (देवर), नपानिया गुजरान, दौत्या, उम्मेदपुरा, जगपुरा, टेकली, श्योपुर खेडली, पिपलिया नग्गा, रटलाई, मिल्की टेकला, सेमलखेड़ा एवं रीसौन के आंगनबाड़ी केन्द्रों के नवीन भवन बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के पनवाड़, नई बस्ती डोबड़ा, मेहरा मौहल्ला, खानपुर, रसूलपुरा खानपुर, टटेरा का बाग़, लालपुरा सारोला, मरायता 2, गुदरी चौराहा, मोथाखेड़ी, मोरूखेड़ी, खेरिया, लात्याखेड़ी, सूरी एवं गोविन्दपुरा में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बिसलाई, मंदिर का चौक करनवास, मोग्या बस्ती गाडरवाडा डून्डी, सिंदनी टापरिया, बडिया बस्ती चलेट, यादव मौहल्ला खानपुर, रान्याखेड़ी, हरिजन बस्ती सारोला, मूण्डला 2 एवं कांकड़दा में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गुणवत्ता विहीन पोषाहार के वितरण पर रोक लगाने एवं पौष्टिक पोषाहार वितरित किए जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के आकोदिया, झून्डी डेडिया, पितामपुरा, देवपुरा, जोलपा-1, मेहण्डड़ी, सरोला कलां-4, शिव नगर ढाणी-1, भरतपुर, मुआखेड़ा, सारोला, घघरावता, सोजपुर, गाडरवाडा नूर जी खेडलीमीरा, बन्या, छत्रपुरा, रतनपुरा, मोड़ी, मालोनी, पीपल्दा, आलोदा के आंगनबाड़ी केन्द्रों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)</u>

120. विधान सभा क्षेत्र भादरा के आंगनबाड़ी केन्द्रों के जर्जर भवनों की शीघ्र मरम्मत एवं नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों में शीघ्र भवन निर्माण किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

122. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगिनियों आदि का मानदेय, भत्ता एवं अन्य सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकन बढ़ाने के लिए बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)</u>

124. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के शौचालय विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी के नवीन केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)</u>

128. सादुलपुर शहर तहसील मुख्यालय पर विभाग के भवन का निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. प्रदेश में विभाग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पोषाहार में जिलेवार मौसमी (ऋतु) फल को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)</u>

130. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में भवन से वंचित आंगनबाड़ी केन्द्रों में नये भवन बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के अनुसूचित जनजाति/विधवा/परित्यक्ता/हिंसा से पीड़ित तथा दिव्यांग महिलाओं को ऋण अनुदान राशि का समय पर भुगतान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती इन्द्रा (वि.सं.20)</u>

134. प्रदेश में विभाग द्वारा महिलाओं को रोजगार दिए जाने हेतु कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत महिला कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

136. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नवीन आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. प्रदेश में आशा सहयोगिनियों एवं आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. प्रदेश में कार्यरत आशा सहयोगिनियों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण व सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)</u>

140. विधान सभा क्षेत्र आसपुर की पंचायत समिति साबला, आसपुर, दोवडा में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने व आवश्यकतानुसार भवनों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)</u>

141. पीलीबंगा शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए जगह उपलब्ध करवाने व भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. पीलीबंगा में महिला एवं बाल विकास कार्यालय हेतु जगह उपलब्ध करवाने व भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा) (वि.सं.154)</u>

143. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में विभाग में सी.डी.पी.ओ. लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

144. प्रदेश में वृद्ध महिलाओं एवं विधवाओं के लिए विशेष आश्रम खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में एनेमिक की समस्या के निदान हेतु कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष स्किल बेस्ड कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं.83)</u>

147. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के प्रत्येक राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना एवं शुद्ध पेयजल, बिजली की सुविधा एवं गर्म पोषाहार देने के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. नवगठित जिला नीम का थाना में जिला स्तर पर महिलाओं हेतु हॉस्टल और पेईंग गेस्ट हाउस बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को सेवा से सेवानिवृत्त होने पर सामाजिक सुरक्षा राशि का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, मरम्मत के लिए विशेष फण्ड जारी करने एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समुचित और निरन्तर प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

151. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आपूर्ति किए जाने वाले पूरक पोषाहार और सेनेटरी नेपकिन को स्थानीय स्तर पर राजीविका अथवा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र मकराना के महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकांश पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

153. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र मकराना के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विभागीय भवनों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विकास चौधरी (वि.सं.148)</u>

155. प्रदेश में प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सेनेटरी नेपकिन वितरण के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगाने व विभाग द्वारा कम्प्यूटर सेंटर स्थापित करके ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में महिलाओं को ट्रेनिंग देने व सिलाई सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में जर्जर आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)

157. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. प्रदेश में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)

160. जैसलमेर जिले में जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. जिला जैसलमेर में पंचायत समिति स्तर पर महिला विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. जैसलमेर जिले में गांवों व ढाणियों में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)

163. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व साथिन का मानदेय एवं सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्र में स्टाफ बढ़ाने एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्लेईंग स्कूल की तर्ज पर चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के प्रत्येक राजस्व गांवों, कच्ची बस्तियों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

168. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) में संचालित भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को भवन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों का जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित यादव (वि.सं.143)

171. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने एवं भवन विहीन केन्द्रों को भवन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पुराने जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं.162)

174. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के आंगनबाड़ी केन्द्रों का विकास और मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

175. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)

176. विधान सभा क्षेत्र शिव में महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त चल रहे पदों पर शीघ्र पदस्थापन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र शिव में जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र, भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र शिव में महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का पुन: सीमांकन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. सीमान्त क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाओं यथा गर्भवतीधात्री महिलाओं, किशोरियों एवं शिशुओं को कुपोषण से बचाव हेतु नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं.116)

181. प्रदेश स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय एवं आवश्यक सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)

182. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में महिला एवं बाल विकास कार्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मुकेश भाकर (वि.सं.118)

183. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में आंगनबाड़ी केन्द्रों में मिलने वाले पोषाहार की गुणवत्ता व केन्द्रों का आधुनिकीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।